दैनिक जागरण

जल्दबाजी में लिया गया सही निर्णय भी गलत परिणाम देता है

नए युग की ओर बांग्लादेश

आनंद कुमार

बांग्लादेश के चुनाव परिणाम सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक संरचना में व्यापक बदलाव के संकेत भी दे रहे हैं

बांग्लादेश का आम चुनाव उसके राजनीतिक इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ में से एक माना जाएगा। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लंबे समय से प्रभावी रही उनकी पार्टी अवामी लीग के प्रभुत्व का अंत किया, के बाद यह पहला आम चुनाव था। इस चुनाव ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को स्पष्ट जनादेश दिया। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना के साथ बांग्लादेश एक नए राजनीतिक युग की ओर बढ़ रहा है, जो पीढ़ीगत परिवर्तन, वैचारिक पुनर्संतुलन और क्षेत्रीय कूटनीतिक समीकरणों से प्रभावित होगा। यह चुनाव केवल अंतरिम सरकार को बदलने की प्रक्रिया नहीं था, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस कर रहे थे। यह उस गहरे राजनीतिक संकट के बाद देश की दिशा तय करने का प्रयास था, जिसने 2024 में पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। जुलाई 2024 का आंदोलन शुरुआत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति के विरोध से शुरू हुआ था, पर जल्द ही यह व्यापक असंतोष का रूप ले बैठा। सैकड़ों लोगों की मौत ने सरकार की वैधता को गंभीर रूप से प्रभावित किया और अंततः सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अंतरिम सरकार ने लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना और संस्थागत सुधारों का वादा किया और इसी क्रम में 13वां संसदीय चुनाव और संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह आयोजित किया गया। इसका परिणाम न केवल सत्ता परिवर्तन है, बल्कि राजनीतिक संरचना में व्यापक बदलाव का संकेत भी है।

इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता अवामी लीग की अनुपस्थिति रही। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित अपराधों के आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने दशकों से चली आ रही द्विदलीय प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल भी खड़े किए। 1990 के बाद से बांग्लादेश की राजनीति अवामी लीग और बीएनपी के बीच घूमती रही। बीएनपी की जीत उसके लिए पुनरुत्थान और परीक्षा, दोनों है। वर्षों तक विपक्ष में रहने और आंतरिक चुनौतियों से जूझने के बाद पार्टी ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की है। तारिक रहमान का नेतृत्व एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। यह परिवर्तन केवल अंतरिम प्रशासन से सत्ता हस्तांतरण नहीं है, बल्कि उनकी मां एवं पूर्व पीएम खालिदा जिया और शेख हसीना के युग से आगे बढ़ने का संकेत भी है। हालांकि बांग्लादेश में वंशवादी राजनीति का प्रभाव बना हुआ है, फिर भी रहमान ने अपने चुनाव अभियान में अपेक्षाकृत संयमित और व्यावहारिक रुख अपनाया। उन्होंने कानून-व्यवस्था, आर्थिक सुधार और युवाओं के लिए रोजगार पर जोर दिया। भारत के प्रति उनका रुख नरम रहा, जो भविष्य की कूटनीतिक संभावनाओं का संकेत देता है। अपनी मां के निधन के कारण विजय उत्सव स्थगित करने का उनका निर्णय राजनीतिक परिपक्वता का संदेश देता है। चुनाव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जमात-ए-इस्लामी का उभार है। वह मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में उभरी है। उसका प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बांग्लादेश की राजनीति में राजनीतिक इस्लाम की उपस्थिति अब भी प्रभावशाली है। हालांकि वह सत्ता में नहीं पहुंची, लेकिन उसकी सीटों में वृद्धि महत्व रखती है। उसका उभार देश के पंथनिरपेक्ष तबकों और पड़ोसी देशों में चिंता का विषय रहेगा।

2024 के आंदोलन से उभरी छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। क्रांतिकारी ऊर्जा को संगठित राजनीतिक शक्ति में बदलना आसान नहीं होता और यही उसके साथ हुआ। जमात-ए-इस्लामी के साथ उसका गठबंधन उसके समर्थकों के बीच असमंजस का कारण बना। यह दर्शाता है कि जनांदोलन से निकली ताकतों को संस्थागत राजनीति में टिके रहने के लिए मजबूत संगठन और संसाधनों की जरूरत होती है। चुनाव ने सामाजिक चुनौतियों को भी उजागर किया। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही, जबकि 2024 के आंदोलन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी। आर्थिक मोर्चे पर नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात विशेषकर परिधान उद्योग पर निर्भर है। राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है। जुलाई राष्ट्रीय चार्टर के तहत प्रस्तावित संवैधानिक सुधार तय करेंगे कि कार्यपालिका की शक्ति सीमित होगी या नहीं?

भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी नहीं, रणनीतिक साझेदार है। करीब 4,000 किमी लंबी साझा सीमा, पूर्वोत्तर भारत के लिए संपर्क मार्ग और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे दोनों देशों को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देकर यह संकेत दिया है कि भारत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगा। हालांकि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी कूटनीतिक जटिलता पैदा कर सकती है। चीन भी इस बदलाव पर नजर रखेगा, क्योंकि उसके निवेश और सामरिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से हालिया संपर्क भी क्षेत्रीय समीकरणों में नया तत्व जोड़ता है, हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ गहरे रणनीतिक बदलाव की संभावना को सीमित करता है। चुनाव नतीजे यह भी दिखाते हैं कि बांग्लादेश वैचारिक ध्रुवीकरण से थक चुका है और स्थिरता तथा आर्थिक प्रगति चाहता है। राजनीतिक इस्लाम की उपस्थिति बढ़ी है, पर उसने मुख्यधारा की सत्ता को प्रतिस्थापित नहीं किया। बीएनपी के सामने अवसर है कि वह अपने जनादेश का उपयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और समावेशी शासन देने के लिए करे। यदि सत्ता का प्रयोग प्रतिशोध के बजाय सुधार के लिए किया जाता है, तो बांग्लादेश अधिक संतुलित और स्थिर भविष्य की ओर जा सकता है। बांग्लादेश की जनता ने परिवर्तन को चुना है, उथल-पुथल को नहीं। इस राजनीतिक संक्रमण की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि नई सरकार लोकतांत्रिक गरिमा, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को किस हद तक सुनिश्चित कर पाती है।

(लेखक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में सीनियर फेलो हैं)

response@jagran.com

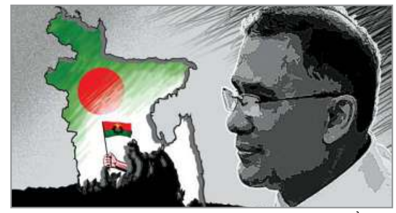

अवधेश राजपूत

बांग्लादेश में बदलाव

लंबे समय तक अस्थिरता-अराजकता से जूझते रहे बांग्लादेश के चुनाव परिणाम इस देश को स्थिरता प्रदान करते दिख रहे हैं। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों से कहीं अधिक सीटें जीतने में सफल रही और उसके नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बांग्लादेश के चुनाव आम तौर पर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन उन्हें निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तथ्य यह भी है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप उभरी जमात-ए-इस्लामी चुनाव नतीजों को स्वीकार करने में आनाकानी करती दिख रही है। बांग्लादेश में हमेशा चुनावों की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। चूंकि कट्टरपंथी और पाकिस्तानपरस्त जमात-ए-इस्लामी परास्त हो गई, इसलिए भारत राहत की सांस ले सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसे उम्मीद से कहीं अधिक सीटें मिलीं। जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को कोई खास सफलता न मिलना भी भारत के लिए राहतकारी है। इन्हीं छात्रों ने जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसके नतीजे में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। भारत विरोधी तेवर अपनाए नेशनल सिटीजन पार्टी का हश्र यही बताता है कि उसका आंदोलन न तो किसी क्रांति का परिचायक था और न ही किसी सकारात्मक बदलाव का।

चूंकि बांग्लादेश में चुनाव के साथ संवैधानिक बदलावों पर जनमत संग्रह भी हुआ, इसलिए वहां नई सरकार के गठन के साथ ही राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन होना तय है। यह स्वाभाविक है कि बांग्लादेश की नई सरकार के रवैये पर भारत की गहरी निगाह होगी। भारत को न केवल यह देखना होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार उसके हितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देती है या नहीं, बल्कि यह भी कि वह कट्टरपंथियों समेत अन्य भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाती है या नहीं? भारत को यह तो खास तौर पर देखना होगा कि इस पड़ोसी देश में हिंदुओं का दमन रुकता है या नहीं? बांग्लादेश की नई सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके यहां पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही गुटों को शरण न मिले। भारत की चिंता का विषय यह भी रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय बांग्लादेश की पाकिस्तान से निकटता अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी। यदि यह निकटता कम नहीं हुई तो भारत के साथ खुद बांग्लादेश के लिए खतरा बढ़ेगा। बांग्लादेश को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसे पाकिस्तान की बर्बरता से मुक्ति और आजादी भारत के सहयोग से ही मिली थी।

सार्थक पहल

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के जीर्णोद्धार के लिए उठाए गए कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। गोड्डा और दुमका जैसे दूरदराज जिलों के सदर अस्पतालों के लिए बड़ी राशि की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना का निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें इस जटिल और महंगे इलाज की आवश्यकता होती है। हालांकि केवल बुनियादी ढांचे का सुधार ही पर्याप्त नहीं होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी है कि चिकित्साकर्मियों की संख्या और गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए। आज भी झारखंड के कई दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सकों और नर्सों की भारी कमी है, जिसके कारण लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई अस्पतालों में बुनियादी उपकरणों की कमी भी बड़ी समस्या है। मेडिकल कालेजों में ओपीडी ब्लाक और उपकरणों के विस्तार की योजनाएं भी सही दिशा में कदम है। इससे इतर इन योजनाओं का असर तभी होगा जब अस्पतालों में सही तरीके से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिलेगा। इसलिए इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनके साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी है कि चिकित्साकर्मियों की संख्या और गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए

खतरा बना एंटीबायोटिक का दुरुपयोग

डा. नरेंद्र सैनी

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई केवल डाक्टरों या सरकार की नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) आज दुनिया के सामने खड़े सबसे गंभीर, लेकिन सबसे कम समझे गए या जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। यह समस्या धीरे-धीरे उपचार के आधार को कमजोर कर रही है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी जब दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, तब सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका असर और भी गहरा है, जहां संक्रमण का बोझ अधिक और स्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं। 2019 में दुनिया भर में लगभग 50 लाख मौतें एएमआर से जुड़ी थीं। यदि वर्तमान में हम इसे लेकर जागरूक नहीं हुए और इस पर नियंत्रण नहीं किया, तो भविष्य में यह संख्या प्रतिवर्ष एक करोड़ तक पहुंच सकती है। यह संकट इसलिए भी खतरनाक है, क्योंकि इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं, जब उपचार बेअसर होने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

प्रधानमंत्री मोदी यह कहते रहे हैं कि चिकित्सकीय परामर्श के बिना एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अपील इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम सर्दी-खांसी, बुखार या वायरल संक्रमण जैसे कई रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। इसके बावजूद दवाओं का अनावश्यक और तर्कहीन उपयोग हमारे समाज में आम व्यवहार बन चुका है। इस तरह का अंधाधुंध प्रयोग सूक्ष्म जीवों को और अधिक प्रतिरोधी बनने का अवसर देता है, जिससे भविष्य में जीवन रक्षक दवाएं असरहीन हो सकती हैं। यह स्थिति इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि जिस गति से सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी बन रहे हैं, उस अनुपात में नई एंटीबायोटिक दवाएं विकसित नहीं हो रहीं। पिछले लगभग दो दशकों में एंटीबायोटिक्स की कोई नई प्रमुख श्रेणी सामने नहीं आई है। एक नई एंटीबायोटिक दवा विकसित करना 15 से 20 वर्षों का लंबा, जटिल और अत्यंत महंगा कार्य है। भारी निवेश के बावजूद आर्थिक प्रतिफल सीमित रहता है। यही कारण है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां इस क्षेत्र में बड़े निवेश से कतराती हैं।

डाक्टर के परामर्श से ही खाएं एंटीबायोटिक दवा। प्रतीकात्मक

सरकार ने एएमआर को रोकने के लिए कई स्तरों पर कार्ययोजना बनाई है। राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दवा प्रतिरोध के रुझानों पर समय रहते नजर रखी जा सके। एंटीबायोटिक की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर नियंत्रण, अस्पतालों में एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप कार्यक्रम और प्रयोगशाला आधारित जांच को बढ़ावा देना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास भी सरकार की वन हेल्थ रणनीति का हिस्सा हैं, जो मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा मानती है। इस लड़ाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अहम भूमिका में है। आइएमए देश भर के चिकित्सकों को एएमआर के प्रति जागरूक करने, जिम्मेदार प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ावा देने और आम जनता तक सही संदेश पहुंचाने में सक्रिय जिम्मेदारी निभा रहा है। आइएमए की एएमआर कमेटी लगातार यह चेतावनी देती रही है कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग केवल इलाज को मुश्किल नहीं बनाता, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए खतरा पैदा करता है। एंटीबायोटिक का सबसे अधिक दुरुपयोग मानव स्वास्थ्य की रक्षा के बजाय पशुओं, फल और सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाने में हो रहा है। इस संकट का एक गंभीर पहलू पर्यावरण और नदियों से भी जुड़ा है। मानव गतिविधियों, अस्पतालों के अपशिष्ट, औद्योगिक कचरे, फार्मों से बहकर आने वाले एंटीबायोटिक अवशेष और पशुओं के मल-मूत्र के कारण नदियां, तालाब और भूजल भी एएमआर से संक्रमित हो रहे हैं। कई नदियों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक अवशेष पाए जाने की चेतावनियां विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं। ये एएमआर का सक्रिय वाहक बनते जा रहे हैं, जो पानी, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला के जरिये मानव तक यह खतरा पहुंचा रहा है। इससे भोजन श्रृंखला दूषित और जल स्रोत संक्रमित हो रहे हैं। सामान्य जल शोधन प्रणालियां एएमआर को छानने में सक्षम नहीं हैं, जिससे यह पानी के जरिये भी मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है।

एएमआर के खिलाफ लड़ाई केवल डाक्टरों या सरकार की नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। जब तक आम नागरिक इस खतरे को नहीं समझेंगे, तब तक नीतियां और नियम सीमित असर ही दिखा पाएंगे। एंटीबायोटिक का उपयोग केवल योग्य चिकित्सकों की पर्ची पर होना चाहिए। दवाओं की पूरी खुराक और सही अवधि का पालन जरूरी है। ओवर-द-काउंटर बिक्री पर लगे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन होना चाहिए। स्वच्छता, साफ-सफाई, सुरक्षित पानी और व्यापक टीकाकरण संक्रमण को रोकने के सबसे प्रभावी साधन हैं। बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाओं से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सही बीमारी में सही दवा दी जाए। साथ ही एंटीमाइक्रोबियल अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकारी निवेश और प्रोत्साहन बढ़ाना समय की मांग है। अंततः एएमआर केवल एक चिकित्सकीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत चुनौती है। आज एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदार उपयोग ही यह तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के पास इलाज के प्रभावी विकल्प बचेंगे या नहीं।

(लेखक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एएमआर कमेटी के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम का स्वरूप

कण-कण में विद्यमान आकर्षण से जगत का अस्तित्व है। यही आकर्षण प्रेम है। प्रेम जगत के लिए उतना ही सत्य है, जितना परमात्मा। प्रेम को जाने बिना उसे जाना नहीं जा सकता। "प्रेम हरि को रूप है, हरि हैं प्रेम स्वरूप" कहकर ईश्वर एवं प्रेम की एकात्मता का प्रतिपादन किया गया है। अतः प्रेम के बिना तो जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता के कारण इसे प्रेमी-प्रेमिका के कलुषित प्रेम तक सीमित कर दिया गया है। यह प्रेम आधारित न होकर वासनाजन्य आकर्षण होता है। आज इसके जिस रूप को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह उचित नहीं। भारत जैसे देश में इसके कुप्रभाव नजर आ रहे हैं। यदि सच्चा प्रेम होगा तो उसकी परिणति पति-पत्नी रूप में होगी। भारतीय संस्कृति में इसका कोई विकल्प नहीं। दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रणय संबंध इसका उदाहरण है, जिनके पुत्र का नाम इस देश के नामकरण का आधार बना।

प्रेम का स्वरूप व्यापक होने से यही सभी संबंधों का आधार है। इसके बिना कोई संबंध होता ही नहीं, यदि होता है तो टिकता नहीं। प्रेम का अतिरेक इन्हें जीवंत रखता है। भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के संबंध की आधारभूमि आंतरिक प्रेम, त्याग एवं समर्पण है, वासना नहीं। इसलिए सात जन्मों का होता है। प्रेम संबंधों का आत्मा है और कसौटी भी। प्रेम के बिना प्रगाढ़ रिश्ता भी निष्प्राण होता है, किंतु प्रेम होने पर कोई भी संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। प्रेम में जड़-चेतन का भी भेद नहीं होता। इसीलिए धरती मां बन जाती है, आकाश पिता और चंदा मामा। सूरजमुखी का सूरज से, चकोर का चंदा से रिश्ता प्रेम की देशकाल निरपेक्षता के प्रमाण हैं। प्रेम की कोई सीमा भी नहीं, वह परमात्मा की तरह अनादि-अनंत है। आज प्रेम की पवित्रता समझकर रिश्तों को दीर्घजीवी बनाने का संकल्प लें। तभी प्रेम की सार्थकता है और जीवन की भी।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

मानसिक विकारों की गिरफ्त में युवा

प्रदीप

तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण अधिकांश लोग मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं

भारत समेत पूरी दुनिया में युवा तेजी से मानसिक विकारों, जैसे अवसाद (डिप्रेशन), चिंता (एंजायटी) और अनिद्रा की चपेट में आ रहे हैं, जो उनके दैनिक जीवन, शिक्षा और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। इंडियन साइकायट्रिक सोसायटी के हालिया आंकड़ों के मुताबिक आज भारत में लगभग 60 प्रतिशत मानसिक विकार 35 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जा रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति (लगभग 10.6 प्रतिशत) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। 21वीं सदी में जीवन बेहद भाग-दौड़ वाला हो गया है। जीवन में सरलता, सहजता और प्रकृति के साथ तालमेल कम होता जा रहा है, चारों तरफ तनाव-ही-तनाव और उससे पैदा हुए शारीरिक और मानसिक विकार। तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण अधिकांश लोग मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर चार में से एक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मानसिक विकार से पीड़ित होता है।

हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कई रसायन प्रभावित करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। उनमें सबसे प्रमुख है सिरोटोनिन। शरीर में इनका अच्छा स्राव हमें खुशमिजाज रखता है। सिरोटोनिन भूख, नींद, सीखने की प्रवृत्ति और याददाश्त संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारे भाव और पर्यावरण के बोध के आधार पर मस्तिष्क नसों में रसायन छोड़ता है। ये ही रसायन खून में घुल कर पूरे शरीर में घूमते हैं और कोशिकाओं और अंगों को संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आंख खोलते ही किसी प्रियजन को देखते हैं, तो मस्तिष्क खून में कुछ खास तरह के रस, कुछ हार्मोन छोड़ता है। इनके नाम हैं डोपामाइन और आक्सिटोसिन। इन रसायनों से कोशिकाओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसीलिए किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने पर चेहरा चमकने, दमकने लगता है। इससे उलटा होता है, जब हम किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तब मस्तिष्क तनाव, शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ने लगता है। यह दिमाग का प्रतिरक्षा तंत्र है, क्योंकि तनाव में शरीर वह सब कर सकता है, जो प्रसन्न रूप में नहीं करता।

युवाओं में मनोविकारों के बढ़ते मामले सिर्फ भावनात्मक दुर्बलता या रासायनिक असंतुलन के ही नतीजे नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक कारकों का जटिल तंत्र काम कर रहा है। आधुनिक जीवनशैली ने युवाओं को अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं, मगर साथ ही अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन की ऐसी संस्कृति भी निर्मित की है, जिसमें असफलता को स्वीकार करने का स्थान अत्यंत सीमित होता जा रहा है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

बढ़ता स्क्रीन टाइम

डा. विशेष गुप्ता द्वारा लिखित आलेख "बच्चों को हिंसक बनाता डिजिटल संसार" इस विषय को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। विद्वानों ने कहानियों के महत्व को अपनी किताबों में बताया है। मुझे बचपन में दादी से सुनी हुई कहानियां आज भी याद हैं, लेकिन मोबाइल फोन पर कुछ आधे सेकेंड पहले देखी गई रील तक याद नहीं रहती। आज किसी माता-पिता को यह कहते हुए सुनती हूं कि बच्चा फोन के बिना खाना नहीं खाता, तो आश्चर्य होता है। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते समय बच्चा रोता है और उसकी मां कहती है कि वह फोन के लिए रो रहा है, तो परिस्थिति की गंभीरता का अहसास होता है। टेक्नोलाजी भावनाएं नहीं समझा सकती, लेकिन इंसानों की भावनाएं कब पूरी तरह उस पर निर्भर हो गईं, यह पता ही नहीं चला। भारत में अब अक्सर घर के बड़ों का स्क्रीन टाइम भी बच्चों के बराबर या उनसे अधिक हो गया है। इंसान की बुनियादी जरूरतें कपड़ा, मकान और रोटी मानी जाती थीं, लेकिन कब इसमें एल्गोरिदम भी शामिल हो गया, इसका अहसास ही नहीं हुआ। स्क्रीन डिपेंडेंसी डिसआर्डर ने कब लोगों को अपना शिकार बना लिया, यह उनके डोपामाइन ने उन्हें समझने नहीं दिया। साथ ही साफ्ट पावर और एडिक्शन के कारण हुई यह नान-वायलेंट मृत्यु भारत में एक नई दुविधा के रूप में जन्म ले रही है। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा पहले ही दी गई इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए यह आवश्यक है कि बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य, जागरूकता और नियमन पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए, ताकि तकनीक सुविधा के साथ-साथ समाज के लिए सुरक्षित भी बन सके।

खुशी जायसवाल, जम्मू

टोल प्लाजा पर विवाद

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की निर्धारित गति 100/70 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन गाजीपुर के पास टोल प्लाजा पर अचानक गति धीमी करनी पड़ती है। नगर निगम दिल्ली द्वारा बनाए गए ये टोल प्लाजा लंबे समय से विवादों में रहे हैं। बीते दिनों एक कार टोल प्लाजा पर खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिसमें एक मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटा घायल है। मृत महिला के तीन और पांच वर्ष के दो बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और मां के साये से वंचित हो गए। इन टोल प्लाजा पर वाणिज्यिक वाहनों से टोल वसूली के कारण भारी जाम लगता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। विडंबना यह है कि प्रदूषण कम करने के नाम पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी वसूला जा रहा है। यह शुल्क उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत लिया जाता है। यह मुद्दा लंबे समय से सरकारों और संबंधित संस्थाओं के संज्ञान में है-केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली सरकार, विपक्षी दल और यहां तक कि न्यायालय भी इन टोल प्लाजा को हटाने की बात कह चुके हैं, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है-नगर निगम दिल्ली, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, न्यायालय के निर्देश या वह चालक जो थकान में तेज गति से वाहन चला रहा था? शायद कोई भी सीधे जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दो महिलाओं की जान चली गई और दो बच्चे अनाथ हो गए। क्या जिम्मेदार अब जागेंगे और कोई ठोस कार्रवाई होगी?

पीयूष गर्ग, नई दिल्ली

समस्याएं यथावत

आजादी के सत्तर साल बाद भी कई समस्याएं विभिन्न रूपों में बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार व्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। यदि आतंकवाद और अलगाववाद पर 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाई जाए, संसदीय गतिरोध पर परिपक्व राजनीति विकसित हो, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और जन-जागरूकता बढ़े, तथा एआइ, आटोमेशन, एफडीआइ, एमएसएमई, ईज आफ डूइंग बिजनेस और मुक्त व्यापार समझौतों जैसे आर्थिक सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, तो 2047 तक भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।

malivishanaram@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

11.7 लाख थी वर्ष 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में उन बच्चों एवं युवाओं की संख्या जो शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रहे यानी ये बच्चे शिक्षा व्यवस्था में नहीं आ सके हैं।

आजकल

संतुलन और विवेक से होगा एआइ का संधान

वर्तमान शिक्षा पद्धति एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है जहां ज्ञान, तकनीक और मानव चेतना के पारस्परिक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। शिक्षा अब पाठ्य-पुस्तकों और कक्षाओं तक सीमित प्रक्रिया से आगे बढ़कर डिजिटल माध्यमों, एल्गोरिदमिक प्रणालियों और कृत्रिम मेधा से गहरे स्तर पर जुड़ चुकी है। आज सूचना की उपलब्धता अभूतपूर्व है, परंतु सीखने की प्रकृति, संज्ञानात्मक श्रम और बौद्धिक अनुशासन जैसे मामले अधिक जटिल बन चुके हैं। ऐसे में तकनीक और उसके उपयोग पर चिंता स्वाभाविक है

पीयूष कुमार दुबे
असिस्टेंट प्रोफेसर, कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रतीकात्मक

तकनीक और कृत्रिम मेधा (एआइ) को लेकर आज जो बहस चल रही है, वह पूरी तरह नई नहीं है। पहले पूरा विज्ञान चर्चा के केंद्र में था। आज वही स्थान विशेष रूप से कृत्रिम मेधा और डिजिटल तकनीक ने ले लिया है। तब निबंध में हमारा निष्कर्ष प्रायः संतुलन और विवेक पर जाकर टिकता था। विज्ञान स्वयं में न वरदान था, न अभिशाप। उसका प्रभाव उसके उपयोग पर निर्भर करता था। देखा जाए तो यही बात आज की तकनीक पर भी लागू होती है।

विचार करें तो नई तकनीकें मूलतः सहायक साधन हैं, किंतु चिंताजनक यह है कि वर्तमान समाज में वे केवल साधन नहीं रह गई हैं, वे सोचने, निर्णय लेने और सीखने की आदतों को प्रभावित करने वाली संरचनाएं बन चुकी हैं। विशेषकर युवाओं के संदर्भ में, डिजिटल उपकरणों और एआइ-आधारित प्रणालियों की निरंतर उपस्थिति ने सीखने की प्रक्रिया को तेज, सुलभ और वैयक्तिकृत तो किया है, पर साथ ही यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या यह सुविधा संज्ञानात्मक प्रयास की मात्रा को कम कर रही है? शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल उत्तर प्राप्त करना नहीं, अपितु प्रश्न गढ़ने, तर्क करने और वैचारिक संघर्ष से गुजरने की क्षमता विकसित करना रहा है। परंतु आज जब तकनीक इन प्रक्रियाओं को सहज बना रही है, तब यह देखना आवश्यक हो जाता है कि यह सहजता कहीं बौद्धिक शिथिलता में तो नहीं बदल रही।

एआइ का शैक्षणिक उपयोग इसी द्वंद्व का सबसे सशक्त उदाहरण है। एआइ-आधारित प्रणालियां विद्यार्थी की गति, रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामग्री प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक समावेशी और अनुकूल बनती है। परंतु हाल के वर्षों में हुए कुछ अध्ययन यह संकेत देते हैं कि जब विद्यार्थी अत्यधिक रूप से एआइ पर निर्भर हो जाते हैं, तब समस्या-समाधान में उनकी सक्रिय संज्ञानात्मक भागीदारी घट सकती है। उदाहरण के तौर पर, गत वर्ष मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन प्रतिभागियों ने निबंध लिखने के लिए एआइ उपकरणों का सहारा लिया, उनके मस्तिष्क में उस समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधि अपेक्षाकृत कम सक्रिय रही।

वस्तुतः एआइ संबंधी चिंताएं वैधानिक व्यवस्था का भी हिस्सा बनती जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के तहत एआइ-जनित सामग्री, विशेष रूप से डीपफेक जैसी भ्रामक तकनीकों के संदर्भ में डिजिटल माध्यमों की जवाबदेही को सुदृढ़ किया गया है। अब डिजिटल माध्यमों के लिए यह आवश्यक किया गया है कि वे एआइ द्वारा निर्मित या परिवर्तित सामग्री के बारे में स्पष्ट संकेत दें तथा हानिकारक या भ्रामक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस प्रकार के नीतिगत पहल इस विषय की गंभीरता को ही रेखांकित करते हैं। इसी संदर्भ में वैश्विक नीति-स्तर पर भी गंभीर विमर्श उभरता दिखाई देता है। यूनेस्को जैसी संस्थाएं शिक्षा में एआइ और न्यूरोटेक्नोलाजी के उपयोग को दक्षता से आगे रखते हुए न्यूरो-डाटा सुरक्षा और मानव बौद्धिक पूंजी के संरक्षण के प्रश्न के रूप में देख रही हैं।

नीति-संबंधी ये चिंताएं इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि शिक्षा में एआइ का प्रश्न केवल कक्षा या पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। यह प्रश्न मानव विकास की दिशा से जुड़ा हुआ है। यदि शिक्षा-प्रणाली तकनीक को बिना नैतिक और संज्ञानात्मक ढांचे के अपनाती है, तो वह अल्पकालिक दक्षता तो उत्पन्न कर सकती है, परंतु इससे दीर्घकालिक बौद्धिक स्वायत्तता के क्षीण होने का संकट भी पैदा हो सकता है।

इसके विपरीत, यदि तकनीक को मानव-केंद्रित शिक्षा की व्यापक दृष्टि के भीतर रखा जाए, तो वह सीखने को अधिक अर्थपूर्ण और समावेशी बना सकती है।

इस पूरे परिदृश्य में तकनीक के विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ तकनीक से दूरी बनाना नहीं, उसके साथ एक सचेत, आलोचनात्मक और नियंत्रित संबंध स्थापित करना है। शिक्षा का लक्ष्य तकनीकी रूप से निर्भर व्यक्ति का निर्माण नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना है जो तकनीक का उपयोग अपने विचारों को स्पष्ट करने, प्रश्नों को गहरा करने और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए कर सके। मनुष्य को यह बात याद रखनी चाहिए कि कृत्रिम मेधा का निर्माण उसने तब किया, जब उसके पास ऐसी कोई तकनीकी शक्ति नहीं थी। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि मानव की समझ, कल्पना और रचनात्मकता स्वभावतः ही अत्यंत गहरी और व्यापक है।

अतः नई तकनीक और कृत्रिम मेधा के साथ युवाओं का तालमेल एक सरल अनुकूलन का प्रश्न नहीं है। यह एक गहन शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रश्न है, जो शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करता है। वैश्विक नीति-विमर्श यह स्पष्ट करते हैं कि एआइ न तो पूर्ण समाधान है और न ही अनिवार्य संकट। वह एक संभावनाशील माध्यम है, जिसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस विवेक और उद्देश्य के साथ अपनाते हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि मनुष्य तकनीक के प्रति संतुलित दृष्टि बनाए रखे। क्षणिक सुविधा या आकर्षण के प्रभाव में अपनी बौद्धिक स्वायत्तता का त्याग उचित नहीं। कृत्रिम मेधा का वास्तविक महत्व तभी है, जब वह मानव की रचनात्मकता को विस्तार दे, न कि उसका स्थान ले।

एआइ की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

ट्रेवर मुंडेल
अध्यक्ष, ग्लोबल हेल्थ, गेट्स फाउंडेशन

दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रगति को अब तक दो बड़ी उपलब्धियों के आधार पर देखा गया है। पहली, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार। दूसरी, ऐसी नई तकनीकों और साधनों का विकास जो बीमारी की पहचान, इलाज और रोकथाम कर सकें। इन प्रयासों ने करोड़ों लोगों को जीवनदान दिया है। लेकिन अब एक और गंभीर चुनौती सामने है, जिस पर उतना ध्यान नहीं गया। लोग अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जांच भी हो रही है, योजनाओं में नाम भी दर्ज हो रहा है, फिर भी रोकी जा सकने वाली जटिलताएं और मौतें हो रही हैं। वजह है कि बीमारी का खतरा देर से पकड़ा जाता है। इलाज के बाद निगरानी कम हो जाती है। अलग-अलग जगहों पर सेवा की गुणवत्ता में अंतर है। रोकथाम, जांच और इलाज आपस में जुड़ी कड़ी बनने के बजाय कई बार अलग हिस्सों में सिमट कर रह जाते हैं। असल चुनौती है जोखिम की सटीक व समय रहते पहचान करना और उस पर नजर बनाए रखना।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की पारंपरिक नीतियां दरअसल व्यापक आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ऐसे में यह तय कर पाना आसान नहीं होता कि किस व्यक्ति को किस समय अधिक प्राथमिकता दी जाए। स्वास्थ्यकर्मी चाहे कितने ही प्रतिबद्ध क्यों न हों, हजारों लोगों के बदलते जोखिम पर अकेले निगाह रखना व्यावहारिक रूप से कठिन है। परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य प्रणालियां नियमित आंकड़ों, सुसंगठित रिकार्ड और डिजिटल प्रक्रियाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर पा रही हैं। इससे समय पर जांच, उपचार संबंधी निर्णयों में स्पष्टता और इलाज की निरंतरता को मजबूत करने में सहायता मिल रही है। भारत ने बड़े पैमाने पर इन प्रयासों को अपनाकर यह दिखाया है कि ऐसे उपाय जमीन पर किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं। इस बदलाव की झलक तीन प्रमुख क्षेत्रों में मिलती है :

पहला, बीमारी और जोखिम की समय रहते पहचान। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किन लोगों में बीमारी की आशंका अधिक है, तो समय रहते हस्तक्षेप संभव होता है और सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जांच के बाद इलाज की निरंतरता सुनिश्चित करना। तीसरा, समुदाय स्तर पर समय पर और स्थानीय जरूरत के अनुरूप रोकथाम। दरअसल अब तक रोकथाम के लिए बड़े अभियानों और सामान्य परामर्श पर ही अधिक भरोसा रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी कई बार तब तक पहुंचती है, जब तक उसका असर सीमित हो चुका होता है। यही कारण है कि विश्वसनीय आंकड़े, मजबूत रिकार्ड और सार्वजनिक प्रणालियों के साथ तालमेल पर विशेष जोर देना जरूरी है। इसमें तीन प्राथमिकताएं सामने आती हैं : पहली, कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल गतिविधियों से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य परिणामों से किया जाए। दूसरी, पूरी देखभाल प्रक्रिया को सहारा देने वाली बुनियाद को मजबूत किया जाए। तीसरी, सफल प्रयोगों को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में रोकथाम सबसे प्रभावी रणनीति रही है। जरूरत इस बात की है कि इसे अधिक सटीकता के साथ लागू किया जाए। साथ ही, हम हर पहल को परखें, ईमानदारी से उसका आकलन करें और उन्हीं उपायों को विस्तार दें जिनसे वास्तव में नुकसान की आशंका बहुत कम है। तब स्वास्थ्य क्षेत्र में एआइ का सबसे बड़ा योगदान किसी नई दवा या उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था के रूप में सामने आएगा जो जोखिम को समय रहते पहचान सके, उसके संकेत पढ़ सके और लोगों को अधिक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ने में निरंतर मदद करे। इन सभी कार्यों में एआइ की व्यापक मदद ली जा सकती है।

खरी-खरी

टैगासुर...

रेखा शाह आरबी

फेसबुक पर प्रोफाइल रखने पर थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। फेसबुक पर यदि आपके शब्दों में चूक हुई तो यहां शब्दों की गोली बरसती है। फेसबुक में ऐसे खतरे भी ज्यादातर मिलेंगे कि आप अपने सिर के बालों को नुकसान पहुंचा लें। यदि समझदार प्राणी है तो जान-माल तो खतरे में नहीं रहता है लेकिन मान, सम्मान पर खतरा तो आ ही जाता है। फेसबुक पर कभी अकाउंट हैक होने का खतरा है, तो कभी किसी के पोस्ट पर मन मुताबिक कमेंट नहीं देने पर दुश्मनी होने का खतरा है।

फेसबुक भी कुंभ मेले जैसा है। जहां पर अपार भीड़ है। जिसमें शरीफ, चोर, लुटेरे, लुच्चे, लफंगे सारे विचरते रहते हैं। कुछ अपने चेहरे पर नकाब डालकर रहते हैं, कुछ खुलेआम रहते हैं। फेसबुक पर रहिए या नहीं रहिए, लेकिन कुछ लोग आपको पोस्ट के साथ टैग कर ही देते हैं। और आप दांत निपोरते हुए रह जाते हैं। वैसे इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप एक पोस्ट अपनी वाल पर लगाएंगे। यह रोज 10 पोस्ट करेंगे और उसमें आपको टैग करके आपकी वाल पर सजा देंगे। ऐसा लगता है कि बिना गुनाह के सजा इंसान काट रहा है। अपनी पोस्ट का अता-पता नहीं रहता है। और लोगों की पोस्ट, पिक्चर से आपकी वाल भरी रहती है। कुछ लोग तो ऐसे टैग करते हैं जैसे राशन कार्ड में नाम जुड़वा रहे हों, पूछने की जरूरत भी नहीं समझते हैं। वह बिना पूछे ही हमारे अकाउंट को अपना अकाउंट मानकर चलते हैं। और उनका यह प्रेम देखकर कुछ बोलते हुए भी नहीं बनता है। आखिर एक हो तो इनसे मुक्ति पा जाए। कह सकते हैं कि फेसबुक पर बैठा हुआ हर तीसरा-चौथा आदमी घाघ टैगासुर है।

किसी के भी द्वारा आपको टैग किए जाने का सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति को अपनी पोस्ट पर विश्वास नहीं है कि उसने कुछ ऐसा लिखा है जिस पर लोग अपने मन से उसे पसंद करें। और एक बार टैग होने के बाद आपने लाइक न किया तो बिना घमंड के घमंडी बन जाने का खतरा, शेयर न किया तो उनकी आंखों में खटकने का खतरा और यदि गुस्से में उन्हें अनफ्रेंड कर दिया तब तो देशद्रोही होने का खतरा पक्का है।

X पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय को समाहित करने वाले भवन का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा है। मोदी सरकार औपनिवेशिक प्रतीकों एवं मानसिकता से दूर जाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। जैसे केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन, राजपथ अब कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग और राज भवन या राज निवास अब लोक भवन या लोक निवास हो गए हैं।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

टी20 विश्व कप रोमांचक बनता जा रहा है। वैसे जिंबाब्वे ने पूर्व में भी आस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल की है, लेकिन कई लोगों को लगता था कि उसकी मौजूदा टीम दो दशक पहले जितनी मजबूत नहीं है, पर उसने फिर से यह कर दिखाया।
विक्रम चंद्रा@vikramchandra

बांग्लादेश में बीएनपी की सत्ता में वापसी के चुनाव परिणाम दिखाते हैं कि तथाकथित 'क्रांति' एक दिखावा थी। बड़ी आबादी ने एक बार फिर मुख्यधारा की पुरानी पार्टी को दो तिहाई बहुमत दिया। भारत को उससे संबंध सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए। यूसुफ ऊंझावाला@YusufDFI

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या वंदे मातरम् के सभी छंद गाने का निर्णय सही है?

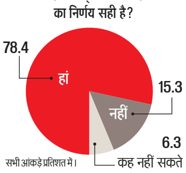

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आने से वहां कट्टरपंथी ताकतों पर अंकुश लगेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

तारिक भाई आज तो बदल चुकी तारीख,
'तवारीख' भी बदलिए यही जीत की सीख।
यही जीत की सीख न पनपें कट्टरपंथी,
चाह रहा है मुल्क करो भारत से संधी।
यूनुस ने तो आय दुश्मनी खूब निभाई,
वही बेतुकी राह न पकड़ें तारिक भाई!
– ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

सत्तापक्ष के विधायकों से असहज सरकार

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार के कारण तमाम लोकतंत्र प्रेमी इस बात से चिंतित थे कि बिना मजबूत विपक्ष के सरकार कैसे चलेगी? विधानसभा के बजट सत्र में सत्तापक्ष के विधायकों के तेवर ने ऐसे लोगों को चिंता मुक्त कर दिया है। विपक्षी दलों के जिन तीखे प्रश्नों से सरकार परेशान होती रहती है, ऐसे प्रश्न सत्तारूढ़ राजग और खासकर उसके सबसे बड़े घटक दल भाजपा के सदस्यों की ओर से ही आ रहे हैं।

सामान्य दशा में अगर विपक्षी सदस्य सरकार की फजीहत करते हैं तो सत्तारूढ़ दलों के सदस्य बचाव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन, बिहार विधानसभा में यह दृश्य दुर्लभ है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य प्रश्न करते हैं और सरकार उत्तर देने में असहज होती है तो शेष सदस्य पूरक माध्यम से विपक्ष की कमी पूरी कर देते हैं। इसी शुक्रवार को बजट सत्र का दूसरा सप्ताह समाप्त हुआ। इस दौरान भाजपा सदस्यों ने कई बार सरकार को कठघरे में खड़ा किया। सरकार के उत्तर को चुनौती दी। लोकगायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित एक सरकारी अस्पताल के भवन और डाक्टरों की कमी से जुड़ा प्रश्न किया। उत्तर में बताया गया था कि भवन ठीक है। मैथिली ने न केवल उत्तर को चुनौती दी, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडेय को उस अस्पताल के निरीक्षण का आमंत्रण भी दे दिया।

कम उम्र और गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण मैथिली से ऐसे पूरक प्रश्न की अपेक्षा नहीं की गई थी, जिससे सरकार को परेशानी हो। लेकिन, अस्पताल भवन की जर्जर अवस्था और गलत सरकारी दावे को वह बर्दाश्त नहीं कर सकीं। मैथिली नई हैं। विधायक जीवेश मिश्रा नए नहीं हैं। यह उनका दूसरा टर्म है। पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री थे। अपने विधानसभा क्षेत्र

विधानसभा में मैथिली ठाकुर। वीडियो ग्रैब

के थाना भवन से जुड़े प्रश्न के उत्तर को उन्होंने चुनौती दी। उनका कहना था कि नए थाना भवन के निर्माण की घोषणा तीन साल पहले हुई थी। आज तक निर्माण नहीं हो सका। इससे पहले भाजपा के जीवेश मिश्रा और राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सरकारी कर्मियों-विधायकों आदि को कैशलेस इलाज की सुविधा के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया था। सत्तारूढ़ दल के कई और विधायक उनके प्रश्न के पक्ष में खड़े हुए। सदन की भावना को देखते हुए सरकार को कैशलेस इलाज की घोषणा करनी पड़ी।

विपक्ष के विधायकों की संख्या कम होने के कारण सदन की कार्यवाही पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। विपक्ष जब मजबूत था, अक्सर प्रश्नकाल बाधित हो जाता था। हंगामा और शोर-शराबा के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती थी। सरकार को उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सरकारी योजनाओं की कमियां प्रकट नहीं हो पाती थीं। विपक्ष को भी अच्छा लगता था। कुछ देर के हंगामे का पुरस्कार उन्हें पर्याप्त मीडिया कवरेज के रूप में मिल जाता था। सरकार इसलिए खुश रहती थी कि उसे फजीहत नहीं झेलनी पड़ती थी। लेकिन, इस बार विपरीत हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों की अति सक्रियता से सरकार की भी आंख खुल रही है। उसे उन कमियों की जानकारी मिल रही है, जो अब तक छिपाई गई थी।

हाल के वर्षों में बिहार में शिक्षा का काफी विकास हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के बजट में भी सबसे अधिक खर्च का प्रविधान शिक्षा मद में ही किया गया है। हरेक प्रखंड में डिग्री कालेज खोले जा रहे हैं। स्कूलों में पांच लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है। सरकार ने 55 कालेजों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन तमाम अच्छी बातों के बीच यह सूचना आश्चर्यजनक है कि बेगूसराय के किसी डिग्री कालेज के आठ कमरों में 20 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं का अध्ययन-अध्यापन चल रहा है। इस करामात की सूचना भी भाजपा विधायक कुंदन कुमार के प्रश्न के उत्तर में आई। सरकार ने इसे गलत नहीं ठहराया। सदन में जब यह प्रश्न चल रहा था, कई कोनों से यह आवाज आ रही थी कि हमारे क्षेत्र के कालेजों का भी यही हाल है।

भाजपा के एक अन्य विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित सरकारी स्कूलों की सफाई का मामला उठाया था। उत्तर में सरकार कह रही थी कि सफाई के लिए तैनात आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बारे में कोई शिकायत नहीं है। वैद्यनाथ प्रसाद ने सरकारी उत्तर को चुनौती दी, तब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मुख्यालय की टीम से जांच कराने को राजी हुए। कोई पूछ सकता है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की सूचना पहले क्यों नहीं मिल पाती है? तंत्र में यह व्यवस्था पहले से है कि हरेक परियोजना के सभी स्तरों की जानकारी विभाग और उसके शीर्ष अधिकारी तक पहुंचती रहे। सरकारी उत्तर को जनप्रतिनिधि अगर ठोस सबूतों के साथ चुनौती दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं चल रही हैं, जितनी दिखाई जा रही हैं। यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता है कि वे समय-समय पर बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण कर लेते हैं। अन्य मंत्री ऐसा कहां कर पाते हैं।

मंथन

बहुभाषी शिक्षा से बनेगी बात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 लागू हुए पांच वर्ष बीत चुके हैं। इसका मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
स्पेशल मानीटर, एनएचआरसी (इंडिया) एवं राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी

समूचे विश्व में 27.2 करोड़ बच्चे और युवा अब भी शिक्षा तक पहुंच से वंचित हैं। हालांकि भारत में यह संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, तथापि वर्ष 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में यह संख्या लगभग 11.7 लाख थी। वस्तुतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न तो विलासिता है और न ही विशेषाधिकार, यह एक मानवाधिकार है। इसमें जीवन बदलने की शक्ति है। शिक्षा से लोग अपनी पूर्ण क्षमता पाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। गरीबी, असमानता और भेदभाव से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे में बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा से वंचित लोग किसी भी नए बदलाव को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

भारत में एनईपी-2020 के माध्यम से बदलाव की कल्पना की जा रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा में भाषा केवल पढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि सीखने, समझने और समावेशन की नींव है। भारत जैसे देश में जहां 13 सौ से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषी शिक्षा अपनाना जरूरी है, ताकि सभी बच्चे उस भाषा में सीख सकें, जिसे वे समझते हों। यह स्पष्ट है कि इतनी भाषाओं और बोलियों में शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करना और सबको उनकी भाषा व बोलियों में शिक्षा देना भारत के लिए आसान नहीं है। किंतु भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसमें से केवल 22 भाषाएं जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत की हैं, उनमें ही शिक्षा के पाठ्यक्रम, पठन-पाठन की व्यवस्था यदि हो सकी तो भी यह क्रांतिकारी व्यवस्था होगी।

फिलहाल, निकट भविष्य में सरकार भी यह दावा नहीं कर सकती कि हम इतने वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। इसकी दो वजहें हैं। पहला, अंग्रेजी शिक्षा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। दूसरा, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह सभी पाठ्यक्रमों को शिक्षा संस्थाओं में लागू करा सके। एक बड़ी बात यह है कि भारत में जो अंग्रेजी सभ्यता के साथ पले-बढ़े हैं, वे अंग्रेजी छोड़ना नहीं चाहते। विश्वविद्यालय अंग्रेजी में ही पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। अधिकांश परीक्षाएं अंग्रेजी में हो रही हैं। साक्षात्कार में अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता है और अंग्रेजी में ही उसका जवाब मांगा जाता है। वहीं कारपोरेट घराने के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने बिजनेस के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। अभिभावकों को भी अपने बच्चे को वर्ल्डक्लास बनाने की छटपटाहट है। ऐसे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाषाई सोच का क्या होगा, कहना मुश्किल है।

बहुभाषी शिक्षा की राह में चुनौतियां : शिक्षा की शुरुआत बच्चों की अपनी भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि वे बेहतर समझ सकें और आगे की शिक्षा में सफल हो सकें। लेकिन संबंधित रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि बहुभाषी शिक्षा को जमीन पर लागू करने में बहुत चुनौतियां हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ यह जो असमंजस के बीच जीने वाली पीढ़ी है, या जो तय नीति के तहत संसाधनों से वंचित रहने को मजबूर पीढ़ी है, उसके बारे में काफी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

शिक्षा मानव अधिकार है तो यह सबकी पहुंच का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन भारत में आज की शिक्षा की भाषाई सामग्री के अभाव में लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होगी। देश की एनईपी-2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाषाई अनूदित सामग्रियों को बड़े पैमाने पर तैयार करना होगा, अन्यथा हम सतत विकास लक्ष्य-2030 को हासिल करने में भी मदद नहीं कर पाएंगे। दावा है कि एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में भारत के शिक्षा परिदृश्य में क्रांति ला दी है, और ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां पेश की हैं जो अनुकूलन, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। यदि देश में इन सभी प्रयासों के साथ मानव अधिकार शिक्षा पर बल दिया जाए तो निश्चय ही भारत को प्रगति हासिल होगी। शिक्षा की गुणवत्ता से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे भारत के मानव विकास सूचकांक में अभिवृद्धि होगी। लेकिन, इसके लिए सही निर्णय, सही पहल और सबकी गरिमा को प्राथमिकता दी जाएगी, तभी सबकुछ संभव है।

प्रतीकात्मक

हमारे शैक्षणिक संस्थान, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों, शोधार्थियों, उद्योग जगत के लोगों, सरकारी प्रतिनिधियों एवं सेवाभावी व परोपकार से जुड़े लोगों द्वारा शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यावहारिक, कौशलोन्मुख और रोजगार के अवसरों के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी हम वास्तव में मानव अधिकार शिक्षा को प्रसारित कर सकेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत की उन्नति के लिए सभी एकजुट हों और नैतिक रूप से अपने दायित्वों को समझें।

पड़ोस में बदलाव

बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली भारी चुनावी जीत के गहरे मायने हैं। समग्रता में देखें, तो यह लंबे समय से जारी इस विपक्षी पार्टी के संघर्ष और अनुभव की जीत है। करीब दो दशक बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अर्थात बीएनपी की सत्ता में वापसी हो रही है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान शनिवार को बांग्लादेश की कमान संभालने वाले हैं। बेशक, भारत के इस पूर्वी पड़ोसी देश में नए युग का आगाज होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में जुलाई 2024 में हुई छात्र क्रांति के बाद से ही इस देश में नीतिगत संकट देखा जा रहा है। अनेक फैसले हुए हैं, जो जनशक्ति या छात्रों के हिंसक या आक्रामक दबाव में हुए हैं। यहां तक कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सलाहकार सरकार भी छात्रों के दबाव में ही गठित हुई थी। हालांकि, चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि छात्र शक्ति पर लोगों ने भरोसा नहीं किया है। नाममात्र की सीटें ही छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) की झोली में गई हैं। अपेक्षाकृत ज्यादा कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और उसके 11 सहयोगी दलों को भी सौ से कम सीटें हासिल हुई हैं। इसका पहला मतलब है कि बांग्लादेश में लोगों ने सरकार चलाने के अनुभव को तरजीह दी है।

बीएनपी की जीत बांग्लादेश में तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर पार्टी की सफलता है। यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव में भाग नहीं ले रही थी। अवामी लीग के खिलाफ जो नाराजगी है, उसकी वजह से उसे चुनाव से दूर रखा गया। आगे यह देखने वाली बात होगी कि सत्ता संभालने के बाद 60 वर्षीय तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी का रवैया विपक्षी दलों के प्रति क्या रहता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में विपक्षी दलों के प्रति सत्तारूढ़ दल का रवैया दुखद रहा है। एक बेहतर राजनीति के लिए संतुलन जरूरी है। हां, अगर बीएनपी यह ठान लेती है कि वह अवामी लीग को देश में फिर पैर नहीं जमाने देगी, तो बांग्लादेश की राजनीति का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। बीएनपी का रुख अवामी लीग और बंगबंधु मुजीबुर्रहमान के प्रति क्या रहता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बीएनपी की खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थीं, तब भी बंगबंधु की विरासत पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन सलाहकार सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस के दौर में बंगबंधु की बेरहम बेकद्री से बांग्लादेश ने अपना नया इतिहास लिखना शुरू किया है। क्या बेकद्री की इस परिपाटी को तारिक रहमान आगे बढ़ाएंगे? तारिक रहमान का रुख भारत में निर्वासन झेल रहीं शेख हसीना के प्रति कितना तल्ख रहेगा? आज ऐसे अनेक सवाल चर्चा में हैं।

पड़ोस में हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद पहली उम्मीद यही है कि कट्टरता पर लगाम लगेगी। फैसले ऐसे होंगे, जो दक्षिण एशिया को तरक्की की ओर ले जाएंगे।

बहरहाल, यह जो चुनी हुई सरकार सत्ता में आ रही है, उसका इंतजार बांग्लादेश में बेसब्री से था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार करीब 18 महीने सत्ता में रही और अब वह इतिहास हो जाएगी। बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद पहली उम्मीद यही करनी चाहिए कि बढ़ती कट्टरता पर लगाम लगेगी। फैसले ऐसे लिए जाएंगे, जो दक्षिण एशिया को तरक्की की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी पार्टी की ओर से उन्हें बधाई दी है। जाहिर-सी बात है, भारत को नई सरकार का इंतजार था। उम्मीद करनी चाहिए, पड़ोस में चुनी हुई नई सरकार से वार्ता में ज्यादा सुविधा और स्पष्टता होगी, जिससे दोनों देशों के संबंधों में जरूरी ऊर्जा का संचार होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
14 फरवरी, 1951

अपहृत महिलायें

विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, उनका सबसे बूरा पहलू था महिलाओं का अपहरण। तभी से इन अपहृत महिलाओं का पता लगाने और उन्हें उनके सम्बन्धियों को लौटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन बातों को तीन वर्ष का लम्बा समय बीत चुका है। उसके बाद भी यह काम अधूरा पड़ा हुआ है, यह लज्जा का ही विषय हो सकता है। अब तक भारत में 14,702 अपहृत महिलाओं का पता लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान के लिए यह संख्या 7,175 तक सीमित रही है। इन संख्याओं का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भारत में महिलायें अधिक संख्या में अपहृत की गयीं और पाकिस्तान में कम। अनुमान तो यह लगाया जाता है कि पाकिस्तान में अपहृत महिलाओं की संख्या कम नहीं है। भारत में इतनी अधिक संख्या में अपहृत महिलाओं का पता लगाना इस बात का प्रमाण है कि इस भूल का परिमार्जन करने में जनता ने काफी सहयोग दिया है और समाजसेवकों तथा सरकारी अधिकारियों ने इस दिशा में तत्परतापूर्वक काम किया है। हमारी मंशा आलोचना करने की नहीं है, किन्तु यह तथ्य है कि अपहृत महिलाओं की बरामदगी के काम में पाकिस्तान में अधिकारियों ने उतनी तत्परता का परिचय नहीं दिया और जनता ने उसी मात्रा में सहयोग का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यहां तक कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में भी अपहृत महिलाएं बतायी जाती हैं। अपहृत महिलाओं का दूसरों के अधिकार में रहना दोनों देशों के लोगों में स्थायी कटुता का कारण है। इस अन्याय को लोग कभी नहीं भूल सकते हैं।

पाकिस्तान से एक प्रतिनिधि-मण्डल अपहृत महिलाओं को बरामद करने के काम को जल्दी पूरा करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत आया है। उसने अमृतसर और जालंधर में अपहृत महिलाओं के कैम्पों को देखा और अधिकारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित किया। दिल्ली में भी प्रतिनिधि-मण्डल यही काम कर रहा है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते कि अपहृत महिलाओं का हर हालत में पता लगाना और उन्हें उनके सम्बन्धियों को लौटाया जाना चाहिए। भारत में अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों, दोनों ने इस काम में प्रतिनिधि-मण्डल को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

बांग्लादेश में साफ जनादेश के मायने

बीएनपी की इस बड़ी जीत और जनमत-संग्रह की मंजूरी के बाद भी यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश की समस्याओं का समाधान निकल ही जाएगा।

यहां स्कैन करें

पिनाक रंजन चक्रवर्ती | पूर्व उच्चायुक्त, बांग्लादेश

बीते 36 साल में बांग्लादेश में पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री बन सकता है। 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को दो-तिहाई से अधिक सीटें मिलने के बाद यह बात करीब-करीब साफ हो गई है कि तारिक रहमान अब इस पड़ोसी मुल्क की कमान संभालने जा रहे हैं।

यह चुनावी नतीजा अपेक्षित ही था, क्योंकि अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद बीएनपी के लिए मैदान खाली हो गया था। जमात-ए-इस्लामी जरूर कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही थी, मगर उसके दावे की बुनियाद कमजोर थी। हां, उसे अपने अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन इसका कारण भी अवामी लीग का प्रतिबंधित होना ही है।

इस चुनाव के साथ मतदाताओं के बीच 'जनमत-संग्रह' भी करवाया गया था। हर वोटर को दो-दो मतपत्र दिए गए थे, जिनमें से एक सांसद के निर्वाचन का था और दूसरा 'जुलाई चार्टर' को लेकर। इस चार्टर को भी मंजूरी मिल गई है। कार्यवाहक सरकार के मुताबिक, यह चार्टर लोकतांत्रिक सुधारों को स्थायी बनाने की कवायद है। इसमें कुल 84 प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम दो कार्यकाल (दस साल), हमारी राज्यसभा जैसे ऊपर सदन के गठन, राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने, अदालत को राजनीतिक प्रभाव से बचाने जैसी सिफारिशें खासा महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि, बीएनपी की बंपर जीत और जनमत-संग्रह पर मंजूरी के बाद भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश की समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। कई सवाल अब भी कायम हैं, जिनके जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं।

सबसे पहला सवाल तो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से ही जुड़ा है। अब उनका क्या होगा? पिछले डेढ़ साल से वह जमात-ए-इस्लामी के इशारे पर सरकार चला रहे थे। यह वह सरकार थी, जिसे परदे के पीछे अमेरिका का समर्थन हासिल था। यहां तक कि उनके कई सलाहकार बांग्लादेशी मूल के होने के बावजूद अमेरिकी नागरिक थे। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ दूरी बरतने व पाकिस्तान के करीब जाने का दांव खेला था, जिसके कारण नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गए थे।

मोहम्मद यूनुस जरूर नोबेल विजेता हैं, लेकिन बतौर मुख्य सलाहकार वह बहुत सफल नहीं रहे। खुद को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने तमाम अहम संस्थानों में जमात के लोगों को भर दिया। यहां तक कि विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, चुनाव आयोग में भी जमात समर्थित लोग नियुक्त कर दिए गए। ऐसे में, माना यही जा रहा है कि सत्ता में बने रहने का अघोषित समझौता करने के बाद ही उन्होंने आम चुनाव की ओर कदम बढ़ाए थे। कयास है कि वह अब राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं।

दूसरा बड़ा सवाल जनमत-संग्रह से संबंधित है। बेशक संसदीय चुनाव के साथ यह कवायद भी की गई, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। संविधान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। अब जब 'जुलाई चार्टर' को लेकर लोगों में सहमति बन गई है, तब सवाल यही है कि इसे किस तरह लागू किया जाएगा? बीएनपी को दो-तिहाई सीटें मिली हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यहां का संविधान बदला जाएगा? यहां के ढांचागत बदलावों पर भी नजर बनी रहेगी।

भारत के साथ नई सरकार के रिश्ते को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बीएनपी का मूल चरित्र है, जो कट्टरपंथियों से जुड़ा दिखता है। हालांकि, भारत सरकार ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ पहले ही बढ़ा दिया है। पिछले दिनों जब खालिदा जिया का देहांत हुआ, तो हमारे विदेश मंत्री वहां गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश भी भेजा था। आज भी चुनाव नतीजों की घोषणा होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि आपसी रिश्ते आगे बढ़ेंगे।

यह सही है कि किसी जमाने में खालिदा जिया भारत-विरोधी मानी जाती थीं। वह कुछ संकीर्णतावादी सोच की थीं। पाकिस्तान को पसंद करती थीं। 2001-06 के दौरान जब वह सत्ता में थीं, तब आईएसआई की शह पर भारतीय सीमा पर उग्रवादियों के कैंप बनाए गए थे। उनको हथियार भी मुहैया कराए गए थे। नतीजतन, भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ गई थी। हालांकि, खालिदा को इसका नुकसान हुआ था, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार उनके बेटे तारिक शायद ही वह गलती दोहराएंगे।

मेरा आकलन है कि बीएनपी सरकार के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे। यूनुस और जमात ने मिलकर पाकिस्तान को जिस तरह से शह दी, वैसा शायद ही तारिक के कार्यकाल में देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि उनको अमेरिका का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। स्थानीय अमेरिकी दूतावास ने जिस तरह से उनको जीत की शुभकामनाएं दी हैं, उनसे लगता है कि दोनों के बीच कुछ-न-कुछ समझौता जरूर हुआ है। वैसे भी, 17 वर्षों का उनका निर्वासन यूं ही खत्म नहीं किया गया होगा। उन पर जितने मुकदमे थे, सभी वापस ले लिए गए हैं। यहां तक कि उनको मृत्युदंड तक मिला हुआ था। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप उन पर थे। ऐसे में, अमेरिका के साथ परदे के पीछे कोई समझौता होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुमकिन है, तारिक रहमान ने यह मान लिया हो कि मोहम्मद यूनुस के समय अमेरिका ने जो समझौते किए हैं, वे बने रहेंगे। इसका एक अर्थ यह भी है कि वहां फिलहाल अमेरिका की दखलंदाजी बनी रह सकती है।

तारिक की जीत में वंशवादी राजनीति की मजबूती देखी जा रही है, तो गलत नहीं हैं। हालांकि, यह दक्षिण एशिया का ही राजनीतिक चरित्र है, इसलिए तारिक की चुनावी जीत को सिर्फ वंशवादी राजनीति में बांधना उचित नहीं होगा। उन्होंने चुनाव प्रचार में अपना उदार रवैया दिखाया था, खासकर अवामी लीग की वापसी का संकेत देकर। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह चाहते हैं, अवामी लीग भी चुनाव में भाग ले, क्योंकि बिना उसके उनकी जीत बेमानी मानी जाएगी। अवामी लीग को हराने का सुख वह महसूस करना चाहते थे। ऐसे में, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अवामी लीग पर से प्रतिबंध हट जाए। वैसे भी, जिस तरह से महज अवामी लीग समर्थक या कार्यकर्ता होने के आरोप में वहां हजारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए हैं, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए धब्बा ही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अब हमें अपने विकास का नया फॉर्मूला चाहिए

यहां स्कैन करें

अरुण मायरा | पूर्व सदस्य, योजना आयोग

साल 2026-27 के बारे में एक आम धारणा यही दिखती है कि यह बजट बुरा नहीं है, मगर बहुत अच्छा भी नहीं है। यह एक 'सुरक्षित' बजट है, जिसने समस्याओं से टकराने का जोखिम उठाने के बजाय जीडीपी बढ़ाने व 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर रखने की कोशिश की है। इसने 'आर्थिक सर्वेक्षण' में बताई गई अर्थव्यवस्था की रणनीतिक कमजोरियों को दूर नहीं किया।

इस समय हम अमेरिका और चीन के भू-राजनीतिक गतिरोध की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। चीन पर हमारी व्यापारिक निर्भरता है, जिसके साथ हमारा सीमा विवाद है; तेल और हथियारों के लिए हम रूस पर निर्भर हैं, जबकि अमेरिका अक्सर पाकिस्तान की हिमायत करता रहता है। हम अमेरिका, चीन या रूस, किसी से रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी औद्योगिक क्षमताएं अभी मजबूत नहीं हैं। सन् 1991 में अपनी औद्योगिक नीतियों को समय से पहले छोड़ देने के कारण खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए हमें इन क्षमताओं को हासिल करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि सन् 1991 से भारत की जीडीपी बढ़ी है और देश में गरीबी भी कम हुई है, लेकिन इसी समय में, चीन की जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय बहुत तेजी से बढ़ी है। भारतीय विकास दर की 'एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी', यानी जीडीपी की प्रति इकाई के मुकाबले अच्छी नौकरियां पैदा होने की दर दुनिया में सबसे कम है। यही स्थिति बनी रही, तो अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए विकास दर को सालाना 12 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा।

हमें अपने विकास के पैटर्न को बदलना होगा। सबसे निचले तबके की आय तेजी से बढ़ानी होगी और पर्यावरणीय नुकसान को रोकना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी पूरी बहस इस बात पर आकर रुक गई है कि जीडीपी और रोजगार की स्थिति यूपीए के दौर में अच्छी थी या एनडीए में बेहतर है, दर-हकीकत दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 10 सालों में अर्थव्यवस्था सालाना 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी (2008-09 को छोड़कर, जब वैश्विक मंदी का संकट आया था) और भाजपा नीत एनडीए के शासन वाले अगले 10 वर्षों में (2020-21 के महामारी के झटके को छोड़कर) भी 7.2 फीसदी की दर से बढ़ी।

असमान विकास की वजह रहे ढांचागत हालात भी नहीं बदले हैं। जीडीपी विकास की 'एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी' 1990 के दशक से कम हो रही है। 1983-84 से 1992-93 के बीच नौकरियां हर साल दो प्रतिशत से कुछ ज्यादा बढ़ीं। साल 1993-94 से 2004-05 के बीच अर्थव्यवस्था हालांकि तेजी से बढ़ी, पर नौकरियों के बढ़ने की दर घटकर 1.85 प्रतिशत हो गई। साल 2004-05 से 2009-10 के बीच 'एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी' गिरकर 0.01 फीसद रह गई थी। यह बेहद बुरा संकेत था। अगर आम लोगों के लिए रोजगार नहीं बढ़ते, उनकी आय तेजी से नहीं बढ़ती, तो तेज विकास में यकीन करने वाले कारोबारी निवेश टिकाऊ नहीं होंगे।

हमें अब ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। सन् 1991 में हमने जो उदार आर्थिक सुधार अपनाए थे, वही हमारी कमजोरी की वजह हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे सुधारों की जरूरत है, जिनसे सभी नागरिकों की दौलत और आय बढ़े। सुधारों की प्रक्रिया में हमें दो बुनियादी सुधार की जरूरत है। एक, जीडीपी विकास के अलावा हमें यह मापना होगा कि पर्यावरणीय संसाधन, जैसे साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी, हवा की गुणवत्ता वगैरह कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं? दूसरा, हमें आर्थिक विकास को सीखने की प्रक्रिया के रूप में फिर से देखना होगा, यानी उद्यमी वह काबिलियत हासिल करें, जो उनके पास अभी नहीं है; लोग कौशल विकास की सीढ़ियां चढ़ें और नीति-नियंता वह करें, जो उन्होंने पहले नहीं किया।

चीन के नेता हमारे नेताओं से ज्यादा बेहतर सीखने वाले साबित हुए हैं। जब हमने उदार बाजार-पूंजीवाद का अमेरिकी मॉडल अपनाया, तब भी चीन 'स्थानीय विशेषताओं वाले समाजवाद' के अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने प्रयोग किए, सीखा और अपने रास्ते में सुधार किए। देंग जियाओ पिंग की यादगार कहावत के मुताबिक, 'अपने पैरों के नीचे पत्थर महसूस करके नदी पार करना।' इसलिए, भारत के विकास के पैटर्न को बदलना होगा। सबसे निचले तबके की आय तेजी से बढ़ानी होगी और पर्यावरणीय नुकसान को देर होने से पहले रोकना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

भक्ति भाव की प्रतीक्षा

महादेव शिव की महिमा अपरंपार है। उनकी पूजा-वंदना प्रभु श्रीराम भी निरंतर करते हैं। तुलसीदास जी ने श्रीराम जी को यह कहते लिखा है कि शिव का द्रोही मेरे स्वप्न में भी नहीं आता है। संसार में संभवतः ऐसा कोई नहीं होगा, जो शिव को जानता हो और उनकी प्रशंसा न करता हो।

कबीरपंथियों के बीच भी एक शिव चर्चा प्रचलित है। छपरा में एक संत थे हलकोरी बाबा, कबीरपंथी थे। वह नाम लिखना भी नहीं जानते थे, किंतु उन्हें गुरु के अनुग्रह से विशिष्ट दृष्टि की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक दिन घर वालों से कहा, मैं अब केवल राम-राम जपूंगा। मेरे हिस्से की जमीन के आधार पर आप मुझे बस रोटी दे देना।

कबीरपंथी सीताराम-सीताराम नहीं कहते हैं। केवल राम-राम कहते हैं, जैसे रामसनेही संप्रदाय के लोग करते हैं। उन्होंने खूब जाप किया, सारी रिद्धियां-सिद्धियां प्राप्त हो गईं। बताते हैं कि वह एक बार लोगों के आग्रह पर तीर्थ यात्रा पर निकले, पर काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में नहीं गए। यह सोचकर नहीं गए कि कबीरपंथी लोग मंदिर जाने की निंदा करेंगे। कबीरपंथी मूर्ति पूजक नहीं हैं। वैसे, जगद्गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य थे कबीर, काशी में उनका भी आश्रम है। पूरे देश में कबीर मठ हैं। एक से एक महात्मा कबीर मठों में हुए हैं। साईं बाबा भी कबीर परंपरा से दीक्षित थे। साईं मतलब होता है स्वामी।

तो हलकोरी बाबा काशी में भगवान विश्वनाथ के यहां नहीं गए। वह काशी से लौटने लगे। एक स्थान पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान विश्वनाथ दिव्य स्वरूप में अनेक मालाओं से सुसज्जित वहां पहुंचे, त्रिशूल, डमरू, चंद्रमा विभूषित ललाट। हलकोरी बाबा समझ गए कि भगवान हैं, तो दंडवत किया, क्षमा याचना भी की और कहा, मैं आपके मंदिर में नहीं आया।

भगवान विश्वनाथ बोले कि यही कहने आया हूं कि आप क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए था।

हलकोरी बाबा ने कहा, मैं मंदिर जाता, तो कबीरपंथी लोग विवाद करते, मुझे सुनाते, निंदा करते, ये कहां चला गया कबीरपंथ की मर्यादा को छोड़कर, इसलिए नहीं आया। आपको आना पड़ा, आपसे क्षमा चाहता हूं।

फिर बहुत विनम्र स्वर में हलकोरी बाबा ने कहा कि वैसे मैं दरिद्र हूं, मेरे जल की क्या महत्ता है? आपके यहां जल चढ़ाने वालों की कमी है क्या? करोड़ों लोग आपके यहां प्रतिदिन जल अर्पित करने आते हैं।

महादेव शिव विश्वनाथ ने कहा, मैं सबका जल ग्रहण नहीं करता, मुझे जल का कोई अभाव नहीं है। मैं केवल उनका जल स्वीकारता हूं, जो मुझे भक्ति-भाव से जल अर्पित करते हैं।

भगवान विश्वनाथ ने कहा, मैं सबका जल ग्रहण नहीं करता, मुझे जल का कोई अभाव नहीं है। मैं केवल उनका जल स्वीकारता हूं, जिनका हृदय आप जैसा निर्मल होता है, जो भक्ति-भाव से जल अर्पित करते हैं।

महादेव की ऐसी सहजता देख हलकोरी बाबा दंडवत हो गए। वह समझ गए कि ईश्वर को जल की प्यास नहीं, भोग की भूख नहीं, केवल भक्ति-भाव की प्रतीक्षा है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

तस्लीमा नसरीन | बांग्लादेशी लेखिका

बांग्लादेश को नए धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व की जरूरत है, जो औरतों के हुकूक, लोगों के मानवाधिकारों, सबकी शिक्षा, सेहत और बोलने की आजादी से वफा निभाए, न कि सियासी खानदानों और मौलवियों की हिमायत करे।

अनुलोम-विलोम
वैलेंटाइन डे

प्यार के बाजारीकरण को कैसे सराहें

वैलेंटाइन डे का नाम लेते ही मन में गुलाब, चॉकलेट, टेडी और महंगे गिफ्ट्स की चमकदार तस्वीरें उभर आती हैं। प्यार जैसे पवित्र भाव को हमने धीरे-धीरे बाजार की सजावटी वस्तु बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो बिना तोहफे के प्रेम अधूरा और बेकार है। क्या सच में प्यार की पहचान इन दिखावटी चीजों से होती है? प्यार की असली भाषा तो त्याग, समर्पण और एक-दूसरे के लिए खुद को पीछे रखना है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी छोड़कर प्रियजन की मुस्कान में अपना सुख खोजता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। हालांकि, दुर्भाग्य से वैलेंटाइन डे इस पवित्र भावना को लगभग भुला चुका है।

'मॉडर्न लव' की दुनिया में सोशल मीडिया ने प्यार को एक मंच बना दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महंगे डिनर, लग्जरी ट्रिप व कीमती तोहफों की तस्वीरें आज प्रेम का प्रमाण मानी जाती हैं। लोग अब एहसास कम करते हैं और ज्यादा दिखाते हैं। पहले के प्रेम में त्याग चुपचाप होता था, बिना किसी प्रचार और प्रदर्शन के। मां का बच्चे के लिए रात भर जागना, पिता का अपनी इच्छाओं को दबाना- ये निःस्वार्थ प्रेम के सच्चे उदाहरण थे, लेकिन आज का वैलेंटाइन डे इन मूल्यों को लगभग भूल चुका है। पूंजीवाद ने प्यार को व्यापार में बदल दिया है, जहां भावनाएं भी बिकाऊ वस्तु बन गई हैं। दिक्कत यह है कि आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ा है। लोग सिर्फ अपने सुख और सुविधा को प्राथमिकता देने लगे हैं। तोहफे केवल क्षणिक आत्म-संतोष देते हैं, जबकि त्याग स्थायी आत्म-परिवर्तन लाता है। डेटिंग एप की संस्कृति ने रिश्तों को अस्थायी और सतही बना दिया है।

भारतीय संस्कृति में सीता, सावित्री व मीरा जैसे आदर्श चरित्र हमें प्रेम में समर्पण और निष्ठा का सही अर्थ समझाते हैं। यहां प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि साधना और तपस्या था, लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से वैलेंटाइन डे पश्चिमी संस्कृति के साथ भारतीय समाज में प्रवेश कर गया। धीरे-धीरे युवा वर्ग ने इसे अपनाया, पर उसके साथ उपभोगवाद भी फैलता गया। तोहफे प्रेम का मापदंड बन गए। आज रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। स्थिरता की जगह अब अस्थिरता ने ले ली है। यह समझना चाहिए कि प्यार की असली भाषा त्याग है, उपहार नहीं। पारंपरिक प्रेम में त्याग से रिश्ते मजबूत और स्थायी होते थे, जबकि आधुनिक प्रेम में दिखावे से वे कमजोर और अस्थिर होते जा रहे हैं। हमें फिर से छोटे-छोटे त्याग, समर्पण को अपनाना होगा। जब हमारे प्रेम में त्याग वापस लौटेगा, तभी वह सच्चा, गहरा और अमर बन सकेगा।

कृति आरके जैन, टिप्पणीकार

स्नेह और संबंधों को समझने का दिन

वैलेंटाइन डे पर यह आरोप गलत है कि इसने प्रेम को बाजार के हवाले कर दिया है। इसके उलट, इसने प्रेम, स्नेह और संबंधों को नया रूप दिया है। यह हमें बताता है कि प्रेम है क्या? यह दिन प्रेमी युगलों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो इस दिन का इस्तेमाल अपने प्यार का इजहार करने और एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम को मजबूत करने के लिए करते हैं। इस दिन को मनाने की परंपरा प्राचीन रोम और ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जब संत वैलेंटाइन ने प्रेम और शादियों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वह परंपरा आज भी कायम है। आज भी यह दिन पूरी दुनिया में प्रेम, दोस्ती और स्नेह के बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दिन अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। एक-दूसरे को उपहार देते हैं और प्रेम भरे संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं। यह दिन युगलों के लिए ही नहीं, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जो इस अवसर पर अपने रिश्तों में प्रेम और स्नेह को प्रगाढ़ बनाते हैं। प्रेम में रत रहना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम है उसका इजहार। इसलिए, यह दिन हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। प्रेमी इस दिन अपने प्रेम का खुलकर इजहार कर पाते हैं। यकीनन, उन्हें यह ताकत वैलेंटाइन डे ने ही दी है।

रीमा सिंह, टिप्पणीकार

वैलेंटाइन डे को सिर्फ 'बॉयफ्रेंड' और 'गर्लफ्रेंड' वाला प्यार समझने वाले लोग भूल गए हैं कि इस दिन का असली महत्व है क्या? यह दिन वास्तव में प्यार, सम्मान और अपनापन जताने का दिन है। यह दिन बताता है कि हमें प्यार का सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें हर रिश्ते में माता-पिता, दोस्त, जीवनसाथी, भाई-बहन सबके प्यार को महत्व देना चाहिए। बाजार ने इस दिन को महत्वपूर्ण नहीं बनाया है, बल्कि यह दिन इसलिए खास बना है, क्योंकि हम इस दिन उन सभी लोगों का आभार जताते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को प्यार से सींचा है। यह दिन बताता है कि सच्चा प्यार केवल उपहार या गुलाब देना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझना और साथ देना है। खुद की कद्र करना, अपने सपनों और खुशियों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इतना ही नहीं, माफ करना, साथ निभाना और भरोसा बनाए रखना असली प्यार है। इसलिए, यह न कहें कि वैलेंटाइन डे ने प्रेम जैसी पवित्र भावना को बाजार की चीज बना दिया, बल्कि इसने प्रेम का कद और ऊंचा उठाया है। इस दिन को यदि हम असल भावना से मनाएंगे, तो समाज में काफी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

किफायती हाइब्रिड कारों का इंतजार

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और 'रेंज एंग्जायटी' के बीच हाइब्रिड कारें एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही हैं। यह तकनीक प्रदूषण कम करती है और बिना चार्जिंग के झंझट के इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का अनुभव भी देती है। आने वाला वक्त और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि मारुति सुजुकी, हुंडई और किया जैसी कंपनियां अपनी किफायती कारों के हाइब्रिड संस्करण पर काम कर रही हैं। हाइब्रिड कारों के मौजूदा हाल के बारे में आइए जानें...

देश में हाइब्रिड वाहनों के लिए यह शानदार दौर माना जा रहा है। बीते वर्ष हाइब्रिड कारों की कुल बिक्री में आई वृद्धि इलेक्ट्रिक कारों से काफी आगे रही। वर्ष 2025 में 2,48,673 माइल्ड-हाइब्रिड वाहन बिके, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की बिक्री में 83% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाइब्रिड सेगमेंट में भारत में टोयोटा की इनोवा हाइक्रॉस, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, कैमरी और वेलफायर, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और इनविक्टो तथा होंडा कार्स इंडिया की होंडा सिटी ई:एचईवी जैसे मॉडल प्रमुख हैं।

दिलचस्प है कि जहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी केवल 5 फीसदी है, वहीं हाइब्रिड कारों पर आकार और सेस के आधार पर कुल कर भार 43 फीसदी तक पहुंच जाता है। यह भी है कि इस समय बाजार में 40 से अधिक इलेक्ट्रिक कार मॉडल उपलब्ध हैं, जबकि हाइब्रिड सेगमेंट में विकल्प अभी सीमित हैं। इसके बावजूद, बीते वर्ष हाइब्रिड कारों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी इस सेगमेंट में ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

क्यों आ रहीं पसंद : विशेषज्ञों का मानना है कि हाइब्रिड वाहनों की जबरदस्त बिक्री के पीछे इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी रेंज की चिंता, चार्जिंग की चुनौतियां, ईंधन दक्षता को लेकर संशय जैसे कारणों ने अहम भूमिका निभाई है। जो खरीदार ई-मोबिलिटी को लेकर संशय में हैं, वे प्रदूषण की चिंता और किफायत के लिए बीच के रास्ते के तौर पर हाइब्रिड को चुन रहे हैं। पेट्रोल कारों की तुलना में हाइब्रिड मॉडल आमतौर पर 30-40 फीसदी तक ज्यादा माइलेज देते हैं।

वैश्विक स्तर पर अभी भी पीछे

विदेशों की तुलना में भारत अभी भी हाइब्रिड वाहनों में पीछे ही कहा जाएगा। हालांकि यह अंतर तेजी से कम हो रहा है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्सपर्ट डॉ. अवनीश कुमार मिश्रा बताते हैं, 'तीन तरह की हाइब्रिड कारें होती हैं। माइल्ड, सेल्फ चार्जिंग और प्लग इन्स। माइल्ड हाइब्रिड और सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कारें भारत में आम लोगों में उपयोग हो रही हैं। सेल्फ चार्जिंग में बैटरी इंजन से पावर लेकर रीचार्ज होती रहती है। फिलहाल यह ज्यादातर महंगे सेगमेंट की कारों तक सीमित है। अब बजट कारों में सेल्फ चार्जिंग तकनीक देने पर जोर-शोर से काम हो रहा है। संभवतः 2026 के अंत तक या 2027 में बजट में आने वाली सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कारें भारत के ऑटोमोटिव बाजार का हिस्सा बन चुकी होंगी।'

कम कीमत की हाइब्रिड कारें

मारुति सुजुकी इस तकनीक को अपने किफायती सेगमेंट की कारों के लिए विकसित कर रही है, जैसे फ्रॉन्क्स हाइब्रिड, बलेनो हाइब्रिड। ये कारें इस साल या अगले साल तक पेश हो सकती हैं। दरअसल, कार निर्माता कंपनियां अब स्थानीय स्तर पर हाइब्रिड किट असेंबलिंग और मेकिंग पर जोर दे रही हैं। होंडा सिटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। हुंडई की क्रेटा या किया जैसी विदेशी कंपनी की सेल्टोस मॉडल हाइब्रिड संस्करण में लोकल हाइब्रिड असेंबलिंग पर काम कर रही हैं, ताकि खरीदार को कम कीमत में हाइब्रिड तकनीक दी जा सके। इससे आने वाले समय में कई हाइब्रिड कारों की कीमतें पेट्रोल कारों के करीब आ सकती हैं।

मिलेगी ज्यादा ईंधन दक्षता

कार कंपनियां अपनी हाइब्रिड कारों की कीमत को घटाने के साथ-साथ उनके माइलेज बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही हैं। मारुति सुजुकी 'सीरीज हाइब्रिड' तकनीक के माध्यम से इसे अंजाम देने में जुटी है। इससे माइलेज 35 किमी प्रति लीटर से ज्यादा तक ले जाने का लक्ष्य है।

प्लग इन हाइब्रिड पर हो रहा काम

विशेषज्ञ कहते हैं कि भविष्य प्लग-इन हाइब्रिड कारों का है। विदेश में ऐसी हाइब्रिड कारें ज्यादा चलन में हैं। इनमें किसी ई-कार की तरह बाहर से बैटरी पैक चार्ज करना होता है। यह लंबी यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन का विकल्प बनता है और ज्यादा सुरक्षा देता है। हालांकि डॉ. अवनीश के अनुसार इस पर भारत में रिसर्च और टेस्टिंग जारी है। बड़े स्तर पर उपयोग में आने में इसे समय लग सकता है। विदेशों में यह तकनीक काफी उपयोग हो रही है। फिलहाल भारत में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड कारें ज्यादा हैं। ये महंगी हैं, लेकिन अपनी ईंधन दक्षता और रेंज के चलते लोकप्रिय हुई हैं।

जहां तक प्लग-इन हाइब्रिड कारों की बात है, फिलहाल ये सिर्फ प्रीमियम लग्जरी ब्रांड, जैसे बीएमडब्लू, वोल्वो में मिलती हैं। हाल ही में टोयोटा ने अपनी महंगे सेगमेंट की प्रियस प्लग-इन हाइब्रिड कार को पुणे के सिएट-2026 में शोकेस किया है। यह कार फ्लेक्स-फ्यूल पर भी चल सकती है। इसकी कीमत और लॉन्चिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

कौन सी नई हाइब्रिड कारें

रेनॉ इस साल अपनी लोकप्रिय कार डस्टर का हाइब्रिड संस्करण पेश कर ही चुकी है। यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्प में भी मिल रही है।

मारुति सुजुकी इसी साल स्विफ्ट और डिजायर कारों का हाइब्रिड वर्जन लाने वाली है। चर्चा है कि मारुति अपनी नई 1.2-लीटर जेड-सीरीज इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक ला रही है। फ्रोंक्स का भी हाइब्रिड वर्जन पाइपलाइन में है, जो किफायती रेंज में बेहतरीन माइलेज और लुक का तालमेल होगा।

वहीं, महिंद्रा अपनी लोकप्रिय कार एक्सयूवी 3एक्सओ को हाइब्रिड अवतार में पेश कर सकती है। संभव है यह इस साल ही लॉन्च हो।

हुंडई की योजना 2030 तक अपनी कारों के लाइनअप में 8 हाइब्रिड कार जोड़ने की है। इस कड़ी में अगले साल की शुरुआत तक हुंडई की क्रेटा हाइब्रिड संस्करण में आ सकती है। यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में हो सकती है। हुंडई एक नई 5-7 सीटर हाइब्रिड कार लेकर आ सकती है। यह हुंडई की अल्काजार मॉडल से ऊपर के सेगमेंट में पेश हो सकती है। बता दें कि अल्काजार की कीमत 14-15 लाख रुपये तक जाती है।

वहीं, हुंडई की आई20 आधारित बेयॉन क्रॉसओवर इस साल के अंत तक आने की भी चर्चा है। यह टर्बो पेट्रोल की हाइब्रिड कार होगी। किया की सेल्टोस हाइब्रिड भी अगले साल की शुरुआत में पेश हो जाएगी। **प्रतिमा पांडेय**

5 हाइब्रिड कारें, जिनमें फुल टैंक पर 1000 किमी रेंज संभव

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
1.5 लीटर पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर
परफॉर्मेंस : 114 बीएचपी (कंबाइंड पावर)
फ्यूल टैंक : 45 लीटर
एआरएआई माइलेज : 27.97 किमी/लीटर
दावा की गई रेंज : 1200 किमी से अधिक
कीमत : 16.63 लाख से 22.86 लाख रुपये।

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
1.5 लीटर पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर
परफॉर्मेंस : 114 बीएचपी (कंबाइंड पावर)
फ्यूल टैंक : 45 लीटर
एआरएआई माइलेज : 27.97 किमी/लीटर
दावा की गई रेंज : 1200 किमी से अधिक
कीमत : 16.72 लाख से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

3. होंडा सिटी ई: एचईवी
1.5 लीटर पेट्रोल इंजन + 2 इलेक्ट्रिक मोटर
परफॉर्मेंस : 125 बीएचपी पावर और 253 एनएम टॉर्क
फ्यूल टैंक क्षमता : 40 लीटर
एआरएआई माइलेज : 27.26 किमी/लीटर
दावा की गई रेंज : 1000 किमी से अधिक
कीमत : 19.99 लाख से 20.85 लाख रुपये के बीच एक्स-शोरूम

4. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस
2.0 लीटर पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर
परफॉर्मेंस : 186 बीएचपी (संयुक्त आउटपुट)
फ्यूल टैंक क्षमता : 52 लीटर
एआरएआई माइलेज : 23.24 किमी/लीटर
दावा की गई रेंज : 1200 किमी से अधिक
कीमत : 26.30 लाख से शुरू (नोएडा-एक्सशोरूम)

5. मारुति सुजुकी इनविक्टो
2.0 लीटर पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर
परफॉर्मेंस : 186 बीएचपी (संयुक्त आउटपुट)
फ्यूल टैंक क्षमता : 52 लीटर
एआरएआई माइलेज : 23.24 किमी/लीटर
दावा की गई रेंज : 1200 किमी से अधिक
कीमत : एक्स-शोरूम कीमत लगभग 24.97 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 28.72 लाख रुपये तक जाती है।

(हिन्दुस्तान टाइम्स)

नए गैजेट्स

ओपो 14एक्स 5जी

फीचर्स में क्या खास : ओपो के14एक्स 5जी को बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.75-इंच की बड़ी एचडी+ स्क्रीन दी गई है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर बनाता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50एमपी का मुख्य रियर कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की शानदार और साफ तस्वीरें लेने के लिए पर्याप्त है।

बैटरी और चार्जिंग : फोन में 6,500 एमएएच की बड़ी बैटरी और 45 वाट फास्ट चार्जिंग दी गई है। कंपनी के मुताबिक, एक बार चार्ज करने पर यह फोन लंबे समय तक वीडियो देखने, नेविगेशन और वीडियो कॉलिंग में साथ देता है। डिवाइस को आईपी 64 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है।

कीमत और वेरिएंट : 4जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जबकि 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है।

दो रंगों में आएगा : प्रिज्म वॉयलेट और आइस ब्लू।

कब और कैसे खरीदें : 16 फरवरी से ई-कॉमर्स मंच फ्लिपकार्ट और ओप्पो इंडिया के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

बोट की नई ब्लूटूथ स्मार्टवॉच

हाल ही में बोट ने भारत में अपनी नई क्रोम आइरिस स्मार्टवॉच पेश की है। यह स्मार्टवॉच रोजमर्रा के इस्तेमाल, फिटनेस और कॉलिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश की गई है।

ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट: इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है, यानी फोन से कनेक्ट होने पर सीधे घड़ी से कॉल की जा सकती है। डिजाइन की बात करें तो मेटल बॉडी दी गई है और इसकी मोटाई सिर्फ 8एमएम है, बेहद हल्का होने के कारण इसे लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है।

काम के फीचर्स : हेल्थ ट्रैकिंग के लिए इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन (एसपीओ2) ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और महिलाओं के लिए वेलनेस ट्रैकिंग जैसे हेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टवॉच को आईपी68 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है और रोजाना इस्तेमाल के लिए सही है।

कीमत, रंग और उपलब्धता : स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 3,499 रुपये रखी गई है। वेलवेट वाइन, सिल्क स्किन, मेटल गोल्ड जैसे कई रंगों में उपलब्ध है। यह ऑनलाइन मंच- अमेजन, फ्लिपकार्ट, बोट की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

एडवेंचर बाइक की बढ़ती लोकप्रियता

मोटरसाइकिल

भारत में एडवेंचर बाइक अब सिर्फ कठिन रास्तों तक सीमित नहीं हैं। कम कीमत में दमदार इंजन, आधुनिक तकनीक और फीचर्स मिलने से ये अब आम राइडर्स के बीच भी लोकप्रिय हो रही हैं। यहां ऐसी ही पांच किफायती मोटरसाइकिलों की चर्चा की गई है, जो हाईवे से लेकर खराब सड़कों पर भी आरामदायक और भरोसेमंद सफर देंगी।

हीरो एक्स पल्स 210

हीरो एक्स पल्स 210 एक किफायती और लोकप्रिय एडवेंचर बाइक है। इसमें 210सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो ताकतवर परफॉर्मेंस देता है। लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, आरामदायक राइडिंग पोजीशन और स्लिपर क्लच इसे कठिन रास्तों और यात्रा के लिए उपयुक्त बनाते हैं। बाइक में डुअल-चैनल एबीएस अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को फिसलने से बचाता है। एलईडी लाइट्स से रात या खराब मौसम में भी सफर सुरक्षित रहता है। बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

कीमत : लगभग 1.62 (एक्स शोरूम) लाख रुपये।

केटीएम एडवेंचर 250

यह एडवेंचर-टूरिंग बाइक 249सीसी इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है, जो सड़क और हल्के ऑफ-रोड दोनों पर अच्छा राइडिंग अनुभव देती है। इसमें सस्पेंशन, एबीएस ब्रेक और 5-इंच डिस्प्ले हैं, साथ ही नेविगेशन और फोन नोटिफिकेशन भी देखे जा सकते हैं। 14.5 लीटर फ्यूल टैंक इसे लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक बनाता है।

कीमत : भारत में लगभग 2.40 लाख रुपये शुरुआती कीमत रखी गई है।

सुजुकी वी- स्ट्रॉम एसएक्स

उबड़-खाबड़ रास्तों और लंबी दूरी तय करने के लिए यह बाइक बेहद पसंद की जाती है। हल्का डिजाइन और आरामदायक सस्पेंशन जैसी खासियतें इसे एक भरोसेमंद एडवेंचर बाइक बनाती हैं। 249 सीसी का इंजन और 6 स्पीड गियरबॉक्स राइड को सुविधाजनक बनाता है। डुअलचैनल एबीएस, मल्टीइंफॉर्मेशन डिस्प्ले, एलईडी लाइट्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी हैं। बाइक चैंपियन येलो नं.2, ग्लास स्पार्कल ब्लू और अन्य ड्यूल-टोन रंगों में मिलेगी। कीमत लगभग 1.98 लाख रुपये (एक्सशोरूम दिल्ली) है। ऑनरोड कीमत शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300

टीवीएस अपाचे आरटीएक्स 300 में 299 सीसी का शक्तिशाली इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स है, जो लंबी यात्रा करने और हर तरह के रास्तों पर आरामदायक राइडिंग अनुभव देता है। डुअल-चैनल एबीएस, चार राइड मोड, नेविगेशन, ब्लूटूथ और क्रूज कंट्रोल जैसे उन्नत फीचर्स हैं। इसकी कीमत और फीचर्स इसे एडवेंचर बाइक सेगमेंट में एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

कीमत : बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.99 लाख रुपये से शुरू होती है। **फीचर डेस्क**

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450

यह दूर-दराज के सफर, पहाड़ी रास्तों और उबड़खाबड़ ट्रैक पर आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है। 450सीसी इंजन और 6स्पीड गियरबॉक्स है, जो संतुलित राइडिंग अनुभव देता है। डुअल- चैनल एबीएस, एलईडी लाइट्स और मजबूत सस्पेंशन जैसे फीचर्स हैं, जो हाईवे और ऑफरोड दोनों परिस्थितियों में मदद करते हैं। इसकी मजबूत बिल्ड और आरामदायक सीट इसे लंबी यात्रा और एडवेंचर राइडिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। एक्सशोरूम कीमत लगभग 3.06 लाख रुपये से शुरू है।

मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3.60 लाख करोड़ रुपये की लागत से राफेल लड़ाकू विमानों के साथ-साथ नौसेना के लिए आठ पी-8 आई टोही विमानों, मिसाइलों तथा स्यूडो सेटेलाइट की खरीद से जुडे.रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। इसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील भी माना जा रहा है। यह फैसला स्वागत-योग्य है। इससे देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। आज देश के सम्मुख एक ओर पाकिस्तान तो दूसरी ओर चीन जैसी चुनौतियां जो खड़ी हैं। इस खरीद के लिए यह अच्छी बात है कि रक्षा खरीद बोर्ड से इसके लिए पहले से ही स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि अंतिम मोहर तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ही लगेगी। इससे पूर्व भारत और फ्रांस के नेताओं के बीच सहमति बनेगी। जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अगले सप्ताह भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस सौदे के तहत भारत, फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। इससे भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रनों की कमी दूर होगी। वर्तमान में वायुसेना के पास मात्र 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं जबकि जरूरत 42 की है। हमारी वायुसेना के पास मिग-21, एंग्लो फ्रेंच जगुआर, फ्रेंच मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमान हैं। लेकिन अब मिग-21 लड़ाकू विमान की सेवानिवृत्ति से यह कमी आई है। पूर्व में वर्ष 2016 के सौदे में 36 राफेल विमान खरीदे गए थे। अब उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द देश को 18 और राफेल विमान मिल जाने चाहिए। शेष 96 विमान भारत में निर्मित होंगे सोर्स कोड शेयरिंग की शर्त से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, रखरखाव लागत कम आएगी। इसके साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी। कुछ विमान दो सीटों वाले होंगे जिन्हें प्रशिक्षण कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल एक बहुद्देशीय विमान है, जो मेटियोर बीवीआर मिसाल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन बम और स्पेक्ट्रा ईडब्लू सूट से लैस है। हवा से हवा, हवा से जमीन पर दूर तक मार करने की क्षमता रखता है। निगरानी मिशन से लेकर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसे विमान वाहक पोत से भी संचालित किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर दौरान इन विमानों ने अपने प्रदर्शन से पाकिस्तान में जमकर कहर बरपाया था। 4.5 जेनरेशन का यह जेट सुखोई-30 एमकेआई का पूरक बनेगा। इसमें नौसेना के 8 पी-8 टोही विमानों, टैंक रोधी सुरंगों वैभव और टी-72 टैंकों तथा इंफ्रेंट्री के लिए युद्धक वाहनों की खरीद को मंजूरी मिली है। यहां यह बताना भी होगा कि अक्सर हमारे रक्षा सौदों को अंतिम रूप तो दे दिया जाता है, लेकिन रक्षा साधनों की आपूर्ति में अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। मसलन तेजस विमानों के निर्माण के लिए जरूरी विशेष प्रकार के इंजिनों की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाने से इसका निर्माण प्रभावित हुआ है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे। जो भी डील हो, उसके तहत तकनीकी हस्तांतरण से लेकर जरूरी संसाधनों के साथ समय पर आपूर्ति निश्चित होनी चाहिए।

महाशिवरात्रि, अंधकार के गर्भ से ही ज्योति का अभ्युदय

परंपरा से परे शिव का विलक्षण व्यक्तित्व

पर्व विशेष

फाल्गुन की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को अलौकिक जागरण का आह्वान होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह तो भारतीय अध्यात्म की उस गहनतम अनुभूति का उत्सव है, जहां अंधकार और प्रकाश, विनाश और सृजन, मृत्यु और अमरता सब एकाकार हो जाते हैं।

रात्रि की गहन निस्तब्धता में जब चराचर सृष्टि निद्रामग्न हो जाती है, तब फाल्गुन की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को अलौकिक जागरण का आह्वान होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह तो भारतीय अध्यात्म की उस गहनतम अनुभूति का उत्सव है, जहां अंधकार और प्रकाश, विनाश और सृजन, मृत्यु और अमरता सब एकाकार हो जाते हैं। जब चंद्रमा अपनी अंतिम कला में क्षीण होकर लुप्त होने को होता है, तब शिव की आराधना का यह महापर्व आता है, मानो अंधकार के गर्भ से ही ज्योति का अभ्युदय होता हो। शिव का व्यक्तित्व भारतीय देवमंडल में अपनी विशिष्टता से दीप्त है। वे न तो वैदिक देवताओं की भांति स्तुतिप्रिय हैं, न पौराणिक देवों की तरह वैभवशाली। उनका रूप तो साक्षात् वैराग्य का साकार स्वरूप है। कैलाश के हिमाच्छादित शिखरों पर ध्यानस्थ, जटाजूट में गंगा की पावन धारा को धारण किए, गले में नागों का हार और शरीर पर चिता की भस्म लपेटे, यह कैसा देवत्व है जो समस्त लौकिक मर्यादाओं से परे है! किंतु इसी विलक्षणता में उनकी महिमा निहित है।

शिव की सरलता अतुलनीय

भोलेनाथ की संज्ञा से विभूषित शिव की सरलता अतुलनीय है। उन्हें न राजसी ठाट बाट चाहिए, न दिव्य भोग विलास। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और भक्त की निष्कपट श्रद्धा बस इतना ही उनका अभीष्ट है। बेलपत्र का त्रिदल त्रिगुणात्मक प्रकृति का प्रतीक है, सत्व, रज और तम का। अथवा वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। या फिर भूत, भविष्य और वर्तमान की त्रिकालीय सत्ता का द्योतक है। शास्त्रकारों ने अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। शिवलिंग पर जल की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है, यह प्रवाह जीवन की शाश्वत गति का, उस अनंत सत्य का प्रतीक है जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। महाशिवरात्रि की रात्रि चार प्रहर की पूजा और जागरण की रात्रि है। यह जागरण केवल देह का नहीं, यह तो चेतना का जागरण है, आत्मा का उन्मेष है। जब संसार निद्रा के आवरण में लिपटा होता है, तब साधक की चेतना जाग्रत होती है। रात्रि का अंधकार बाहर का है, परंतु भीतर तो दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है।

अर्धनारीश्वर का रूप

एक ओर महाकाल का रौद्र रूप है, दूसरी ओर भक्तवत्सल का कोमल स्वरूप। पार्वती के साथ उनका संयोग प्रकृति और पुरुष के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर का रूप तो और भी विलक्षण है आधे शिव, आधी शक्ति। यह द्वैत के परे अद्वैत की अनुभूति है। यह संकेत करता है कि सृष्टि का संचालन शिव और शक्ति के समन्वय से होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अपूर्ण है।

शिवलिंग की उपासना भारतीय अध्यात्म की मौलिक देन है। लिंग का तात्पर्य है प्रतीक, चिह्न। यह उस निराकार परब्रह्म का साकार संकेत है जिसे न तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, न रूप में बांधा जा सकता है। शिवलिंग मूर्ति नहीं है, यह तो उस अनंत का, उस असीम का प्रतीक है। जहां भाषा मौन हो जाती है, जहां विचार की गति रुक जाती है, वहां प्रतीक बोलने लगते हैं। शिवलिंग वही कहता है जो वेदों का गान है, जो उपनिषदों का रहस्य है।

सर्जन और विनाश का चक्र

शिव का तांडव नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार का महाकाव्य है। नटराज का रूप गतिशीलता और स्थिरता का अनुपम समन्वय है। चरण गतिमान हैं, परंतु मुख पर शांति की छाया है। हाथों में डमरू बज रहा है, जिससे सृष्टि का नाद उत्पन्न हो रहा है और अग्नि प्रज्वलित है जिससे संहार होता है। यही तो जीवन का शाश्वत सत्य है, सर्जन और विनाश का अनवरत चक्र। परंतु इस नृत्य के बीच नटराज का मुखमंडल अविचल है, शांत है। यह संदेश है कि बाहर कितना भी कोलाहल हो, भीतर शांति बनी रहनी चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। सर्वत्र शिव विराजमान हैं। श्रद्धालु दूर दूर से कावड़ लेकर आते हैं, गंगाजल से शिव का अभिषेक करते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह तो आस्था का जीवंत प्रवाह है। आधुनिकता के इस युग में भी जब अनेक परंपराएं विलुप्त हो रही हैं, महाशिवरात्रि की श्रद्धा अक्षुण्ण है।

देवेन्द्रराज सुथार
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जीवन का उच्चतम दर्शन

मंदिरों में घंटानाद गूंजता है, मंत्रोच्चार की पावन ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है, धूप दीप की सुगंध से सारा परिवेश आप्लावित हो जाता है। यह वातावरण लौकिक और अलौकिक के संगम का है, जहां पृथ्वी और आकाश मिल जाते हैं। समुद्र मंथन का आख्यान शिव की उदात्तता का अमर गान है। जब देवासुर संग्राम में अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मंथन हुआ, तब चौदह रत्नों के साथ हलाहल विष भी प्रकट हुआ। वह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से त्रिलोक जलने लगा। देवता भी विचलित हो गए, असुर भी भयभीत हो उठे। तब महादेव ने उस विष को स्वयं पान किया और कंठ में धारण कर लिया। विष से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह आख्यान केवल पौराणिक कथा नहीं, यह तो जीवन का उच्चतम दर्शन है। शिव संसार के समस्त विष को, समस्त कष्ट को, समस्त पीड़ा को स्वयं में धारण कर लेते हैं ताकि जगत सुरक्षित रहे।

जीवन बोध

आत्मिक सजगता

मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रकृति की भांति विनम्रतापूर्वक परोपकार, सेवा भाव तथा कार्य से जुड़ा रहना है। मानव ने भले ही कितने वैज्ञानिक चमत्कार कर दिए हों, पर इन चमत्कारों के पीछे की भावना परोपकारी कम और अर्थकारी अधिक थी। अब भी स्थिति नहीं बदली। बल्कि पहले से जटिल हो चुकी है। ऐसे में मनुष्य के पास अपनी आत्मिक सजगता का अंतिम उपाय ही बचता है, जिसके बलबूते वह विचार करता है कि नश्वर शरीर के साथ सांसारिक सुख सुविधाओं का मोह पालना मानव का कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। अपने जीवन से पूर्व का सच हम नहीं जानते। परंतु मृत्यु के लिए लक्षितए नियत जीवन की परिणति से तो हम साक्षात अवगत होते ही हैं। तब भी अपने परिवेश को कृत्रिम गतिविधियों, विचारों और भावनाओं से भरने का उल्लास हम से छूटता नहीं तथा जैसे जैसे मनुष्य परिपक्व दृष्टि से जीवन के सत्य से अवगत होता है, वह क्षणभंगुर जीवन के ईश्वर प्रदत्त उद्देश्यों के प्रति एकाग्रचित्त होने लगता है। इस वैचारिक युक्ति से आत्मज्ञान उभरता है तथा मनुष्य उसमें स्थिर होने के प्रयास करने लगता है। वह अपने शरीर के पंचतत्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगता है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सूक्ष्मांश स्वयं को वह इन्हीं के प्रति समर्पित कर देता है।

विकेश कुमार बडोला

हेल्थ इज वेल्थ

- 8 मिनट का तेज गुस्सा खून की नसों को 1 घंटे तक सख्त कर सकता है, नई रिसर्च में 280 लोगों पर स्टडी से पता चला कि गुस्से का असर 40 मिनट तक रहता है, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, बार बार गुस्सा होने से दिल को नुकसान पहुंचाता है।
- शोधकर्ताओं ने बताया कि गुस्सा खून की नसों को फ्रीज कर देता है, यानी वे लचीली नहीं रहतीं और फैल नहीं पातीं, इससे खून का बहाव रुक जाता है, जो दिल और दिमाग के लिए खतरनाक है। रिसर्च से साबित हुआ कि गुस्सा कंट्रोल करना हृदय की रक्षा का वैज्ञानिक तरीका है।
- इसके लिए गहरी सांस लें, गुस्से के समय 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें और छोड़ें, एक्सरसाइज करें रोजाना वॉक या योग से तनाव कम होता है। ध्यान या मेडिटेशन से भावनाओं पर कंट्रोल बढ़ता है, पॉजिटिव सोच रखें, गुस्से के बजाय समस्या का समाधान सोचें।

जल तरंग

सड़कों पर रेला

वैलेंटाइन डे के दिन सड़कों पर जो रेला निकलता है, उसे देखकर लगता है कि देश की सारी बेरोजगारी अचानक प्रेम में तब्दील हो गई है। निब्बा, जिसकी बाइक का साइलेंसर मोहल्ले की शांति को वैसे ही चीरता है जैसे कोई अनाड़ी सर्जन पेट फाड़ता है, आज अपने पीछे बैठाकर ऐसे हवा से बातें करता है जैसे उसने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया हो। निब्बी भी, जो चेहरे पर पाउडर की इतनी परतें जमाए रहती है कि अगर वह जोर से छींक दे तो पास खड़े व्यक्ति को धूलभरी आंधी का अहसास हो जाए, आज के दिन अपने अस्तित्व को उन चंद शब्दों में ढूंढती है, जिनका डिक्शनरी से कोई वास्ता नहीं है। बाइक की पिछली सीट पर चिपककर बैठी वह निब्बी जब निब्बे के कान में फुसफुसाती है, तो निब्बा अपनी भूख भूलकर गर्व से ऐसे फूल जाता है मानो उसे पद्मश्री मिल गया हो। आज के दिन ओयो नामक संस्थान किसी सिद्ध पीठ की तरह चमकने लगते हैं। यहां के रिसेप्शन पर खड़ा वह आदमी, जिसकी नज़रें पहचान पत्रों को वैसे ही स्कैन करती हैं जैसे कोई पुलिसवाला अपराधी को, आज साक्षात नियति बनकर खड़ा रहता है। निब्बा अपनी जेब में पड़े उन चंद रुपयों को वैसे ही सहलाता है जैसे कोई सट्टेबाज अपनी आखिरी बाजी को, क्योंकि उसे पता है कि इस पीली लाइट वाली दुनिया का दरवाजा इसी रिसेप्शनिस्ट की टेढ़ी भौंहों से होकर खुलता है। अंदर जाते समय निब्बी का चेहरा वैसा ही मासूम होता है जैसा किसी घोटाले में पकड़े गए नेता का होता है। होटल का गलियारा वह जगह है जहां निब्बा का आत्मविश्वास वैसे ही डगमगाता है जैसे बिना खंभे के टिकी हुई कोई कच्ची दीवार। वह पंखे की पंखुड़ियों, टीवी के रिमोट को ऐसे संदेह से देखता है मानो वह किसी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का मुख्य गवाह बनने वाला हो। आधुनिक प्रेम की यह विडंबना है कि यहां दो दिलों के मिलने से पहले, तलाशी लेना अनिवार्य हो गया है। प्राइवेसी की यह भूख इतनी गहरी है कि प्रेमी अब एक दूसरे की आंखों में कम और आईने के पीछे लगे किसी काल्पनिक कैमरे को ज्यादा ढूंढते हैं। पिज्जा का डिब्बा खुलता है, लेकिन उसे खाने से पहले उसकी सत्रह अलग अलग कोणों से फोटो खींची जाती है। निब्बा घुटनों के बल बैठकर, लेटकर, तिरछा होकर निब्बी की ऐसी फोटो खींचता है मानो वह किसी वाइल्डलाइफ मैग्जीन के लिए किसी दुर्लभ प्रजाति की तस्वीर ले रहा हो। प्रेम अब महसूस करने की चीज़ नहीं रही, वह पूरी तरह से अपलोड करने की चीज़ बन गई है। निब्बी का अपना संघर्ष भी कम नहीं है। वह अपनी जुल्फों को बार बार चेहरे पर लाती है ताकि इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट रील बन सके। सड़कों पर बिकते लाल गुलाब, जिनका दाम आज के दिन पेट्रोल से भी महंगा होता है, शाम तक कूड़े के ढेर में तब्दील होने के लिए अभिशप्त हैं।

डॉ सुरेश कुमार मिश्रा
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

सब्जी तौलते समय मक्खी तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वही सोना तौलते वक्त बैठ जाए, तो उसकी कीमत हजारों में हो जाएगी। हम ऐसे लोगों के साथ बैठें, जिनसे हमारी कीमत बढ़े ।
श्री चन्द्रप्रभ जी।

विंडो टू द वर्ल्ड

बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, इस मंदिर को पेरुवुदैयार कोविल, राजराजेश्वर मंदिर और पेरिया कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर एक हजार वर्ष से अधिक पुराना है और वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। प्रवेश द्वार पर नंदी की प्रतिमा है, यह प्रतिमा एक ही पत्थर से तराशी गई है। मंदिर मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना है।

अपनों से अपनी सी बात

गुस्से पर काबू रखें

मान लीजिए कभी आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं।दूसरे ने बड़ी भारी गलती की है, आप को गुस्सा भी बहुत आया हुआ है।उस पर गुस्सा होने से पहले एक मिनट के लिए आप सोचना कि आपका गुस्सा जायज है या नाजायज़ है, उचित है कि अनुचित आपको करने का अधिकार है या नही दूसरी बात सोचना कि गुस्सा करने से क्या बन जाएगा उसको आप बुरा भला कहेंगे, डांटेंगे, मारेंगें, थपड़ लगाएंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा तीसरी बात गुस्सा करने से उसका कुछ बिगड़े या बने, वह तो बाद कि बात है, सबसे पहले तो आप का ही नुकसान होगा।यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी हथेली पर जलते हुए अंगारे लेकर दूसरे पर फेंके।वो तो पता नहीं जलेगा कि नहीं अलबत्ता आपकी हथेली पहले जरूर जल जाएगी।पहले आप का ही नुकसान होगा।आपका बीपी, शुगर बढ़ जाएगा।रूस के जार को एक बार उसके मन्त्री ने भरी सभा मे टोक दिया, आपकी नीतियां ही गलत हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए।उस जार को अपने मन्त्री पर इतना अधिक गुस्सा आया कि उसको मारने के लिए उसने हाथ उठाया, उसके सिर पर खून सवार था।मुझे ज्ञान देने चला है, मुझे सिखागा, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं !जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया मारने के लिए, उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया, जार को लकवा मार गया।बहुत ज्यादा हाई बीपी के कारण उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। बहुत अधिक गुस्से के कारण उसका बीपी ख्रनाक स्तर तक बढ़ गया था।और उसकी तत्क्षण मौत हो गई वहीं दरबार में ही।गुस्सा कभी गुस्से से शान्त नहीं होता, उल्टा आग बढ़ती ही है।यह सब सोचकर आपको अपने को नियन्त्रित करना चाहिए।

ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता में देश का अग्रणी प्रदेश बन गया

विकसित राजस्थान का नया पावर हाउस

पुष्पेंद्र सिंह राणावत
विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट, राजस्थान को 'अंधेरे से उजाले' की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

राजस्थान की रेतीली धरती और असीमित धूप अब लोककथाओं के साथ ही आधुनिक भारत की ऊर्जा क्रांति का केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट, राजस्थान को 'अंधेरे से उजाले' की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह बजट 'विकसित राजस्थान @ 2047' के उस भव्य भवन की नींव है, जिसकी धमनियों में अक्षय ऊर्जा की शक्ति प्रवाहित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' और 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र को आत्मसात करते हुए यह बजट सेवा, सुशासन और विशेष रूप से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को समर्पित है। विकसित अर्थव्यवस्था की पहली शर्त निर्बाध और सस्ती बिजली होती है। इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान अब केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए 'पावर हाउस' बनने की राह पर है। प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो साहसिक कदम उठाए हैं, वे अभूतपूर्व हैं।

ऊर्जा क्षमता में देश का अग्रणी प्रदेश

बजट के अनुसार, राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता में देश का अग्रणी प्रदेश बन गया है। सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों के साथ मिलकर 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले जॉइंट वेंचर किए हैं। यह भारी-भरकम निवेश न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को आधुनिक बनाएगा, बल्कि राजस्थान को 'ग्रीन एनर्जी' के वैश्विक मानचित्र पर भी स्थापित करेगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे सौर ऊर्जा के लिए वरदान बनाती है। बजट में 19,209 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की वृद्धि यह बताता है कि सरकार सूर्य की ऊर्जा को राजस्व और समृद्धि में बदलने के लिए गंभीर है। विशेष रूप से 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। प्रदेश में 1 लाख 30 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट्स की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब विकास आम आदमी के घर की छत तक पहुँच गया है। यह योजना न केवल मध्यम वर्ग को बिजली बिलों से मुक्ति दिला रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

'रियल टाइम मॉनिटरिंग'

बजट का सबसे आधुनिक पहलू ऊर्जा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समावेश है। बिजली कटौती और तकनीकी खराबी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती रही है। इसका समाधान निकालते हुए सरकार ने अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रिड को एआई एनेबल्ड करने का निर्णय लिया है। सबस्टेशनों और ट्रांसफार्मरों पर इन्टरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स के माध्यम से 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब कोई फॉल्ट होने के बाद उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तकनीक पहले ही बता देगी कि कहाँ समस्या आने वाली है। यह 'डिजिटल प्लेटफॉर्म' उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की गारंटी देता है और बिजली चोरी तथा छीजत को कम करने में भी क्रांतिकारी साबित होगा। बिजली को सुरक्षित रूप से अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रदेश के विद्युत तंत्र के विस्तार के लिए ग्रिड सब-स्टेशन का एक विशाल जाल बिछाने का संकल्प लिया है। सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 KV के 2 जीएसएस और 220 KV के 5 जीएसएस स्थापित किये गये। आगामी वर्ष के लिए 220 KV के 6, 132 KV के 13 और 33 KV के 110 नए जीएसएस का निर्माण किया जायेगा। बीकानेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में लगभग 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास और उन पर 2,900 करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान के रेगिस्तान को स्वर्ण ऊर्जा में बदल देगा। ऊर्जा इस बजट की शक्ति है और इसका मानवीय चेहरा GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) में निहित है। सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को 28,400 करोड़ रुपये की पेंशन सीधे उनके खातों में पहुँचाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी सम्मान से जी सके। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाकर और समयबद्ध रोजगार के अवसर पैदा कर सरकार युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस यह बताता है कि यह सरकार किसानों के पसीने की कीमत समझती है। 'लखपति दीदी' और सुपोषण किट जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कुपोषण से लड़ने का एक सशक्त जरिया हैं। राजस्थान सरकार ने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन का उत्कृष्ट नमूना पेश किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 21 लाख 52 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में 41.39% अधिक है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अब 2,02,349 रुपये तक पहुँचने का अनुमान है, जो प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार का स्पष्ट संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकोषीय घाटा मात्र 2.54% रहने का अनुमान है, जो वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) की सीमाओं के भीतर है।

जागरूक संपादकीय
जागरूक टाइम्स। मुंबई। शनिवार, 14 फरवरी 2026

श्रीरामचरितमानस

सदगुर ग्यान बिराग जोग के।
बिबुध बैद भव भीम रोग के॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के।
बीज सकल ब्रत धरम नेम के॥2॥

भावार्थ : ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य (अश्विनीकुमार) के समान हैं। ये श्री सीतारामजी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता-पिता हैं और सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं॥2॥

डिजिटल संसार

पिछले दिनों गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों ने अपने आवास की नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 12,14 और16 साल की आयु अपने जीवन के सपनों को बुनने और उन्हें बड़े लक्ष्यों के साथ पूरा करने की होती है, मगर लगता है इस उम्र में समाज और परिवार की वास्तविक दुनिया को छोड़कर आभासी दुनिया, गेमिंग और डिजिटल मीडिया की गिरफ्त में आकर बचपन हिंसा की ओर मुड़ चला है। तीनों को कोरोना काल से ही कोरियाई लव गेम, कोरियाई ड्रामे, गाने और मूवी देखने की लत लग गई थी। वे तीनों कोरियाई संस्कृति से इतनी प्रभावित थीं कि अपने नाम के साथ-साथ जीवनशैली को भी उसी संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया था। टास्क-बेस्ड डिजिटल गेम्स ने इन लड़कियों को पहले किताबों से दूर किया, फिर उनकी वास्तविक दुनिया भी समाप्त कर डाली। कोरियाई गेम की लत के कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तीनों बहनों में एक बहन डेथ कमांडर की भूमिका निभाते हुए बाकी दोनों को टास्क पूरा कराने में भूमिका निभाती थी। तीनों लड़कियों के सुसाइड नोट से जुड़े शब्द आइ एम सारी पापा-मैं गेम नहीं छोड़ पा रही हूं, यही बताते हैं कि ये किशोरियां एक टास्क-बेस्ड डिजिटल गेम से जुड़ी पूर्व नियोजित योजना की शिकार थीं। गाजियाबाद की घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी है, जो अपने बच्चों पर भरोसा किए बैठे हैं कि उनका बच्चा बंद कमरे में मोबाइल चलाते हुए सुरक्षित है। इस घटना के बाद से कई माता-पिता अपने बच्चों को लेकर मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि टास्क-बेस्ड गेम में डिजिटल कंटेंट को नाबालिग वर्ग तक बड़ी चतुराई से पहुंचाया जाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि किशोर-किशोरियों के बीच कोरियाई, चीनी एवं जापानी कंटेंट को बिटक्वाइन मुद्रा का लालच देकर भी योजनाबद्ध तरीके से उन तक पहुंचाया जा रहा है। बीते दिनों संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य आनलाइन प्लेटफार्म्स पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके सामाजिक जीवन को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इससे निपटने के लिए आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल एवं सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। आस्ट्रेलिया और फिनलैंड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के लिए कानून लागू हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली में ऐसा कानून लाने पर सहमति बन चुकी है। ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस भी इससे जुड़ा कानून बनाने की तैयारी में हैं। भारत में एक अरब से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 50 करोड़ से अधिक यूट्यूब, 40 करोड़ से अधिक फेसबुक तथा 48 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम यूजर हैं।

बांग्लादेश चुनाव परिणाम

तारिक रहमान होंगे नए प्रधानमंत्री

विजय कपूर

जनरल ज़िया-उर-रहमान व खालिदा ज़िया के 60 वर्षीय बेटे तारिक रहमान 17 साल तक निर्वासन में रहने के बाद स्वदेश लौटे, चुनाव लड़ा और अब वह बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) गठबंधन ने 12 फरवरी 2026 को जातीय संसद के लिए हुए 13वें आम चुनाव में 212 सीटें जीती हैं, स्थानीय जमुना आदि टीवी चैनलों के अनुसार। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को कुल 70 सीटें हासिल हुईं हैं, जिसमें 5 सीटें नेशनल सिटीजन पार्टी की हैं, जिसने जेन जी आंदोलन में शेख हसीना का तख्ता पलटने में अहम भूमिका अदा की थी। शेख हसीना, जो इस समय भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए वह चुनाव में भाग न ले सकी। शेख हसीना ने चुनाव को 'सुनियोजित स्वांग' बताया है।

इमेज

300 संसदीय सीटों (जिनमें से एक पर चुनाव स्थगित हुआ, प्रत्याशी के निधन के कारण) के लिए 50 राजनीतिक दलों के सदस्यों व स्वतंत्र प्रत्याशियों सहित लगभग 2000 उम्मीदवार मैदान में थे और तकरीबन 48 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2024 के आम चुनाव के 42 प्रतिशत मतदान से बेहतर रहा। इस मतदान में मतदाताओं को दो वोट डालने थे, एक सांसद चुनने के लिए और दूसरी संवैधानिक 'सुधारों' के संदर्भ में जनमत संग्रह के लिए। बांग्लादेश के एक सदन वाले राष्ट्रीय संसद को जातीय संघसद कहते हैं। इसमें 300 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो चुनाव के बाद पार्टियों में उनकी जीत के अनुपात में विभाजित कर दी जाती हैं। बांग्लादेश में 1973 से 2026 तक जो कुल 13 आम चुनाव हुए हैं, उनमें से सिर्फ पांच (1991, 1996, 2001, 2008 व 2026) को ही अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव घोषित किए हैं। 1996 में दो बार आम चुनाव कराने पड़े थे; क्योंकि 1996-1 चुनाव को अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने बायकाट किया था और बीएनपी ने खुद को 278 सीटों पर जीता हुआ दिखाया था। दरअसल, बांग्लादेश में अधिकतर चुनावों की कहानी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बायकाट व उन पर प्रतिबंध के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। इस बार के आम चुनाव में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध था और जो पार्टियां- बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी, जो वर्षों तक चुनावी दौड़ से बाहर रहीं या उन्हें बाहर रखा गया, सत्ता की मुख्य दावेदार बनकर उभरी। शेख हसीना ने 2009 के बाद से 15 साल तक निरंतर राज किया और उनके शासनकाल में बांग्लादेश में स्थिरता व आर्थिक विकास देखने को मिला। लेकिन साथ ही उन पर तानाशाह होने के भी आरोप लगे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और 2024 में उन्हें अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। यह केवल इतना नहीं था कि अलोकप्रिय हुए नेता को हिंसक विद्रोह में सत्ता से हटा दिया गया बल्कि छात्रों के आंदोलन में बांग्लादेश के बुनियादी

इतिहास को भी मिटाने का प्रयास किया गया, जिसमें शेख हसीना के पिता व उनकी पार्टी अवामी लीग के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान प्रमुख शख्सियत थे। जैसे ही अवामी लीग के लीडर व समर्थक अंडरग्राउंड हुए बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता के नये दावेदारों के रूप में उभरने लगीं, विशेषकर नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में। हालांकि अब तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी गठबंधन का सत्ता में आना तय हो गया है, लेकिन बांग्लादेश के समक्ष चुनौतियों का अम्बार लगा हुआ है। सबसे पहले तो पिछले 18 माह में धीमे हुए आर्थिक विकास को पटरी पर लाने की आवश्यकता है ताकि बेरोज़गारी, महंगाई आदि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय पर जो हिंसक हमले हो रहे हैं, उन पर त्वरित प्रभाव से विराम लगाया जाए। बीएनपी से सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद की जा सकती है, विशेषकर इसलिए कि उसके प्रमुख हिन्दू लीडर ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट से शानदार जीत दर्ज की है, जमात-ए-इस्लामी के मुहम्मद शाहीनूर इस्लाम को पराजित करके। रॉय की जीत बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है कि ढाका-3, जो मुस्लिम बहुल सीट है, पर पहली बार कोई हिन्दू प्रत्याशी जीता है। रॉय बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। बहरहाल, तारिक रहमान के समक्ष भारत से संबंध सुधारने की भी चुनौती है, जो शेख हसीना को शरण देने की वजह से प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि तारिक रहमान जब आत्म-निर्वासन से बांग्लादेश लौटे थे, तो नई दिल्ली ने अपने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को उनसे मुलाक़ात करने के लिए ढाका भेजा था। इसलिए भारत व बांग्लादेश के संबंध बेहतर होने की संभावना है। बांग्लादेश में मतदान के साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर, जो 84 पॉइंट का सुधार पैकेज है, पर भी जनमतसंग्रह हुआ था। इस चार्टर को जनता ने अपनी सहमति दी है, लेकिन जनमत संग्रह कहीं भी अच्छा विचार साबित नहीं हुआ है। ब्रिटेन के सांसद 1998 में इस विषय पर कुछ भी तय नहीं कर पाये थे। ब्रिटेन से अधिक स्विट्ज़रलैंड जनमत संग्रह में माहिर रहा है कि उसने 1981 व 1999 के बीच 148 जनमत संग्रह कराए। भारत में 1975 के बाद से कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने आखिरी बार यह 2002 में कराया था। क्या इससे स्विस लोकतंत्र हम से अधिक 'परफेक्ट' हो जाता है? सिद्धांत में, शायद। व्यवहार में, हमें नतीजों के आधार पर समीक्षा करनी चाहिए। आज़ाद भारत में प्रत्येक पुरुष व महिला को 1950 में ही मतदान का अधिकार मिल गया था। स्विट्ज़रलैंड में पुरुषों ने 1959 में महिलाओं को मतदान दिए जाने के जनमत संग्रह को ठुकरा दिया था और इस गलती का सुधार इसके 12 साल बाद किया गया। यह सही है कि जनमत संग्रह लोकतंत्र की जड़ों के बहुत करीब है, लेकिन विशेषज्ञों की राय से संचालित प्रतिनिधि लोकतंत्र के अपने लाभ हैं। अधिकतर समकालीन मुद्दे जैसे भारत में अधिक परमाणु ऊर्जा प्लांट्स और वह भी थोरियम ईंधन वाले, होने चाहिए या नहीं, आम मतदाताओं के लिए बहुत जटिल हैं। सरकारें जनता को अपनी नीतियों के लाभ व हानि के बारे में जागरूक करें, लेकिन इस प्रकार का पांच मिनट का ज्ञान प्रोफेशनल महारत का विकल्प नहीं है। साथ ही जनमत संग्रह अक्सर तब आयोजित किया जाता है, जब सरकारें कोई स्टैंड लेने से डरती हैं। याद करें कि केरल ने 2018 में जनमत संग्रह कराने का ऑफर दिया था कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। उसी साल ब्रिटेन ने 52 प्रतिशत 'हां' व 48 प्रतिशत 'न' से यूरोपीय संघ से निकलना तय किया, जो गलत साबित हुआ। जनमत संग्रह की सबसे समस्या बहुसंख्यावाद है, जिससे से अल्पसंख्यकों के हित प्रभावित होते हैं।

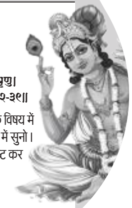

गीता सार

एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रृणु।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥२-३९॥

भावार्थ : हे पार्थ! तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे॥39॥

खेल-खिलाड़ी

भारतीय बैडमिंटन क्षितिज पर चमका सितारा सारिम अन्ना

देविका सिहाग

"मैं जीत गई।" इस अहसास को समझने में समय लगा। बैंकाक में थाईलैंड मास्टर्स 2026 में सफलता आगमन जैसी कम और खामोश घोषणा जैसी अधिक प्रतीत हुई। मात्र 20 वर्ष की आयु में देविका सिहाग सबसे कम उम्र की और केवल तीसरी-भारतीय महिला एकल शटलर बनी हैं साइना नेहवाल व पीवी सिंधु के बाद, जिन्होंने बीडब्लूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता है। इस प्रकार भारतीय बैडमिंटन की विशिष्ट विजेता सूची में एक और नाम जुड़ गया है। कुल ढाई लाख प्राइज पूल की यह प्रतियोगिता बैंकाक के निमिबुत्र स्टेडियम में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक खेली गई। "इस प्रतियोगिता में जाने से पहले मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। शुरू से ही मैं बहुत अच्छा खेल रही थी। नंबर 1 सीड सुपानिदा (कटेथोंग) को पराजित करने के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी कामयाबी की प्रबल संभावनाएं हैं।" देविका ने बैंकाक से लौटने के बाद बताया। पंचकुला की रहने वाली देविका की हाइट 172 सेमी है, जिसकी वजह से वह बंग्लुरु में सेंटर ऑफ़ बैडमिंटन एक्सीलेंस, जिसका पिछला नाम प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी (पीपीबीए) था, के ट्रेनियों में सबसे लम्बे कद की लड़की हो जाती हैं। देविका के मामले में कद गारंटी की बजाय संसाधन है। वह जिस स्पीड की संभावना प्रदर्शित कर रही हैं, उसमें अभी पैनापन लाने की ज़रूरत है। वह कहती हैं, "सिंधु दीदी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं साफ देख सकती हूं कि हमारी स्पीड्स में कितना अंतर है। अब मुझे मालूम है कि मुझे अपने खेल में जबरदस्त गति लाने की आवश्यकता है ताकि हाई-रैंक खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर सकूं।" इस बिंदु तक की यात्रा कुलीन अकादमियों के नियंत्रित वातावरण से बहुत दूर आरंभ हुई थी, पंचकुला में जहां देविका अपने चार शुरुआती वर्षों में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में कोच रोहित मंधाना की निगरानी में ट्रेनिंग करती थीं। वहां उन्होंने प्रतिस्पर्धा की रिद्म सीखी। उनके पिता अजित सिहाग जो वकील हैं और अध्यापिका माता ने उन्हें व उनके भाई को बैडमिंटन में फिटनेस के लिए प्रवेश दिलाया था। इससे पहले देविका स्केटर थीं।

तिथि विशेष

वैलेंटाइन डे

वैलेंटाइन डे हर वर्ष 14 फरवरी को विश्वभर में मनाया जाता है। यह दिन प्रेम, स्नेह, अपनापन और भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आधुनिक समय में इसे खास तौर पर प्रेमी-प्रेमिकाओं के त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल रोमांटिक प्रेम तक सीमित नहीं है। यह दिन माता-पिता, भाई-बहन, मित्र और सभी प्रियजनों के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने का अवसर भी है। वैलेंटाइन डे का नाम सेंट वैलेंटाइन के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि वे तीसरी शताब्दी में रोम के एक पादरी थे। उस समय के रोमन सम्राट क्लॉडियस द्वितीय ने सैनिकों के विवाह पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अविवाहित सैनिक बेहतर योद्धा होते हैं। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने प्रेम और विवाह का समर्थन करते हुए गुप्त रूप से सैनिकों के विवाह कराए। जब यह बात सम्राट को पता चली, तो उन्होंने वैलेंटाइन को मृत्युदंड दे दिया। 14 फरवरी को उनके बलिदान की स्मृति में यह दिन मनाया जाने लगा। समय के साथ यह दिवस प्रेम के उत्सव के रूप में लोकप्रिय हो गया। आज के दौर में लोग अपने प्रियजनों को कार्ड, फूल, चॉकलेट और उपहार देकर अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं। लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन गुलाब का विशेष महत्व होता है। सोशल मीडिया और डिजिटल युग में लोग संदेश, तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से भी अपनी भावनाएँ साझा करते हैं। भारत में भी वैलेंटाइन डे का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। कॉलेज, बाजार और कैफे इस दिन विशेष सजावट से सजे होते हैं। कुछ स्थानों पर सांस्कृतिक मतभेदों के कारण इस दिन को लेकर अलग-अलग विचार भी देखने को मिलते हैं, फिर भी प्रेम और सम्मान की भावना सर्वत्र स्वीकार्य है।

नदी गाथा

गंगा और नर्मदा जैसी महान नदी ताप्ती

वीना गौतम

ताप्ती जिसे तापी नदी भी कहते हैं, भारत की उन चुनिंदा बड़ी पश्चिम वाहिनी नदियों में से है, जो मध्य भारत से निकलकर सीधे अरब सागर में गिरती है। यह विशेषता इसे गंगा जैसी विशाल पूर्व वाहिनी नदी और नर्मदा जैसी महान पश्चिम वाहिनी नदी के समकक्ष ला खड़ा कर देती है। भौगोलिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक स्तरों पर इस नदी का योगदान अत्यंत व्यापक है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतूल जिले के पास सतपुड़ा पर्वतमाला में है। यहां से लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती यह नदी अंततः अरब सागर में जा मिलती है। इसके किनारे सूरत जैसा औद्योगिक और व्यापारिक शहर स्थित है। ताप्ती नदी का जलभरण क्षेत्र लगभग 65 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और 724 किलोमीटर लंबी इस नदी को इसकी जो सहायक नदियां इसकी जलराशि को सम्पन्नता प्रदान करती हैं, उनमें-पूर्णा, गिर्णा, वाघुर और अंजली नदियां हैं।

इमेज

इसका मुहाना अरब सागर में बनता है। ताप्ती को गंगा और नर्मदा के समकक्ष महानदी इसलिए माना जाता है, क्योंकि यह भी इन्हीं की तरह विशाल नदी घाटी प्रणाली बनाती है। क्योंकि ताप्ती बेसिन एक स्वतंत्र और बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, जो लाखों लोगों की कृषि, पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह गुण ही इसे पश्चिम की नर्मदा और पूर्व की गंगा जैसी नदी के समकक्ष ला खड़ा करता है। जैसे गंगा नदी घाटी में प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे ही ताप्ती घाटी में भी आदिवासी समाज, कृषि संस्कृतियां और व्यापारिक नगर विकसित हुए। ताप्ती घाटी कपास, सोयाबीन, गन्ना, केला और विभिन्न तरह की दालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की तरह यह भी कृषि आधारित जीवनरेखा की भूमिका निभाती है। नर्मदा की तरह ताप्ती को भी अनेक स्थानों में पवित्र नदी का दर्जा दिया जाता है और इसके किनारे मेले और पवित्र स्नानों से संबंधित पर्व संपन्न होते हैं। देश की दूसरी पवित्र नदियों की तरह ताप्ती के तट में भी अनेक महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। जहां तक इसके बहाव की गति की बात है, तो शुष्क मौसम में इसका बहाव 0.3 से 0.6 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि मानसून के दौरान ताप्ती नदी का बहाव 1.5 से 3 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचता है। चूंकि यह पश्चिम वाहिनी है, इस कारण इसमें ढाल अपेक्षाकृत ज्यादा है। यही कारण है कि इसका प्रवाह पूर्वगामी नदियों

के मुकाबले ज्यादा है, जिससे जल विद्युत उत्पादन के लिए ताप्ती महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ताप्ती का औसत वार्षिक प्रवाह 17 से 18 बिलियन घन मीटर आंका गया है। इसका अधिकांश भाग जून से सितंबर यानी मानसून के दौरान प्राप्त होता है। ताप्ती नदी की वर्षा पर निर्भरता करीब 75 फीसदी है और शेष 25 फीसदी जलराशि इसके भूजल, पुनर्भरण और सहायक नदियों के जरिये प्राप्त होता है। इसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, पेयजल के रूप में, औद्योगिक उपयोग हेतु तथा विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। ताप्ती नदी की मिट्टी जलोढ़ है, जो अत्यंत उपजाऊ होती है। इस कारण इसके परिक्षेत्र में दोहरी फसल प्रणाली सहजता से संभव है और किसान अपेक्षाकृत कम सिंचाई लागत में खेती कर पाते हैं। ताप्ती नदी ग्रामीण रोजगार का भी बड़ा आधार बनाती है। गंगा की तरह ताप्ती को भी अन्न भंडार के रूप में देखा जाता है। ताप्ती के किनारे स्थित शहर विशेष रूप से कपड़ा, रसायन, हीरा कटाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे लाखों रोजगार और शहरी विकास को बल मिलता है। जहां तक इसके पारिस्थितिक तंत्र की महत्ता का सवाल है तो ताप्ती नदी में मीठे पानी की अनेक महत्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां पाईं जाती हैं, जिनमें रोहू, कतला और मृगल शामिल हैं। सतपुड़ा क्षेत्र से गुजरते समय यह नदी कई वन क्षेत्रों को जीवन देती है, जिसमें हिरण, तेंदुआ, भालू जैसे जीवों को पानी और भोजन मिलता है। ताप्ती नदी के डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों की कई प्रजातियां पायी जाती हैं और प्रवासी पक्षियों का भी यह आश्रयस्थल बनती है। ताप्ती बेसिन में नदी का पानी आसपास के जलस्रोतों को भरता है, जिससे कुओं, नलकूपों आदि में पूरे साल जल उपलब्ध रहता है। देश की दूसरी महा नदियों की तरह ताप्ती भी कई तरह की औद्योगिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ये भी औद्योगिक प्रदूषण से ग्रस्त है। इस नदी में भी बड़े पैमाने पर शहरी अपशिष्ट आकर मिलता है तथा इसमें भी अवैध रेत खनन आदि की घटनाएं होती हैं।

वायरल

बच्ची ने टीचर से किया सवाल, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

स्कूलों में अक्सर बच्चों के सवाल मासूम होते हैं, लेकिन कई बार वही सवाल बड़ों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक सवाल एक बच्ची ने टीचर से पूछा है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। स्कूलों में अक्सर बच्चों के सवाल मासूम होते हैं, लेकिन कई बार वही सवाल बड़ों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाल ही में एक कक्षा में ऐसा ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब एक छोटी बच्ची ने अपनी टीचर से पूछा "अगर पाकिस्तान से पांच चिड़िया उड़ीं, तो इंडिया में कितनी आई?" टीचर भी इस अनोखे सवाल पर मुस्कुरा उठीं और बच्ची की जिज्ञासा की तारीफ की, साथ ही बाकी बच्चों से यह सवाल पूछने लगी। सवाल के जवाब में किसी बच्चे ने कहा तीन तो किसी ने कहा पांच चिड़िया। फिर एक बच्चे ने आखिर में कहा कि पांच चिड़िया पाकिस्तान से उड़ीं, तो इंडिया में दो आई। जब टीचन ने पूछा ऐसा क्यों तो बच्चे ने जबाव में कहा क्योंकि INDIA में दो 'I' आते हैं।

पंचांग

14 फरवरी 2026

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - उत्तरायण
- ऋतु - शिशिर
- मास - फाल्गुन
- पक्ष - कृष्ण
- तिथि - द्वादशी 16.02 तक
- वार - शनिवार
- नक्षत्र - पूर्वाषाढ़ा 18.16 तक
- योग वज्र - 27.18 तक
- करण - गर 28.38 तक
- सूर्योदय - 07.09 प्रात: (मुंबई)
- सूर्यास्त - 06.36 शाम (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.16 प्रात: (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 06.33 शाम (भीनमाल)
- चंद्र राशि - धन 24.43 तक
- अभिजीत - 12.29 से 13.15
- राहु काल - 10.00 से 11.26
- दिशा शूल - पूर्व
- व्रत त्यौहार - शनि प्रदोष, स्थिरयोग 18.16 से सूर्योदय

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

X का एक्सरे

मेरे लिए एसओपी का मतलब है स्टालिन ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चुनाव के समय लोगों को पैसे बांटे जाते हैं। अगर कोई हजारों रुपए देने आए तो वह पैसा ले लें, क्योंकि वह आपका ही पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बादवोट अपनी मर्जी से दीजिएऔर ऐसे लोगों को 'सीटी बजाकर' विदा कर दीजिए।

दलपति विजय

भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि इसके बिना कितना भी बजट लेकर आएं विकास होने वाला नहीं है। ऐसे अफसर प्रशासन में हर स्तर पर हैं और इन पर कार्रवाई जरूरी है। एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी और दरोगा डकैती में लिप्त पाए जा रहे हैं।

माता प्रसाद पांडेय

आजकल सरकार और न्यायपालिका के बीच के रिश्तों पर बहुत बातें होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू का 26 जून 1959 को जस्टिस विवियन बोस को लिखा गया यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह पत्र दिखाता है कि नेहरू संस्थाओं का कितना सम्मान करते थे। नेहरू असाधारण संस्था निर्माता थे।

जयराम रमेश

मैंने पांच दशकों से अधिक समय तक सांसद के रूप में सेवा की है। एक विधायक और संसद सदस्य के रूप में समर्पण के साथ काम किया है। हमेशा गरिमा, शिष्टाचार और भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखा है। मेरे भाषण के इतने बड़े हिस्से को हटाना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

मल्लिकार्जुन खरगे

नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

संपादकीय

तंत्र की लापरवाही दे रही है अपराधियों को मौका

देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां शामिल होती हैं। इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली से आठ सौ से अधिक लोगों के लापता होने की खबरों ने इस मसले की गंभीरता को फिर से उजागर किया है। मगर हैरत की बात है कि इस आपराधिक समस्या से निपटने के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकीकृत प्रयास होते नजर नहीं आए हैं। यहां तक कि लापता होने की घटनाएं और उनमें से कितने लोगों को ढूंढ़ लिया गया तथा ऐसे मामलों के पीछे किसका हाथ था, इसका एकीकृत राज्यवार ब्योरा भी मुश्किल से दर्ज हो पाता है।

यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मसले पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह या राज्य-विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। इसके लिए तमाम राज्यों से ऐसे मामलों की संख्या और कार्रवाई का ब्योरा संकलित कर उनका विश्लेषण करने का निर्देश भी दिया गया है।

गौरतलब है कि देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के मामलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर सभी राज्य ऐसी घटनाओं का ब्योरा दर्ज करा सकते हैं। मगर, इस प्रक्रिया में भी सरकारी तंत्र की उदासीनता साफ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में खुद यह बात स्वीकार की है कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उनसे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े

उपलब्ध नहीं कराए हैं।

दरअसल, पिछले वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को लापता बच्चों के सिलसिले में छह साल के राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध कराने और ऐसे आंकड़ों के संकलन में राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने को कहा था। इससे पहले राज्यों को बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया था। इसके बावजूद अगर राज्यों की ओर से संबंधित ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इससे सरकारी तंत्र में व्यवस्थागत खामियों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

इसमें दोराय नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में विशेषकर बच्चों, महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की घटनाएं जितनी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं, उससे इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे देशव्यापी या राज्य स्तरीय गिरोहों का हाथ हो सकता है। इसलिए इस बात की गहन जांच-पड़ताल जरूरी है कि लापता होने की ज्यादातर घटनाओं में किसी तरह कोई समानता तो नहीं है! मगर यह तभी संभव होगा, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों से जुड़े आंकड़ों का संकलन हो पाएगा। इस मसले की गंभीरता का अंदाजा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रपट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक, वर्ष 2023 में देश भर में आठ लाख से ज्यादा लोग लापता हुए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। ऐसे में जरूरी है कि हर राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और लापता होने के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा कायम रह सके।

मदद करने वाले कुचले गए

सरकार के तमाम दावों के बावजूद वाहनों की तेज रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। देश भर में हर साल होने वाले सड़क हादसों में तेज गति से वाहन चलाना एक बड़े कारण के रूप में उभरकर सामने आता है। वजह साफ है कि यातायात नियमों का पूरी तरह अमल सुनिश्चित करने में हर स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। खास तौर से राजमार्गों पर चलने वाले भारी वाहनों से जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह है कि व्यवस्था में खामियों का खमियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-62 के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर सोमवार देर रात हुआ, जिसमें एक घायल व्यक्ति की मदद कर रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिनमें से दो की मौत हो गई। इस घटना ने सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजमार्गों पर वाहनों के गति मापक यंत्रों का अभाव है या फिर उनका संचालन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है?

दरअसल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर एक ट्रक की टक्कर से पिकअप वाहन में सवार व्यक्ति घायल हो गया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोग घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए और उसे क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। इस बीच सामने से आए एक अन्य तेज रफ्तार ट्रक ने तीन लोगों को टक्कर मार दी।

कहा जा रहा है कि इस हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए तत्काल कोई मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में राजमार्गों पर कोई हादसा होने पर तुरंत सहायता पहुंचाने के सरकारी तंत्र पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरा, इस बात पर भी गंभीरता से गौर करने की जरूरत है कि आखिर वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? जाहिर है अगर कुछ वाहन चालकों को यातायात नियमों की परवाह नहीं है और न ही उन्हें कानून का खौफ है, तो इसकी मूल वजह का पता लगाए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं हो सकता है।

आज का कार्टून

जेन-जेड की डिजिटल दुनिया...

यूनेस्को की एक रपट के मुताबिक, शिक्षा में तकनीक का अधिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। इसे सीखने में मदद करने तक ही सीमित रखना चाहिए, न कि पथ निर्देशक बनने देना चाहिए। इसके नकारात्मक प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। हाल में गाजियाबाद में जो घटना हुई है, उससे भी सबक लिया जा सकता है, जहां तीन नाबालिग बहनों ने आभासी दुनिया में गुम होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह घटना एक उदाहरण भर है। पहले भी डिजिटल लत के कारण ऐसी घटनाएं होती रही हैं। दरअसल, हमारी नई पीढ़ी सपने में जीने लगी है। उनकी ताकत डिजिटल की बैसाखियों पर निर्भर है। जो ताकत दुनिया को सशक्त करने के लिए बनाई गई थी, वह नौजवानों को एक काल्पनिक जगत में कैद कर रही है। अब वे घंटों कंप्यूटर के सामने या स्मार्टफोन लेकर बैठे रहते हैं। युवा आभासी दुनिया को सच मान कर जीवन की वास्तविकताओं से दूर जाकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं, जिसका वजूद उनकी कल्पना में तो है, लेकिन असल जिंदगी में कहीं नहीं।

सुरेश सेठ

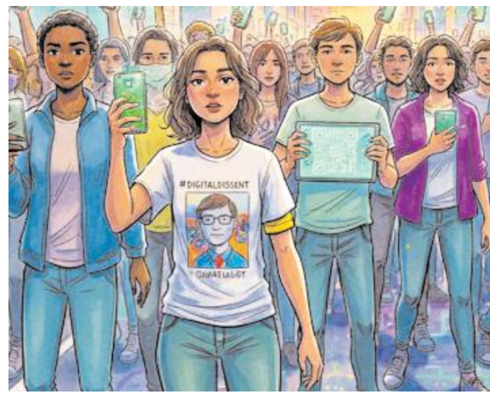

दुनियाभर में युवाओं की नई पौध कहीं अधिक प्रखर और त्वरित कदमों से आगे बढ़ने वाली पीढ़ी है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर की इस पीढ़ी को आजकल 'जेन-जेड' कहा जा रहा है। यही वह नई युवा शक्ति है, जो अपने-अपने देशों में अन्याय और विसंगतियों के विरुद्ध खड़ी हो रही है। कुछ समय पहले पूरी दुनिया ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उन प्रदर्शनों को देखा, जिनमें हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। उस समय ऐसा लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा। जो विसंगतियां हैं, अब वे खत्म होंगी। चाहे वह भ्रष्टाचार हो या नेताओं का परिवारवाद या फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और इन देशों में ढर्रा वही रहा, जो पहले था। सत्ता परिवर्तनों के बावजूद कोई खास बदलाव सामने नहीं आया।

नई युवा शक्ति का असमानता और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना उन देशों के लिए असरदार हो सकता है, जहां स्थिति सचमुच बेहद खराब है और जहां अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है। मगर दिक्कत यह है कि कृत्रिम मेधा और सोशल मीडिया से प्रभावित यह पीढ़ी तत्काल सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहती है। मगर सच तो यह है कि अचानक सड़कों पर उतर जाने से रातों-रात व्यवस्था नहीं बदल जाती। यह पीढ़ी अपनी ताकत का धैर्य और सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करे, तो दुनिया में जो बदलाव वे चाहते हैं, वह संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस पीढ़ी की सार्थकता और उसकी ताकत पर दुनिया का भरोसा कायम हो सकता है। मगर अभी ऐसा हुआ नहीं है। इस समय बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल दुनिया से प्रभावित इस शक्ति को अगर सही दिशा नहीं मिली, तो इससे उनका ही नुकसान हो सकता है।

भारत में इस युवा पीढ़ी को सार्थक निवेश के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश इनका साथ लेकर प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होना चाहता है। मगर, ये उम्मीदें आगे कितनी सच होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। देश की युवा आबादी कार्ययोग्य है, लेकिन उन्हें काम देने की बजाय अनुकंपा पर जीने की राह दिखाई जा रही है। अगर वे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए दूसरे देशों की ओर पलायन करते हैं, तो वहां से उन्हें किस तरह से स्वदेश वापस भेजा गया है, इसे सभी ने देखा है। अपने देश में तो रोजगार की गुंजाइश बढ़ नहीं रही, ऐसे में युवा करे, तो क्या करें। वहीं इनके सही राह से भटक जाने का जो जोखिम है, इसे कौन समझेगा।

युवा देश की अमूल्य निधि होते हैं। उनके प्रखर और विकासोन्मुख होने की बात कही जाती है। मगर अभी दुनिया के कई देशों में अनुसंधान का निष्कर्ष यह बताता है कि आधुनिक तकनीक अपनाने वाली इस पीढ़ी की मेधा शक्ति पिछली पीढ़ी से कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका कारण यह बताया जाता है कि 'जेन-जेड' कहलाने वाली यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है। स्वयं खोज करने या अनुसंधान करने की बजाय उन्हें पहले से तैयार सब चीजें चाहिए। कई बार उनमें मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती। उनमें कितनी संभावनाएं हैं, यह सामने आना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि भारत कृत्रिम मेधा और डिजिटल दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह साफ है कि नई पीढ़ी मेधा और स्मृति के मामले में पिछली पीढ़ी जितनी भी नहीं दिखाई देती है।

समस्या सुलझाने का उनका तरीका त्वरित बेशक हो, लेकिन वह ठोस और व्यावहारिक नहीं होता। बड़े-बुजुर्ग जटिल से जटिल समस्याओं का धीरज से सामना करते हुए न केवल उन्हें सुलझाने में कामयाब हो जाते थे, बल्कि एक नया पैमाना भी बना देते थे। वहीं आज की युवा पीढ़ी संक्षिप्त वीडियो से स्वयं को प्रशिक्षित करने और इसी से रास्ता तलाशने में लगी रहती है। अध्यापकों के साथ आमने-सामने बातचीत अब होती नहीं। नतीजा बच्चों की बौद्धिक क्षमता घटने लगी है।

देश में तकनीक के अधिक इस्तेमाल के कारण किसी में स्वयं खोज करने की पहल नहीं दिखाई देती। शोध विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले पचास- साठ साल में जैसे-जैसे भारत सहित पूरी दुनिया में तकनीक का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा है, बच्चों में सीखने की क्षमता घट गई है। मगर जो बच्चे प्रौद्योगिकी का कम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनके परिणाम उन बच्चों से बेहतर हैं, जो डिजिटल सुविधा पर निर्भर हैं।

भारत समेत पूरी दुनिया में कृत्रिम मेधा का बोलबाला हो गया है। सब जगह कागज रहित कार्य संस्कृति विकसित होने लगी है। दूसरी ओर इसी नई तकनीक का नतीजा है कि अब पुस्तकों के जरिए कम और स्मार्ट फोन, लैपटाप एवं कंप्यूटर पर शिक्षा देने का चलन बढ़ रहा है। कारण यह है कि युवा पीढ़ी यानी जेन-जी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करती है। वे कहीं अधिक आत्मविश्वासी हैं। उनको लगता है कि वे हर चीज जानते हैं। उनके पास सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं। बच्चों को हम स्मार्टफोन तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी मौलिकता कम होती जा रही है। डिजिटल दुनिया की इस अपार ताकत ने एक नए खतरे को जन्म दिया है।

अब कहा जा रहा है कि तकनीक में तरक्की तो कीजिए, लेकिन इस पर नियंत्रण भी रखिए। विशेषज्ञों ने इस पूरे परिदृश्य पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि एक समय में पूरी दुनिया इस डिजिटल ताकत से बेहद प्रभावित थी। अब उसका असर घटने लगा है। कुछ देश तो तकनीक के बेतहाशा उपयोग से अब पीछे हटने लगे हैं। स्वीडन ने हाल ही में विद्यालयों में डिजिटल उपकरणों को हटा कर फिर से कागज-कलम और किताबों की ओर लौटने का फैसला किया है। फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों में स्कूलों में लैपटाप और टैबलेट के इस्तेमाल को अब सीमित किया जा रहा है।

यूनेस्को की एक रपट के मुताबिक, शिक्षा में तकनीक का अधिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। इसे सीखने में मदद करने तक ही सीमित रखना चाहिए, न कि पथ निर्देशक बनने देना चाहिए। इसके नकारात्मक प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। हाल में गाजियाबाद में जो घटना हुई है, उससे भी सबक लिया जा सकता है, जहां तीन नाबालिग बहनों ने आभासी दुनिया में गुम होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह घटना एक उदाहरण भर है। पहले भी डिजिटल लत के कारण ऐसी घटनाएं होती रही हैं।

दरअसल, हमारी नई पीढ़ी सपने में जीने लगी है। उनकी ताकत डिजिटल की बैसाखियों पर निर्भर है। जो ताकत दुनिया को सशक्त करने के लिए बनाई गई थी, वह नौजवानों को एक काल्पनिक जगत में कैद कर रही है। अब वे घंटों कंप्यूटर के सामने या स्मार्टफोन लेकर बैठे रहते हैं। युवा आभासी दुनिया को सच मान कर जीवन की वास्तविकताओं से दूर जाकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं, जिसका वजूद उनकी कल्पना में तो है, लेकिन असल जिंदगी में कहीं नहीं। नई पीढ़ी यानी 'जेन-जेड' के उभरने और संवरने से पहले ही डिजिटल की ताकत उसे यथार्थ से दूर ले जा रही है। इस पर नियंत्रण तो किसी सीमा तक करना ही होगा, ताकि वह नई पीढ़ी के लिए चुनौती न बन जाए।

आधुनिक जीवन में रिश्तों की बदलती परिभाषा

समस्या तब उत्पन्न होती है जब विवेक का स्थान केवल लाभ-लालसा ले लेती है।संतुलन ही समाधान है- ऐसा संतुलन जिसमें 'मैं' सुरक्षित रहे और 'हम' भी जीवित रहें। इतिहास और वर्तमान- दोनों इस सत्य के साक्षी हैं कि केवल अपने लिए जीने वाले लोग क्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं, पर समाज उन्हें याद नहीं रखता। समाज उन्हें स्मरण करता है, जिन्होंने अपने स्वार्थ की सीमा वहीं रोक दी, जहां दूसरों की पीड़ा शुरू होती है। ऐसे लोग पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आज आवश्यकता है स्वार्थ की ऐसी नई परिभाषा गढ़ने की, जो आत्मविकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच सेतु बने।

महिमा सामंत

निजी स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का एक ऐसा पक्ष है, जो जन्म से उसके साथ चलता है। स्वयं की सुरक्षा, प्रगति और पहचान की चाह स्वाभाविक है। यही स्वार्थ मनुष्य को परिश्रम करना, आगे बढ़ना और अपने लिए बेहतर जीवन गढ़ना सिखाता है। मगर जब यही भावना सीमाएं लांघने लगे, तब यह समाज के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय- हर क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ है। इस होड़ में कई बार व्यक्ति अपने लाभ को ही सर्वोच्च मान लेता है और दूसरों के हिस्से की जमीन भी अपने पांव तले दबाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां स्वस्थ स्वार्थ अस्वस्थ बन जाता है। ऐसा स्वार्थ सफलता का भ्रम तो रचता है, पर भीतर से मनुष्य को खोखला कर देता है।स्वार्थ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे-धीरे रिश्तों में प्रवेश करता है। आज अनेक संबंध सुविधा और उपयोगिता पर टिके दिखाई देते हैं। जब तक व्यक्ति काम का है, तब तक वह अपना है; और काम निकलते ही दूरी बन जाती है। यह सोच परिवारों में दरार, मित्रता में अविश्वास और समाज में असंवेदनशीलता को जन्म देती है। छात्र जीवन में जैसे ही किसी एक को बेहतर अंक या अवसर

मिल जाता है, दूरी अपने आप बन जाती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रेरणा देती है, लेकिन जब स्वार्थ हावी हो जाएं, तब मित्रता बोझ बन जाती है, जो समय की कसौटी पर टिक नहीं पाती।

कार्यस्थलों पर 'टीमवर्क' यानी 'सामूहिक भावना के साथ काम' की बातें होती हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ बनी रहती है। किसी सहकर्मी के विचार को अपना बताकर प्रस्तुत करना, किसी के अच्छे काम को खराब बताना, सही को गलत कहना और सफलता मिलते ही आगे बढ़ जाना- ये व्यवहार संस्थानों को भीतर से कमजोर कर देते हैं। जहां भरोसा नहीं होता, ईर्ष्या हावी होती है, वहां कार्यक्षमता भी धीरे-धीरे गिरने लगती है। स्वार्थ भले ही व्यक्ति को अस्थायी लाभ दिला दे, पर कार्य-संस्कृति को स्थायी नुकसान पहुंचाता है। स्वार्थ का सबसे संवेदनशील और पीड़ादायक रूप परिवार में देखने को मिलता है। संपत्ति के बंटवारे में भाई-भाई का दुश्मन बन जाना, बुजुर्गों को बोझ समझना या रिश्तों को सुविधा के तराजू पर तौलना- ये दृश्य आज आम होते जा रहे हैं। परिवार वह स्थान होना चाहिए, जहां निस्वार्थ होना सबसे अधिक हो, लेकिन जब वही स्थान स्वार्थ का शिकार बन जाए, तो समाज की नींव हिलने लगती है। माता-पिता का प्रेम इस संसार का सबसे निस्वार्थ भाव है। वे अपनी इच्छाएं, सुख-सुविधाएं और कई बार अपने सपने तक बच्चों के भविष्य के लिए त्याग देते हैं। जीवनभर देते रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। विडंबना यह है कि ऐसे निस्वार्थ प्रेम के बावजूद कुछ बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही माता-पिता से दूरी बना लेना, उनकी जरूरतों को बोझ समझना या उन्हें अकेला छोड़ देना- ये दृश्य आज चुभते हुए सच बन चुके हैं। यह स्वार्थ केवल माता-पिता को नहीं, मानवीय संवेदना को भी चोट पहुंचाता है।

इन उदाहरणों के बीच हमारे सैनिक निस्वार्थ भावना का जीवंत प्रतीक हैं। वे अपने परिवार, आराम और कभी-कभी अपने प्राण तक देश के लिए समर्पित कर देते हैं। सीमा पर खड़ा सैनिक यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वह केवल यह सोचता है कि देश सुरक्षित रहे। जब हम अपने छोटे-छोटे लाभ के लिए रिश्तों और जिम्मेदारियों से समझौता कर लेते हैं, तब सैनिकों का त्याग हमें आईना दिखाता है। उनका बलिदान याद दिलाता है कि सच्चा कर्तव्य वही है, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर निभाया जाए।

एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी में एकलव्य ने बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और लगन से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए स्वार्थवश एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, जिससे स्वार्थ की सीमाओं और पक्षपात की तस्वीर उजागर हुई। ऐसे प्रसंगों से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि स्वार्थ न केवल दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि नैतिकता, न्याय और रिश्तों की नींव को भी कमजोर कर देता है।

प्रश्न यह नहीं कि हम स्वार्थी हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि हमारा स्वार्थ रिश्तों को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। जिस दिन हम अपने लाभ की सीमा वहां रोक देंगे, जहां से दूसरों की पीड़ा शुरू होती है, उसी दिन स्वार्थ मानवता में बदल जाएगा। हालांकि कहना मुश्किल है कि स्वार्थ पूरी तरह त्याज्य है। आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना- ये सब स्वार्थ नहीं, बल्कि विवेक हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब विवेक का स्थान केवल लाभ-लालसा ले लेती है।संतुलन ही समाधान है- ऐसा संतुलन जिसमें 'मैं' सुरक्षित रहे और 'हम' भी जीवित रहें। इतिहास और वर्तमान- दोनों इस सत्य के साक्षी हैं कि केवल अपने लिए जीने वाले लोग क्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं, पर समाज उन्हें याद नहीं रखता। समाज उन्हें स्मरण करता है, जिन्होंने अपने स्वार्थ की सीमा वहीं रोक दी, जहां दूसरों की पीड़ा शुरू होती है। ऐसे लोग पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। आज आवश्यकता है स्वार्थ की ऐसी नई परिभाषा गढ़ने की, जो आत्मविकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच सेतु बने। अगर व्यक्ति यह समझ ले कि समाज के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है, तो स्वार्थ स्वतः ही मानवीय हो जाएगा। आखिरकार स्वार्थ समस्या नहीं है, समस्या है उसकी दिशा। सही दिशा में प्रवाहित स्वार्थ समाज को आगे बढ़ाता है और गलत दिशा में बहता स्वार्थ उसे भीतर से तोड़ देता है। चुनाव हमारे हाथ में है- हम अपने स्वार्थ से केवल ऊंचे बनना चाहते हैं या व्यापक भी!

बांग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ

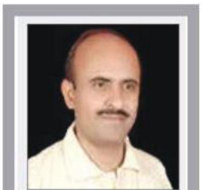

कमलेश पांडेय

बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण।

बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। इससे बंगलादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ स्पष्ट हैं, क्योंकि यह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जो 2024 के छात्र-आंदोलन से उभरा था।

चूंकि बीएनपी पहले से सत्ता में रहती आई है, इसलिए उसकी जीत के वैश्विक मायने भी हैं। वह यह कि पार्टी कमोबेश पूर्व प्रधानमंत्री स्व.बेगम खालिदा जिया के अधूरे सपनों को ही साकार करेगी। वो भी तब जब उनके पुत्र तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देखा जाए तो बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां जमात को महज 42-68 सीटें ही मिलीं हैं। इसप्रकार तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, देश के संभावित प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण। इसलिए उनकी जीत से भारत को सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों की चिंता बढ़ सकती है, हालांकि बीएनपी समानता-आधारित संबंधों का वादा कर रही है। खासकर हसीना युग के बाद विदेश नीति में बदलाव से व्यापार, जल बंटवारा और कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है।

वहीं बीएनपी की जीत से दुनिया के लिए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है, लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश ($2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में।

यह ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध सुधारने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से ₹बहुत मैत्रीपूर्ण₹ चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरार है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं। खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना, क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातें कीं, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा फखरुल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करने का आश्वासन दिया।

वहीं, व्यापार और वीजा बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है, जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे। खासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी बीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फेलानी घटना) पर जोर दे रही है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि बीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिसे भारत शरण दे रहा है, इससे जन-भावना भी प्रभावित हो रही है।

वहीं, जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-चीन झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चूंकि बीएनपी ₹समानता-आधारित₹ पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही है, जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएं रीसेट सुनि त करेंगी, लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास दूर करने में समय लगेगा।

यद्यपि तारिक रहमान, जो बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाते दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंडपॉइंट्स यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया, जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है।

वहीं, समानता का जोर के मद्देनजर ₹बराबरी के रिश्ते₹ चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई, लेकिन टकराव से बचते हैं। हाँ, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग, जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियां ₹इंडिया-न्यूट्रल₹ मान रही हैं, जो 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव, लेकिन पाकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं।

देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के 17 मिनट के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के राज पर जोर दिया जो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है।

वहीं, 'बांग्लादेश फर्स्ट' नारा यानी ₹ना दिल्ली, ना रावलपिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश' कहकर तटस्थ विदेश नीति का संकेत दिया, जो पुराने भारत-विरोधी रुख से अलग है। उनके सकारात्मक संदेश साफ हैं। वो ये कि अंग्रेजी में अंतरराष्ट्रीय अपील की, समावेशी बांग्लादेश का खाका पेश किया, जो खुफिया एजेंसियों ने 'री-अश्योरेंस सिग्नल' माना। देखा जाए तो उनके ये भाषण बीएनपी की री-ब्रांडिंग का हिस्सा हैं, जहां 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से दूरी दिखाई गई। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के साथ संबंध सुधारने का रणनीतिक संकेत है, हालांकि हसीना प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे लंबित हैं।

संपादकीय

रेरा को सही फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा को जो कड़ी फटकार लगाई, उसके लिए वही उत्तरदायी है। इस प्राधिकरण का गठन जिन उम्मीदों के साथ किया गया था, वह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। रेरा की लचर कार्यप्रणाली के चलते न जाने कितने लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होते हैं और सब जानते हैं कि वहां से न्याय मिलने में समय लगता है। रेरा की निराशाजनक कार्यप्रणाली को इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसे बंद करना ही बेहतर है। उसने यह कठोर टिप्पणी भी की कि वह दिवालिया बिल्डरों को राहत देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वह फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करने के स्थान पर उन बिल्डरों की पक्षधरता करता है, जिन पर उसे निगाह रखनी चाहिए, ताकि वे अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें और उनमें मनमाने तरीके से बदलाव न कर सकें। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के खिलाफ कठोर टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के एक मामले में की हो, लेकिन उसका यह आकलन तो लगभग सभी राज्यों के रेरा पर लागू होता है कि जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था, वे निराश और हताश हैं और उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिल रही। संभवतः इसीलिए उसने यहां तक कहा कि यदि इस संस्था को समाप्त भी कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ गया है कि सभी राज्य रेरा के नए सिरे से गठन पर विचार करें। इसमें संदेह है कि उसकी ओर से स्पष्ट निर्देश के बिना ऐसा हो सकेगा। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार यह देखे कि सभी राज्यों के रेरा सही तरह काम करें, क्योंकि सबमें खामियां घर कर गई हैं। कई मामलों में यह देखने में आया है कि रेरा ने उन बिल्डरों का बचाव किया, जो फ्लैट खरीदारों से साफ तौर पर वादाखिलाफी कर रहे थे। यदि रेरा के अस्तित्व में होने के बाद भी देश भर में लाखों प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। बहुत दिन नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही यह उजागर हुआ था कि दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बिल्डरों ने बैंकों से मिलकर लाखों फ्लैट खरीदारों के साथ ठगी की। यह ठगी सबवेंशन स्कीम के जरिये की गई। सबवेंशन स्कीम के तहत किसी परियोजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे बिल्डरों के खातों में भेजी जाती थी। उन्हें घर खरीदारों को फ्लैट सौंपने तक ईएमआइ का भुगतान करना होता था, लेकिन कई मामलों में बिल्डरों ने फ्लैट तैयार किए बिना ईएमआइ का भुगतान बंद कर दिया। इस पर बैंक फ्लैट खरीदारों से शेष ईएमआइ की मांग करने लगे। इसे अन्याय और अंधेर के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

चिंतन-मनन

भक्तों की सहायता करते हैं ईश्वर

ईश्वर को हम भले ही न देख पाएं लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा होता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों एवं सद्व्यक्तियों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। शास्त्र कहता है कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी संतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाये नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं।

गजराज की कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गये। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। सूरदास जी के जीवन की भी एक ऐसी ही कथा है।

सूरदास जी देख नहीं सकते थे। एक बार गलती से एक गड्ढ़े में गिर गये। गड्ढ़े से निकलने का काफी प्रयास करने पर भी वह बाहर निकलने में असफल रहे। इस स्थिति में सूरदास जी ने गोपाल को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में पहुंच गये और सूरदास जी को गड्ढ़े से बाहर निकाला। मीरा के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने मीरा को मारने के लिए भेजे गये विष को प्रभावहीन कर दिया।

बघेलखण्ड के बान्धवगढ़ में रहने वाले सेन नामक नाई की भी भगवान ने सहायता की और बघेलखंड का राजा सेन नाई का भक्त बन गया। यह घटना पांच छः सौ साल पुरानी है। सेन नाई राजा की सेवा करता था। इसका काम प्रतिदिन राजा की हजामत बनाना और तेल मालिश करके स्नान कराना था। एक दिन सेन नाई जब राजमहल की ओर चला तब रास्ते में संतों की टोली मिल गयी। नाई उन्हें लेकर घर आ गया और उनकी खूब सेवा की। संतों के साथ बैठकर संत्संग में भाग लिया।

राजा के स्नान करने का समय बीता जा रहा था। नाई के नहीं आने से राजा क्रोधित हो रहे थे। इसी समय भगवान स्वयं सेन नाई का वेष धारणकर राजा की सेवा में पहुंच गये। नई बने भगवान की सेवा से राजा का क्रोध दूर हो गया और मन हर्षित हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद सेन नाई को याद आया कि राजा की सेवा में देरी हो गयी है।

भारतीय राजनीति की सशक्त और संवेदनशील आवाज थी सुषमा स्वराज

सुरेन्द्र शर्मा

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की उन विरल हस्तियों में से थीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, वाक्पटुता, संवेदनशीलता और कार्यकुशलता से जनमानस में विशेष स्थान बनाया। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्त्रोत, कुशल प्रशासक और करुणामयी नेता थीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की और विशेष रूप से भारत की विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ऐतिहासिक माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है।।

सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, जिससे बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्रसेवा की भावना विकसित हुई। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन में वे एक उत्कृष्ट वक्ता और सक्रिय छात्रनेता रहीं। वे कई बार सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार जीत चुकी थीं, जिससे उनकी भाषण कला का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सुषमा स्वराज ने बहुत कम आयु में राजनीति में प्रवेश किया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनीं और 27 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गईं। उस समय वे देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री थीं। यह उनकी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ नि य का प्रमाण था। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी जुड़ी रहीं।

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद सुषमा स्वराज ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रहीं। वर्ष 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, हालांकि उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। हर पद पर उन्होंने दक्षता और ईमानदारी से कार्य किया।

सुषमा स्वराज की पहचान एक ओजस्वी वक्ता के रूप में भी रही। संसद में उनके भाषण तार्किक, प्रभावशाली और मर्यादित होते थे। वे विपक्ष में रहते हुए भी अपनी बात मजबूती से रखती थीं और सत्ता में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती थीं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान दक्षता से बोलती थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण विशेष रूप से सराहा गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को मजबूती प्रदान की।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह पद केवल सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने, नीतियों की समीक्षा करने और जनता की आवाज को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने का दायित्व भी निभाता है। सुषमा स्वराज ने वर्ष 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने अपनी वाक्पटुता, तर्कशक्ति, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से इस पद की गरिमा को नई ऊँचाई दी

नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी पहचान उनकी प्रभावशाली और मर्यादित वक्तृत्व शैली थी। वे अपने भाषणों में तथ्यों, तर्कों और उदाहरणों का संतुलित उपयोग करती थीं। उनकी भाषा में तीखापन तो होता था, लेकिन वह कभी व्यक्तिगत कटाक्ष या असंसदीय शब्दों तक नहीं पहुँचता था। वे सरकार की नीतियों की कठोर आलोचना करती थीं, परंतु सदैव संसदीय मयार्दा का पालन करती थीं।

जब भी संसद में कोई महत्वपूर्ण विधेयक या मुद्दा चर्चा के लिए आता, सुषमा स्वराज विपक्ष की ओर से स्पष्ट और सुविचारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थीं। उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था, क्योंकि वे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करती थीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव भी देती थीं।

भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर भूमिका 15वीं लोकसभा के दौरान केंद्र में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला (कोलगेट), कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आदि। इन मुद्दों पर सुषमा स्वराज ने विपक्ष की ओर से सशक्त आवाज उठाई।

उन्होंने संसद में इन मामलों की निष्पक्ष जाँच और जवाबदेही की मांग की। कई बार संसद में गतिरोध की स्थिति बनी, लेकिन उनका तर्क था कि जब तक गंभीर आरोपों पर स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक सरकार को जवाब देना होगा। उनके नेतृत्व में विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग उठाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया।

वैलेंटाइन डे प्यार के उत्सव का नया बाजार

हर्षवर्धन पान्डे

पिछले कुछ समय से ग्लोबलाइज्ड समाज में प्यार भी ग्लोबल ट्रेंड का हो गया है। आज जहाँ इजहार और इकरार करने के तौर तरीके बदल गए हैं वहीँ इंटरनेट के इस दौर में प्यार भी बाजारू हो चला है। पहली बार शहरी चकाचौंध से इतर प्यार का यह उत्सव एक बड़ा बाजार को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर जगह वैलेंटाइन की संस्कृति पसरती जा रही है। आज युवा भी इसकी गिरफ्त में पूरी तरह से नजर आते है तभी तो शहरों से लेकर कस्बो तक वैलेंटाइन का जलवा देखते ही बनता है। आलम यह है ये बड़ा उत्सव बन चुका है जो भारतीयों में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है।

वैलेंटाइन के चकाचौंध पर अगर दृष्टि डालें तो इस सम्बन्ध में कई किस्से प्रचलित हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की माने तो यह वैलेंटाइन अथवा वलेंतिनस नाम के तीन लोगों को मान्यता देता है जिसमें से दो के सम्बन्ध वैलेंटाइन डे से जोड़े जाते है लेकिन बताया जाता है इन दो में से भी संत वैलेंटाइन खास चर्चा में रहे। कहा जाता है संत वैलेंटाइन प्राचीन रोम में एक धर्म गुरू थे। उन दिनों वहाँ पर क्लाउडियस दो का शासन था। उसका मानना था अविवाहित युवक बेहतर सैनिक हो सकते हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में उन्हें अपनी पत्नी या बच्चों की चिंता नही सताती। अपनी इस मान्यता के कारण उसने तत्कालीन रोम में युवको के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया।

किन्दवंतियो की मानें तो संत वैलेंटाइन के क्लाउडियस के इस फेसले का विरोध करने का फैसला किया। बताया जाता है कि वैलेंटाइन ने इस दौरान कई युवक युवतियों का प्रेम विवाह करा दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फासी की सजा दे दी। कहा जाता है संत के इस त्याग के कारण हर साल 14 फरवरी को उनकी याद में युवा वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 1260 में संकलित की गई ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वॉराजिन नामक पुस्तक में भी सेंट वेलेंटाइन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रोम में तीसरी शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस के अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती है। उसने फरमान जारी किया कि उसका कोई सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा। संत वेलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया। उन्हीं के आ ान पर अनेक सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह किए।

कैथोलिक चर्च की एक अन्य मान्यता के अनुसार एक दूसरे संत वैलेंटाइन की मौत प्राचीन रोम में ईसाईयों पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के दरमियान हो गई। यहाँ इस पर नई मान्यता यह है ईसाईयों के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले इस संत की याद में ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक अन्य किंदवंती के अनुसार वैलेंटाइन नाम के एक शख्स ने अपनी मौत से पहले अपनी प्रेमिका को पहला वैलेंटाइन संदेश भेजा जो एक प्रेम पत्र था। उसकी प्रेमिका उसी जेल के जेलर की पुत्री थी जहाँ उसको बंद किया गया था। उस वेलेंनटाइन नाम के शख्स ने प्रेम पत्र लिखा फ्रॉम यूअर वेलेंनटाइन । आज भी यह वैलेंटाइन पर लिखे जाने वाले हर पत्र के नीचे लिखा रहता है। क्लॉडियस ने 14 फरवरी को संत वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। तब से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि सेंट वेलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया व जेकोबस को एक पत्र लिखा, जिसमें अंत में उन्होंने लिखा था तुम्हारा वेलेंटाइन। 14 फरवरी के बहाने जिसे बाद में इस संत के नाम पूरे विश्व में निःस्वार्थ प्रेम से मनाया जाने लगा। यही नहीं वैलेंटाइन के बारे में कुछ अन्य बातें भी है। इसके अनुसार तर्क यह दिए जाते है प्राचीन रोम के प्रसिद्ध पर्व ल्युपरकेलिया के ईसाईकरण की याद में मनाया जाता है। यह पर्व रोमन साम्राज्य के संस्थापक रोम्योलुयास और रीमस की याद में मनाया जाता है। इस आयोजन पर रोमन धर्मगुरु उस गुफा में एकत्रित होते थे जहाँ एक मादा भेडिये ने रोम्योलुयास और रीमस को पाला था इस भेडिये को ल्युपा कहते थे और इसी के नाम पर उस त्यौहार का नाम ल्युपर केलिया पड़ गया। इस अवसर पर वहां बड़ा आयोजन होता था। लोग अपने घरो की सफाई करते थे साथ ही अच्छी फसल की कामना के लिए बकरी की बलि देते थे। कहा जाता है प्राचीन समय में यह परम्परा खासी लोक प्रिय हो गई। एक अन्य किंदवंती यह कहती है 14 फरवरी को फ्रांस में चिडियों के प्रजनन की शुरूआत मानी जाती थी जिस कारण खुशी में यह त्यौहार वहा प्रेम पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। प्रेम के तार रोम से भी सीधे जुड़े नजर आते हैं। वहाँ पर क्यूपिड को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाने लगा जबकि यूनान में इसको इरोश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन वैलेंटाइन संदेश के बारे में भी लोगो में एकरूपता नजर नही आती। कुछ ने माना है कि यह इंग्लैंड के राजा ड्यूक ने लिखा जो आज भी वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है।

आज युवाओं में वैलेंटाइन की खुमारी सर चढ़कर बोल रही है। इस दिन के लिए सभी पलके बिछाये बैठे रहते हैं। भईया प्रेम का इजहार जो करना है ? वैलेन्टाइन प्रेमी इसको प्यार का इजहार करने का दिन बताते है। यूँ तो प्यार करना कोई गुनाह नही है लेकिन जब प्यार किया ही है तो इजहार करने मे देर नही होनी चाहिए लेकिन अभी का समय ऐसा है जहाँ युवक युवतिया प्यार की सही परिभाषा नही जान पाये हैं। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे है प्यार को आप एक दिन के लिए नहीं बाँध सकते। वह तो प्यार को हंसी मजाक का खेल समझ रहे है। आज का प्यार मैगी के नूडल जैसा बाजारू बन गया है जो दो मिनट चलता है। सच्चे प्रेमी के लिए तो पूरा साल प्रेम का प्रतीक बना रहता है लेकिन आज के बाजार ने प्यार की परिभाषा बदल दी है। इसका प्रभाव यह है 14 फरवरी को प्रेम दिवस का रूप दे दिया गया है जिसके चलते संसार भर के कपल प्यार का इजहार करने को उत्सुक रहते हैं। जहां चीन में यह दिन नाइट्स ऑफ सेवेन्स प्यार करने वालों के लिए खास होता है, वहीं जापान व कोरिया में इस पर्व को वाइट डे का नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इन देशों में इस दिन से पूरे एक महीने तक लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। आज 14 फरवरी का कितना महत्व बढ गया है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है इस अवसर पर बाजारों में खासी रौनक छा जाती है। गिफ्ट सेंटर में उमड़ने वाला सैलाब, चहल पहल इस बात को बताने के लिए काफी है यह किस प्रकार आम आदमी के दिलो में एक बड़े पर्व की भांति अपनी पहचान बनने में कामयाब हुआ है। इस अवसर पर प्रेमी होटलों , रेस्तारा में देखे जा सकते हैं।

यूं तो हमारी संस्कृति में प्रेम को परमात्मा का दूसरा रूप बताया गया है अतः प्रेम करना गुनाह और प्रेम का विरोधी होना सही नहीं होगा लेकिन वैलेंटाइन के नाम पर जिस तरह का पा मीपरस्त विस्तार हो रहा है वह सही नहीं है। वैसे भी यह प्रेम की स्टाइल भारतीय जीवन मूल्यों से किसी तरह मेल नहीं खाती। आज का वैलेंटाइन डे भारतीय काव्य शास्त्र में बताये गए मदनोत्सव का पा मी संस्करण प्रतीत होता है लेकिन बड़ा सवाल जेहन में हमारे यह आ रहा है क्या आप प्रेम जैसे चीज को एक दिन के लिए बाध सकते है? शायद नहीं। एक समय ऐसा था जब राधा, कृष्ण , मीरा वाला प्रेम हुआ करता था जो आज के वैलेंटाइन प्रेमियों का जैसा नहीं होता था। आज लोग प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रहे है। हीर- रांझा, लैला- मजनू रोमियो-जूलियट के प्रसंगों का हवाला देने वाले हमारे आज के प्रेमी यह भूल जाते है मीरा वाला प्रेम सच्ची आत्मा से सम्बन्ध रखता था। आज तो प्यार बाहरी आकर्षण की चीज बनती जा रही है। प्यार को गिफ्ट और पॉकेट में तोला जाने लगा है। वैलेंटाइन के प्रेम में फसने वाले कुछ युवा सफल तो कुछ असफल साबित होते है। जो असफल हो गए तो समझ लो बरबाद हो गए क्युकि यह प्रेम रुपी बग बड़ा खतरनाक है। एक बार अगर इसकी जकड में आप आ गए तो यह फिर भविष्य में भी पीछा नहीं छोडेगा। असफल लोगों के तबाह होने के कारण यह वैलेंटाइन डे घातक बन जाता है। वैलेंटाइन के नाम पर आज हमारे समाज में जिस तरह की उद्दंडता हो रही है वह चिंतनीय ही है। संपन्न तबके साथ आज का मध्यम वर्ग और अब निम्न तबका भी इसके मकड़ जाल में फसकर अपना पैसा और समय दोनों खराब करते जा रहे है। आज वैलेंटाइन की स्टाइल बदल गई है। गुलाब, गिफ्ट दिए,पार्टी में थिरके बिना काम नही चलता। यह मनाने के लिए आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। यह भी कोई बात हुई क्या जहाँ प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए जेब की बोली लगानी पड़ती हो ?

आज के समय में वैलेंटाइन प्रेमियों की तादात बढ रही है। साल -दर -साल। इस बार भी प्रेम का सेंसेक्स पहले से ही कुलाचे मार रहा है। वैलेंटाइन ने एक बड़े उत्सव का रूप ले लिया है। मॉल , गिफ्ट, आर्चीस , डिस्को थेक का आज इससे चोली दामन का साथ बन गया है। अगर आप में यह सब कर सकने की सामर्थ्य नही है तो आपका प्रेमी नाराज। बस फिर प्रेम का द एंड समझे। प्यार का स्टाइल समय बदलने के साथ बदल रहा है। वैलेंटाइन प्रेमी भी हर साल बदलते ही जा रहे है। आज प्यार की परिभाषा बदल गई है। वैलेंटाइन का चस्का हमारे युवाओ में तो सर चढ़कर बोल रहा है लेकिन उनका प्रेम आज आत्मिक न होकर क्षणिक बन गया है। उनका प्यार पैसों में तोला जाने लगा है। आज की युवा पीढ़ी को न तो प्रेम की गहराई का अहसास है न ही वह सच्चे प्रेम को परिभाषित कर सकती है। उनके लिए प्यार मौज मस्ती और सैर - सपाटे का खेल बन गया है जहाँ बाजार में प्यार नीलाम हो गया है और पूरे विश्व में इस दिन प्यार के नाम पर मुनाफे का बड़ा कारोबार किया जा रहा है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

PM RAHAT योजना के माध्यम से जीवन रक्षक सुरक्षा, 'लखपति दीदी' लक्ष्य के विस्तार से महिला सशक्तिकरण, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के सुदृढ़ीकरण से किसानों को मजबूती, तथा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देना समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम हैं।

-पुष्कर सिंह धामी

'सेवा तीर्थ' पिछले 11 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में सेवा-भाव से चल रही सरकार के संकल्प का प्रतीक है। हर देशवासी तक विकास और जन-कल्याणकारी कार्यों की पहुँच सुनिश्चित कर, विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में यह मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है।

-अमित शाह

संपादकीय

कानून एवं व्यवस्था

भाजपा शासित राज्यों में विकास का सूचकांक कितना है? क्या ये राज्य शेष भारत के समानांतर या उससे कहीं ज्यादा गति से प्रगति कर रहे हैं,यह एक अलग विषय है। जिस पर राष्ट्रीय बहस कराई जा सकती है। लेकिन एक बात जो सर्वविदित है,जिसका प्रायः सभी लोहा मानते हैं,वह कानून एवं व्यवस्था है। तकरीबन सभी भाजपा शासित राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले कमोवेश बेहतर है। छत्तीसगढ़ जैसा नक्सल पीड़ित राज्य में भी अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसे गिन रहा है। जहां वे अभी तक समानांतर सरकार चलाते रहे हैं। लेकिन अब सरकार का दावा है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद पूरे देश से समूल खत्म हो जाएगा। पड़ोसी राज्य उड़ीसा भी नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। ऐसे में उत्तरप्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी द्वारा सूबे की योगी सरकार को कानून और व्यवस्था के नाम पर घेरना और विधानसभा का बहिर्गमन कर देना बेहद हास्यास्पद लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून एवं व्यवस्था के मामले में एक तरह से पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। उस सूबे में कानून एवं व्यवस्था को आधार बनाकर राजनीतिक हंगामा खड़ा करना समझ में नहीं आता है। यह सही है कि उत्तरप्रदेश में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग कर रहा है। कभी उसे लगता था कि पीडीए के नाम पर गोलबंदी करके वह चुनाव जीत सकता है। लेकिन हाल के कुछ उपचुनावों में उसे जिस तरह झटका लगा है और उसका यह प्रयोग नाकाफी साबित हुआ है। उसके बाद अब वह पीडीए से बाहर के लोगों को जोड़ने का भी उपक्रम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पर डोरे डालने लगी है। योगी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों पर डोरे डालने शुरू कर दिया है और उन्हें भरपूर सम्मान देने का आश्वासन भी दे रही है। पार्टी ने साफ आरोप लगाया है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सपा ही नहीं बसपा भी हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और पार्टी में उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का वादा कर रही है। खैर ये कुछ मुद्दे हैं,जिनके आधार पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और घेरना भी चाहिए। ब्राह्मण किसी की जागीर नहीं हैं। अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो उसे पूरा हक है कि वह किसी के भी साथ चला जाए। इतिहास भी यही बताता है कि ब्राह्मण ने अतीत में चाहे सपा हो या बसपा जिसका भी साथ दिया सूबे की सत्ता उसी के कब्जे में चली गई है। इसलिए चुनावी बेला में ब्राह्मण एक बार फिर से प्रासंगिक हो गया है। लेकिन कानून-व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है,जिस पर योगी सरकार को अगर राष्ट्रीय चैंपियन कहा जाए तो भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हां! यह अलग बात है कि उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ऐसे राज्य की कानून-व्यव्स्था को पूरी तरह काबू में रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपराधी अब सूबे में अपराध करने से पहले कई बार सोचते हैं।कुछ अपराधी अगर दुस्साहस करके इसे तोड़ने या बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो यूपी पुलिस ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाती है कि जो अपने आप में नजीर बन जाती है। हाँ !सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है,इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ पुलिस अधिकारियों की कार्य शैली भी कभी-कभी सवालों के घेरे में आ जाती है,जिनसे भी सरकार सख्ती से निपटती है। लेकिन कानून-व्यवस्था योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च वरियता दे रखी है। यही कारण है कि अब यह सूबा भयमुक्त प्रदेश बन चुका है। महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं में भारी कमी आई है। लोग बिना किसी भय के प्रदेश के किसी भी हिस्से में बेखौफ यात्रा कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को चुनावी ही सही,लेकिन ऐसे मुद्दे की तलाश करनी चाहिए,जो जनता के मन को छू सके। रोजगार इसमें से एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है।

एनएचआरसी इंडिया जेंडर इक्वलिटी हेतु महिला कैदियों के साथ

प्रो.कन्हैया त्रिपाठी

भारत में बंद बंदी महिलाओं के बारे में सोचता ही कौन है? आयोग के अध्यक्ष द्वारा सही समय पर जब भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की गुहार हुई, उस समय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गयी कि वे बताएं की कैदी महिलाओं की स्थिति क्या है? इस रिपोर्ट में उन्होंने अपेक्षा की है कि महिला कैदियों और शिशुओं के साथ रहने वाली महिला कैदियों, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों के साथ-साथ एक साल से अधिक समय से जेलों में बंद महिला और पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या उन्हें राज्य व संघ राज्य क्षेत्र बताएं।

एनएचआरसी इंडिया जेंडर इक्वलिटी हेतु महिला कैदियों के साथ है। भारत में महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का द्वार अब सरकार ने खोल दी है। भारत सरकार की मंशा है कि हमारी भारतीय महिलाएं सशक्त हो, समर्थ हों और सक्षम भारत का निर्माण करें। इसके लिए अनेक योजनायें और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी जैसे इनिशिएटिव की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भारत सरकार हो या कोई अन्य एजेंसीज जो महिलाओं के हित में कार्य करना चाहती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि स्त्रियाँ भी अपने हित-अहित को समझें और सकारात्मक होकर कार्य करें।

अपराध की दुनिया में सम्मिलित महिलाओं की ओर जब-जब ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि इनकी सकारात्मक ऊर्जा जिस ओर लगनी चाहिए थी, उससे ये महिलाएं भटक गयीं और उन्हें आज बंदी जीवन जीना पड़ रहा है। शोध अध्येता यह बताते हैं कि दुनिया में लगभग 8 लाख महिलाएं तो जेलों में बंद हैं। वह कैदी जीवन जी रही हैं। ऐसे भी अध्ययन प्रकाश में आये हैं कि जेलों में बंद महिलाओं को जेल जीवन बोरिंग नहीं लग रहे हैं और वे व्यक्तिगत रूप से शानदार और सुंदर पल जी रही हैं। महिलाएं जीवित अनुभव के साथ, नए और हस्तांतरणीय कौशल सीखने का मौका पा रही हैं, साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना पैदा करने में जेल मदद कर रहे हैं। पर, जेल में बंद महिलाओं की विरासत में यह खुश महिलाएं न जाने क्यों ऐसा सोच रही हैं? जेल तो जेल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस ने बार-बार वैश्विक स्तर पर जेलों में महिलाओं की बढ़ती संख्या और उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के बारे में चिंताओं को उजागर किया। उन्होंने जेल प्रणालियों को महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मातृत्व, स्वास्थ्य और उनके परिवारों पर कारावास के प्रभाव से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न घटक महिला कैदियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके कारावास के मूल कारणों को दूर करने के लिए काम करने वाले जमीनी स्तर के संगठनों के लिए अधिक धन और समर्थन का भी बार-बार आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र ने जो किया वह उसकी सभी देशों के लिए पहल मानी जाएगी लेकिन एनएचआरसी, भारत ने कुछ समय पहले देश भर की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित कैदियों को हो रही कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया।

बहुत साफ शब्दों में आयोग के कहा है कि मुख्य सचिव हमें अवगत करें कि राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या कितनी है, उन महिला कैदियों की संख्या जिनके बच्चे माताओं के जेल में रहने के कारण जेलों में बंद हैं? उन महिला कैदियों की संख्या, जो दोषी करार दी गई हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं, उन महिला विचाराधीन कैदियों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं और और पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या भी और जो एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं, उन्हें बताया जाए।

वस्तुतः भारत के जेल आज भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वहां का प्रशासन ज्यादा ही लचर हैं। आए दिन मारपीट जेलों की रवायत है। महिला बंदी ऐसी स्थिति में कैसे रहती होंगी, यह कहना मुश्किल है। इससे बंदी महिलाओं के जीवन में अनेक कष्ट उनके बंदी होने से ज्यादा कष्टप्रद लगने लगे हैं। कैदी होने का यह कतई मतलब नहीं है कि कैदी-जन जीवन के अधिकार भी खो चुके हैं। मानव अधिकार की बुनियाद ही जीवन के अधिकार में सम्मिलत है, और जीवन के अधिकार में ही तो जुड़ी हैं उनकी बुनियादी जीवन की ज़रूरतें। यही ज़रूरतें ही तो नहीं पूरी हो पा रही हैं इन बंदियों की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो चिंता व्यक्त की, वह यूं ही नहीं है। बल्कि महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन होता देख उसने सभी राज्यों को अपनी चिंता ज़ाहिर की है। उसकी चिंता सबसे ज्यादा बुनियादी ज़रूरतों को लेकर भी है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक परेशानी, अपर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाएँ, खराब गुणवत्ता वाला भोजन जिसके कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण होता है। जेलों में उनके साथ रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना जैसे अनेक विषय शामिल हैं।

महिलाओं की विशेष ज़रूरतें यदि नहीं मिलेंगी, तो वे जियेंगी कैसे? जेंडर इक्वैलिटी को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि उन्हें उनकी कंडिशनिंग के हिसाब से औपचारिक संसाधन ही जेल प्रशासन नहीं रख रहे हैं तो निश्चय ही यह एक प्रकार से मानवाधिकारों का हनन है। भारतीय जेलों में प्रताड़ना की शिकार कैदी महिलाओं की निगरानी पर भी आयोग यदि अपने विशेष दस्ते भेजे तो निश्चय ही जेलों के भीतर हिंसा की शिकार महिलाओं को सजा के साथ जीवन के मौलिक अधिकार मिलेंगे व उन्हें जीने का हक मिलेगा। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भारत की तमाम जेलों की समस्या बनी हुई है। यदि भारत में अपराध कम नहीं हुए तो विश्वविद्यालयों से ज्यादा जेलों का निर्माण ज़रूरी लगेगा। इन अपराधों पर तो अंकुश बिलकुल सरकारें खो रही हैं क्योंकि जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत में दी जाती है, वही सबसे ज्यादा अपराध में संलग्न पाए जा रहे हैं। ये अपराधी अपने साथ महिलाओं को भी इस प्रकार शामिल करते हैं कि वे अनचाहे भी अपराध से अपने आपको बचा नहीं पातीं।

जब इन्हें जेलों में जीवन बिताना पड़ता है तो अपराधबोध भी इनके जीवन का हक नहीं दिला पाते। मॉनीटर्स और प्रतिवेदकों द्वारा इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान से एक बात तो स्पष्ट हो गयी है कि वह कैदी महिलाओं के प्रति पूरी संवेदना रखता है।

खालिदा की राह पर चले तारिक तो भारत को हो सकता है नुकसान

अजय कुमार

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है, निर्यात का बड़ा हिस्सा भारत जाता है। वैश्विक दबाव में भी बदलाव संभव है। लेकिन पार्टी की विचारधारा के कारण संबंध वैसे ही तनावपूर्ण रह सकते हैं, जैसे अल्पसंख्यक सुरक्षा और सीमा विवाद पर। अगर तारिक सत्ता में आए, तो चीन-पाकिस्तान झुकाव बढ़ सकता है, जिससे भारत सतर्क होगा। फिर भी, कूटनीतिक यात्राओं से नरमी आ सकती है, जैसा २०१२ में हुआ। कुल मिलाकर, पूरी तरह वैसा ही रहना मुश्किल, कुछ सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं यदि आर्थिक हित प्राथमिक हों।बांग्लादेश की राजनीति हमेशा भारत के लिए महत्वपूर्ण रही है। खालिदा जिया काल की खटास ने सीमा सुरक्षा और व्यापार प्रभावित किया, जबकि हसीना ने सहयोग बढ़ाया।

बांग्लादेश की राजनीति में बेगम खालिदा जिया का नाम एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उनकी सरकार के दौरान भारत के साथ संबंधों में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रही, जबकि उनके बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व में आने पर ये रिश्ते या तो वैसे ही रह सकते हैं या कुछ बदलाव दिख सकते हैं। बेगम खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 1991 से 1996 तथा 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान भारत के साथ उनके संबंधों को कई कारणों से खराब माना जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने 1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि को गुलामी की संधि करार दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते पर ही सवाल उठ गए। उनकी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध बढ़ाए, खासकर 2002 में चीन के साथ बड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे भारत ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। फरक्का बैराज को लेकर भी उन्होंने भारत की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे बांग्लादेश को गंगा का पानी नहीं मिल पाता। ट्रांजिट सुविधा के मुद्दे पर भी उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के रास्ते जाने का विरोध किया, इसे अपनी संप्रभुता से जोड़कर देखा। इसके अलावा, खालिदा जिया के शासनकाल में भारत ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को शरण दे रहा है, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ा। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामले भी बढ़े, जैसे 1992 के बाबरी मस्जिद विवाद के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की, जिसमें हजारों हिंदू प्रभावित हुए। 2005 में जमात-उल-मुजाहिदीन के 500 बम धमाकों ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया, क्योंकि भारत ने इसे अपने खिलाफ साजिश माना। इन सबके बावजूद 2012 में खालिदा जिया ने भारत यात्रा की और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने संबंध सुधारने की बात कही, लेकिन वापस लौटते ही उनका रुख फिर कड़ा हो गया। कुल मिलाकर, उनकी सरकार में संबंध सुलगते रहे, कोई गर्मजोशी नहीं दिखी।

इसके विपरीत, शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया, लेकिन इस बार अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। उन्होंने 1972 की संधि का सम्मान किया और कई समझौते किए। उदाहरण के लिए, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के दौरान भूमि सीमा समझौता हुआ, जिससे 162 छिटमहल सुलझ गए और हजारों लोगों को नागरिकता मिली। गंगा जल बंटवारे पर 1996 का समझौता हसीना ने मजबूती से लागू किया। ट्रांजिट सुविधा दी गई, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ हुआ। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ा, खासकर उग्रवादियों को सौंपने के मामले में। व्यापार बढ़ा, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। कोविड महामारी में भारत ने टीके उपलब्ध कराए, जिसे हसीना ने सराहा। बुनियादी ढांचे परियोजनाओं जैसे माहेनगर रेल पुल और कुशियारा नदी पर पुल का निर्माण भारत की मदद से हुआ। सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बढ़ा, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास और सांस्कृतिक उत्सव। इन उदाहरणों से साफ है कि हसीना काल में संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत हुए।अब सवाल है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से संबंध कैसे होंगे। तारिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मां की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। 17 साल बाद वे 2025 में बांग्लादेश लौटे, जहां उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तारिक का रुख भी राष्ट्रवादी है, वे भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर उग्रवादियों को शरण देने के आरोपों को खारिज किया, लेकिन पाकिस्तान और चीन के प्रति नरमी दिखाई। हालांकि, हाल के वर्षों में कुछ बदलाव दिखे हैं। खालिदा जिया की हालत खराब होने और उनकी मृत्यु के बाद तारिक ही पार्टी का चेहरा हैं। वे आर्थिक विकास और लोकतंत्र पर जोर देते हैं, जिससे भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने की जरूरत समझते होंगे।

कविता

प्रेम

प्रेम के बीज
आंखों में
बोए जाते हैं

आंसुओं से
नमी पा
लहलहाती हैं
प्रेम की फसलें

पर यह क्या!
प्रेम किया
जमाना
दुश्मन हो गया

दुश्मनी की
सब प्रेम की बात
करने लगे!

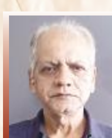

राजेश पाठक

आपका मत

'घूसखोर पंडित' पर फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'घूसखोर पंडित' फिल्म के टाइटल पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस तरह के टाइटल से समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें नया टाइटल बताया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि फिल्म में किसी वर्ग को अपमानित करने वाली कोई सामग्री ना हो। इस मामले में कोर्ट ने जोर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति या समूह किसी समाज या समुदाय की भावनाओं को आहत करे, बल्कि आजादी की सीमाएं वहां खत्म हो जाती हैं जहां दूसरों की गरिमा और सम्मान पर आंच आती है। समस्या यह है कि हमारे फिल्म उद्योग में कई बार सामाजिक संदर्भों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। निर्माता मनोरंजन एवं व्यावसायिक लाभ के चक्कर में ऐसे टाइटल, गाने या डायलॉग चुनते हैं जो समाज के ताने-बाने को बिगाड़ देते है। जिससे तनाव पैदा होता है और कभी-कभी यह तनाव हिंसक रूप ले लेता है, जैसे सिनेमाघरों में तोड़फोड़, सड़कों पर आंदोलन या सामाजिक बहिष्कार। कुल मिलाकर, इस मामले ने अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन की बहस को फिर से जीवंत कर दिया है, और उम्मीद है कि भविष्य में फिल्म उद्योग अधिक सतर्कता बरतेगा ताकि मनोरंजन समाज को जोड़े न कि तोड़े।

-वीरेंद्र कुमार

लोकसत्य

आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।

loksatyaedit01@gmail.com

Blogger

कोचिंग संस्कृति और बच्चों की मौतें

डॉ० प्रियंका सौरभ

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम सफलता को किस रूप में परिभाषित करते हैं। क्या एक अच्छा इंसान बनना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और अपनी रुचि के क्षेत्र में संतुष्ट जीवन जीना सफलता नहीं है? यदि नहीं, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो चयनित तो होगी, लेकिन भीतर से टूटी हुई और असंतुष्ट होगी।

कोटा में एक और छात्रा की आत्महत्या—यह कोई साधारण खबर नहीं है और न ही किसी एक परिवार की निजी त्रासदी भर। यह उस शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक मानसिकता और तथाकथित "सफलता मॉडल" पर गहरा प्रश्नचिह्न है, जिसे हमने पिछले दो दशकों में बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति का सुसाइड नोट केवल व्यक्तिगत पीड़ा का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि वह एक आरोपपत्र की तरह हमारे पूरे समाज के सामने खड़ा होता है—माता-पिता, कोचिंग संस्थान, स्कूल और नीति-निर्माता सभी इसके दायरे में आते हैं।

कृति ने अपने सुसाइड नोट में भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की थी कि अगर वे सच में चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे, तो कोचिंग संस्थानों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान छात्रों को भीतर से खोखला कर देते हैं। यह कथन किसी क्षणिक आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि उस लंबे मानसिक उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी, जिसे आज लाखों छात्र रोज़ झेल रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि कृति ने ऐसा क्यों लिखा, बल्कि यह है कि क्या वह ग़लत थी।

आज भारत में कोचिंग शिक्षा का सहायक माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि एक विशाल और मुनाफ़े पर आधारित उद्योग बन चुकी है। कोटा, सीकर, हैदराबाद, दिल्ली और पटना जैसे शहर "एजुकेशन हब" कहलाते हैं, जहाँ हर साल लाखों किशोर अपने माता-पिता के सपनों का बोझ उठाए पहुँचते हैं। इन सपनों के केंद्र में कुछ सीमित शब्द होते हैं—आईआईटी, एम्स, नीट, रैंक और सेलेक्शन। कोचिंग संस्थान बच्चों को यह यक़ीन दिलाते हैं कि यदि वे चयनित नहीं हुए, तो वे असफल हैं। सफलता की यह परिभाषा इतनी संकीर्ण है कि उसमें औसत छात्र के लिए कोई जगह नहीं बचती, और असफलता से उबरने की कोई मानवीय प्रक्रिया भी नहीं होती।

सफलता के नाम पर असफल समाज

कृति का यह कथन कि "90+ अंक लाने वाली लड़की भी आत्महत्या कर सकती है" हमारे उस भ्रम को तोड़ता है, जिसमें हम यह मान लेते हैं कि मानसिक संकट केवल कमजोर या असफल छात्रों तक सीमित है। यह सोच न सिर्फ़ ग़लत है, बल्कि ख़तरनाक भी है। आज का दबाव केवल परीक्षा पास करने या अच्छे अंक लाने का नहीं रह गया है, बल्कि माता-पिता, शिक्षकों और समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का बन गया है। हर बच्चा अपने भीतर एक काल्पनिक 'परफेक्ट स्टूडेंट' की छवि ढो रहा है, जिससे वह लगातार हारता चला जाता है। ऊँचे अंक और बेहतर प्रदर्शन भी अब मानसिक शांति की गारंटी नहीं रहे, क्योंकि समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि उस माहौल की है जिसमें पढ़ाई कराई जा रही है।

सामाजिक तुलना—कि फलाँ का बेटा डॉक्टर बन गया या फलाँ की बेटी आईआईटी में पहुँच गई—हमें इतना अंधा कर देती है कि हम बच्चों की इच्छाओं, क्षमताओं और सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं।

कृति ने अपनी छोटी बहन को लेकर जो चेतावनी दी, वह इस सुसाइड नोट को और भी मार्मिक बना देती है। वह चाहती है कि उसकी बहन को वही पढ़ने दिया जाए, जो वह पढ़ना चाहती है, और वही बनने दिया जाए, जो वह बनना चाहती है। यह विडंबना है कि मरते समय भी वह किसी और की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी। यह चेतावनी केवल एक माँ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है, जो बच्चों को सुनने के बजाय उन पर अपने सपने थोपता है।

आज के स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को गणित के सूत्र, रसायन के समीकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीतियाँ तो सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन के सबसे ज़रूरी पाठ सिखाने में पूरी तरह असफल हो रहे हैं। वे बच्चों को यह नहीं सिखा पा रहे कि असफलता से कैसे निपटना है, मानसिक तनाव को कैसे समझना है और मदद माँगना कमजोरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा को प्रेरणा के बजाय भय का औज़ार बना दिया गया है। रैंक लिस्ट, मॉक टेस्ट और लगातार तुलना बच्चों के मन में स्थायी हीनभावना भर देती है, जिससे वे खुद को केवल अंकों और चयन के चश्मे से देखने लगते हैं।

सम्पादकीय

देव संस्कृति के आलोक में

मंडी शहर पुनः शिवरात्रि की चहलकदमी में अपने सांस्कृतिक महत्त्व की प्रस्तुति दे रहा है। देव संस्कृति की परंपराओं में विराजित विश्वास सारे माहौल को रुहानियत से जोड़ देगा और तब परंपराओं के दर्पण में यह शहर अपनी संस्कृति की फेहरिस्त पर हस्ताक्षर करता दिखेगा। इस अद्भुत नजारे से असली हासिल है क्या और यह उत्सव साल भर के दर्शन में आखिर मंडी के भरोसे क्या छोड़ जाता। शिवरात्रि चार दिन की चांदनी नहीं, मंदिरों के शहर का वर्ष भर का उजाला क्यों न बने। हर देवता के पीछे अगर एक इतिहास चलता है, तो आस्था के ये पुंज निरंतर प्रदर्शित होने चाहिएं। देव संस्कृति के आलोक में शिवरात्रि का महत्त्व इसके हर पहलू की जानकारी है, तो मंडी विश्वविद्यालय में देव संस्कृति की खंडपीठ स्थापित होनी चाहिए। शहर में एक ऐसे कला-संस्कृति केंद्र की जरूरत है, जहां एक शाखा में अध्ययन की परिपाटी हो, तो दूसरी ओर कला संग्रह के माध्यम से देव संस्कृति की जीवंतता, पृष्ठभूमि में उपजता बोध तथा वाद्य यंत्रों के मार्फत गूंजती कला का स्थायी प्रदर्शन हो। कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में मंडी की पृष्ठभूमि में काशी का उद्घोष अगर हर दिन सुनाना है, तो एक व्यापक योजना की जरूरत है। बेहद दुख की बात है कि मंडी का विस्तार शहर की मानसिकता में ही होता रहा, जबकि यह एक तीर्थ, हिमाचल का धार्मिक हृदय तथा सांस्कृतिक उजास का चेहरा रहा है। गलियों में गूंजते मंदिरों के घंटे अब अतिक्रमण की दीवारों ने रौंद दिए। प्रदक्षिणा की खोज में आस्था के पांव थक जाते हैं। इस मामले में सरकारों की नीतियां भी कम दोषी नहीं। एडीबी के सामर्थ्य में पर्यटन के कंगूरे खड़े करने वालों ने मंडी के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व पर क्या किया। क्या सारे मंदिरों का एक सर्किट बना कर हम एलिवेटिड परिक्रमा की शुरुआत नहीं कर सकते। ब्यास के तट पर मंडी शहर का वैभव अगर स्थायी घाट तथा कृत्रिम झील के आधार पर होता, तो शिव की धरती को साल भर पूजा जाता। बेशक महोत्सव की धाक में एक सरकारी आचार संहिता बन गई है। जलेब अब उत्सव और शानो शौकत की तरह पगडियां गिनते हैं, तो राजसी ठाठ में सरकार के ओहदे दिखाई देते हैं। बड़े होते शहर में गिनती के कदम, ये तेरा अनुशासन था कि हम भीड़ से देखें। अब जनता देखती है, त्योहार के साथ चलती नहीं।

आएंगे बड़े से बड़े गायक और झूमेंगे उस ताल पर, जो हमारी है ही नहीं। सुना है बड़ा झूला आकाश से दिखाएगा मेला, जहां व्यापार की मोमबत्तियां शहर के बाजार में पिघलेंगी। हमें क्यों लगता है कि सभी मेले एक सरीखे हो गए हैं। सभी के सभी कार्बन कापी। क्या मंडी की शिवरात्रि का गीत-संगीत और हरोली उत्सव का म्यूजिक एक जैसा होना चाहिए।

सरकार से सवालःक्या सरकारी स्कूलों में बच्चों के मन की सुनवाई की कोई व्यवस्था है?

डॉ. एन.पी. गांधी

पढ़ाई का दबाव उतना घातक नहीं होता जितनी घातक होती है बच्चों के मन की अनसुनी। जब कोई बच्चा महीनों स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई से दूर होता है और 'मुझे नहीं पढ़ना'कहता है, तब यह जिद नहीं, चेतावनी होती है। क्या सरकारी स्कूलों में ऐसे संकेत पहचानने की कोई व्यवस्था है? क्या मानसिक काउंसलिंग केवल कोचिंग तक सीमित रहेगी? यह घटना सरकार से तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है—क्योंकि एक परीक्षा से बड़ा होता है एक बच्चे का जीवन।

कोटा जिले के दीगोद क्षेत्र में गुरुवार को दसवीं की बोर्ड परीक्षा के दिन एक 16 वर्षीय छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, बाद में न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।परिवार के अनुसार छात्रा पिछले डेढ़ महीने से पढ़ाई को लेकर गंभीर मानसिक तनाव में थी और स्कूल भी नियमित नहीं जा रही थी। पिता ने केवल इतना कहा था कि परीक्षा दे दो, परिणाम की चिंता मत करना, लेकिन उसके भीतर चल रहा दबाव शब्दों में व्यक्त नहीं हो सका। घटना के दिन सुबह माता-पिता मजदूरी के लिए कोटा निकल गए थे। लगभग पौने दस बजे गांव से सूचना मिली कि बेटी ने फांसी लगा ली। भाई ने तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, पर डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। स्थानीय पुलिस के अनुसार पढ़ाई का तनाव प्रमुख कारण माना जा रहा है।कोटा में दसवीं की परीक्षा से ठीक पहले 16 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी पर बड़ा सवाल है।

पढ़ाई का दबाव उतना घातक नहीं होता जितनी घातक होती है बच्चों के मन की अनसुनी। जब कोई बच्चा महीनों स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई से दूर होता है और 'मुझे नहीं पढ़ना'कहता है, तब यह जिद नहीं, चेतावनी होती है। क्या सरकारी स्कूलों में ऐसे संकेत पहचानने की कोई व्यवस्था है? क्या मानसिक काउंसलिंग केवल कोचिंग तक सीमित रहेगी? यह घटना सरकार से तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती है—क्योंकि एक परीक्षा से बड़ा होता है एक बच्चे का जीवन।

आखिर क्यों टूट जाते हैं नाजुक मन

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान

संस्थान,मुंबई के एलुमनाई एवं ग्लोबल एन.एल.पी. लाइफ करियर कोच डॉ. नयन प्रकाश गांधी के अनुसार आत्महत्या कभी अचानक लिया गया निर्णय नहीं होती। यह लंबे समय से चल रहे मानसिक संघर्ष, असफलता के डर और भावनात्मक थकान का परिणाम होती है।इस मामले में चेतावनी संकेत स्पष्ट थे—

पढ़ाई में रुचि खत्म होना,लंबे समय तक स्कूल न जाना,मुझे नहीं पढ़ना एवं किशोरावस्था में बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उनकी सोच पूरी तरह परिपक्व नहीं होती और असफलता का भय उन्हें असहनीय लग सकता है। जब बच्चा यह महसूस करता है कि वह अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो अपराधबोध और हीनता की भावना गहराने लगती है।डॉ. गांधी बताते हैं कि एन.एल.पी एनएलपी (न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग) के माध्यम से सोच, भावनाओं और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उनके अनुभव में बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है बिना शर्त स्वीकृति की। जहां स्वीकृति मिलती है, वहां आत्मघाती विचार कमजोर पड़ जाते हैं।

समाधान क्या?

माता-पिता, स्कूल और सरकार की साझा जिम्मेदारी

यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए चेतावनी है।

माता-पिता क्या करें?

बच्चे के व्यवहार में बदलाव को गंभीरता से लें

रोज संवाद करें, केवल निर्देश न दें

परिणाम से अधिक बच्चे को महत्व दें

निःशुल्क छात्र मानसिक परीक्षा तनाव ,करियर दबाव सबंधी काउंसलिग की हो अनिवार्यता

स्कूल और शिक्षा विभाग की भूमिका

लंबे समय तक अनुपस्थित छात्रों पर अनिवार्य फॉलो-अप

सरकारी स्कूलों में मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य हो

कोचिंग ही नहीं, सरकारी स्कूलों में भी साप्ताहिक जीवन प्रबंधन,मानसिक तनाव नियंत्रण,करियर मार्गदर्शन,मोटिवेशनल वर्कशॉप अनिवार्य की जाए ।

डॉ. गांधी के अनुसार विभिन्न शोध बताते हैं कि परीक्षा-पूर्व तनाव प्रबंधन सत्र और नियमित काउंसलिंग से इस प्रकार की आत्महत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है,जिससे प्रारंभिक अवस्था में ही तनाव ज्ञात होने पर उसका उचित समाधान किया जा सके । क्योंकि सच यही है,एक परीक्षा से बड़ा होता है एक बच्चे का जीवन,परंतु सरकार ,प्रशासन के बाद भी गांधी अहम भूमिका माता पिता की मानते है अतः गांव कस्बे स्तर पर माता पिता के लिए भी बच्चों के मानसिक तनाव को भांपने समझने हेतु ,बच्चों के साथ उचित व्यवहार ,तकनीकी समझ ,साइबर यौन अपराध आदि हेतु भी जागरूकता संबंधित प्रशिक्षण आवश्यक है ,जो सामाजिक संस्थाओं की भूमिका ,क्षेत्र विशेष में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट के सामाजिक प्रतिबद्धता से पूरा किया जा सकता है ।

दाढ़ी पर नहीं, सोच पर बहस ज़रूरी

डॉ. सत्यवान सौरभ

बीते कुछ वर्षों में दाढ़ी को लेकर एक तीखी बहस उभरी है। कुछ लोग इसे आधुनिक फैशन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक भ्रम और अंधानुकरण का उदाहरण। यह बहस तब और जटिल हो जाती है जब इसे धर्म, राजनीति या साज़िश से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर, शोर से दूर रहकर, विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टि से इस विषय को देखें। क्योंकि जब मुद्दे विचार के बजाय पहचान की लड़ाई बन जाते हैं, तब समाधान नहीं, विभाजन पैदा होता है।

हर दौर की अपनी पहचान होती है। यह पहचान केवल कपड़ों, हेयर-स्टाइल या चेहरे पर उगे बालों से नहीं बनती, बल्कि उस सोच से बनती है जो व्यक्ति और समाज—दोनों को दिशा देती है। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे कैसे दिखते हैं यह कम, और क्या सोचते हैं तथा किसका अनुकरण करते हैं—यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बाहरी आकर्षण, सोशल मीडिया की चमक और तात्कालिक लोकप्रियता ने पहचान की परिभाषा को सतही बना दिया है।

बीते कुछ वर्षों में दाढ़ी को लेकर एक तीखी बहस उभरी है। कुछ लोग इसे आधुनिक फैशन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक भ्रम और अंधानुकरण का उदाहरण। यह बहस तब और जटिल हो जाती है जब इसे धर्म, राजनीति या साज़िश से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर, शोर से दूर रहकर, विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टि से इस विषय को देखें। क्योंकि जब मुद्दे विचार के बजाय पहचान की लड़ाई बन जाते हैं, तब समाधान नहीं, विभाजन पैदा होता है।

इतिहास गवाह है कि दाढ़ी और क्लीन शेव—दोनों ही भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। वैदिक काल के ऋषि-मुनि जटाधारी थे, तो राजदरबारों में सुसज्जित, साफ़-सुथरे व्यक्तित्व भी दिखाई देते थे। मध्यकाल हो या आधुनिक काल—हर युग में दोनों प्रकार के रूप साथ-साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरू—सभी का रूप अलग था, पर उद्देश्य एक। स्पष्ट है कि दाढ़ी कोई नई या बाहरी चीज़ नहीं है, और न ही क्लीन शेव कोई विदेशी अवधारणा। दोनों ही समय, परिस्थिति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बदलते रहे हैं। आज दाढ़ी का चलन केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक फैशन का हिस्सा बन चुका है। हॉलीवुड, यूरोपीय फैशन, खेल जगत, संगीत उद्योग और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स—हर जगह दाढ़ी अलग-अलग शैलियों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इन रुझानों को और तेज़ कर दिया है। एक तस्वीर, एक वीडियो या एक रील के ज़रिये ट्रेंड पल भर में दुनिया भर में फैल जाते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि कोई एक उद्योग, समूह या विचारधारा ही किसी फैशन को फैला रही है, वास्तविकता का सरलीकरण

होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अंधानुकरण एक गंभीर समस्या बन चुका है। जब युवा किसी भी ट्रेंड को बिना सोचे-समझे केवल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय है या कूल माना जा रहा है, तब उनका व्यक्तित्व उधार का हो जाता है। फैशन तब समस्या बनता है जब वह सोच पर हावी हो जाए और पहचान को केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित कर दे। सवाल दाढ़ी रखने या न रखने का नहीं है; सवाल यह है कि क्या हम अपने चुनाव के कारण जानते हैं, या सिर्फ़ भीड़ के साथ चल रहे हैं? इस संदर्भ में सिनेमा और डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा ज़रूरी है। मनोरंजन उद्योग न केवल कहानियाँ सुनाता है, बल्कि जीवन-शैली के मानक भी गढ़ता है। बार-बार एक ही तरह के लुक, स्टाइल और हीरोइज़्म को आदर्श बनाकर प्रस्तुत करने से युवाओं के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। इससे विविधता कम होती है और एकरूपता बढ़ती है। जिम्मेदार मीडिया वही है जो समाज की बहुलता को दिखाए—जहाँ सादगी भी आकर्षक हो, और अलग-अलग व्यक्तित्व भी स्वीकार्य हों। लेकिन दर्शक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दिखावे और मूल्य में अंतर करना सीखें। ईश्वर, संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा में भी संतुलन आवश्यक है। हमारी परंपराएँ अत्यंत विविध रही हैं। कहीं जटाधारी तपस्वी हैं, तो कहीं सुसज्जित देव-प्रतिमाएँ; कहीं वैराग्य है, तो कहीं श्रृंगार। सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आचरण, करुणा, संयम और विवेक है। यदि हम सौंदर्य को केवल चेहरे, दाढ़ी या फैशन तक सीमित कर दें, तो हम अपनी ही सांस्कृतिक गहराई को कम कर देते हैं। आज के युवाओं के सामने असली खतरा किसी एक फैशन से नहीं, बल्कि आत्मबोध की कमी से है। जब युवा अपने इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक बहुलता को समझते हैं, तब वे किसी भी ट्रेंड को अपनाएँ—या न अपनाएँ—वह उनका सजग और स्वतंत्र निर्णय होता है। लेकिन जब पहचान केवल बाहरी प्रतीकों पर टिक जाती है, तब भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता है।

समाधान डर, आरोप या साज़िश की भाषा में नहीं है। समाधान शिक्षा, संवाद और आत्मविश्वास में है। युवाओं को यह समझाना ज़रूरी है कि फैशन क्षणिक होता है, लेकिन चरित्र स्थायी। आज जो ट्रेंड है, कल बदल जाएगा; पर जो मूल्य आप अपनाते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए चयन सोच-समझकर होना चाहिए—न दबाव में, न डर में, और न ही अंधानुकरण में। समाज को विभाजन की भाषा से भी सावधान रहना चाहिए। जब हम किसी चलन को डर या साज़िश के चश्मे से देखते हैं, तो संवाद बंद हो जाता है और ध्रुवीकरण बढ़ता है। इसके विपरीत, जब हम प्रश्न पूछते हैं—क्यों?, कैसे? और किस हद तक?—तब समझ विकसित होती है। स्वस्थ समाज वही है जो असहमति को जगह देता है, लेकिन सम्मान और तथ्य के साथ। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम युवाओं को आलोचनात्मक सोच सिखाएँ—ताकि वे हर ट्रेंड को आँख बंद करके न अपनाएँ। उन्हें अपने शरीर, समय और पहचान पर अधिकार का बोध हो। फैशन अपनाना गलत नहीं; गलत है फैशन के पीछे खुद को खो देना। व्यक्तित्व की असली सुंदरता बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और विवेक में होती है।

व्यंग्य

बारी बरसी खटन गया सी...

राफेल डील, आई, देखी, डांस हुआ। सुप्रीम कोर्ट बैठा, CBI बैठी, ED बैठी, सबने कहा, कुछ नहीं मगर इनकी थिरकन अभी थमी नहीं। अब राफेल आसमान में उड़ते हैं और ये ज़मीन पर वही स्टेप्स दोहराते हैं। असल ज़िंदगी में रीप्ले नहीं मिलता पर यहाँ तो हर साल रीमिक्स है।

विवेक रंजन श्रीवास्तव

बारी बरसी खटन गया सी...ये गीत पंजाब के उस मेहनतकश का लोक गीत है, जो बारह साल परदेस में कमाकर लौटा है। हर बार उसकी झोली में कुछ नया गिफ्ट होता है , कभी लोई, कभी सितारा, कभी गहना, कभी चूल्हा-ताला। ढोल बजता है। भांगड़ा चलता है और सारा गांव, साले-बिरादरी नाच उठते हैं क्योंकि मेहनत रंग लाई है। कुछ हाथ लगा है। अब इसी गीत की रस्म को कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का नया मनोरंजक कायदा बना लिया है।

फर्क सिर्फ इतना है कि वहां बारह साल बाद सच में कुछ लेकर लौटा था। ये लोग रोज़ सुबह उठते हैं, खाली हाथ में थाल सजाते हैं, ऊपर से झूठे सबूत की चटनी परोसते हैं, और ढोल बजवा देते हैं. और अब डांस करेंगे सारे के सारे!

बारी बरसी खटन गया सी। हर चुनाव, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बजट सत्र, यही क्रम है।

हाथ में कुछ ठोस नहीं मगर उल्लास ऐसा मानो पूरी दिल्ली जीत ली हो।

राफेल डील, आई, देखी, डांस हुआ। सुप्रीम कोर्ट बैठा, छ्क्क्ह बैठी, श्च्ष्ठ बैठी, सबने कहा, कुछ नहीं मगर इनकी थिरकन अभी थमी नहीं। अब राफेल आसमान में उड़ते हैं और ये ज़मीन पर वही स्टेप्स दोहराते हैं। असल ज़िंदगी में रीप्ले नहीं मिलता पर यहाँ तो हर साल रीमिक्स है।चौकीदार चोर है, क्या पंचलाइन थी! इतनी जोरदार कि पार्टी कार्यकर्ता झूम उठे। मगर सबूत? वो तो बाद में देखेंगे, पहले डांस।

अब सात साल हो गए। अदालत ने कहा, सबूत नहीं मिला। जाँच एजेंसी ने कहा सबूत नहीं मिला। पर ये कहते हैं हमें तो अब भी यकीन है। ईवीएम और वोट चोरी , चुनाव हारो, तुरंत मशीन पर ठुमका लगाओ । कभी बैटरी बदली, कभी हैकिंग, कभी हनुमान चालीसा। मगर जब पूछो कि पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल में तुम जीते कैसे? तब मशीन ठीक थी या उसमें भी भगवान का चमत्कार? सवाल सुनते ही डांस और तेज़ क्योंकि यह सवालों के जवाब का नहीं, जश्न का मौका है। संविधान की प्रति, लाल किताब हाथ में, आँखों में नमी, होंठों पर गांधी, मन में नेहरू, और जेब में... खैर। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। तीनों थाली में सजे, वही ठुमके पर संविधान पढ़ने का वक्त कहाँ? जब तक अनुच्छेद पढ़ोगे, तब तक कोई और डांस शुरू हो जाएगा। नरवडे जी की अप्रकाशित पुस्तक, ये तो कमाल है। अप्रकाशित। यानी अभी छपी नहीं। किसी ने पढ़ी नहीं। उसमें है क्या, पता नहीं मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, आरोप लग चुके, डांस शुरू हो चुका। फेक कापी हवा में लहरा कर डांस किया जा चुका ।

साहित्य जगत में किताब छपने पर चर्चा होती है, यहाँ किताब छपने से पहले ही चर्चा, आरोप, और भांगड़ा , सब एक साथ।

अमेरिका से डील, अब ये तो सबसे ताज़ा एंट्री है। डील में हुआ क्या, पता नहीं। किसने की, कैसे की, कितने में की , बारीक अध्ययन, , विवेचन, जानकारी शून्य है मगर आरोप हवा में हैं, अडानी और अंबानी को उछाल कर, हवा हवाई डांस चल रहा है। इतनी ऊर्जा है, कि पावर परचेज के टाई-अप करना चाहिए। अब सवाल यह नहीं कि इन मुद्दों में दम है या नहीं। सवाल यह है कि जब हर बार थाल खाली निकलती है तो फिर भी ढोल क्यों बजता है भेड़िया आया भेड़िया आया, आख़िर कब तक लकड़ी की हांडी कितनी बार चढ सकती है?

क्योंकि अब आरोप कोई बहस नहीं, रस्म बन गए है और रस्में सबूतों की मोहताज नहीं होतीं। राफेल झूठा, चौकीदार सच्चा, फिर भी नारा वही। ईवीएम सही, वोट सुरक्षित, फिर भी चीख वही। किताब अप्रकाशित, आरोप प्रकाशित, फिर भी थिरकन वही।

बारी बरसी खटन गया सी। हर बार खाली हाथ,पर हर बार पूरा उल्लास। सारी दुनिया देख लई, माँ तेरे जेहा न कोई।

नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी है

सुनील कुमार महला

स्त्री की गरिमा और उसका सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रहे हैं। हमारे यहां नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है तथा शास्त्रों में कहा गया है-%यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।% यहां पाठकों को बताता चलूं कि यह प्रसिद्ध संस्कृत वचन %मनुस्मृति% से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जहां नारी का सम्मान और आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में, यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दर्शाता है। नारी को शक्ति, करुणा, त्याग और सृजन की प्रतीक माना गया है।सच तो यह है कि परिवार और समाज की असली आधारशिला नारी ही होती है और जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा मिलती है, वह समाज और देश प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत, जहां नारी का अपमान होता है, वहां अशांति और पतन का वातावरण बनता है। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अहिल्याबाई होल्कर जैसी महान महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार और समाज के निर्माण में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है; वह मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन को संवेदना, संतुलन और संस्कार प्रदान करती है। आज के आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री का सम्मान केवल परंपरा या शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में उन्नत और सभ्य बन सकेगा। बहरहाल, स्त्रियों की गरिमा व सम्मान के क्रम में हाल ही में जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। जब कुछ लोग वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि जैस्मीन सैंडलस एक प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी पंजाबी गायिका और गीतकार हैं, जिन्होंने अपने अलग अंदाज़ और दमदार आवाज़ से संगीत जगत में खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 4 सितंबर 1985 को पंजाब के जालंधर में हुआ और बाद में वह अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में पली-बढ़ीं। उन्होंने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हुईं। बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म %किक% के गीत %यार ना मिले% से मिली। उनके गानों में पॉप, आर एंड बी और पंजाबी फोक का मिश्रण देखने को मिलता है। जैस्मीन न सिर्फ गायिका हैं बल्कि अपने कई गीत स्वयं लिखती भी हैं, और अपनी बेबाक शैली व ऊर्जावान स्टेज परफ़ॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं।जैस्मीन सैंडलस ने संगीत कार्यक्रम के दौरान यह बात साफतौर पर कहीं कि जब तक महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वह मंच पर नहीं गाएंगी। वास्तव में,यह घटना बताती है कि आज भी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। दुख की बात यह है कि ऐसे मामलों में कई लोग सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं।आज आए दिन मीडिया की सुर्खियों में यह खबरें हमें पढ़ने को मिलतीं रहतीं हैं कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को आज अभद्र टिप्पणियों, घूरने, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस, ट्रेन, बाजार, दफ्तर या यहां तक कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी वे असुरक्षा की भावना से घिरी रहती हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि घर से बाहर कदम रखते ही उन्हें अपने कपड़ों, समय और रास्तों तक के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेना पड़ता है।

वास्तव में,यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच की समस्या भी है। जब तक महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता और संवेदनशीलता की भावना समाज में मजबूत नहीं होगी, तब तक केवल सख्त कानून भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएंगे। परिवार, विद्यालय और समाज सभी को मिलकर ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी, जिसमें महिला को स्वतंत्र और सुरक्षित नागरिक के रूप में स्वीकार किया जाए।

संपादकीय

लंबी यात्राएं छोटी हुईं लेकिन गंतव्य और धुंधला हो गया

आज के दौर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आदमी ने रोशनी की रफ्तार से भागना सीख लिया है, पर वह पहुंच कहां रहा है, यह पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता। पुराने जमाने में जब बैलगाड़ियां पगडंडियों पर रेंगती थीं, तब लोगों के पास एक-दूसरे के दुख-सुख बांचने की असीम फुरसत थी।

आज की चमचमाती सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन दूरियों को निगल चुके हैं, फिर भी हर चेहरे पर एक अजीब हताशा है, जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी घड़ियों की सुइयां चुरा ले गया हो। यह आधुनिकता का वह तिलिस्म है, जहां यात्राएं छोटी हो गईं, पर गंतव्य और धुंधला होता गया। यह विकास की वह ऊंचाई है, जहां आक्सीजन तो भरपूर है, पर आदमी को सांस लेने की मोहलत नहीं है।

इतिहास गवाह है कि कभी संयुक्त परिवारों की चौपालों पर बारह-पंद्रह लोगों की बैठकें जमती थीं और किस्से खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। आज के 'स्मार्ट' दौर में घर संकुचित होकर दो कमरों के फ्लैट में सिमट गए हैं, फिर भी सन्नाटा ऐसा कि दीवारें भी आपस में बात नहीं करतीं।

दिलों की दूरी मीलों लंबी

यह विडंबना ही है कि जब संदेश भेजने के लिए कबूतरों या डाकियों का इंतजार होता था, तब रिश्तों में गर्माहट थी। अब जब पलक झपकते ही खबर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, तब दिलों की दूरी मीलों लंबी हो गई है।तकनीक ने हमें वह 'जादुई आईना' तो दे दिया, जिसमें हम सात समंदर पार का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन बगल की कुर्सी पर बैठे इंसान की खामोश चीख सुनने की फुरसत का एक भी लम्हा हमारे पास शेष नहीं रहा।

आज के नवयुवक, जो अपनी अंगुलियों पर पूरी दुनिया नचाने का दावा करते हैं, उनकी कार्यकुशलता देखकर साक्षात विधाता भी चकरा जाएं। एक हाथ से तेज रफ्तार गाड़ी का नियंत्रण और दूसरे हाथ से आभासी दुनिया की खिड़कियों पर अंगुली चलाना- यह कोई करतब नहीं, बल्कि उस 'तनाव' का प्रमाण है, जो आज की मुद्रा बन चुका है।

सड़क के जाम में फंसे लोग जब अपनी निजी लेन बनाने की कोशिश में दूसरों को कुचलने पर उतारू होते हैं, तो लगता है, जैसे वे किसी गंभीर शोध कार्य के अंतिम चरण में हों। असलियत में वे बस उस काल्पनिक दौड़ का हिस्सा हैं, जिसका कोई 'अंतिम बिंदु' नहीं है। उनकी व्यस्तता उस गुब्बारे की तरह है, जो फूला तो बहुत है, पर अंदर सिर्फ खाली हवा है।

मनोरंजन की दुनिया के लिए रातों की नींद कुर्बान

पुराने समय में बैंक के बाहर कतारों में खड़े होकर लोग गांव-जवार की राजनीति से लेकर मानसून तक की चर्चा कर लेते थे। अब जब सब कुछ जेब में रखे उस काले शीशे के टुकड़े में समा गया है, तब इंसान के पास खुद से बात करने का भी अवसर नहीं बचा। अस्पतालों की जांच रपटें अब ईमेल पर तैरती हुई आती हैं, पर उन्हें गौर से देखने का धीरज गायब है।

इंसान ने समय बचाने के लिए मशीनें तो बना लीं, पर उन मशीनों ने इंसान की फुरसत के आखिरी कतरे को भी अपनी बैटरी चार्ज करने में खर्च कर दिया। ये विडंबनाएं तब और भी हास्यास्पद हो जाती हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरह 'स्वस्थ रहने' की चाहत सिर्फ एक 'स्टेटस सिंबल' या हैसियत का प्रतीक बन गई है।

शरीर को साधने की क्रियाओं के लिए जहां वक्त का अकाल पड़ा है, वहीं स्क्रीन पर नाचती हुई मनोरंजन की दुनिया के लिए रातों की नींद कुर्बान है।

माता-पिता का हाल जानने के लिए जब कंठ सूखने लगता है, तब उसे 'व्यस्तता' का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त किसी बेतुकी बहस या

यथार्थ और कल्पना में उलझा बचपन, आभासी दुनिया के जाल में उलझी पूरी पीढ़ी

पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग इलाकों से कई ऐसी खबरें आईं, जिनमें स्मार्टफोन में किसी वीडियो गेम के असर में बच्चों ने जान गंवा दी या फिर गेम खेलने से मना किए जाने पर आत्मघाती कदम उठा लिया। कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं, जिनकी बच्चों को लत लग जाती है और उसमें दिए जाने वाले जोखिम भरे लक्ष्य उनके लिए घातक साबित होते हैं।

हमारे देश में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता कम ही नजर आती है। बच्चों की उदासी को नखरे, चुप्पी को जिद और चिड़चिड़ेपन को स्वभाव मानकर टाल दिया जाता है। बच्चों के साथ संवादहीनता तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा कर सकती है।

ऐसे में बच्चों का अकेलापन उन्हें डिजिटल मंचों पर परोसी जा रही विभिन्न सामग्री की ओर आकर्षित करने लगता है। धीरे-धीरे वे आभासी दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि काल्पनिक और वास्तविकता के बीच अंतर को भी भूल जाते हैं।

विशेषकर आजकल स्मार्टफोन में जिस तरह के आनलाइन खेल परोसे जा रहे हैं, उनसे बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे आभासी दुनिया को ही असलियत समझने लगते हैं और कई बार आत्मघाती कदम तक उठाने को तैयार हो जाते हैं।

पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग इलाकों से कई ऐसी खबरें आईं, जिनमें स्मार्टफोन में किसी वीडियो गेम के असर में बच्चों ने जान गंवा दी या फिर गेम खेलने से मना किए जाने पर आत्मघाती कदम उठा लिया। कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं, जिनकी बच्चों को लत लग जाती है और उसमें दिए जाने वाले जोखिम भरे लक्ष्य उनके लिए घातक साबित होते हैं।

माता-पिता नियंत्रक नहीं, संवादक बनें

भारतीय समाज में अधिकतर माता-पिता यह मान लेते हैं कि अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन के साथ घर के किसी कमरे में है, तो वह सुरक्षित है। मगर उन्हें शायद इस बात का आभास नहीं होता है कि स्मार्टफोन के जरिए पूरी दुनिया उस कमरे में घुस आती है। यहीं नहीं, पढ़ाई, करिअर और अनुशासन पर जोर देते-देते कई बार बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद भी छूट जाता है और यही चूक आगे चलकर जोखिमपूर्ण साबित हो सकती है।ऐसे में जरूरत इस बात की है कि माता-पिता नियंत्रक नहीं, संवादक बनें। बच्चे दिनभर की अपनी गतिविधियों में क्या कर रहे हैं, क्या देख-सुन रहे हैं, यह जानना जरूरी है। अगर बच्चा स्मार्टफोन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे, तो उसके पीछे कारण को समझना भी अति आवश्यक है।

आजकल आभासी दुनिया में ऐसे कई तरह के खेल परोसे जा रहे हैं, जो बच्चों और किशोरों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाते हैं। शुरू में ये खेल बहुत रोचक होते हैं, जिस कारण बच्चा उनमें फंसता जाता है। ऐसे खेलों के प्रति बच्चों का झुकाव उनके भीतर पनप रहे अकेलेपन और उदासी की ओर इशारा करता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे संकेत लंबे समय से चल रहे मानसिक दबाव और भावनात्मक अलगाव का परिणाम होते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह के खेल में ज्यादा रुचि लेने लगे, तो धीरे-धीरे उसे आभासी दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा 'वास्तविक' लगने लगती है।

इन संदर्भों ने एक बार फिर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने बच्चों की बदलती दुनिया को सचमुच समझ पा रहे हैं? क्या हम उनसे इतना संवाद स्थापित कर रहे हैं कि वे बेझिझक अपने मन की उलझन हमसे साझा कर सकें?

आभासी दुनिया के खेलों के जाल में उलझी पूरी पीढ़ी

आभासी दुनिया के खेलों के जाल में उलझे और लत का शिकार होकर गुम होते बच्चों की त्रासदी सिर्फ कुछ परिवारों से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि यह एक समूची पीढ़ी का संकट है, जो वास्तविक दुनिया से कटती जा रही है। जहां भावनाएं 'स्क्रीन' पर व्यक्त होती हैं, रिश्ते आभासी हो जाते हैं और पहचान 'एल्गोरिद्म' गढ़ते हैं। वह भी उम्र के बेहद नाजुक पड़ाव पर!

किशोरावस्था की बात की जाए, तो यह जीवन का वह दौर होता है, जहां भावनाएं तीव्र होती हैं, खुद की पहचान बन रही होती है और उस पहचान की स्वीकृति की भूख सबसे ज्यादा होती है।

इस उम्र में डांट, तिरस्कार या अचानक लगाया गया प्रतिबंध कई बार किशोरों द्वारा अनुशासन नहीं, बल्कि अस्वीकृति के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब ऐसे समय में कोई किशोर खुद को घर, स्कूल या समाज में समझा हुआ महसूस नहीं करता, तो वह किसी ऐसे माध्यम की ओर आकर्षित होता है, जहां उसे लगे कि उसकी भावनाओं को यहां समझा जाएगा। भले ही वह माध्यम आनलाइन खेल, सोशल मीडिया मंच या कोई आभासी समुदाय ही क्यों न हो।

यह समझना बेहद जरूरी है कि आनलाइन खेल या डिजिटल सामग्री सीधे तौर पर आत्मघाती व्यवहार का कारण नहीं होते। उनकी ओर आकर्षित होना एक संकेत होता है; मन के भीतर चल रही बेचैनी का, जिसे बच्चा शब्दों में कह नहीं पाता।

जब आनलाइन खेल या आभासी दुनिया ही दोस्त, पहचान और भावनात्मक सहारा बन जाए, तब समस्या गहरी हो जाती है। वहां जीत-हार और आभासी सराहना असली जीवन की चुनौतियों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि बिना संवाद और समझ विकसित किए बगैर, बच्चों या किशोरों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर अचानक रोक लगा दी जाए, तो वे खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हैं।

हालांकि, आज के तकनीकी दौर और इस उम्र में आभासी दुनिया की सामग्री से प्रभावित होना स्वाभाविक है, मगर समस्या तब पैदा होती है, जब यह आकर्षण वास्तविक जीवन से पलायन का माध्यम बन जाता है। कुछ किशोर खुद को उस काल्पनिक दुनिया में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां भावनाएं सुंदर दिखती हैं, रिश्ते आदर्श लगते हैं और संघर्ष 'टास्क' दिखते हैं। धीरे-धीरे वास्तविक जीवन उन्हें कठोर, अस्वीकारात्मक और बोझिल लगने लगता है। यही प्रवृत्ति कई बार जोखिम में डाल देती है।

स्मार्ट फोन या लैपटाप के इस्तेमाल की समय सीमा निर्धारित की जाए

ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के लिए स्मार्ट फोन या लैपटाप के इस्तेमाल की समय सीमा निर्धारित की जाए। मगर, उनके साथ भावनात्मक समय बिताना, डांटने से पहले सुनना और रोकने से पहले समझना भी उतना ही जरूरी है। स्कूलों की भूमिका भी केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं रह सकती। आज जरूरत है कि स्कूलों में डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाए।बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि डिजिटल मंचों पर मौजूद तमाम सामग्री हमेशा सच या वास्तविकता नहीं होती। उनमें फर्क करने का विवेक बच्चों के भीतर विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी यह समझने की जरूरत है कि किसी बच्चे का अक्सर चुप रहना, अलग-थलग रहना या पढ़ाई से कट जाना आलस्य नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे संघर्ष के संकेत हो सकते हैं।

आभासी दुनिया में बच्चों के लिए परोसी जा रही सामग्री में उम्र के अनुसार सुरक्षा, अभिभावकों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही प्राथमिकता देनी होगी।

डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश संवाद से बेहतर हो सकती है

डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश केवल नियमों से नहीं, बल्कि संवाद और आपसी समझ से ही बेहतर हो सकती है। स्मार्टफोन बंद कराया जा सकता है, लेकिन मन नहीं। खेल हटाया जा सकता है, लेकिन अकेलापन तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि हम संवेदनशीलता को केंद्र में नहीं रखेंगे।

मोबाइल, नशा और तनाव - बचपन पर तीन वार,

डॉ. विजय गर्ग

आज का बचपन तीन अदृश्य वार झेल रहा है—मोबाइल की लत, नशे का बढ़ता प्रचलन और तनाव का असामयिक बोझ। कभी जो बचपन खिलौनों, खेल के मैदानों और खुली हंसी में बीतता था, वह आज स्क्रीन की रोशनी, सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के दबाव में सिमटता जा रहा है। प्रश्न यह है कि यदि हमारे बच्चे खतरे में हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है?

मोबाइल: सुविधा से लत तक

मोबाइल फोन आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, जानकारी और संचार के लिए यह उपयोगी साधन है। लेकिन जब

यही साधन बच्चों के हाथों में अनियंत्रित रूप से पहुंच जाता है, तो वह मनोरंजन से अधिक लत का माध्यम बन जाता है।

घंटों तक गेम खेलना, सोशल मीडिया पर तुलना करना, देर रात तक स्क्रीन देखना—ये सब बच्चों की नींद, आंखों, मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। वास्तविक मित्रता की जगह वर्चुअल संबंध ले लेते हैं। परिणामस्वरूप बच्चा धीरे-धीरे परिवार और समाज से कटने लगता है।

नशा: जिज्ञासा से विनाश तक

किशोरावस्था जिज्ञासा और प्रयोग का समय होती है। यदि इस समय सही मार्गदर्शन न मिले तो बच्चे तंबाकू, शराब या अन्य नशे की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कई बार यह शुरुआत 'सिर्फ एक बार' से होती है, जो आगे चलकर आदत बन जाती है।नशा न केवल शरीर को कमजोर करता है, बल्कि आत्मविश्वास, चरित्र और भविष्य को भी प्रभावित करता है। यह परिवारों को तोड़ देता है और समाज को खोखला करता है।

तनाव: बचपन से पहले ही बोझ

आज के बच्चे पढ़ाई, प्रतियोगिता और अपेक्षाओं के दबाव में जी रहे हैं। अंक और रैंक उनकी पहचान बन गए हैं। माता-पिता और समाज की ऊँची उम्मीदें कई बार बच्चों पर असहनीय दबाव डाल देती हैं।

तनाव के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और कभी-कभी आत्मघाती विचार तक पनप सकते हैं। बचपन, जो सहजता और आनंद का समय होना चाहिए, चिंता और भय का कारण बन रहा है।

1. परिवार:

बच्चों को मोबाइल देकर चुप कराना आसान समाधान है, लेकिन इसके दूरगामी दुष्परिणाम हैं। यदि माता-पिता स्वयं स्क्रीन में डूबे रहें, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। संवाद की कमी और समय का अभाव बच्चों को गलत दिशाओं में ले जा सकता है।

2. समाज और मित्र मंडली:

साथियों का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। यदि परिवेश स्वस्थ नहीं है, तो बच्चा जल्दी प्रभावित हो सकता है।

3. शिक्षा प्रणाली:

केवल अंकों पर आधारित शिक्षा बच्चों में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ाती है, पर जीवन कौशल, नैतिकता और मानसिक संतुलन की शिक्षा पीछे छूट जाती है।

4. तकनीकी और मनोरंजन उद्योग:

ऐप्स और गेम्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता अधिक से अधिक समय स्क्रीन पर बिताए। बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता है।

समाधान की दिशा

घर में डिजिटल अनुशासन तय किया जाए—स्क्रीन टाइम सीमित हो।

बच्चों के साथ खुला संवाद और गुणवत्तापूर्ण समय बिताया जाए।

खेल, संगीत, पुस्तकें और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श की व्यवस्था हो। नशे के विरुद्ध जागरूकता और सख्त सामाजिक संदेश दिए जाएं।

निष्कर्ष

बचपन राष्ट्र की नींव है। यदि यह नींव ही कमजोर हो जाए तो भविष्य भी डगमगा जाएगा। मोबाइल, नशा और तनाव—ये तीनों मिलकर बच्चों के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

ज़िम्मेदार केवल कोई एक नहीं—परिवार, समाज, शिक्षा व्यवस्था और हम सभी हैं। यदि हम समय रहते सचेत हो जाएं, तो बचपन को फिर से मुस्कुराने का अवसर मिल सकता है।

बच्चों को केवल संसाधन नहीं, समय, संस्कार और संवेदना दीजिए—तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

शब्दों का फेर या कूटनीतिक जीत? बाध्यकारी शर्तों से मुक्त हुआ भारत, अमेरिका ने बदला रुख

मगर भविष्य में भारतीय कृषि और किसानों पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई गई। अब अमेरिका की ओर से जारी नए तथ्य-पत्र में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया है। मसलन, समझौते के प्रारूप में पहले जहां भारत की ओर से पांच सौ अरब डालर से अधिक मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदने को 'प्रतिबद्धता' बताया गया था।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का अंतिम स्वरूप में पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच इसके अहम बिंदुओं के नफे-नुकसान के मसले पर जो बहस चल रही है, उसके असर भी सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के शुरुआती स्वरूप में कई अन्य अमेरिकी वस्तुओं सहित कुछ दालों पर भी भारत की ओर से शुल्क कम या समाप्त करने की खबर आई थी।

मगर भविष्य में भारतीय कृषि और किसानों पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई गई। अब अमेरिका की ओर से जारी नए तथ्य-पत्र में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया है। मसलन, समझौते के प्रारूप में पहले जहां भारत की ओर से पांच सौ अरब डालर से अधिक मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदने को 'प्रतिबद्धता' बताया गया था।

संशोधन में क्या-क्या?

वहीं संशोधित संस्करण में इसे खरीदने के 'इरादे' के रूप में पेश किया गया है। यानी यह नियम अब भारत के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा, संशोधन के बाद समझौते के प्रारूप में से कई कृषि वस्तुओं, खासकर दालों को इस सूची से बाहर करने की खबर है। इसके बाद स्वाभाविक ही भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिका की ओर से खड़ी होने वाली प्रतिस्पर्धा से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यों भी, भारत दालों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

इसी वजह से खासतौर पर दालों को किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा माना जाता रहा है। हाल ही में जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में सहमति के स्तर तक पहुंचने की खबरें आई थीं, तब अमेरिका की ओर से शुल्क अठारह फीसद करने सहित इसके सकारात्मक पहलुओं की खासी चर्चा हुई थी। मगर कृषि तथा अन्य उत्पादों के संबंध में भारत के रुख को लेकर कई तरह की चिंता भी उभरी थी।

विपक्ष ने लगाए आरोप

यह आशंका जताई गई कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं को भारत में निर्बाध छूट दी गई, तो यहां के कृषि क्षेत्र पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसीलिए किसानों की ओर से विरोध के स्वर भी उभरे। विपक्षी दलों ने भी ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।

इन उतार-चढ़ावों के बीच व्यापार समझौते के प्रारूप में अब जिन बदलावों की खबर आई है, वह भारत के लिए सकारात्मक और राहत की बात साबित हो सकती है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी साझेदारी कसौटी पर तभी उचित साबित हो सकती है, जब इसमें परस्पर और समान हित पर आधारित शर्तें शामिल हों। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में अमेरिका और भारत की स्थिति को एक समान आधार पर नहीं देखा जा सकता।

इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते में संतुलन के कारक संदर्भों पर निर्भर करेंगे। भारत अगर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार बिना कोई शर्त लगाए खोलता है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके सामने प्रतिस्पर्धा एक चुनौती बन कर खड़ी हो सकती है। तमाम चिंता के बीच अमेरिका के साथ जारी बातचीत में भारत के कृषि क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।

अब संशोधन के बाद अगर दोनों देशों के हित को सुनिश्चित करने वाली संतुलित नीतियां आकार ले पाती हैं, तब व्यापार समझौता भारत के लिए भी लाभकारी होगा। फिलहाल समझौते की शर्तों में अमेरिका की ओर से जो बदलाव किए गए हैं, वे अब आगे की वार्ता में एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की गरिमा का होता हनन और एक कलाकार की दहाड़

गायिका ने अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकते हुए कहा कि जब तक लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वे नहीं गाएंगी। उनके इस कदम की सभी ने सराहना की। यह दुखद ही है कि महिलाओं को तंग किए जाने पर सैंडलस को सुरक्षाकर्मियों से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन उन्होंने गाने से इनकार कर न केवल महिलाओं के आत्मसम्मान का सवाल उठाया, बल्कि वैसे लोगों को भी आईना दिखाया, जो भीड़ का हिस्सा बन कर अभद्रता करते हैं

घर से लेकर कार्यस्थल तक और यहां तक कि सार्वजनिक जगहों पर भी कुछ लोग स्त्रियों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की इस गंभीर क्षति को रोकने का प्रयास कम ही दिखता है। मगर पिछले दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित संगीत कार्यक्रम में महिलाओं को परेशान किए जाने की घटना को पंजाबी गायिका जैस्मीन सैंडलस ने गंभीरता से लिया।

गायिका ने अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकते हुए कहा कि जब तक लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वे नहीं गाएंगी। उनके इस कदम की सभी ने सराहना की। यह दुखद ही है कि महिलाओं को तंग किए जाने पर सैंडलस को सुरक्षाकर्मियों से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन उन्होंने गाने से इनकार कर न केवल महिलाओं के आत्मसम्मान का सवाल उठाया, बल्कि वैसे लोगों को भी आईना दिखाया, जो भीड़ का हिस्सा बन कर अभद्रता करते हैं।

सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिसकर्मियों पर भी होता है। मगर सवाल है कि कौन होते हैं वे लोग, जिनसे महिलाओं को बचाने की जरूरत पड़ती है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि कुछ कुंठित पुरुषों की वजह से अमूमन हर जगह महिलाओं के सामने खुद को सुरक्षित रखने या बचाने का सवाल ही प्राथमिक होता है?आज भी अपने घर के आसपास, गली-मोहल्ले से लेकर सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान महिलाओं को प्रायः अभद्रता का सामना करना पड़ता है। किसी संगीत कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वहां वे महिलाओं या लड़कियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मगर दिल्ली के संगीत कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोगों को न तो महिलाओं के सम्मान की फिक्र थी, न ही खुद को असभ्य कहे जाने की।विडंबना यह है कि महिलाओं की गरिमा पर चोट पहुंचाते हुए देखने के बावजूद ज्यादातर लोग चुप रहना ही चुनते हैं। ऐसे में गायिका जैस्मीन सैंडलस ने महिलाओं की गरिमा के हक में और उनके उत्पीड़न के खिलाफ जो सशक्त प्रतिरोध दर्ज किया है, वह समूचे समाज के लिए एक सबक की तरह है

अमृत विचार

शनिवार, 14 फरवरी 2026

सपने वो नहीं हैं, जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं, जो आपको सोने नहीं देते।

–एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति

बहुप्रतीक्षित निर्णय

रक्षा खरीद परिषद द्वारा 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी से वायुसेना की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उम्मीद है कि अगले तीन साल के भीतर ही हमें शुरुआती तौर पर विमानों की आपूर्ति होने लगे और सात साल के भीतर ही हम देश में ही 60 फीसद स्वदेशी कल पुर्जों से राफेल विमान बनाने भी लगें। ऐसे में यह सौदा हमारी हवाई शक्ति को पुनर्स्थापित करने के साथ स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी गति देगा। रक्षा आधुनिकीकरण, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला यह कदम वैश्विक सुरक्षा संरचना में भारत की भूमिका को मजबूत करने, फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग गहराने के अलावा सामरिक संतुलन और वैश्विक रक्षा साझेदारियों के पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे सैन्य क्षमता में ही नहीं भारत की रक्षा-उद्योग प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ेगा।

सौदे में राफेल के अलावा 6 पी-8आई समुद्री टोही विमान, तकनीकी हस्तांतरण सहित रूसी आईएल-76एमडी-90ए परिवहन विमान, टी-72 टैंक, एयरशिप हाई एल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट, एंटी-टैंक माइंस और डोर्नियर विमान भी शामिल हैं। ये सेना की लॉजिस्टिक, टोही एवं युद्ध क्षमता को मजबूत करेंगे, विशेषकर लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में। कुल मिलाकर तीनों सेनाओं का एकीकरण बढ़ेगा तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है कि सौदा अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के समक्ष जाएगा, जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े मामलों पर स्वीकृति प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज़ रहती है पर आमतौर पर तकनीकी-वित्तीय समीक्षाएं और विस्तृत वार्ता हुआ महीने लग जाते हैं, पर इस बार देरी की आशंका कम है, क्योंकि एक तो उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, दूसरे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी दो दिन बाद ही आने वाले हैं, जो इस पर हस्ताक्षर करेंगे, हालांकि इस श्रेणी के युद्धक विमानों की खरीद का प्रस्ताव 13 साल पहले दिया गया था, पर वित्तीय और नीति निर्णयों में इतनी जटिलता थी कि कई दौर की समीक्षा और लागत-लाभ गहन विचार के बावजूद बात सिरे नहीं चढ़ सकी थी। कभी मेक-इन-इंडिया और तकनीकी हस्तांतरण पर विवाद तो कभी कोविड के दौर और उसके बाद वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां, रक्षा क्षेत्र की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में देरी ने इस सौदे को लंबित रखा, जबकि स्क्वाड्रन संख्या की कमी लंबे समय से वायुसेना के लिए लगातार चिंता का विषय थी। 2016 में हुई 36 विमानों की खरीद वाली पहली राफेल डील के बावजूद भारत की वायु सेना 42 स्क्वाड्रनों की अधिकृत ताकत के मुकाबले लगभग 29 स्क्वाड्रनों के स्तर पर काम कर रही है।

इस सौदे के बाद वायु सेना को एयर सुपीरियोरिटी और 'स्टैंड-ऑफ' स्ट्राइक क्षमता में इज़ाफ़ा होगा, समुद्री निगरानी और समुद्र में सामरिक क्षमता को बल मिलेगा। अलग-अलग सैन्य क्षेत्रों में आधुनिक उपकरण से समग्र शक्ति में वृद्धि होगी। विमान निर्माण में 60 फीसदी ऐसे स्थानीय सामग्री और स्वदेशी कल पुर्जे के इस्तेमाल जिनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों और फ्रांसीसी तकनीक-प्रशिक्षण नियंत्रणों के तहत सुनिश्चित होगी, दूरगामी निर्णय है। इससे भारत के रक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी क्षमता विकसित होगी।

आस्था से तर्क की ओर बढ़ती दुनिया

राजेश श्रीनेत
वरिष्ठ पत्रकार

विश्व में नास्तिकता अथवा अनीश्वरवाद का प्रसार अब केवल बौद्धिक या दार्शनिक विमर्श का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आधुनिक समाजों में हो रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का संकेतक बन चुका है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक तक आते-आते अनेक देशों में ईश्वर में पारंपरिक आस्था कमजोर पड़ी है और स्वयं को नास्तिक, अज्ञेयवादी या किसी संगठित धर्म से असंबद्ध बताने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे शिक्षा का विस्तार, वैज्ञानिक चेतना, तकनीकी विकास, शहरीकरण और धार्मिक संस्थाओं के प्रति घटता विश्वास जैसे कई कारण रहे हैं।

आंकड़े इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। अमेरिका में इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, जहां लगभग छठा हिस्सा आबादी का स्वयं को किसी धर्म से असंबद्ध बताता था, वहीं हाल के वर्षों में यह अनुपात लगभग एक तिहाई तक पहुंच गया है। यूरोप के कई देशों में स्थिति इससे भी आगे निकल चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में नियमित धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वालों की संख्या लगातार घट रही है और बड़ी आबादी ईश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं मानती। स्कैंडिनेवियाई देशों में तो लगभग आधी आबादी स्वयं को नास्तिक या धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़ती है।

इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। भारत को प्रायः एक गहरे धार्मिक समाज के रूप में देखा जाता है, जहां धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक जीवन का आधार है। यहां विवाह, जन्म, मृत्यु और पर्व-त्योहार सभी धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं। इसके बावजूद आधुनिक भारत में भी नास्तिकता और धार्मिक असंबद्धता की प्रवृत्ति धीरे-धीरे उभर रही है।

उत्तरी यूरोप के देशों में, जहां नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को धर्म से अलग करके देखा जाता है, वहीं भारत में नैतिकता को अक्सर धार्मिक मूल्यों से जोड़ दिया जाता है। यह अंतर नास्तिकता की स्वीकार्यता को भी प्रभावित करता है। स्वीडन या डेनमार्क जैसे देशों में नास्तिक होना सामाजिक रूप से सामान्य और स्वीकार्य है, जबकि भारत में नास्तिकता अब भी संदेह या सामाजिक दूरी का कारण बन सकती है। इसके बावजूद शहरी और शिक्षित वर्गों में ईश्वर और धर्म को लेकर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है।

पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत की तुलना भी रोचक है। चीन में बड़ी आबादी स्वयं को किसी धर्म से नहीं जोड़ती, क्योंकि वहां लंबे समय से राज्य व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में संगठित धर्म की भूमिका सीमित रही है। जापान में धार्मिक परंपराएं सांस्कृतिक रूप में मौजूद हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ईश्वर में विश्वास अपेक्षाकृत कमजोर है। भारत में इसके विपरीत धार्मिक आस्था व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर गहराई से जुड़ी है, हालांकि नई पीढ़ी इस संबंध को पुनः परिभाषित कर रही है।

वैश्विक सामाजिक सर्वेक्षण यह संकेत देते हैं कि युवा पीढ़ी अपने माता-पिता की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक विचारों वाली है। यह प्रवृत्ति भारत में भी दिखाई देने लगी है। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और महानगरों में रहने वाले युवाओं के बीच संगठित धर्म से दूरी बढ़ रही है। वे स्वयं को धार्मिक कहने के बजाय तर्कवादी, वैज्ञानिक सोच वाला या केवल सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ मानना अधिक सहज समझते हैं, हालांकि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण यह दूरी अक्सर सार्वजनिक पहचान का रूप नहीं ले पाती।

वहीं भारत की एक विशिष्टता यह भी है कि यहां नास्तिकता कोई विदेशी या आधुनिक अवधारणा नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में चार्वाक जैसे भौतिकवादी विचारक मौजूद रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर और परलोक की अवधारणाओं को अस्वीकार किया। बौद्ध और जैन दर्शन में भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की केंद्रीय भूमिका नहीं मिलती। इसके बावजूद आधुनिक भारत में नास्तिकता को प्रायः पश्चिमी प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जिससे इसकी सामाजिक स्वीकार्यता सीमित रह जाती है।

शिक्षा का प्रभाव इस तुलना को और स्पष्ट करता है। पश्चिमी देशों में जैसे-जैसे शिक्षा और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का स्तर बढ़ा, वैसे-वैसे धार्मिक आस्था में गिरावट आई। भारत में शिक्षा के विस्तार के बावजूद यह गिरावट उतनी तेज नहीं रही। यहां विज्ञान और धर्म अक्सर साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं। एक ही व्यक्ति वैज्ञानिक सोच में विश्वास भी रखता है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेता है। यह द्वैत भारतीय समाज की जटिलता और बहुस्तरीय चरित्र को दर्शाता है।

तकनीक और इंटरनेट ने भारत में नास्तिकता और तर्कवाद को नई आवाज दी है। सामाजिक माध्यमों और डिजिटल मंचों के माध्यम से धार्मिक मान्यताओं पर खुली बहस संभव हो पाई है। पहले जो प्रश्न सीमित बौद्धिक दायरों में रहते थे, वे अब आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद सामाजिक संरचना और पारिवारिक अपेक्षाएं अब भी इतनी मजबूत हैं कि नास्तिकता को खुली पहचान के रूप में अपनाना आसान नहीं है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि नास्तिकता के बढ़ने का अर्थ नैतिकता या सामाजिक जिम्मेदारी का क्षरण नहीं है। कई कम धार्मिक समाजों में सामाजिक सुरक्षा, कानून का पालन और नागरिक सहयोग का स्तर ऊंचा पाया गया है। भारत के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां अक्सर नैतिक मूल्यों को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। बदलते समय में यह समझ विकसित हो रही है कि नैतिकता का आधार केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, शिक्षा और सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं।

> बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक तक आते-आते अनेक देशों में ईश्वर में पारंपरिक आस्था कमजोर पड़ी है और स्वयं को नास्तिक बताने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है।

सोशल फोरम

बलेसरा काहें बिकाला

दयानंद पांडेय
ब्लॉगर

जैसे कोई नरम और मीठी ऊंख हो। एक गुल्ला छीलिए तो पोर खुल जाए। कुछ वैसे ही मीठी, नरम और फोफर आवाज बलेसरा की है। अपनी गमक, माटी की महक और एक खास ठसक लिए हुए। बलेसरा मतलब बालेश्वर। आठवीं तक पढ़े बालेश्वर का नाम आज की तारीख में भोजपुरी लोक गायकी में शिखर पर है। उनकी गायकी में ही कहें तो, 'आज बलेसरा बिकाला।' इसी बलेसरा से जब पूछा कि 'तू गायक नाईं होत न का होत?' तो वह बोले, खेती-मजूरी करतीं और का होतीं? दरअसल तथ्य भी यही है कि बलेसरा की लोक गायकी की यात्रा सुविचारित तो नहीं है। वह छूटते ही कहते हैं, 'कोई गुरु नहीं।'

तो सीखा कैसे? -बस गाते गाते। और शिष्य? -शिष्य मानता ही नहीं किसी को।' फिर भी हमारे गाने बहुत लोग गाते हैं।

बलेसरा ने बचपन में गायकी की यात्रा शुरू की नकल कर-कर के। वह कहते हैं, 'गांव में शादी ब्याह में, रामलीला, नौटंकी में गाना शुरू किए। कलाकारों की कॉपी करना शुरू किया।'

किन कलाकारों की?

-भोजपुरी लोक गायकों की। जैसे वलीउल्लाह थे, जयश्री थे। हमने न सिर्फ इनकी कॉपी की, बल्कि कोशिश की कि इन की टीम में आ जाऊं। पर इन लोगों ने अपनी टीम में हमें नहीं लिया। गावों के मंचों पर चंग बजा-बजा कर अकेले ही गाना शुरू किया। पैसे कुछ भी नहीं मिलते थे। खाली वाहवाही मिलती थी।' जिला पोस्ट मधुबन गांव बदनपुर में पहली जनवरी, 1942 में जनमे बालेश्वर वाहवाही से ही खुश थे कि उन का नाम होने लगा था।

लखनऊ आ कर काफी भटका। मैंने लखनऊ में ही गली-चौराहों पर भटकना ठीक समझा। इधर-उधर घूम-घाम गाता रहा। 1965 में आकाशवाणी लखनऊ में गाने के लिए इम्तेहान दिया, लेकिन फेल हो गया। अनुभव नहीं था। मेरी परेशानी बढ़ती गई। तभी एक छोटी सी नौकरी कर ली। गाना फिर भी नहीं छोड़ा। बाद में सूचना विभाग के केबी चंद्रा ने बताया कि आकाशवाणी का इम्तहान कैसे दूं। फिर दस बरस बाद दोबारा आकाशवाणी लखनऊ में इम्तहान दिया तो पास हो गया। आकाशवाणी पर हमारी बुलंद आवाज जब छा गई तो कई और लोग भी मौका देने को तैयार हो गए। हरवंश जायसवाल ने सरकारी प्रोग्राम में हम से चार साल तक कार्यक्रम करवाया। अब कार्यक्रमों से पैसा तो मिलने लगा था, नाम-मात्र का ही सही पर वाहवाही खूब मिलती थी और मैं खुश था। -फेसबुक वॉल से

प्रसंगवश

मदनोत्सव को विस्मृत कर दिया वेलेंटाइन डे ने

बीते कुछ वर्षों में मदनोत्सव की परंपरा पर विस्मृति की परत कुछ ऐसी जमीं कि करीब दो दशक पूर्व रोम से आकर वेलेंटाइन बाबा प्रेम का संदेश देने लगे हैं। वैलेंटाइन डे को पैसा बरसाने का माध्यम बना दिया है। यानी प्यार आज एक बाजार का रूप ले चुका है। इसमें दोष बाबा वेलेंटाइन का तो कतई नहीं है। दोष उन उर्वर दिमागों का है, जिन्हें बाजारवाद के मौजूदा दौर में यह भली-भांति पता है कि दिल का सौदा सिर्फ लेन-देन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी बदौलत चोखा मुनाफा कमाया जा सकता है।

कहते हैं प्यार दिलों को जोड़ता है, पर बिकता भी यही है। शायद संत वेलेंटाइन का दिल इस बात को सुनकर टूट जाए, पर बाकी लोगों को इससे क्या, वे तो पूरा मजा ले रहे हैं। 14 फरवरी, वेलेंटाइन डे का जिक्र आते ही युवा दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दिलो-दिमाग में कल्पनाओं को नए पंख मिल जाते हैं और मन प्रणय की नई उड़ान भरने लगता है। शोशेबाजी में डूबी इस नई पीढ़ी का झुकाव दिखावे की तरफ देखकर ही व्यापारियों ने मध्ययुगीन पश्चिमी परंपरा को प्यार के देसी कारोबार में तब्दील कर दिया है। प्रेम तो किसी से भी, कैसे भी और कभी भी हो सकता है। प्रेमी अपने दिल की बात आसानी से कह सकें, इसलिए प्रणय निवेदन का एक खास दिन नियत किया गया होगा।

दीपक नौगाई
लेखक

हमारे देश में बसंत के मौसम में मदनोत्सव हुआ करता था। बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। मदन का अर्थ है काम का देवता। महोत्सव प्रेमियों के चरम उत्कर्ष की परिणिति हुआ करता था, क्योंकि अपनी परंपराओं को भुला दिया गया, इसलिए 90 के दशक में उदारीकरण के नाम पर बाजारवाद को मुख्य दरवाजे से बुलाया गया, तो खिड़की से बाजारू प्रवृत्तियों ने वेलेंटाइन बाबा को भी बुला लिया, इसलिए मदनोत्सव की परंपरा तो अब पहले जैसी दिखती नहीं, लेकिन वेलेंटाइन डे जरूर अपने पूरे यौवन के साथ फल-फूल रहा है।

वेलेंटाइन बाबा का प्रेम संदेश पूरी मानव जाति के लिए था और उसे केवल दो प्रेमियों के प्रणय के मध्य सीमित नहीं किया जा सकता, इसलिए वेलेंटाइन डे को बहुत सादगी से मनाया जाना और सभी को प्रेम संदेश देना ही प्रेम के उस मसीहा का सम्मान करना माना जाता है। 14 फरवरी का प्रेम पर्व बाबा वेलेंटाइन तथा देशी मदनोत्सव को जानने और मनाने का भी है।

यह बहुत ही सादगी पूर्ण और प्यारा सा त्यौहार है। इसे संत वेलेंटाइन को याद कर मनाया जाना चाहिए, जिन्होंने प्यार के सम्मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन इसके विपरीत हमारे यहां वेलेंटाइन डे की पवित्रता का मजाक उड़ाया जाता है। इसकी वजह सिर्फ दुस्साहसी प्यार का बढ़ता चलन ही नहीं है, देसी बाजार की समझ रखने वाले बड़े माहिर अंदाज में वेलेंटाइन डे को भुनाने लगे हैं। सच्चे प्यार का अर्थ उपहारों या प्रतीकों के आदान-प्रदान तक सीमित होकर रह गया है और वेलेंटाइन की फिज़ा पूरी मदहोशी के साथ सोशल मीडिया, टीवी और उपहारों की दुकानों में नजर आती है।

प्यार ने जब बाजार का रूप ले लिया है, तो लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि प्रेम का इजहार करने के लिए महंगे उपहारों की जरूरत होती है। साथ में यह भावना भी कि यदि आपका प्रेमी आपको कीमती उपहार नहीं दे सकता, तो उसे छोड़कर दूसरा प्रेमी चुन लीजिए। इस तरह का संदेश हमारी सामाजिक मान्यताओं को तो चोट पहुंचा ही रहा है, लोगों को बाजारवाद की दौड़ में शामिल होने के लिए आकर्षित भी कर रहा है।

आमने सामने

हरियाणा में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर पेंशन डबल की जाएगी। भाजपा सरकार ने केवल लगातार बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, बल्कि नवंबर से अब तक बढ़ी हुई पेंशन भी नहीं दी गई है। अभी तक एक लाख से अधिक लोगों की पेंशन काटी जा चुकी है।

-अभय सिंह चौटाला
राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनेलो

जब उनकी सरकार आएगी तब वे अपने वादे पूरे कर लें। अभी तो हालात ऐसे हैं कि 'न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी'। यानी फिलहाल यह केवल बयान के अलावा और कुछ नहीं है।

-कृष्ण बेदी
काबीना मंत्री
हरियाणा सरकार

चंबल के दस्यु जैसे ही हैं डिजिटल डकैत

अजय दयाल
हल्द्वानी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साइबर ठगी के जरिए लूटी गई रकम के आपराधिक कृत्य को यूं ही डकैती नहीं करार दिया। किसी का घर बैठे उसके मेहनत की बड़ी कमाई लुट जाना वाकई डकैती ही है। आज भले दृश्य चंबल के डाकुओं जैसा न हो पर डिजिटल दुनिया के नये डाकू आपराधिक कृत्य ठीक वैसा ही कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि घर में दरवाजा तोड़ कर नहीं घुस रहे, हथियार के बल पर धमका कर आबरू, गहना, दौलत लूटना या मर्डर नहीं कर रहे, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि किसी को डिजिटल अरेस्ट कर, वही सब कुछ अनैतिक, आपराधिक कर रहे हैं, जैसा कि चंबल के दस्यु किया करते थे।

अब वीडियो कॉल पर किसी स्त्री-पुरुष का चारित्रिक हनन करने के नाम वसूली क्या है? अब तो डिजिटल रेप की भी शब्दावली आम होती जा रही है। वहीं, डिजिटली बंधक बनाकर किसी की जमा-पूंजी लूट लेना क्या है? और जिसका यह सब कुछ लुट जाए उसकी सदमे से मृत्यु हो जाना अथवा उसका सुसाइड कर लेना क्या हत्या नहीं? दरअसल, साइबर ठगी किसी व्यक्ति या परिवार को केवल आर्थिक रूप से ही चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि इस कारण उसे मानसिक आघात भी पहुंचता है और सामाजिक दुर्गति हो जाती है। यहां तक कि ऐसे कारणों से उसकी मृत्यु तक हो जाना वाकई गंभीर और दुखदायी है।

यानी ऐसी वारदातों के चलते जीवन भर की जमा-पूंजी, रिटायरमेंट फंड या बच्चों की शिक्षा के लिए रखे पैसे एक झटके में चले जाते हैं, जिससे परिवार कर्ज में डूब जाता है। पीड़ित शख्स और उसके परिजन अक्सर गहरे सदमे, अवसाद में चले जाते हैं, आत्म-दोष महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, तमाम मामलों में पीड़ित परिवार आपसी झगड़ों और अलगाव का शिकार बन जाते हैं। डिजिटल क्राइम के शिकार का समाज में मजाक बनने लगता है, उसे लोग मूर्ख तक करार देने लगते हैं। यही कारण है कि इस भय से कई लोग इसकी पुलिसिया रिपोर्ट तक कराने की हिम्मत नहीं जुटाते कि बात सार्वजनिक होगी और लोग मजाक बनाएंगे। वास्तव में यह स्थिति भुक्तभोगी को अंदर से खोखला कर देती है।

एक रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल डकैतों ने हमारे देश में बीते साढ़े चार सालों में साइबर ठगी के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की रकम लूटी है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि देश के कई छोटे राज्यों का वार्षिक बजट भी इसके मुकाबले कम है। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी भयावह स्थिति पर चिंता प्रकट की और साफ शब्दों में कहा कि यह कृत्य महज धोखाधड़ी नहीं, बल्कि 'खुलेआम डकैती' है।

अदालत ने बैंकों की भी कार्यशैली पर कटाक्ष किया। कहा कि डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसकर जो ग्राहक बड़े लेन-देन कर देते हैं, उसके लिए बैंक भी जिम्मेदार हैं। कायदे से बैंकों को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए कि बड़ा लेनदेन समय रहते तत्काल चिन्हित हो सके। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में एक व्यावहारिक और उदार नजरिया अपनाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष भी पूरे होमवर्क के साथ किया। मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक, अगर कोई बड़ी व्यापारिक कंपनी करोड़ों का लेन-देन करती है, तो यह सामान्य प्रक्रिया हो सकती है और माना जा सकता है कि बैंक की व्यवस्था उस पर संदेह न करे, लेकिन जब कोई आम ग्राहक, जो आमतौर पर केवल 10 हजार या 20 हजार रुपये निकालता है, अचानक 25 लाख या 50 लाख रुपये का लेन-देन करने लगे, तो ऐसे में बैंकों को 'अलर्ट' जारी करना चाहिए। ऐसा अलर्ट जारी करने में बैंकों में लगे एआई टूल्स कब काम आएंगे।

ग्राहकों को सतर्क, सावधान करने संबंधी संदेश बैंकों और केंद्र की सुरक्षा इकाइयों के माध्यम से चलते रहते हैं। बस इन जागरूकता फैलाने वाले संदेशों को अमल में भी लाने की आवश्यकता है। जैसे कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है, संदेह होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करना है या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी है वगैरह-वगैरह। यही नहीं अगर आप या आपका परिचित ऐसे किसी घटनाक्रम का शिकार होकर डिप्रेशन में जा रहा है, तो हेल्पलाइन–निमहांस (एनआईएमएचएएनएस) जैसे संसाधनों से सहायता भी ली जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरबीआई, बैंकों और दूरसंचार विभाग जैसी इकाइयों के साथ मिलकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (एसओपी) बनाने को कह दिया है। पिछले साल दिसंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अपराधियों द्वारा देश से बाहर भेजी जा रही भारी-भरकम धनराशि पर भी चिंता प्रकट की थी। उस वक्त भी अदालत ने केंद्र सरकार से 'एमिकस क्यूरी' (अदालती मित्र) द्वारा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के सुझावों पर विचार करने को कहा था।

> डिजिटल ठगी करने वाले दुनिया के नए डकैत हैं। बस वो घर का दरवाजा तोड़ कर नहीं घुस रहे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट कर चंबल के दस्यु जैसा ही काम कर रहे हैं।

सामयिकी

'फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम' से भारतीय भी प्रभावित

जितना स्क्रीन टाइम, उतना बड़ा नुकसान, लेकिन चिकित्सा से जुड़ी नई रिसर्च रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। रिसर्च बताती है कि मोबाइल या स्क्रीन का अत्याधिक प्रयोग ने नाना प्रकार की स्वास्थ्य बीमारियों को परोसना आरंभ कर दिया है, जिससे दृष्टि हानि, मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित विकार, अजीब किस्म के कैंसर लक्षण और मोटापा जैसी दीर्घकालिक समस्याओं के होने का पता चला है। 10 मुल्क इस समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

गाजियाबाद जिला अस्पताल की इस रिपोर्ट में स्मार्टफोन को सिरहाने रखकर सोने को सबसे अधिक खतरनाक बताया गया है, जिन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जेब में रखा फोन वाइब्रेट कर रहा है या बज रहा है, पर चेक करने पर न कोई कॉल और न कोई मैसेज होता है। अगर ऐसा किसी भी मोबाइल धारक को एहसास होता है, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये सिर्फ वहम नहीं, बल्कि एक नई मानसिक बीमारी की दस्तक है। इसे 'फोन फोबिया' या 'फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम' कहते हैं। इससे भारत में काफी बड़ी आबादी प्रभावित है, जिनमें नाबालिग, जिनकी उम्र 14 से 17 के बीच है, ज्यादा हैं। कामकाजी लोगों को छोड़कर स्कूल-कॉलेज बच्चे और युवा पीढ़ी इस समस्या में सर्वाधिक फंसा है। रिपोर्ट की मानें तो ये खतरनाक मानसिक संकट भविष्य के लिए किसी चुनौती से कम नहीं? सेलफोन विकिरण से लोगों की ग्रैनुलोसा कोशिकाएं सूखने लगी हैं। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के आसपास पानी की मात्रा में कमी और एएलटी-एएसटी का स्तर बढ़ना भी रिपोर्ट में बताया गया है।

डॉ. रमेश ठाकुर
लेखक

डब्ल्यूएचओ की मानें तो पिछले चार वर्षों में विभिन्न प्रकार के कैंसर इंसानों में पाए जाने लगे हैं, क्या उनका संबंध मोबाइल से है? इसकी खोज और पड़ताल के लिए दुनिया भर में बड़े स्तर पर अध्ययन किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का कारण भी बनने लगी हैं। सालाना छह लाख से ज्यादा मोबाइल फोबिया के शिकार मरीज देशभर के अस्पतालों में भर्ती होते हैं। विश्व का आंकड़ा करोड़ों में है। बढ़ती समस्या का बाद नौबत ऐसी आ चुकी है कि विभिन्न प्रदेशों के मुखिया अपने प्रदेश वासियों से कम मोबाइल इस्तेमाल और सतर्कता बरतने का आह्वान करने लगे हैं। जिला अस्पताल की इस रिपोर्ट के बाद ही बीते दिनों देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को युवाओं के नाम एक सार्वजनिक खत लिखना पड़ा। जागरूकता फैलाने के लिए बकायदा अखबारों में इश्तेहार भी सरकार को देने पड़े।

गाजियाबाद जिला अस्पताल की ओर से यह सर्वे बीते माह जनवरी में करवाया गया था, जिसमें 70-75 फीसदी युवाओं ने माना कि वो प्रत्येक चार या पांच मिनट में अपना मोबाइल देखते हैं, जिसमें 40 फीसदी ने यह भी स्वीकारा कि ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं देखने पर उन्हें बेचैनी, अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन का एहसास होने लगता है।

मनोवैज्ञानिकों और काउंसलरों की सलाह है कि अगर मोबाइल फोबिया से खुद को बचाना है, तो मोबाइल के प्रयोग का वक्त तय करें, सोने से पहले फोन का इस्तेमाल कतई न करें और गैरजरूरी नोटिफिकेशन को इग्नोर करते रहें। इसके अलावा ट्रैकर का उपयोग करना चाहिए। अलार्म के लिए फोन की जगह घड़ी का उपयोग किया जाए। एक्टिविटी जरूर बढ़ाएं, खाली समय में किताबें पढ़ें, व्यायाम करें या मित्रों-परिजनों से बात करें। लत अगर बहुत अधिक है, तो बिना देर किए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं। विशेषज्ञों की मानें तो वयस्कों के लिए दो से तीन घंटे और बच्चों-किशोरों के लिए दो घंटे तक ही एक दिन में मोबाइल चलाना चाहिए।

आग राग गाता मदमाता आया फागुन

आसमान का रंग बदला और धरती खिलखिला उठी। ऋतु ने अंगड़ाई ली, प्रकृति मुस्कुराई। धूप थोड़ी तपी तो ढेरों फूल खिले। कूक-कूक कर हूक उठाती कोयल की पंचम तान प्राणों को सुलगाती अंग-अंग में आग जगाने लगी। दबी आग किस अनुराग से जगती है यह बसंत को पता है। बाग-बगीचों में, दूर सुदूर खेतों में, नदी तालाब के कूल कछारों में, हरे-हरे पत्तों, डालियों और रंग-बिरंगे फूलों की नरम-नरम पंखुड़ियों पर कोमल मुलायम मखमली आग तैरने लगी -
तन मन यौवन जल रहा,जले फाग की आग।
जमकर आज दिगंत में, गुंजे आग का राग।।'

संजय पंकज
वरिष्ठ लेखक

दिग्वधुओं ने अपने घूंघट उठा लिए। लाज के अंदाज बदल गए। पेड़ों ने साज संभाला। लताओं ने पाजेब पहन ली। जीवंतता से भर गया जर्रा जर्रा। जड़ में चैतन्य क्या उतरा कि कंकड़ कंकड़ में शिवशंकर नाच उठे। भूत-प्रेत-बैताल भी साज सज्जा में सुसज्जित हो रंग गुलाल उड़ाने लगे। बाबा बौड़म अघोरेश्वर देवाधिदेव महादेव आशुतोष भूत भावन भोलेनाथ बारात लेकर निकल पड़े। वसंत का राग-अनुराग शिव की बारात में रंग-गंध की तरंग लिए जा घुसा। रागी-विरागी योगेश्वर शिव लय के आरोह-अवरोह से पोर-पोर झंकृत हुए, तो उनके पांवों में थिरकन उतर आई और वे उमंग में लगे नाचने। वसंत ने अनंत शिव में असीम ऊर्जा का संचार किया तो वे नटराज हो गए और जब वसंत ने उन्हें मदन-रूप में उन्मत्त करना चाहा तो रौद्र रूद्र बनकर, उन्होंने प्रलयंकारी तांडव का धमाल मचाया। वसंत छंद बनकर कंठहार होता है, तो बेतरतीब होकर अंगार भर रह जाता है। लास्य और तांडव का संतुलन है वसंत। सलीके से वसंत को संभाल लेने का उन्नत अवसर महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि शिव-शक्ति के महामिलन का विराट आध्यात्मिक पर्व है।

वसंत फागुन की अगवानी करता हर दिशा में दमक रहा है। रंग-तरंगों पर मंद-मंद लहराती मलय बयार, टेसू के फूलों से फूटती लाल-लाल बौछार, पिक पंचम की उल्लसित ज्वार। ऐसे में भला कैसे न झरना हुआ मन सागर हो जाए। पूरा का पूरा वासंती परिवेश है। खुशबू से भरी झूमती हवाएं, बहकती हुई दिशाएं। आम पर बौर लद गए, पीपल के पत्तों में चमक बढ़ गई। गेहूं की बालियां निखरने लगीं, महुए की मादकता बिखरने लगीं। बलखाती लहराती नदियों को सूरज की किरणों ने चूमा तो वह लहर-लहर पर चमक उछालती कौंधने लगीं। अपने आप ही सबकी चाल बहकी, हर गाल बिना गुलाल मले ही गुलाबी हो गए, अनजाने ही मद में पद डगमग-डगमग होने लगे। आसमान मदहोश मुस्कुराहटों से धरती को निहारने लगा तो धरती भी निहाल हुई और सरसों के पीले फूलों की पिचकारियां मारने लगी। उड़ने लगी बहुरंगी तितलियां, मचलने लगे भौंरे, गाने लगी चिड़ियां। अंग अंग में तैरने लगा सुरीला नशा, पूरे वातावरण में फैल गया सुरूर और मृदुल गुदगुदाहटों से मादक हो उठा अंतरिक्ष। आक्षितिज आलोड़ित होने लगा अनकहे आस्वाद का अद्भुत आलोक। ऐसा आलोक जिसमें अदृश्य है रंग ही रंग, गंध ही गंध, संगीत ही संगीत। कुछ भी अछूता नहीं रहा। जड़ चेतन सब स्पंदित उद्वेलित हो उठे। लय की लहरियों पर तरंगित होता हुआ प्रेम पुलकित पैंगें मारता फागुन आ गया। -

'फागुन ने अंकित किया,प्यार प्यार बस प्यार।
प्यार नाम है जिंदगी, प्यार धरा का हार।।'

शिव-शक्ति को संयोजित करता वसंत रंग गंध की पालकी उठाए फागुन का अलख जगाने लगा। 'नव गति नव लय ताल छंद नव' पर जब सब मदहोश होने लगे तो फागुन ने कोयल-स्वर में मधुर शोर मचाना शुरू किया। तब भी मदहोशी नहीं टूटी, तो फागुन ने पेड़ों पर मंजरियों की आग जला दी। टेसू और पलाश के फूल दहक उठे। फागुन ने आग की लपटें उठाई तो आकुल आह्लाद के उन्मादी स्फुलिंग उड़ने लगे। फागुन के अग्नि-अंक में समाहित होने लगा अस्तित्व। कुटिलता की होलिका जलकर राख हो गई और आह्लाद का प्रह्लाद अलौकिक रंग-गंध में डूबकर उबर आया। आह्लाद, आनंद और आत्मीयता का फागुनोत्सव परम सत्ता को भी ऐसा छू गया कि दिगंबर शिव मसान में ही मगन मस्त हो खेलने लगे होली। वसंत की मादकता और फागुनी उल्लास से उन्मादित हुआ कामदेव तो उसने दिगंबर शिव पर ही संधान कर दिया अपना मदन-बाण। काम के बाण से विद्ध हो शिव उन्मत्त नहीं हुए उद्धत हुए और लगे क्रोध में नाचने। ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रेमी शिव। उन्होंने अपने प्रेम की अक्षुण्णता और अखंडता के लिए काम को भस्म कर दिया। एक दूसरे में अंतर्भुक्त शिव और शक्ति काम रहित कामजित हैं। वसंत और फागुन कामोद्वेलन के समस्त द्वंद्वों से परे कामोद्दीपक अलौकिक ऊर्जा हैं। फागुन की मस्ती होली के रूप में व्यक्त होती है। भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में योगीराज शिव और योगेश्वर कृष्ण में सन्निहित फागुनोत्सव के असीम प्रवाह और अनंत उल्लास के दर्शन हमारे चित्त की निर्मलता और भाव के औदात्य के परिचायक हैं। शिव और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं। असीम, अनंत, अटूट, अखंड, अछोर और अनीह है दोनों का प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा और दिव्यता में डूबे शिव और कृष्ण शाश्वत हैं। शाश्वत है वसंत और शाश्वत है फागुन भी। -

' प्रेम अनोखा रंग है , प्रेम अनोखा छंद।
फागुन ने चिल्ला कहा,इसको दिया अनंत।।

अहर्निश अनंत राग गाता अंबर और धरती के बीच अनुराग से भरा हुआ जो शून्य है वह अनछुआ, अनदेखा, अनकहा और अलौकिक है। जाने कब से सौंदर्य का अदृश्य सागर लगातार लहरा रहा है धरती और अंबर के बीच। धरती और अंबर के बीच ही जीवन और मरण का महारास चलता रहता है। यह शून्य ही ब्रह्म और जीव का सम्मोहक क्रीडा स्थल है। माया का खेल चल रहा है निरंतर। रंग और गंध का आनंद उत्सव मनाता आग राग गाता मदमाता फागुन आया है। फागुन के आते ही आए हैं अनेकानेक भाव विभाव अनुभाव। आई हैं अंतश्चेतना में अनंत अनुभूतियां।

वसंत और फागुन को अंतर में समाहित कर हम प्रार्थना करें कि इन अनुभूतियों की आग में असीम करुणा समाहित हो और राग अनुराग की ऐसी लय संपूर्ण विश्व में फैल जाए, जिसमें सब रंग-गंध के प्रेमपुलक में डूब एकरस एकतान हो जाएं। कोई किसी से विलग नहीं हो और फाग-आग के राग में ऐसे लहराएं कि एक दूसरे के अस्तित्व को कोई विलग भी नहीं कर सके। फागुन का संदेश है कि हम शुद्धआत्मा प्रबुद्ध बनें और हर युद्ध के विरुद्ध करुणा का ध्वजारोहण करें।

'होली में सबको मिले, हंसी-खुशी सौगात।
सराबोर दिन रंग में, गंध भरी हो रात।।

सक्सेस स्टोरी

कल्पना सरोज : झोपड़ी से उद्योगपति तक

कल्पना सरोज भारत की एक प्रेरणादायक महिला उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गरीबी, जातिगत भेदभाव और व्यक्तिगत संघर्षों से उबरकर एक सफल व्यवसाय साम्राज्य स्थापित किया है। वे कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 112 मिलियन डॉलर आंकी जाती है। उनकी कहानी को अक्सर 'स्लमडॉग मिलियनेयर' की वास्तविक संस्करण के रूप में वर्णित किया जाता है।

प्रारंभिक जीवन

कल्पना सरोज का जन्म 1960 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और परिवार गरीबी और जातिगत भेदभाव से जूझता था। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां वे पढ़ाई में उत्कृष्ट रहीं। हालांकि, दलित होने के कारण उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ाकृवे स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकती थीं, और अन्य बच्चों के माता-पिता उन्हें अलग रखते थे।

रूफिया खान
शिक्षिका

विवाह और शुरुआती संघर्ष

उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह आम था, और लड़कियों को परिवार का बोझ माना जाता था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में कल्पना का विवाह कर दिया गया। वे मुंबई के एक स्लम में पति और ससुराल वालों के साथ रहने लगीं, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ीं। वे भूखी रखी जातीं, पीटी जातीं और नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया जाता। छह महीने बाद, उनके पिता ने उन्हें पहचानकर वापस घर ले आए और विवाह समाप्त कर दिया। लेकिन गांव में वापस आने पर उन्हें और उनके परिवार को ताने और अपमान सहने पड़े। हताश होकर उन्होंने तीन बोतल कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन परिवार ने उन्हें बचा लिया।

मुंबई में नई शुरुआत

गांव में नौकरी के अवसर न होने पर, कल्पना ने माता-पिता को मनाकर मुंबई में चाचा के घर जाने की अनुमति ली। वहां उन्होंने एक गारमेंट फैक्ट्री में काम शुरू किया, जहां उन्हें महीने में 60 रुपये मिलते थे। वे सीनियर टेलर बन गईं और अतिरिक्त सिलाई से 100 रुपये और कमातीं। जब उनके पिता की नौकरी चली गई, तो वे परिवार की एकमात्र कमाने वाली बनीं। उन्होंने 40 रुपये में एक कमरा किराए पर लिया और परिवार को मुंबई बुला लिया। एक दुखद घटना में उनकी छोटी बहन की बीमारी से मौत हो गई, क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। इसने उन्हें धन कमाने की प्रेरणा दी और वे 16 घंटे काम करने लगीं, एक आदत जो आज भी जारी है।

व्यावसायिक यात्रा

1975 में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत 50,000 रुपये का लोन लेकर उन्होंने एक बुटीक खोला और फर्नीचर का रीसेलिंग बिजनेस शुरू किया। वे उल्हासनगर से सस्ते फर्नीचर खरीदकर बेचतीं। व्यवसाय स्थिर होने पर, उन्होंने बेरोजगारों की मदद के लिए एक एसोसिएशन बनाई। 1995 में, उन्होंने एक विवादित जमीन ख़रीदी, जिस पर दो साल मुकदमा चला, लेकिन जीत हासिल की। फिर एक बिल्डर के साथ साझेदारी में 35 प्रतिशत लाभ पर विकास किया, और रियल एस्टेट में प्रवेश किया। 1998 तक, उनका रियल एस्टेट टर्नओवर 4 करोड़ रुपये पहुंच गया। उन्होंने गन्ने की फैक्ट्री में निवेश किया और कई कंपनियां स्थापित कीं, जैसे कमानी स्टील री-रोलिंग मिल्स, कमानी ट्यूब्स, कल्पना सरोज एंड एसोसिएट्स, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सैकृपा शुगर फैक्ट्री, और केएस क्रिएशन्स फिल्म प्रोडक्शन। उनके कुल बिजनेस टर्नओवर हजारों करोड़ रुपये है।

कमानी ट्यूब्स का पुनरुद्धार

2000 में, कल्पना के पास व्यक्तिगत संघर्ष, उद्यमिता और ब्लू-कॉलर वर्कर्स की फाइनेंस का अनुभव था। 2001 में, दिवालिया कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स ने उनकी एनजीओ से मदद मांगी। कंपनी पर 116 करोड़ रुपये का कर्ज था, 140 मुकदमे थे, और उपयोगिताएं बंद थीं। कल्पना ने सीईओ बनकर कर्ज चुकाए, मशीनरी बदली, उत्पादन शुरू किया, और कंपनी को लाभदायक बनाया। यह भारत की पहली कंपनी थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने मालिकाना हक वर्कर्स यूनियन को सौंपा था। आज कंपनी 750 करोड़ रुपये की है।

सामाजिक कार्य

कल्पना ने एक छोटी एनजीओ शुरू की, जो वंचितों को सरकारी लोन और योजनाओं की जानकारी देती है। उन्होंने कल्पना सरोज फाउंडेशन स्थापित किया, जो सामाजिक कल्याण कार्य करता है। वे दलित समुदाय की मदद करती हैं, बेरोजगारों को सहायता प्रदान करती हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती हैं। वे भारतीय महिला बैंक के बोर्ड मेंबर भी रहीं। वे भारतीय महिला बैंक के बोर्ड मेंबर रहीं और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल हैं। एक बौद्ध अनुयायी के रूप में, वे डॉ. भीमराव अंबेडकर से प्रेरित हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज़ोर देती हैं।

पुरस्कार और सम्मान

2013 में, उन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उद्यमी हैं, और भारत सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया।

वर्तमान स्थिति

आज 60 के दशक में होते हुए भी, कल्पना सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का नेतृत्व करती हैं। उनकी कहानी साबित करती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका दर्शन है, ''कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आप चाहते हैं, वह आपको मिलेगा अगर आप पूरे मन से काम करें और एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ें।'' कल्पना सरोज की जीवन गाथा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों से उबरकर सफलता कैसे पाई जा सकती है।

एक खत के जरिए छलका पलायन का दर्द

प्रिय भाई, मैं आशा करती हूं कि तुम अपने परिवार के साथ दिल्ली में कुशलता से और प्रसन्न होगे। पिछले दिनों धुमाकोट के पड़ोसियों से पता चला कि मां जी और बाबूजी दोनों का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। आसपास के लोग यथासंभव उनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं पीरुमदारा में रहते हुए भी बराबर उनका हाल-चाल लेती रहती हूं, फिर भी मन आशंकित रहता है। तुम्हें भी उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए और समय निकालकर उनसे फोन पर बात किया करो। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूं। इस वर्ष पहाड़ों में अधिक वर्षा के कारण मौसम कुछ ज्यादा ठंडा हो गया है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पिताजी को कफ की शिकायत रहती है, खासकर जाड़े के दिनों में, जिससे उनका अस्थमा बढ़ जाता है। वहीं वात रोग के कारण मां जी के दाहिने घुटने में सूजन आ गई है। मेरा मन नहीं माना और मैं उन्हें देखने गांव पहुंच गई। मुझे देखकर मां जी और बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, "बेटी, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। भावेश दिल्ली जाकर बस गया है, अब हमारा हाल-चाल भी नहीं लेता।" यह सुनकर मेरा हृदय बहुत व्यथित हो उठा। तुम्हारा दूसरा भाई सुनील निजी कंपनी में काम करने के कारण नोएडा में अत्यधिक व्यस्त रहता है। पिछले वर्ष गांव में पूजा के अवसर पर वह बहुत कम समय के लिए ही आ पाया था। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांव में मां-बाबूजी की देखभाल कैसे हो और कौन करे। इस विषय पर मैं लगातार सोचती रहती हूं। मैंने जीजा जी से बात की तो उन्होंने सुझाव दिया कि मैं मां-बाबूजी को पीरुमदारा ले आऊं, पर बात इतनी सरल नहीं है। गांव में हमारा पुश्तैनी मकान और दो नाली जमीन है। मैंने कई बार मां-बाबूजी से कहा कि वे मेरे साथ पीरुमदारा चलकर रहें। एक बार बहुत समझाने पर उन्हें यहां ले भी आई, लेकिन उनका मन नहीं लगा और वे वापस गांव लौट गए। अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। दोनों ही कमजोर हो चुके हैं। उनके स्वास्थ्य, खान-पान और दवाइयों का नियमित ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह लिखते हुए मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है कि तीन संतानों के माता-पिता बुढ़ापे में आज अकेले जीवन काट रहे हैं। पड़ोस की सरुली ताई बताती हैं कि वे रामनगर की ओर से आने वाली हर बस को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, शायद भावेश या सुनील आ रहे हों। तुम जानते हो कि मेरी शादी को बारह वर्ष हो चुके हैं और मैं अपने परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियों में भी बंधी हूँ। कोविड काल में सासू मां के निधन के बाद मेरे ससुर जी अकेले पड़ गए हैं। उन्हें शुगर और बीपी की समस्या है। इसके बावजूद उन्होंने स्वयं कहा कि मैं धुमाकोट जाकर अपने माता-पिता के साथ कुछ दिन रह आऊं। मैं केवल यही चाहती हूं कि अम्मा-बाबूजी का शेष जीवन सम्मान और सुकून के साथ बीते। तुम आर्थिक रूप से सक्षम हो और माता-पिता के त्याग व संघर्ष को भली-भांति समझते हो। उन्होंने कभी बेटा-बेटी में भेद नहीं किया। इसलिए गांव में लोग कहते हैं कि "राधिका पटवाल जी का तीसरा बेटा है।" इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करना और मेरे इस पत्र का उत्तर देना।

संतोष कुमार तिवारी
नैनीताल

जॉब का पहला दिन

जिम्मेदारी की दहलीज पर पहला कदम

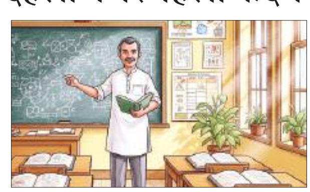

20 दिसंबर 2010 का दिन था, जब मुझे पहली बार स्थायी तौर पर अपनी प्रथम नियुक्ति के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जाहिदपुर, शाहबाद, रामपुर में जाना था। मेरा जन्मदिन 24 दिसंबर को होता है। इस प्रकार से दिसंबर में सरकारी सेवा में आना एक प्रकार से जन्मदिन के पूर्व उपहार जैसा था। मैंने जीवन में कभी कोई ट्यूशन तक नहीं पढ़ाई थी। बस बीएड और विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के दौरान, जो शिक्षण अनुभव था वही था। ऐसे में जब पहली बार विद्यालय पहुंचा, तो वास्तविक परिस्थितियां किताबी ज्ञान से अलग और चुनौतीपूर्ण थीं।

इन परिस्थितियों ने मुझे जहां जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करवाया, मुझे तपाया वहीं मुझे मजबूत भी किया। विद्यालय में बिताया गया हर एक पल मेरे अनुभव को पुख्ता कर रहा था। मैं धीरे-धीरे इन चुनौतियों से लड़ना और मुस्कराकर हर समस्या का हल ढूंढना सीख गया। परिषदीय विद्यालयों में होने वाली दैनिक प्रार्थना 'वह शक्ति हमें दो दयानिधे' ने मुझे बहुत हिम्मत प्रदान करी। जब इस प्रार्थना को प्रतिदिन सुनता था। तब मन में एक ही बात आती थी कि 'हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे' क्योंकि इस राह पर चलेंगे तभी तो 'उनको तारें खुद तर जावें' वाली पंक्ति सत्य सिद्ध होगी। पदोन्नति के बाद 2016 में बरेली में स्थानांतरण भी हो गया। 2016 से अब तक मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रहटुइया, मझगवां, बरेली में कार्यरत हूं। रामपुर में मैं कक्षा 1- 5 तक के बच्चों को पढ़ाता था, तो यहां कक्षा 6 से 8 के बच्चों को शिक्षित करने लगा और इनमें प्रतियोगिता की भावना का संचार किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2023 और 2025 में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति जैसी कठिन प्रतियोगिता में विद्यालय से छात्र सफल हुए और 2026 में भी दो छात्रों के सफल होने की संभावना है। विद्यालय और बच्चों से मुझे इतना प्रेम है कि 2024 में 'भूतिया मास्साब' नाम का उपन्यास लिखा है जिसमें एक ऐसे अध्यापक की कहानी है जो मृत्यु के बाद भी भूत के रूप में अपने बच्चों की सहायता करते रहते हैं। हिन्दी फंतासी जो लगभग अछूता क्षेत्र है उसमें मैं 'हाथिस्तान' नाम की शृंखला लिख रहा हूं।

प्रांजल सक्सेना
शिक्षक, बरेली

पीएचडी की यात्रा की चुनौतियों का सामना कैसे करें?

डॉ राजेश के पिलानिया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, गुरुग्राम

अनुसंधान, विशेष रूप से पीएचडी का शोध, एक बहुत ही गहन और अकेली यात्रा होती है। इसमें किसी एक विषय पर 3 से 5 या उससे भी अधिक वर्षों तक काम करना पड़ता है। शोध एक रोलर-कोस्टर की तरह होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि शोध सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब किसी विपरीत शोध को देखकर ऐसा महसूस होता है कि काम कहीं अटक गया है या शायद सही दिशा में नहीं जा रहा है।

पिछले लगभग तीन दशकों में लेखक ने विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शोधकर्ताओं और शोध छात्रों से बातचीत की है और कई बार यह समस्या सामने आई है कि शोध एक लंबी यात्रा है, जिसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इसके साथ ही भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना भी रहती है, जो एक शोधकर्ता के सामने आने वाली अन्य दैनिक पेशेवर चुनौतियों के अतिरिक्त होती है।

एक पीएचडी शोधार्थी इन चुनौतियों का इस तरह ध्यान कैसे रखे कि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सके और शोध यात्रा का आनंद भी ले सके? इसके लिए पाँच सुझाव प्रस्तुत हैं।

पहला, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छे संबंधों तथा उत्पादक और नवाचारी बने रहने पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले 50 वर्षों के शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि खुशी स्वास्थ्य, संबंधों, उत्पादकता और नवाचार में सहायक होती है। खुशी के साथ शोधकर्ता का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, संबंध मजबूत होते हैं और काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसलिए, एक शोधकर्ता के लिए, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, खुशी को गंभीरता से लेना और उसे दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक है।

दूसरा, असुरक्षाओं का समाधान है–नियमित रूप से और एकाग्र मन से काम करना। असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए व्यक्ति को उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हैं। ऐसा करने से पीएचडी शोधार्थी को उच्च गुणवत्ता वाले दैनिक शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नौकरी या भविष्य से जुड़ी चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। केंद्रित, समर्पित और गुणवत्तापूर्ण कार्य भविष्य की असुरक्षाओं के विरुद्ध सबसे अच्छा संरक्षण है।

तीसरा, हास्यबोध बनाए रखना चाहिए और चीज़ों को व्यक्तिगत या अत्यधिक गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से काम करना जरूरी है, लेकिन साथ ही स्वयं पर हँसना और बातों को हल्के में लेना भी सीखना चाहिए। हास्यबोध विकसित करके, स्वयं पर हँसकर और चीज़ों को बहुत गंभीरता से न लेकर, व्यक्ति कठिन समय में भी लचीलापन बनाए रख सकता है और आगे बढ़ता रह सकता है।

चौथा, परिणाम की अत्यधिक चिंता करने के बजाय शोध की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिशा के लिए लक्ष्य होना आवश्यक है, लेकिन मुख्य ध्यान रोज़मर्रा की प्रक्रिया पर होना चाहिए। सिद्धांत और शोध दोनों यह दर्शाते हैं कि परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।

पाँचवाँ और अंतिम, हर दिन सीखते रहना और स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए। निरंतर सीखने और निरंतर सुधार के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का कार्य किया जा सकता है। अच्छा कार्य और अच्छा परिणाम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होता है।

ये पाँच कदम पीएचडी शोध यात्रा का सामना करने का एक अच्छा तरीका हैं। खुश रहकर, शोध प्रक्रिया का आनंद लेकर और लगातार सीखते व सुधार करते हुए, व्यक्ति वर्तमान का आनंद ले सकता है और भविष्य से जुड़ी असुरक्षाओं को भी कम कर सकता है।

लेखक डॉ राजेश के पिलानिया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, गुरुग्राम में प्रोफेसर हैं। वे भारत के हैप्पीनेस प्रोफेसर और भारत के हैप्पीनेस गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं।

बच्चों को हिंसक बनाता डिजिटल संसार

गाजियाबाद की घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी है, जो अपने बच्चों पर भरोसा किए बैठे हैं कि उनका बच्चा बंद कमरे में मोबाइल चलाते हुए सुरक्षित है। इस घटना के बाद से कई माता-पिता अपने बच्चों को लेकर मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि टास्क-बेस्ड गेम में डिजिटल कंटेंट को नाबालिग वर्ग तक बड़ी चतुराई से पहुंचाया जाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि किशोर-किशोरियों के बीच कोरियाई, चीनी एवं जापानी कंटेंट को बिटक्वाइन मुद्रा का लालच देकर भी योजनाबद्ध तरीके से उन तक पहुंचाया जा रहा है। बीते दिनों संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य आनलाइन प्लेटफार्म्स पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके सामाजिक जीवन को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। इससे निपटने के लिए आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल एवं सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। आस्ट्रेलिया और फिनलैंड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के लिए कानून लागू हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली में ऐसा कानून लाने पर सहमति बन चुकी है। ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस भी इससे जुड़ा कानून बनाने की तैयारी में हैं। भारत में एक अरब

पिछले दिनों गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों ने अपने आवास की नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 12,14,16 साल की आयु अपने जीवन के सपनों को बुनने और उन्हें बड़े लक्ष्यों के साथ पूरा करने की होती है, मगर लगता है इस उम्र में समाज और परिवार की वास्तविक दुनिया को छोड़कर आभासी दुनिया, गेमिंग और डिजिटल मीडिया की गिरफ्त में आकर बचपन हिंसा की ओर मुड़ चला है। तीनों को कोरोना काल से ही कोरियाई लव गेम, कोरियाई ड्रामे, गाने और मूवी देखने की लत लग गई थी। वे तीनों कोरियाई संस्कृति से इतनी प्रभावित थीं कि अपने नाम के साथ-साथ जीवनशैली को भी उसी संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया था। टास्क-बेस्ड डिजिटल गेम्स ने इन लड़कियों को पहले किताबों से दूर किया, फिर उनकी वास्तविक दुनिया भी समाप्त कर डाली। कोरियाई गेम की लत के कारण ही उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तीनों बहनों में एक बहन डेथ कमांडर की भूमिका निभाते हुए बाकी दोनों को टास्क पूरा कराने में भूमिका निभाती थी। तीनों लड़कियों के सुसाइड नोट से जुड़े शब्द आइ.एम.सारी पापा-मैं गेम नहीं छोड़ पा रही हूं, यही बताते हैं कि ये किशोरियां एक टास्क-बेस्ड डिजिटल गेम से जुड़ी पूर्व नियोजित योजना की शिकार थीं।

गाजियाबाद की घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी है, जो अपने बच्चों पर भरोसा किए बैठे हैं कि उनका बच्चा बंद कमरे में मोबाइल चलाते हुए सुरक्षित है। इस घटना के बाद से कई माता-पिता अपने बच्चों को लेकर मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताते हैं कि टास्क-बेस्ड गेम में डिजिटल कंटेंट को नाबालिग वर्ग तक बड़ी चतुराई से पहुंचाया जाता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि किशोर-किशोरियों के बीच कोरियाई, चीनी एवं जापानी कंटेंट को बिटक्वाइन मुद्रा का लालच देकर भी योजनाबद्ध तरीके से उन तक पहुंचाया जा रहा है। बीते दिनों संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य आनलाइन प्लेटफार्म्स पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके सामाजिक जीवन को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है।

इससे निपटने के लिए आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल एवं सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। आस्ट्रेलिया और फिनलैंड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के लिए कानून लागू हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली में ऐसा कानून लाने पर सहमति बन चुकी है। ब्रिटेन, डेनमार्क और ग्रीस भी इससे जुड़ा कानून बनाने की तैयारी में हैं। भारत में एक अरब से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 50 करोड़ से अधिक यूट्यूब, 40 करोड़ से अधिक फेसबुक तथा 48 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम यूजर हैं। इंटरनेट मीडिया के इन प्लेटफार्म्स पर 75 प्रतिशत से अधिक यूजर्स कम उम्र के हैं। इसके कारण उनमें नींद की कमी, कम एकाग्रता, घबराहट, अवसाद एवं आत्मविश्वास में कमी और साइबर बुलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। इनके कारण बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन भी लगातार प्रभावित हो रहा है।

परिवार के विखंडन के इस दौर में सबसे अधिक बचपन प्रभावित हुआ है। दादा-दादी, नाना-नानी के संरक्षण में कहानियां सुनने वाला बचपन अब कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, वीडियो और मोबाइल गेम्स जैसे संचार माध्यमों के बीच की मशीनी दुनिया के साथ विकसित हो रहा है। बच्चों के इस मनो-शारीरिक विकास में दैहिक समाज नदारद है। आज आर्थिक दबावों के समक्ष माता-पिता को भी इतनी फुरसत नहीं है, जो बच्चे को यह बता सकें कि जीवन में उसके लिए चीजों को चयन करने की दिशा क्या होगी।

बच्चों को अपने सामने बिठा कर संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों की सीख देने वाले परिवार और स्कूल भी उनसे दूर हो रहे हैं। बच्चों का बचपन मनोरंजन की दैहिक दुनिया से छिटककर संचार माध्यमों की दुनिया तक सिमट रहा है, जहां उनके मनपसंद कार्यक्रम चयन का अपना भरा-पूरा यांत्रिक संसार है। बच्चों के विवेक हरण एवं चेतना के दमन का कार्य करते हुए ये सभी साधन उनके जीवन को रोमांचक बना रहे हैं। इसी दौरान कभी-कभी टास्क बेस्ड रोमांच उन्हें आत्मघात की ओर भी ले जाता है।

इक्कीसवीं सदी में पारस्परिकता, वैयक्तिकता, प्रेम, बंधुत्व, मनुष्यता, सहानुभूति एवं मानवीय संवेदना जैसे मूल्यों का अभाव है। इससे सबसे अधिक बच्चों का बचपन ही प्रभावित हो रहा है। संचार माध्यमों ने इन बच्चों को भी उपभोक्ता बना कर रख दिया है। परिणामस्वरूप बच्चे भी इस बाजार की गलाकाट होड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बच्चों की इस पीढ़ी में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो है, परंतु जीवन में असफलता की स्थिति में धैर्य एवं संयम का पूर्णतः अभाव है।

सम्पादकीय

शब्दों का फेर या कूटनीतिक जीत? बाध्यकारी शर्तों से मुक्त हुआ भारत

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का अंतिम स्वरूप में पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच इसके अहम बिंदुओं के नफे-नुकसान के मसले पर जो बहस चल रही है, उसके असर भी सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के शुरुआती स्वरूप में कई अन्य अमेरिकी वस्तुओं सहित कुछ दालों पर भी भारत की ओर से शुल्क कम या समाप्त करने की खबर आई थी। मगर भविष्य में भारतीय कृषि और किसानों पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई गई। अब अमेरिका की ओर से जारी नए तथ्य-पत्र में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया है। मसलन, समझौते के प्रारूप में पहले जहां भारत की ओर से पांच सौ अरब डालर से अधिक मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदने को 'प्रतिबद्धता' बताया गया था। वहीं संशोधित संस्करण में इसे खरीदने के 'इरादे' के रूप में पेश किया गया है। यानी यह नियम अब भारत के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा, संशोधन के बाद समझौते के प्रारूप में से कई कृषि वस्तुओं, खासकर दालों को इस सूची से बाहर करने की खबर है। इसके बाद स्वाभाविक ही भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिका की ओर से खड़ी होने वाली प्रतिस्पर्धा से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यों भी, भारत दालों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी वजह से खासतौर पर दालों को किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा माना जाता रहा है। हाल ही में जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में सहमति के स्तर तक पहुंचने की खबरें आई थीं, तब अमेरिका की ओर से शुल्क अठारह फीसद करने सहित इसके सकारात्मक पहलुओं की खासी चर्चा हुई थी। मगर कृषि तथा अन्य उत्पादों के संबंध में भारत के रुख को लेकर कई तरह की चिंता भी उभरी थी। यह आशंका जताई गई कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं को भारत में निर्बाध छूट दी गई, तो यहां के कृषि क्षेत्र पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसीलिए किसानों की ओर से विरोध के स्वर भी उभरे। विपक्षी दलों ने भी ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। इन उतार-चढ़ावों के बीच व्यापार समझौते के प्रारूप में अब जिन बदलावों की खबर आई है, वह भारत के लिए सकारात्मक और राहत की बात साबित हो सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी साझेदारी कसौटी पर तभी उचित साबित हो सकती है, जब इसमें परस्पर और समान हित पर आधारित शर्तें शामिल हों। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में अमेरिका और भारत की स्थिति को एक समान आधार पर नहीं देखा जा सकता। इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते में संतुलन के कारक संदर्भों पर निर्भर करेंगे। भारत अगर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार बिना कोई शर्त लगाए खोलता है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके सामने प्रतिस्पर्धा एक चुनौती बन कर खड़ी हो सकती है।

सवालों के घेरे में राहुल की नेतृत्व क्षमता

एक और अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी पार्टी आलाकमान से असंतुष्ट हैं। अल्वी का कहना है कि कि पार्टी में आंतरिक संवाद के लिए कोई जगह नहीं और यहां तक कि वरिष्ठ नेताओं के लिए भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच टेढ़ी खीर है। जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे दिग्गजों के समय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे समय मिलने में समस्या नहीं होती थी। अल्वी के अनुसार उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक का उपयोग तो करती है, लेकिन मुसलमानों की परवाह नहीं करती। पार्टी की नीतियों से कोई संकेत नहीं मिलता कि मुस्लिमों के जीवन की दशा-दिशा सुधारने की उसकी कोई मंशा है। पार्टी से निराश मुस्लिम नेताओं में एक नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी है। जमीन से जुड़ाव रखने वाले सिद्दीकी बसपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। बसपा से किनारा कर कांग्रेस से जुड़ने वाले

कांग्रेस में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर सवालों का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। बीते दिनों कुछ मुस्लिम नेताओं ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोला है। निश्चित रूप से यह उनकी पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं, जो अपने वजूद के लिए एक बड़ी हद तक मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली कांग्रेस से अगर मुस्लिमों का ही मोहभंग हो रहा है तो यह उसके लिए बड़े खतरे की घंटी है। राहुल की नेतृत्व क्षमताओं पर सवाल उठाने वालों में एक नाम पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे डा. शकील अहमद का है। बिहार के पारंपरिक कांग्रेसी परिवार से आने वाले शकील अहमद कई बार विधायक, सांसद और मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि वे 'डरपोक' हैं।

उन्हें वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने में असहजता होती है, क्योंकि उन्हें 'आप' कहकर संबोधित करना पड़ता है। यह उन्हें रास नहीं आता। अहमद ने राहुल को अहंकारी, विशेषाधिकारों से ग्रस्त और असुरक्षित भी बताया है। अहमद का कहना है कि उन्होंने राहुल से अधिक असुरक्षित नेता देखा ही नहीं। वे वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाकर परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खरगे को कठपुतली अध्यक्ष बताते हुए अहमद ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े निर्णय राहुल गांधी ही लेते हैं। अहमद ने यहां तक कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले का निर्देश भी दिया। एक और अनुभवी एवं वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी पार्टी आलाकमान से असंतुष्ट हैं। अल्वी का कहना है कि कि पार्टी में आंतरिक संवाद के लिए कोई जगह नहीं और यहां तक कि वरिष्ठ नेताओं के लिए भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच टेढ़ी खीर है। जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे दिग्गजों के समय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनसे समय मिलने में समस्या नहीं होती थी। अल्वी के अनुसार उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक का उपयोग तो करती है, लेकिन मुसलमानों की परवाह नहीं करती। पार्टी की नीतियों से कोई संकेत नहीं मिलता कि मुस्लिमों के जीवन की दशा-दिशा सुधारने की उसकी कोई मंशा है। पार्टी से निराश मुस्लिम नेताओं में एक नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी है। जमीन से जुड़ाव रखने वाले सिद्दीकी बसपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। बसपा से किनारा कर कांग्रेस से जुड़ने वाले सिद्दीकी का भी पार्टी से मोहभंग हो गया। उनका कहना है कि व्यापक जनाधार के बावजूद कांग्रेस उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही थी और अनदेखी के कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। देखा जाए तो केवल मुस्लिम नेता ही नहीं, बल्कि अन्य वरिष्ठ नेता भी पार्टी में अपनी अनदेखी से क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक नेता शशि थरूर हैं। देश-विदेश में अपनी विद्वता से खास पहचान बनाने वाले थरूर किसी भी पार्टी के लिए बहुत उपयोगिता रखते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही दल में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उनकी उपेक्षा शकील अहमद के उन आरोपों को ही पुष्ट करती है कि पार्टी में सक्षम लोगों को किनारे किया जाता है। संभव है कि थरूर से आलाकमान की नाराजगी अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी खरगे के खिलाफ चुनाव लड़ने से लेकर आपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी दृष्टिकोण से सहमति जताने के कारण भी हो सकती है। जबकि आपरेशन सिंदूर में थरूर ने वही रुख अपनाया था, जो कोई भी सच्चा भारतीय अपनाता। आत्ममंथन का आह्वान करने वाले ऐसे नेताओं की बातों पर कान देने के बजाय पार्टी आलाकमान के करीबी उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं।

रेरा को सही फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा को जो कड़ी फटकार लगाई, उसके लिए वही उत्तरदायी है। इस प्राधिकरण का गठन जिन उम्मीदों के साथ किया गया था, वह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। रेरा की लचर कार्यप्रणाली के चलते न जाने कितने लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होते हैं और सब जानते हैं कि वहां से न्याय मिलने में समय लगता है। रेरा की निराशाजनक कार्यप्रणाली को इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसे बंद करना ही बेहतर है। उसने यह कठोर टिप्पणी भी की कि वह दिवालिया बिल्डरों को राहत देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इसका

सीधा मतलब है कि वह फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करने के स्थान पर उन बिल्डरों की पक्षधरता करता है, जिन पर उसे निगाह रखनी चाहिए, ताकि वे अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें और उनमें मनमाने तरीके से बदलाव न कर सकें। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के खिलाफ कठोर टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के एक मामले में की हो, लेकिन उसका यह आकलन तो लगभग सभी राज्यों के रेरा पर लागू होता है कि जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था, वे निराश और हताश हैं और उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिल रही। संभवतः इसीलिए उसने यहां तक कहा कि यदि इस संस्था को समाप्त भी कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ गया है कि सभी राज्य रेरा के नए सिरे से गठन पर विचार करें। इसमें संदेह है कि उसकी ओर से स्पष्ट निर्देश के बिना ऐसा हो सकेगा। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार यह देखे कि सभी राज्यों के रेरा सही तरह काम करें, क्योंकि सबमें खामियां घर कर गई हैं। कई मामलों में यह देखने में आया है कि रेरा ने उन बिल्डरों का बचाव किया, जो फ्लैट खरीदारों से साफ तौर पर वादाखिलाफी कर रहे थे। यदि रेरा के अस्तित्व में होने के बाद भी देश भर में लाखों प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। बहुत दिन नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही यह उजागर हुआ था कि दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बिल्डरों ने बैंकों से मिलकर लाखों फ्लैट खरीदारों के साथ ठगी की। यह ठगी सबवेंशन स्कीम के जरिये की गई।

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, शनिवार, 14 फरवरी 2026

यह जानना कि हम क्या जानते हैं और यह जानना कि हम क्या नहीं जानते, यही सच्चा ज्ञान है। –निकोलस कोपरनिकस

तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, हसीना विरोधी और कट्टरपंथी बुरी तरह हारे

शुक्रवार सुबह बांग्लादेश के आम चुनावों के परिणाम घोषित हो गए। 300 सीटों वाली संसद की 299 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। तारिक रहमान जो 17 वर्ष से देश के बाहर बैठकर बांग्लादेश की राजनीति में अपनी पार्टी बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं का संचालन कर रहे थे, के गठबंधन को 212 सीटों पर जीत मिली। कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी का गठबंधन जिसमें पिछले साल विद्रोह करने वाले छात्र संगठनों सहित कुल 11 दल थे, को करारी हार मिली और उन्हें 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीएनपी गठबंधन की जीत का अर्थ यह है कि तारिक रहमान को सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करने की पूरी छूट मिल गई। जनमत संग्रह का मुख्य विषय संविधान संशोधन ही था, जिसके मुख्य बिंदु थेः दो सदन वाली व्यवस्था, नये ऊपरी सदन में 100 सदस्य, पीएम के कार्यकाल को दस साल करना (इसमें पांच साल के दो टर्म होंगे) और छात्र आंदोलन की मुख्य मांग जुलाई चार्टर लागू करना। शेख हसीना के भारत शरण लेने के 18 महीने बाद हुए चुनावों में वीरवार को करीब 60 प्रतिशत तक हुई। शुक्रवार सुबह से दोपहर तक घोषित चुनाव परिणामों ने सीधा संदेश दिया कि जनता ने तारिक रहमान की बीएनपी को बांग्लादेश की बागडोर सौंप दी है। तारिक पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं। बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद महिलाओं का भारी वोट तारिक रहमान को मिला। महिलाओं ने जमात की कट्टरवादी राजनीति के खिलाफ वोट किया है। बांग्लादेश में रहते कुल आबादी के 9 प्रतिशत हिंदुओं ने भी बीएनपी को वोट देना बेहतर समझा क्योंकि जमात-ए-इस्लामी की कट्टरपंथी नीतियां उन्हें निरापद नहीं लगती थीं। इधर भारत में शरण लिए हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन चुनावों को फर्जी बताते हुए नतीजे रद्द करने की मांग की है लेकिन भारत ने इन चुनाव परिणामों का स्वागत किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए फोन पर बात की। ममता बनर्जी ने भी रहमान को भाई कहते हुए जीत की मुबारकबाद दी। जवाब में बीएनपी के चेयरमैन ने तारिक रहमान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की इच्छा जताई। बेशक अतीत का अनुभव यही है कि तारिक रहमान की पार्टी भारत के प्रति बहुत मित्रवत नहीं रही है लेकिन अब नई स्थितियों के अनुसार नेताओं के तेवर बदलते रहते हैं। भारत को ज्ञात है कि कट्टरपंथी जमात के स्थान पर तारिक रहमान और उनकी पार्टी की सत्ता में रिश्तों को रिसैट करने में आसानी होगी। संभव है कि दोनों देशों के बीच बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली, शेख हसीना सरकार के समय हुए समझौतों का यथावत रखने और अलगाववादी संगठनों को संरक्षण न देने जैसे मुद्दों पर सहमति बन सकती है।

हमारा विचार है, तारिक रहमान यह नहीं भूलेंगे कि बांग्लादेश के 1 करोड़ 60 लाख हिंदू वोटरों ने उत्साह से मतदान में भाग लेते हुए बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी को अधिक समर्थन दिया है। अब वे नई सरकार से सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। बांग्लादेश की नई सरकार का रवैया पाकिस्तान के साथ कैसा रहता है, यह भी देखने की बात होगी। फिलहाल बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मित्रवत ढंग से चल रहा है।

जमात-ए-इस्लामी जिसने एक सार्थक विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने का वक्तव्य दिया है, उनका हो-हल्ला भी अधिकतर पाकिस्तान के हक में ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बनते हुए एक ऐसा सामंजस्य पैदा करना होगा जिसमें पड़ोसी भारत के साथ सही आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार रहे और पाकिस्तान भी नाराज न हो। हमारे विचार में बांग्लादेश के चुनाव परिणाम भारत के लिए निराशाजनक नहीं है और दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करेंगे। –शीतल विज

श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों संबंधी बैठक

वीरवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम कुपित हो गया था। इसके चलते अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी थी। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह इतना था कि अंततः अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की संख्या में बढ़ौतरी ही देखी गई। इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ नये फैसले बैठक में किए गए हैं। पहली घोषणा यह है कि अमरनाथ यात्रा की पहली पूजा 29 जून को होगी। बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और सांग शो श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह किए जाएंगे। इसमें बाबा बर्फानी ही नहीं, केन्द्र शासित प्रदेश का आध्यात्मिक इतिहास खूबसूरती से प्रदर्शित किया जाएगा।

फिलहाल यात्रा की औपचारिक तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने कुछ कदम अभी से उठाने का फैसला कर लिया है। पहला कदम यह है कि रजिस्टर्ड यात्रियों, यात्रा श्रमिकों और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा का कवर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में यात्रा को सुगम, सहज और सुरक्षित करने के लिए बहुत से कल्याणकारी उपाय करने का भी फैसला किया गया। राज्यपाल ने अधिकारियों को यात्रा के मार्ग में उपयुक्त शौचालय सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया, ये कहां बनाए जाएंगे इसकी पहचान अभी से की जाए। पिछला अनुभव यह था कि तीर्थ यात्रा में सेवाप्रदाता, सुरक्षा कर्मी और यात्री भी मार्ग पटरियों पर भारी बारिश के कारण बहुत तंग हुए थे, अब बारिश से बचाव के लिए अधिक शैड बनाए जाएंगे।

मौसम का अनुमान लगाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारा जाएगा ताकि मौसम का अचानक कुठाराघात न हो, इसके बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त की जा सके। प्रशासन, सुरक्षा, निगरानी और सेवा-यह चार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए डिजिटल प्रीपेड सिस्टम बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने के लिए अब दो रास्ते बन चुके हैं। दोनों रास्तों के कमजोर हिस्सों पर क्रैश बैरियर और सेफ्टी रेलिंग लगाए जाएंगे। अब अलग-अलग विभाग इन कामों की तरक्की और सफलता की चौकसी करेंगे। गौरतलब है कि देश-विदेश से भारी संख्या में यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आते हैं। पिछली बार यात्रियों की चाक-चौबंद सुरक्षा के दौरान सुविधाओं में जो कुछ त्रुटियां रह गई थीं, इस बार श्रद्धालुओं और प्रबंधकों को उनका सामना न करना पड़े, इस पर श्राइन बोर्ड की 50वीं बैठक में मुख्य जोर दिया गया है। –शीतल विज

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

डिजिटल धोखाधड़ी पर तुरंत लगे लगाम ताकि नासूर न बने वित्तीय लेनदेन

यदि सोशल मीडिया कुछ ही घंटों में संदिग्ध अकाउंट हटाए, केवाईसी डेटा जांच एजेंसियों से साझा करे, तो नैटवर्क तोड़ा जा सकता है

संजय श्रीवास्तव

कई राज्यों के बजट से भी अधिक के डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को पूरे देश में एक मानकीकृत संचालन प्रक्रिया अथवा एसओपी लागू करने का निर्देश अत्यंत स्वागतयोग्य है। उसने सीबीआई से डिजिटल अरैस्ट के अपराधियों की पहचानने के लिए भी कहा है और बैंकों को भी उनकी कार्यप्रणाली में खोट तथा लापरवाही ही नहीं बल्कि मिलीभगत के लिए भी लताड़ा है। वाकई 54 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस मर्ज की अकसीर दवा न तलाशी गई तो रोग वित्तीय नासूर बन जाएगा।

बेशक, बैंक यदि संदिग्ध लेनदेन पर ग्राहकों को सतर्क करते हैं और साइबर अपराधों की पहचान तथा जांच के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय मजबूत रखते, तो आंकड़े शायद अलग दिखते। पर फिर भी इस पर पूरी रोक के लिए व्यापक बहुआयामी उपाय अपनाने होंगे जिसमें न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था सुधार, तकनीक, जन जागरूकता बल्कि दूसरे कारकों पर भी ध्यान देना होगा। डिजिटल युग की तेज रफ्तार ने आसान भुगतान को साइबर ठगों ने विविध तरीकों से लूट का हथियार बना लिया। वह फिशिंग ई-मेल से लिंक क्लिक करवाता है, स्मिशिंग से एसएमएस तो विशिंग फोन कॉल से ओटीपी मांगता है। स्पियर फिशिंग लक्षित व्यक्ति पर हमला करता है, तो स्किमिंग एटीएम से कार्ड डेटा चुराता है और सिम स्वैप नंबर हाईजैक करता है। वैबसाइट स्पूफिंग बैंक साइट की नकल से, मेलवेयर डिवाइस संक्रमित करता है। जनता को स्मिशिंग-स्पियर फिशिंग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये रोजमर्रा के संदेश सरीखे लगते हैं। ऐसे में लगता है कि तकनीकी का जंजाल ही सबकी वजह है पर डिजिटल फ्रॉड के मामलों में सिर्फ तकनीक दोषी नहीं है अथवा महज सरकार या फिर मात्र बैंकिंग व्यवस्था बल्कि जनता की अल्पज्ञता, लोभ-लालच और भय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जागरूकता अभियान, विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा शिक्षाएं और आम नागरिकों को साधारण फ्रॉड के तरीकों से परिचित कराना अब अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि इस खेल में बैंक भी शामिल हैं, बैंक केवल लेनदेन का 'ब्रोकरेज हब' बन गए जबकि उन्हें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय निगरानी और अलर्ट सिस्टम लागू करना चाहिए था। यदि बैंक संदिग्ध तौरपर किसी खाते से अचानक बड़ी रकम निकासी या अंजान स्रोतों से फंड ट्रांसफर को समय पर चिन्हित कर सूचना की प्रणाली को ईमानदारी से अपनाते तो यह मामले काफी कम होते।

म्यूल अकाउंट फ्रॉड का केंद्र हैं। म्यूल खातों द्वारा भारी राशि का अंतरण और अपराधियों द्वारा पैसों की हेराफेरी कर करोड़ों रुपये विदेशों को भेज पाना बिना बैंकों की लापरवाही और उनके इस खेल में शामिल हुए बिना संभव नहीं। इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि बैंक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग उचित प्रकार से अपनाएं तथा एआई से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करने के अलावा एफआईयू-इंडिया को रिपोर्टिंग और अंतर-बैंक डेटा शेयरिंग बढ़ाएं तो ये उपाय 50 फीसदी तक डिजिटल फ्रॉड रोक सकते हैं। नए खातों पर लेनदेन सीमा, लाभार्थी जोड़ने पर 'कूलिंग-ऑफ' अवधि और उच्च-जोखिम श्रेणी की सतत निगरानी प्रभावी उपाय हो सकते हैं। फ्रॉड

की जड़ें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्मों से जुड़ती हैं, फर्जी विज्ञापन, स्पूफ वैबसाइट, डीएम या मैसेजिंग के जरिए फिशिंग और म्यूल अकाउंट में धन-स्थानांतरण के ये कारक हैं। यदि सोशल मीडिया कुछ ही घंटों में संदिग्ध अकाउंट हटाए, केवाईसी डेटा जांच एजेंसियों से साझा करे, तो नैटवर्क तोड़ा जा सकता है। साइबर अपराधी कमाई को क्रिप्टो, प्रीपेड कार्ड, या लेयरिंग के जरिए बाहर भेजते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एफआईयू-ईडी-सीबीआई समन्वय और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर सख्त नियम अनुपालन आवश्यक है। संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस पर अस्थायी होल्ड और लाभार्थी देशों के साथ त्वरित म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समझौते इसमें मददगार हो सकते हैं। हालांकि सीबीआई और राज्य साइबर सेल की क्षमता बढ़ी है, डिजिटल अरैस्ट के कई मामले सुलझाए गए हैं तो पिछले साल बैंक फ्रॉड मामलों में गिरावट आई पर राशि 3 गुना बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये हो गई कार्ड-इंटरनैट फ्रॉड के 13,516 मामलों में 520 करोड़ की ठगी हुई और कुल डिजिटल फ्रॉड 54,000 करोड़ के पार चला गया। जाहिर है परिमाण को देखते हुए सफलता नाकाफी थी। सीमा-पार ट्रैकिंग और त्वरित डेटा-शेयरिंग में अभी भी संसाधन व अधिकार-क्षेत्र की चुनौतियां दूर करना, साइबर अदालतें और फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल अदालत को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक एसओपी निस्संदेह समयोचित हस्तक्षेप है, पर किसी एक एसओपी के जरिए इतने बड़े और विविध स्तर पर होने वाले साइबर और डिजिटल वित्तीय अपराध को नहीं रोका जा सकता है। एसओपी के कड़ाई से पालन से कुछ मामलों को तो रोका जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं है। आरबीआई ने इस तरह की मानकीकृत संचालन प्रक्रिया तैयार कर रखी है, अब नये सिरे से व्यापक एसओपी तैयार करना, उसे देशव्यापी स्तर पर लागू करवाना तभी प्रभावी होगा, जब इसे वित्तीय संस्थानों, बैंक अधिकारियों, टैलीकॉम पोर्टलों और साइबर पुलिस के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करने और त्वरित कार्रवाई की तकनीकी सक्षमता के साथ जोड़कर व्यवहारिक तौरपर कड़ाई से लागू किया जाए।

एआई आधारित अलर्ट सिस्टम को निगरानी में शामिल करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपाय है। डिजिटल साधनों के व्यापक और तीव्र विस्तार के अनुरूप डिजिटल प्राइवेसी के उल्लंघन के खिलाफ पर्याप्त कानून और सुरक्षा ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। लाखों लोग एक ही फोन नंबर या ईमेल से कई प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जिससे फ्रॉड करने वालों को उपयोगकर्ता के प्रोफाइल तक आसानी से पहुंच मिल जाती है। आवश्यकता है कि डेटा सुरक्षा कानून को अधिक स्पष्ट, उपयोगकर्ता-केंद्रित और सख्त बनाया जाए और इसका पालन भी सुनिश्चित हो। इसके साथ-साथ डिजिटल शिक्षा, व्यापक जागरूकता, डेटा प्राइवेसी कानूनों का सख्त अनुपालन और बैंकिंग तंत्र की सक्रिय भूमिका भी अत्यावश्यक है।

एसओपी आवश्यक है, पर तकनीकी ढांचे, एआई-आधारित अलर्ट, म्यूल अकाउंट पर नकेल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जवाबदेही और स्पष्ट मुआवजा कानून एवं त्वरित मुआवजा तंत्र के साथ जोड़े बिना यह पर्याप्त नहीं, इन सबका संयोजन ही समाधान देगा। ऐसा न हो सका तो ठगी जारी रहेगी और बैंकिंग प्रणाली में जनता का भरोसा क्षीण होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव डगमगा जाएगी। बात डिजिटल फ्रॉड से पीडितों को मुआवजे की भी है। कोर्ट ने सरकार को पीड़ितों को पैसा लौटाने की ठोस नीति मांगी है। मुआवजे के जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, संबंधित बैंक की अथवा आरबीआई की? मुआवजा बैंक-सरकार का संयुक्त दायित्व लगता है पर सिद्धांततः प्राथमिक जिम्मेदारी उस बैंक या फिर भुगतान इंटरमीडियरी की होनी चाहिए जहां सुरक्षा में चूक हुई। जहां तक आरबीआई का प्रश्न है उसने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया पर कमजोर सुरक्षा के लिए वह सीधे दोषी नहीं। आरबीआई नियामक है, उसका दायित्व मौद्रिक स्थिरता और बैंकिंग निगरानी है।

अगर आरबीआई मुआवजे के काम में उतरता है तो उसका यह हस्तक्षेप 'मिशन क्रीप' बनेगा, डोमेन ओवरलैप या अधिकार क्षेत्र में टकराव पैदा होगा। यदि यह धारणा बने कि हर नुकसान की भरपाई केंद्रीय बैंक करेगा, तो बैंकों और उपभोक्ताओं की सतर्कता घट सकती है। फिलहाल इतना कहना पर्याप्त होगा कि डिजिटल फ्रॉड के व्यापक अपराध के निबटने, पीड़ितों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति और भरोसे के लिए हमें एसओपी तथा कानून बनाने के अलावा भी बहुत कुछ करना होगा जैसे डिजिटल शिक्षा, डेटा प्राइवेसी कानूनों का सख्त अनुपालन और बैंकिंग तंत्र को दुरुस्त करना। डिजिटल इंडिया के लिए फ्रॉड प्रूफ होना अनिवार्य तत्व है।

बांग्लादेश को किस दिशा में ले जाएंगे तारिक रहमान

बांग्लादेश चुनाव/ विजय कपूर

जनरल जिया-उर-रहमान व खालिदा जिया के 60-वर्षीय बेटे तारिक रहमान 17-साल तक निर्वासन में रहने के बाद स्वदेश लौटे, चुनाव लड़ा और अब वह बांग्लादेश के नये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) गठबंधन ने 12 फरवरी 2026 को जातीय संसद के लिए हुए 13वें आम चुनाव में 212 सीटें जीती है, स्थानीय जमुना आदि टीवी चैनलों के अनुसार। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को कुल 70 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें 5 सीटें नैशनल सिटीजन पार्टी की हैं, जिसने जेन जी आंदोलन में शेख हसीना का तख्ता पलटने में अहम भूमिका अदा की थी। शेख हसीना, जो इस समय भारत में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं, कि अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए वह चुनाव में भाग न ले सकी।

शेख हसीना ने चुनाव को 'सुनियोजित स्वांग' बताया है। बहरहाल, 300 में से 299 संसदीय सीटों के लिए 50 राजनीतिक दलों के सदस्यों व स्वतंत्र प्रत्याशियों सहित लगभग 2000 उम्मीदवार मैदान में थे और तकरीबन 48 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2024 के आम चुनाव के 42 प्रतिशत मतदान से बेहतर रहा। इस मतदान में मतदाताओं को दो वोट डालनी थीं, एक सांसद चुनने के लिए और दूसरी संवैधानिक 'सुधारों' के संदर्भ में जनमत संग्रह के लिए। बांग्लादेश के एक सदन वाले राष्ट्रीय संसद को जातीय संघसद कहते हैं। इसमें 300 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो चुनाव के बाद पार्टियों में उनकी जीत के अनुपात में विभाजित कर दी जाती हैं। बांग्लादेश में 1973 से 2026 तक जो कुल 13 आम चुनाव हुए हैं, उनमें से सिर्फ पांच (1991, 1996-2, 2001, 2008 व 2026) को ही अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव घोषित किए हैं। 1996 में दो बार आम चुनाव कराने पड़े थे; क्योंकि 1996-1 चुनाव को अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने बायकाट किया था और बीएनपी ने खुद को 278 सीटों पर जीता हुआ दिखाया था। दरअसल, बांग्लादेश में अधिकतर चुनावों की कहानी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बायकाट व उन पर प्रतिबंध के इर्दगिर्द ही घूमती रही है।

इस बार के आम चुनाव में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध था और जो पार्टियां- बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी, जो वर्षों तक चुनावी दौड़ से बाहर रहीं या उन्हें बाहर रखा गया, सत्ता की मुख्य दावेदार बनकर उभरी। शेख हसीना ने 2009 के बाद से 15 साल तक निरंतर राज किया और उनके शासनकाल में बांग्लादेश में स्थिरता व आर्थिक विकास देखने को मिला। लेकिन साथ ही उन पर तानाशाह होने के भी आरोप लगे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और 2024 में उन्हें अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। यह केवल इतना नहीं था कि अलोकप्रिय हुए नेता को हिंसक विद्रोह में सत्ता से हटा दिया गया बल्कि छात्रों के आंदोलन में बांग्लादेश के बुनियादी इतिहास को भी मिटाने का प्रयास किया गया, जिसमें शेख हसीना के पिता व उनकी पार्टी अवामी लीग के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान प्रमुख शख्सियत थे। जैसे ही अवामी लीग के लीडर व समर्थक अंडरग्राउंड हुए बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता के नये दावेदारों के रूप में उभरने लगीं, विशेषकर नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में।

हालांकि अब तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी गठबंधन का सत्ता में आना तय हो गया है, लेकिन बांग्लादेश के समक्ष चुनौतियों का अम्बार लगा हुआ है। सबसे पहले तो पिछले 18 माह में धीमे हुए आर्थिक विकास को पटरी पर लाने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगारी, महंगाई आदि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर जो हिंसक हमले हो रहे हैं, उन पर त्वरित प्रभाव से विराम लगाया जाए। बीएनपी से सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद की जा सकती है, विशेषकर इसलिए कि उसके प्रमुख हिंदू लीडर ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका-3 सीट से शानदार जीत दर्ज की है, जमात-ए-इस्लामी के मुहम्मद शाहीनूर इस्लाम को पराजित करके। रॉय की जीत बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है कि ढाका-3, जो मुस्लिम बहुल सीट है, पर पहली बार कोई हिंदू प्रत्याशी जीता है। रॉय बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं।

बहरहाल, तारिक रहमान के समक्ष भारत से संबंध सुधारने की भी चुनौती है, जो शेख हसीना को शरण देने की वजह से प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि तारिक रहमान जब आत्म-निर्वासन से बांग्लादेश लौटे थे, तो नई दिल्ली ने अपने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को उनसे मुलाकात करने के लिए ढाका भेजा था। इसलिए भारत व बांग्लादेश के संबंध बेहतर होने की संभावना है। बांग्लादेश में मतदान के साथ ही जुलाई नैशनल चार्टर, जो 84-पॉइंट का सुधार पैकेज है, पर भी जनमत संग्रह हुआ था। इस चार्टर को जनता ने अपनी सहमति दी है, लेकिन जनमत संग्रह कहीं भी अच्छा विचार साबित नहीं हुआ है। ब्रिटेन के सांसद 1998 में इस विषय पर कुछ भी तय नहीं कर पाए थे। ब्रिटेन से अधिक स्विट्जरलैंड जनमत संग्रह में माहिर रहा है कि उसने 1981 व 1999 के बीच 148 जनमत संग्रह कराए। भारत में 1975 के बाद से कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। पाक ने आखिरी बार 2002 में कराया था। क्या इससे स्विस लोकतंत्र हम से अधिक 'परफैक्ट' हो जाता है? सिद्धांत में, शायद। व्यवहार में, हमें नतीजों के आधार पर समीक्षा करनी चाहिए।

आजाद भारत में प्रत्येक पुरुष व महिला को 1950 में ही मतदान का अधिकार मिल गया था। स्विट्जरलैंड में पुरुषों ने 1959 में महिलाओं को मतदान दिए जाने के जनमत संग्रह को ठुकरा दिया था और इस गलती का सुधार इसके 12 साल बाद किया गया। यह सही है कि जनमत संग्रह लोकतंत्र की जड़ों के बहुत करीब है, लेकिन विशेषज्ञों की राय से संचालित प्रतिनिधि लोकतंत्र के अपने लाभ हैं। अधिकतर समकालीन मुद्दे जैसे भारत में अधिक परमाणु ऊर्जा प्लांट्स और वह भी थोरियम ईंधन वाले, होने चाहिए या नहीं, आम मतदाताओं के लिए बहुत जटिल हैं। सरकारें जनता को अपनी नीतियों के लाभ व हानि के बारे में जागरूक करें, लेकिन 5 मिनट का ज्ञान प्रोफैशनल महारत का विकल्प नहीं है।

याद करें कि केरल ने 2018 में जनमत संग्रह कराने का ऑफर दिया था कि महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। उसी साल ब्रिटेन ने 52 प्रतिशत 'हां' व 48 प्रतिशत 'न' से यूरोपीय संघ से निकलना तय किया, जो अब गलत साबित हुआ। जनमत संग्रह की सबसे बड़ी समस्या बहुसंख्यावाद है, जिससे से अल्पसंख्यकों के हित प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश में 'बेगमों की जंग' पर तो विराम लग गया है कि खालिदा जिया का निधन हो चुका है और शेख हसीना देश में मौजूद नहीं हैं और 'मानवता के विरुद्ध अपराधों' के लिए अदालत उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है। इसलिए बांग्लादेश में तारिक रहमान के साथ एक नये युग का आरंभ हो रहा है। वक्त ही बताएगा कि वह अपने देश को किस दिशा में लेकर जाएंगे, जबकि उनसे उम्मीदें तो बहुत हैं।

एपस्टीन फाइल्स की चर्चा देश में क्यों

मीडिया में पिछले कई दिनों से एपस्टीन फाइल्स का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। एपस्टीन फाइल्स नाम अपने आप में चौंका देने वाला है। लोग इसके फोटो, इसके कामकाज, शैली और इसके अंदर दिखाए जाने वाले कुकर्मों पर चर्चा कर रहे हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया गया है। विश्व के लगभग सभी बड़े चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों का यह काला सच है। अमेरिका और बहुत से यूरोपीय देशों में ऐसा खुला व्यवहार साधारण सी बात हो सकती है क्योंकि यह वहां की नीति का हिस्सा है लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मारना, उनका मांस खाना, उनका यौन उत्पीड़न करना आदि इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। अब चलते हैं भारतीय जीवन शैली की ओर। भारतीय जीवन शैली अध्यात्म से जुड़ी हुई है. यह आत्मा के मुक्त होने की साधना पर चलती है। यहां आवागमन के चक्कर से मुक्ति का सबसे बड़ा काम होता है। भारतीय सनातन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो यहां भोगवादी संस्कृति नहीं बल्कि आध्यात्मिक संस्कृति का सबसे बड़ा काम होता है।

यहां पर तीज-त्यौहार, व्रत इतने हैं कि लोग उन्हीं में अपने जीवन की व्यवस्था और व्यस्तता को रखते हैं। संकल्प सिद्धि वाले इस देश में भोगवादी संस्कृति कहां टिकने वाली है। यहां व्रत और तीज-त्योहार का पालन पारिवारिक लोग ही कर रहे होते हैं। जब करवा चौथ की बात होती है तो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए महिलाएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती, चंद्रमा को देखकर ही व्रत को खोलती हैं। छठ मईया का व्रत तो पूरी रात जल में खड़ा रहना और सूर्योदय के साथ उसको खोलना है। भारतीय संस्कृति में व्रत की महिमा है। खाने-पीने या भोग की प्रवृत्ति न होकर अन्न-जल और विषय वस्तुओं को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने की बहुत बड़ी सार्थकता है। हम यहां भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और कर्म प्रधान समाज में कर्म करते हुए, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं जबकि इसके दूसरी ओर यदि आप यूरोपीय या अमेरिका के अन्य देशों की बात करें तो वहां पर अध्यात्मवादी नहीं बल्कि भोगवादी संस्कृति आप देखोगे। वहां कपड़े पहनना ना पहनना, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ, पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ, अपने संबंध स्थापित कर लेता हैं। ऐसे ही वहां संतान उत्पत्ति हो भी रही है।

तर्क/ डा. नीरज भारद्वाज

परिवार के प्रति बहुत कम लोगों का रुझान देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तो शादी ही नहीं करते बल्कि अपनी दैहिक भूख मिटाने के लिए बाजार का सहारा लेते हैं। सही मायनों में यही एपस्टीन फाइल्स हैं। इन देशों में देह बाजार में बिकती है, लोग उपभोग की वस्तु का मूल्य देकर सुख भोग लेते हैं। इन देशों में हर चीज बाजार है। मनुष्यता के नाम पर भी नर-नारी के बीच के संबंधों को ज्यादा महत्ता नहीं देते। यदि एक ऐसी फाइल्स अमेरिका और यूरोप के लोगों को लेकर खुलती है, जिसमें अलग-अलग देशों के बड़े-बड़े धनपति और उद्योगपति दिखाई देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।

दूसरी ओर शोर मच रहा है कि वहां पर कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा था। वह उन देशों की विडंबना है। वह किस तरीके से उन सब संबंधों को देखते-समझते रहते हैं, यह उनकी समझ है। माना कि बच्चों के साथ यौन शोषण होना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनकी पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान सभी कुछ इनसे ले लेना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय परिवेश अर्थात सनातन संस्कृति में ऐसी चर्चाओं को करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या हम भी इस ओर बढ़ रहे हैं? भारतीय लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। अपवाद तो हर जगह मिल ही जाते हैं।

विश्व चारों तरफ युद्ध के माहौल से जूझ रहा है। इसमें यूरोपीय देश और अमेरिका यह सब वैश्विक मंदी से डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में विश्व का ध्यान युद्ध, डॉलर की टूटती हुई कीमतें, उद्योग और वहां के व्यापार में हो रहे घाटे को देखते हुए विश्व का ध्यान भंग करने के लिए अमेरिका और अन्य देश मिलकर ऐसी चर्चा को विश्व में जीवित करना चाह रहे हैं जिससे कि विश्व का ध्यान उन सब बातों से हट जाए। डी डॉलराइजेशन, वहां की मार्कीट में क्राइसिस आना, उद्योगपतियों का उसे देश के प्रति ध्यान हटना आदि, एशियाई देशों का वर्चस्व बढ़ना, व्यापारियों का वहां खर्च करना, नए उद्योग-धंधों का शुरू करना आदि भी इन देशों को खटक रहा है। वहां डर का माहौल बना हुआ है, इस डर के माहौल से उबरने के लिए अमेरिका, उसके सहयोगी देश या वहां की सरकार ऐसे खुलासे दुनिया के सामने रख देना चाहती है। लोगों का ध्यान भंग हो जाएगा और वह यहीं उलझ कर रह जाएंगे तथा अपना काम निकालने की सोच रहे हैं जबकि यह सारी घटना या इन फाइल्स के जो भी कार्य हैं, वह बहुत साल पुराने हैं और कुछ ताजा भी हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं गिनाई जा सकती हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इन देशों का वास्तविक चेहरा यही है, निर्णय आपको लेना है।

कार्टून कोना

विश्व मित्र

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही नौ मार्च तक स्थगित

वैलेंटाइन डे की आड़ में जवानों की शहादत गुमनाम न हो जाए

जहां देश में युवक और युवती आपसी प्रेम के इजहार को लेकर बड़े ही बेसब्री से 14 फरवरी का इंतजार करते है और पर्व 7 फरवरी से 14 फरवरी तक विभिन्न दिवस के रूप मनाया जाता है लेकिन देश के युवा वैलेंटाइन डे के चक्कर में देश के वीर जवानों की शहादत को ध्यान में न रखकर केवल प्रेम और मोहब्बत के झूठे जंजाल में खुद को बर्बाद कर रहे हैं। प्रेम के नाम पर केवल मौज-मस्ती और दिखावा युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है।

जहां देश में लोग वीर जवानों की कुर्बानी को याद करते हैं और शहीद जवानों की याद में 14 फरवरी को 'ब्लैक डे' मनाया जाता है वहीं देश के भविष्य युवा वीरों की शहादत को याद करने की बजाय भारतीय संस्कृति को गंदा करने वाले वैलेंटाइन डे में मशगूल रहते हैं। 14 फरवरी को भारत के इतिहास में 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 2019 में पुलवामा में हुआ हमला आतंकवाद का एक विनाशकारी रूप था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जम्मू-कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। जैसे ही काफिला अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास पहुंचा, एक वाहन काफिले में शामिल बसों के बहुत करीब आ गया। सैनिकों की ओर से ड्राइवर को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वाहन ने आदेशों की अनदेखी करना जारी रखा। एक भयावह क्षण में, वाहन बसों में से एक से टकरा गया जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 40 बहादुर सैनिकों की जान चली गई।

बलिदान/ संतोष कुमार तिवारी

यह आतंकवादी हमला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवंतीपोरा के गोरीपोरा में हुआ। सीआरपीएफ का काफिला, जिसमें 60 से अधिक सैन्य वाहन और लगभग 2,547 सैनिक शामिल थे, इस क्षेत्र से गुजर रहा था। विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने सैन्य बसों में से एक को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, जो इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसने आसपास के क्षेत्र को धुएं और आग के घने बादल में घेर लिया। दुखद रूप से इस भीषण हमले में 40 से अधिक सैनिकों की जान चली गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अवंतीपोरा में हुए विनाशकारी हमले की जिम्मेदारी ली। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि काफिले में शामिल कई बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकवाद के इस क्रूर कृत्य ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया और सभी की निगाहें सरकार और सेना पर टिक गई जो शहीद सैनिकों का बदला लेने के लिए एक मजबूत और निर्णायक जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुलवामा आतंकवादी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने 25 फरवरी 2019 की देर रात पाकिस्तान के बालाकोट पर जवाबी हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन के दौरान, लगभग 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। यह ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ किया गया और पाकिस्तान को चौंका दिया गया।

इस निर्णायक कार्रवाई को बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक नाम दिया गया। बालाकोट हवाई हमले के दौरान, भारत के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने एक पाकिस्तानी एफ-16 जैट को भी मार गिराया। हालांकि, ऑपरेशन के दौरान, मिग-21 क्षतिग्रस्त हो गया और पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद, अभिनंदन को 1 मार्च, 2019 को पाकिस्तान द्वारा रिहा कर दिया गया। उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित 'वीर चक्र' से सम्मानित किया।

देश के वीर जवानों की शहादत पर यदि देश का युवा जिसके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है, वह देशभक्ति से हटकर फर्जी प्रेम दिवस मनाने में जुटा हो तो सोचा जा सकता है कि हमारा देश कहां जा रहा है? देश के युवाओं से अपील है कि आपके कंधे पर देश की जिम्मेदारी है और आप जिस क्षेत्र में है, उस काम को जिम्मेदारी से करें और राष्ट्रहित सर्वोपरि को ध्यान में रखकर कार्य करें। वैलेंटाइन डे के नाम पर जिस तरह देश के युवा क्षणिक प्रेम के लिए भारतीय संस्कृति और संस्कार को तिलांजलि दे रहे है और जवानों की शहादत गुमनाम हो रही है, वह सर्वथा अनुचित है।

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नैटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

प्रेरणा

सुबह का एक छोटा-सा सकारात्मक विचार पूरे दिन को बदल सकता है। - **दलाई लामा**

संपादकीय

एआई में मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका में आना होगा

नई दिल्ली में सोमवार से आयोजित पांच दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट (चौथा संस्करण) पहली बार ग्लोबल साउथ में होने जा रही है। भारत इसे गरीब और विकासशील देशों के लिए लाभकारी बनाना चाहेगा। इसमें हमारे लिए दो स्वर्णिम अवसर हैं। पहला पश्चिमी कॉर्पोरेट जगत चाइना प्लस वन नीति के तहत पहले ही चीन का विकल्प तलाश रहा था। ये कंपनियां भारत को न केवल उपभोक्ता के रूप में पाती हैं बल्कि डेटा की सबसे बड़ी खान के रूप में भारत को उत्पादन-स्थल भी बना सकती हैं। लेकिन यहां भारत को अपनी भूमिका बदलनी होगी। हमेशा उपभोक्ता बने रहने से अग्रिम पंक्ति तक पहुंचना संभव नहीं होता। लिहाजा भारत का टैलेंट पूल इन कंपनियों में काम जरूर करे, लेकिन सरकार की नजर स्वयं ताइवान की टीएसएमसी की भूमिका में आने की रहे, यानी फाउंड्री, एडवांस्ड पैकेजिंग, चिप, प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग के अवसर तलाशे जाएं। इन बड़ी कंपनियों को भारत में निर्माण से यह लाभ भी होगा कि उपभोक्ता-बाजार भी तलाशना नहीं पड़ेगा। इस बैठक में भारत चर्चा का केंद्र-बिंदु उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कृषि, वस्तु-निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य में एआई टूल्स का इस्तेमाल करना बनाना चाहेगा। हां, भारत को इस अवसर के लाभ लेने के लिए डेटा सेंटर्स में भारी बिजली-पानी की जरूरत भी सुनिश्चित करनी होगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

भगवान को ढूंढा और दुनिया की वस्तुओं को खोजा जाए

ढूंढना और खोजना, दो अलग-अलग बातें हैं। ढूंढा उसे जाता है, जो पहले से प्राप्त हो और आप कहीं रखकर भूल गए। खोजा उसे जाता है, जो अप्राप्त हो। इसलिए भगवान को ढूंढा जाए और दुनिया की वस्तुओं को खोजा जाए। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति है और संसार की वस्तुएं अप्राप्त की प्राप्ति हैं। आजकल एआई के माध्यम से अप्राप्त की प्राप्ति बहुत आसान हो गई। इसका जन्म कोई आज नहीं हुआ। लगभग 75 साल पहले एलन ट्यूरिंग ने दिमाग वाली मशीन बना दी थी और उसी के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराया गया। दुनिया के देश जान चुके हैं कि एआई के जो फायदे होंगे वो अपनी जगह, पर जो नुकसान है- वह बहुत बड़ा विस्फोट होगा। हमें एक निजी अनुशासन बना लेना चाहिए कि हम किस सीमा तक इस भस्मासुर का सदुपयोग करें। और उसके बाद एक लक्ष्मण रेखा खींच ली जाए कि न तो यह रावण अंदर आ सके और न ही हमारी शांति, शक्ति और भक्ति रूपी सीता बाहर जा सके।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

डिफ्रेंट एंगल • दुनिया अब कम शराब पी रही है...

जिंदगी का स्वाद किसी भी तरह के नशे से बेहतर है!

वेलनेस

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

एक सकारात्मक तथ्य सुनें : दुनिया अब पहले की तुलना में शराब का कम सेवन कर रही है। शराब उन चीजों में मानी जाती है, जिस पर अगर कड़ी पाबंदियां, नियंत्रण और टैक्स न लगाए जाएं, तो मनुष्य उस पर टूट पड़ेंगे। और इसके बावजूद वैश्विक रुझान स्पष्ट हैं कि बिक्री घट रही है। लोग अब पीना नहीं चाहते। अमेरिका में गैलप सर्वेक्षण से पता चला कि 2025 में 54% अमेरिकी ही किसी रूप में शराब का सेवन कर रहे थे- यह 90 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। कुछ श्रेणियां विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं। जैसे वाइन की खपत में उल्लेखनीय गिरावट है- लगभग 20% या उससे अधिक। यहां तक कि बीयर-प्रेमी यूरोप में भी मार्केट-रिसर्च से पता चला कि 71% उपभोक्ता अब या तो कम पी रहे हैं या पूरी तरह शराब छोड़ रहे हैं।

इस ग्लोबल ट्रेंड में भारत जरूर अपवाद लग सकता है, जहां शराब-बिक्री की मात्रा लगभग 7% वार्षिक दर से बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका और यूरोप में आज भी जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक शराब खपत लगभग 8-9 लीटर के आसपास है, वहीं भारत में यह लगभग 3 लीटर प्रतिवर्ष ही है। संभव है कि भविष्य में भारत में भी शराब की बिक्री किसी स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाए और फिर गिरावट देखने को मिले। भारत के कुछ शहरी वर्गों में परिवर्तन के शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं। महानगरों में ऐसे समूह उभर रहे हैं, जहां जेन-जी उपभोक्ताओं के बीच बीयर और पारंपरिक शराब की खपत स्थिर हो रही है या घट रही है।

लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि दुनिया अब पहले की तुलना में कम क्यों पी रही है? एक कारण तो यह है कि आज लोग पहले की तुलना में स्वास्थ्य को लेकर अधिक सचेत हैं। कम सिगरेट, अधिक योग, अधिक ग्रीन जूस और कम शराब- यह हेल्थ का मूलमंत्र बनता जा रहा है। प्रमुख स्वास्थ्य मंचों पर प्रकाशित लेख भी इस ट्रेंड को रेखांकित करते हैं कि लोग अब 'हैंगओवर' की तुलना में 'वेलनेस' को प्राथमिकता दे रहे हैं।

दूसरे, अब सामाजिक निगरानी भी खासी बढ़ गई है। आज हर जेब में एक वीडियो कैमरा है, जो किसी भी क्षण आपका वीडियो बनाकर शेयर कर सकता है। कोई व्यक्ति अगली सुबह सोशल मीडिया पर यह बता सकता है कि आप पिछली रात पब में क्या कर रहे थे। लड़ाई-फसाद, बेसुरे गाने से लेकर उलटियां करने और बेहोश होने तक- शराब से जुड़े ये तमाम दृश्य यदि सार्वजनिक हो जाएं, तो गहरी सामाजिक शर्म का कारण बन सकते हैं। नौकरी जा सकती है, सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता है।

हालिया अध्ययनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब हर हाल में नुकसानदेह है- यहां तक कि सीमित मात्रा में लिए जाने पर भी। प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पीने का कोई भी स्तर वास्तव में सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, सुविधा के मिले-जुले असर से ड्रिंकिंग-कल्चर में बदलाव आ रहे हैं।

इस बदलाव का समाज पर यह सकारात्मक असर पड़ेगा कि बीमारियों और दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गैर-मादक पेयों तथा 'सोबर-इवेंट्स' जैसे स्वस्थ विकल्पों का उभार होगा। ये बात और है कि अब ऐसी जगहें कम होती जा रही हैं, जहां लोग अपने घर और दफ्तर के बाहर 'ऑफलाइन' मिलते थे और ड्रिंकिंग इसका एक बहाना हुआ करता था। यानी इसका असर 'सोशलाइजेशन' पर पड़ेगा। सरकारों की कमाई भी घटेगी। ऐसे बार और रेस्तरां पर भी इसकी मार पड़ेगी, जिनके लिए शराब की बिक्री राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैसे आज का सबसे बड़ा एडिक्शन शराब का नहीं, स्क्रीन और सोशल मीडिया से मिलने वाले डोपामिन-हिट्स का है। मनोवैज्ञानिक फोन के अत्यधिक उपयोग की तुलना शराब जैसे व्यसन से करते हैं।

> **आज लोग पहले की तुलना में स्वास्थ्य को लेकर अधिक सचेत हैं। कम सिगरेट, अधिक योग, अधिक ग्रीन जूस और कम शराब- यह हेल्थ का मूलमंत्र बनता जा रहा है। लोग अब 'हैंगओवर' की तुलना में 'वेलनेस' को प्राथमिकता दे रहे हैं।**

बहरहाल, अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जीवन शराब के बिना भी सामाजिक और जीवंत हो सकता है। अगर पीते हैं तो इसे कम करने पर विचार करें। आपका लिवर इसके लिए आपको थैंक्यू कहेगा, आपकी जेब पहले की तुलना में आपका ज्यादा साथ देगी और लॉन्ग-टर्म में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही यह भी याद रखें कि शराब की जगह किसी और लत को अपने जीवन में न आने दें। फोन, अनवरत स्क्रॉलिंग, 'लाइक्स' का जुनून यदि नियंत्रित न हो, तो ये भी उतने ही हानिकारक हो सकते हैं।

सामाजिक जीवन, सार्थक संबंध, साझा मुस्कराहटें- यही वो चीजें हैं जिनके लिए जीना सार्थक है।

तो आइए, शराब के बजाय जीवन का अधिक स्वाद लें। चीयर्स!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • लोकतंत्र को जिम्मेदार बनाने में मददगार

सरकारों में जनता का भरोसा लौटाने में सक्षम है एआई

कृत्रिम मेधा

डॉ. सामी महरूम
ब्रिटेन के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में रिसर्च डायरेक्टर

एक ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति लोगों का अविश्वास चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, तब कई लोगों को आशंका है कि एआई गलत सूचनाओं को बढ़ावा देकर और तथ्यों पर भरोसा कमजोर करके इस संकट को और गहराएगा। लेकिन इसका उल्टा भी संभव है कि एआई के नए उपकरण लोकतंत्रों पर भरोसे के संकट का समाधान बन जाएं!

ओईसीडी के अनुसार, उसके सदस्य देशों में से औसतन केवल 39% नागरिक अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। 2021 में यह आंकड़ा 45% था। अमेरिका में प्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि सरकार पर भरोसा ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर- लगभग 17%- के आसपास आ गया है। फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ यही हाल है। इसके विपरीत, दुनिया की अधिक प्रभावी 'टेक्नोक्रेटिक' सरकारों में भरोसे का स्तर काफी ऊंचा है- सिंगापुर और यूएई में तो यह 70% से अधिक है। यहां तक कि चीन भी इस मामले में आगे है।

टेक्नोक्रेटिक व्यवस्थाएं परिणाम देने में सक्षम हैं और साथ ही जनता की चिंताओं के प्रति संवेदनशील भी बनी रहती हैं। यह लोकतांत्रिक सरकारों के सामने खड़ी एक गहरी चुनौती की ओर संकेत करता है। उनके नीति-निर्माण में तर्कसंगति नहीं दिखाई देती। एक तरफ तो वे अनुभवी नीति-निर्माता हैं, जो राजनीतिक व्यवहार्यता, जनभावना और पूर्व में सफल रहे उपायों के आधार पर नीतियां बनाते हैं। दूसरी तरफ उन अर्थशास्त्रियों और तकनीकी विशेषज्ञ की दुनिया है, जो दक्षता को अधिकतम करने के उद्देश्य से नीतियां गढ़ना चाहते हैं। दोनों में तालमेल नहीं बन पाता है।

टेक्नोक्रेटिक सफलता की कहानियों ने इस दुविधा से स्वयं को बचाए रखा है। सिंगापुर की सरकार कठोर नीतिगत-विश्लेषण करते हुए यह भी समझने की कोशिश करती है कि जनता इसे किस प्रकार ग्रहण करेगी। इसी तरह, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में नीति-निर्माता तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ नागरिक संतुष्टि को मापने की प्रणालियों में भी भारी निवेश करते हैं। यूएई में सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं के पास ग्राहक संतुष्टि फीडबैक बूथ लगे होते हैं।

पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए ऐसा करना अभी तक कठिन सिद्ध हुआ है। इसका एक कारण तो यह है कि सरकारी कामकाज लगातार विरोध करने वाली दलगत राजनीति से कमजोर होता है। जहां अर्थशास्त्री बताते हैं कि फ्यूल सब्सिडी हटाने से पैसों की बचत होगी और असमानता घटेगी, वहीं निर्वाचित प्रतिनिधि जानते हैं कि ऐसा कदम राजनीतिक भूचाल ला सकता है। जहां सरकारी खजाने के मॉडल पेंशन सुधारों की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं, वहीं जनमत सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि ऐसी नीतियां चुनावी आत्मघात सिद्ध हो सकती हैं। नतीजतन सरकारें तकनीकी और राजनीति के बीच झूलती रहती हैं और इससे कामकाज ठप हो जाता है।

एआई इस खाई को पाटने में मददगार हो सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल नीतियों के विश्लेषण की विशिष्ट क्षमता दिखाते हैं। एआई-ऑग्मेंटेड नीतिगत-विश्लेषण के अपने प्रयोगों में मैंने पाया है कि ये प्रणालियां उस क्षेत्र में विशेष रूप से सक्षम हैं, जिसे मैं 'भावनात्मक रूप से सजग पॉलिसी-डिजाइन' कहता हूं। जहां पारंपरिक उपकरण यह दिखा सकते हैं कि 'भीड़-शुल्क' (कंजेशन चार्ज) से यातायात के दबाव में 22% की कमी आती है, वहीं एआई प्रणालियां हमें यह भी याद दिला सकती हैं कि 'कंजेशन चार्ज' शब्द की तुलना में 'स्वच्छ-वायु शुल्क' लोगों द्वारा बेहतर ढंग से स्वीकार्य होगा; या यह कि चुनावी वर्ष में कंजेशन चार्ज को लागू करना राजनीतिक जोखिम को कई गुना बढ़ा सकता है।

> **एआई-पॉवर्ड विश्लेषण बता सकता है कि विशिष्ट मुद्दों पर समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया, संसदीय बहसों में कैसी चर्चा हो रही है। यह संकेत दे सकता है कि राजनीतिक अवसरों की खिड़की कब खुली है या बंद हो चुकी है।**

यहां मुद्दा यह नहीं है कि हम मानवीय निर्णय को रिप्लेस कर दें। बल्कि यह है कि हम अनुभवी नीति-निर्माताओं के नॉलेज को और स्पष्ट, व्यवस्थित और परीक्षण-योग्य बनाएं। एआई इसमें हमारी मदद करता है। इसके अलावा, जब एआई उपकरणों को वेब-सर्च क्षमताओं के साथ जोड़ा जाता है, तो वे लगभग रियल-टाइम में जनभावनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नीतियां पिछली तिमाही की चिंताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं, वे अगली तिमाही में लागू होने तक राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं रह सकती हैं।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

14 फरवरी के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में

इकोनॉमिस्ट ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन के फैसले पर राय दी है कि इसके सभी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। मैगजीन ने एशिया में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते प्रसार पर खास खबर दी है।

The Economist

दैनिक भास्कर — अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

ओपिनियन • सोशल मीडिया बैन के बाद ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के चेहरे खुरचने के मामले, फिर भी बड़ी संख्या में लोग प्रतिबंध के पक्ष में

सोशल मीडिया बैन : बच्चों को फायदा या नुकसान, बहस शुरू

बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को रोकने की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रिटेन सहित दर्जन भर देश इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के बच्चों पर साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। जैसे- ऑस्ट्रेलिया में कुछ टीनएजर्स ने खुद को उम्र से बड़ा दिखाने के लिए अपने चेहरे खरोंच लिए। वहीं कुछ बच्चों के अनजान और असुरक्षित साइट्स पर जाने का खतरा बढ़ गया। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिबंधों के सभी पहलुओं पर विचार की जरूरत है।

हालांकि तमाम दुष्प्रभावों के बावजूद एक बड़ा वर्ग अभी भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रतिबंध के पक्ष में है। 70 प्रतिशत से अधिक ब्रिटिश और दो तिहाई अमेरिकी भी प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया की पाबंदी का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। पैरेंट्स को उन हादसों ने हिला दिया है, जिनमें बच्चों की आत्महत्या के मामलों में सोशल मीडिया की भूमिका रही है। वह उन्हें संकोच, मायूसी और अकेलेपन की ओर ले जाता है। पैरेंट्स बच्चों को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके पिछड़ने की आशंका भी रहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किया जाए? उम्र सीमा बढ़ाने की बजाय नियामक एजेंसियों को सोशल साइट्स को टीनएजर्स के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास तेज करने चाहिए। टेक्नोलॉजी कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वे यह डेटा शेयर करें कि किशोर उनके प्लेटफार्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इससे शोधकर्ताओं को नुकसान का जायजा लेने और उसे रोकने के तरीके खोजने में मदद मिलेगी। बच्चों को लंबे समय तक ऑनलाइन व्यस्त रखने वाले फीचर्स पर विचार करने के लिए कहा जाए। टेक कंपनियों से युवाओं के कंटेंट का सख्ती से मॉडरेशन करने के लिए कहा जाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया से नुकसान के सवालों का अब तक ठोस जवाब नहीं मिला है। कुछ बच्चों के लिए उसके खराब होने के सबूत मिल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान के दावे के पक्ष में सीमित सबूत हैं। प्रतिबंध के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हैं। पहला तो यह बहुत मुश्किल है। दूसरा- सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने से मुश्किलें भी सामने आ रही हैं।

आयु सीमा बढ़ाने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि सिर्फ टाली जा सकती हैं। जब बच्चे 16 साल के होंगे तब वे अचानक सोशल साइट्स के संपर्क में आएंगे, जिनके इस्तेमाल का उन्हें अनुभव नहीं होगा। वहीं पैरेंट्स को भी आभासी सुरक्षा का अनुभव होगा कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रतिबंध के समर्थक सोशल मीडिया के कुछ फायदों की अनदेखी भी करते हैं। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित होता है जो अपनी लोकेशन, जेंडर या अलग दिमागी हालत के कारण अलग-थलग महसूस करते हैं। सोशल मीडिया बच्चों के लिए वर्तमान घटनाओं की जानकारी पाने का रास्ता बन गया है चाहे वे सही हों या गलत। पहले बच्चे मीडिया के अन्य माध्यमों से जानकारी पा लेते थे, लेकिन अब ऐसा कम है। संभव है कई बच्चे वीडियो गेम या स्ट्रीमिंग सीरीज या फिल्मों में व्यस्त रहने लगें। बच्चों के ऑनलाइन व्यस्त रहने का एक कारण यह भी है कि पैरेंट्स ने पहले ही उन्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने से रोके रखा है। राजनेता कहते हैं कि सोशल मीडिया बैन ही एकमात्र विकल्प है। दरअसल, वे बच्चों की जरूरी देखभाल से बच रहे हैं। यदि नियामक एजेंसियां दो दशक से अधिक पुराने सोशल मीडिया को काबू में रखने के रास्ते नहीं खोज पा रही हैं तो बच्चों के एआई टूल्स के इस्तेमाल को लेकर क्या उम्मीद की जाए।

कई देश प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं

ऑस्ट्रेलिया के बाद जनवरी में ब्रिटेन और फ्रांस की संसद के निचले सदन ऐसी रोक लगा चुके हैं। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और नार्वे भी प्रतिबंध पर विचार कर रहे हैं। ब्राजील में अगले माह से सोशल एप्स पर आयु की पुष्टि करनी होगी। चीन ने बच्चों के लिए स्क्रीन की समय सीमा तय की है। अमेरिकी अदालतों में 9 फरवरी को मेटा और यूट्यूब के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई शुरू हो चुकी है।

10-12 साल के आधे बच्चे स्नैपचैट चला रहे

ब्रिटेन के टेक रेगुलेटर ऑफकॉम के सर्वे में पाया गया कि 10-12 वर्ष आयु के आधे से अधिक बच्चे स्नैपचैट, 60 प्रतिशत टिकटॉक और 70 प्रतिशत से ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। रिसर्च के अनुसार ऑनलाइन प्रताड़ना के शिकार ज्यादातर बच्चों को असली दुनिया में भी तंग किया जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर तो दिखता है

मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे 17 से 25 साल की उम्र के लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि उन्हें तीन सप्ताह तक सोशल मीडिया से अलग रखने पर उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर भी, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि सोशल मीडिया औसत बच्चे के लिए नुकसानदेह है।

नुकसान के सबूतों पर सवाल भी

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एमी ओर्बन की एक रिसर्च में सबूत पाए गए कि अवसाद, असामाजिक बर्ताव जैसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं और सोशल मीडिया पर बिताए गए समय के बीच संबंध है। लेकिन अधिकतर अध्ययन लोगों द्वारा स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

वर्ल्ड इन ब्रीफ

आर्कटिक में चीन की बढ़ती हलचल से यूरोप में चिंता

बर्फ से ढके आर्कटिक क्षेत्र में चीन पिछले साल बहुत ज्यादा सक्रिय रहा। सितंबर में उसके आइस ब्रेकिंग शिप ने सैकड़ों वैज्ञानिकों के साथ गहरे समुद्र में रिसर्च की है। अक्टूबर में आर्कटिक होकर चीन का एक कंटेनर शिप यूरोप गया था। लेकिन आर्कटिक के कुछ क्षेत्रों में चीन की गतिविधियां अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों को आशंका है कि चीन वहां नेवी के जहाजों और सबमरीन्स के जरिये डेटा जुटा रहा है।

एपस्टीन विवाद में अब तक 14 लाख ईमेल हुए प्रोसेस

अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े विवाद में अब तक करीब 14 लाख ईमेल को प्रोसेस किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी को 30 लाख पन्नों से अधिक के दस्तावेज जारी किए थे, जिनका एआई टूल के माध्यम से एनालिसिस किया गया। इनमें ज्यादातर ईमेल उसके कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं और कारोबारी संपर्कों के साथ थे। हालांकि टॉप 500 ईमेल अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ थे। इनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोग भी शामिल हैं।

अमेरिका में कंपनियां शुरू करने के 57 लाख आवेदन

अमेरिका में महामारी के बाद नई कंपनियों के लॉन्च होने की तेजी अब भी जारी है। सेंसस ब्यूरो को 2025 में नए कारोबार शुरू करने के लिए 57 लाख आवेदन मिले हैं। 2019 के बाद से स्वरोजगार करने वाले कुल अमेरिकी वयस्कों की संख्या 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गई है। यह 13 लाख नए उद्यमियों के बराबर है। फिर भी श्वेत अमेरिकियों में अपना रोजगार करने की दर मुश्किल से बढ़ी है। अश्वेतों की बढ़ोतरी एक प्रतिशत है। अश्वेत बहुल इलाकों में ज्यादा नई कंपनियां बनी हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

राजनीति • नई पीएम ताकाइची का एजेंडा

जापान को चीन और रूस की चुनौती के बीच तेजी से संतुलन बनाना होगा

जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने 8 फरवरी को हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पार्टी ने संसद के 465 सदस्यीय निचले सदन में 365 सीटें जीत कर, करीब 70 फीसदी सीटें हासिल की हैं। विजेता प्रधानमंत्री ताकाइची सानेई के सामने देश को बदलने का ऐतिहासिक मौका है। यह जीत दीर्घकालिक जनसंख्या और आर्थिक चुनौतियों से निपटने का दुर्लभ मौका देगी। हालांकि उन्हें चीन और रूस की चुनौती के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ वफादार दक्षिणपंथियों नहीं बल्कि सभी जापानियों की नेता बनना पड़ेगा। वे एक शक्तिशाली नेता के तौर पर उभरी हैं। ताकाइची ने जापानी वोटरों की सिक्योरिटी और बदलाव की आकांक्षाओं को भुनाया है। वे लोकतांत्रिक जापान की अगुआई करने वाली पहली महिला हैं। वे जापान की प्रतिरक्षा व्यवस्था में बदलाव की गति तेज कर सकती हैं। 2012-20 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन के कड़े तेवरों और अमेरिका की अविश्वसनीयता को देखते हुए सेनाओं को मजबूत बनाना शुरू किया था। ताकाइची ने रक्षा खर्च को 2027 के बजाय पहले ही जीडीपी का 2 प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकें।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

इकोनॉमी

सऊदी अरब में कई मेगा प्रोजेक्ट के काम रुके

सऊदी अरब में तेल के दामों में गिरावट का असर दिखाई पड़ने लगा है। विजन 2030 के तहत शुरू विराट और भव्य प्रोजेक्ट- मुकाब का काम रोक दिया गया है। पिछले माह ही शाही सरकार ने रेगिस्तान में 500 अरब डॉलर की लागत से आलीशान लिनियर सिटी- द लाइन का निर्माण लगभग बंद कर दिया है। 2029 के एशियाई विंटर गेम्स भी कजाखस्तान में होंगे क्योंकि सऊदी अरब के पहाड़ी उत्तर पश्चिमी इलाकों में स्की रिसॉर्ट समय पर नहीं बन पाएगा। सरकार अब टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जैसे कुछ सेक्टरों पर फोकस करेगी।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रियाद पर ज्यादा ध्यान देने से राजधानी में हाउसिंग और अन्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। रियाद में 2020 के बाद मकान किराए 50 फीसदी बढ़े हैं। मकानों की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई है। फाइनेंस, टेक और अन्य क्षेत्रों में हुनरमंद विदेशियों के आने से स्थानीय लोगों को विदेशियों से होड़ करनी पड़ी है। लोगों में जॉब और वेतन को लेकर चिंता बढ़ी है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

नया ट्रेंड • एशिया में स्टेबलकॉइंस का दबदबा

भारत में पिछले साल 30 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी विदेश से आई

सरकारों की बेरुखी के बावजूद भारत सहित एशिया के कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। डेटा फर्म चेनालिसिस इंडेक्स के मुताबिक 2024 और 2025 के बीच भारत में 30.63 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टोकरेंसी आई। भारत लगातार तीसरे साल दुनिया में पहले स्थान पर रहा।

इंडेक्स में टॉप बीस देशों में नौ एशियाई हैं। इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और पाकिस्तान (तीसरे नंबर पर) भी हैं। मुनाफे के लिए ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्षेत्र में क्रिप्टो सिर्फ वायदा सौदों से नहीं जुड़ा है बल्कि यह फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया तरीका है। चेनालिसिस के चेंगयी ओंग कहते हैं, क्रिप्टो का इस्तेमाल वास्तविक दुनिया की समस्याओं का हल करने में होने लगा है।

बाहर से पैसे भेजने में इसका मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के दो करोड़ 40 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025 में 200 डॉलर घर भेजने का औसत खर्च 6.5 प्रतिशत था। कई देशों के लिए यह बड़ी समस्या है जैसे कि फिलीपीन्स के जीडीपी में रिमिटेंस की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है। इसका एक हल स्टेबलकॉइंस हैं। ओंग कहते हैं, बिटकॉइन के विपरीत इसकी कीमत अधिक स्थिर रहती है। स्टेबलकॉइंस क्रिप्टो के लेनदेन का मुख्य जरिया बन गए हैं। पिछले साल जनवरी और जुलाई में दुनियाभर में स्टेबलकॉइंस का लेनदेन 362 लाख करोड़ रुपए का रहा। यह हर साल दुनियाभर में होने वाले लेनदेन का छोटा हिस्सा है लेकिन बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टोकरेंसी के कारण स्टेबलकॉइंस से लेनदेन होने लगा है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

संवाद
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । कानपुर (कानपुर व लखनऊ में एक साथ प्रसारित) । शनिवार, 14 फरवरी 2026

सकारात्मक संकेत
बांग्लादेश चुनाव का भारत पर असर

बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP) के प्रमुख तारिक रहमान 17 साल बाद जब अपने देश लौटे तो उनका पहला सार्वजनिक बयान था कि मेरे पास एक प्लान है। अब जब वह देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, तो डेढ़ साल से अस्थिरता और गंभीर सुरक्षा संकट झेल रहे बांग्लादेश को एक कारगर प्लान की जरूरत भी पड़ेगी। बांग्लादेश की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं।

संतुलित रुख । तारिक ने अपने भाषण में दो बातों पर खासा जोर दिया था। एक, धर्म व्यक्ति का विषय है और वह ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो सभी का हो। दूसरे, उन्होंने बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उनका रुख अंतरिम सरकार की तुलना में ज्यादा सुलझा और सकारात्मक है। मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश का झुकाव चीन-पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दिखा।

BNP की जीत

भारत का संदेश । तारिक रहमान ने ज्यादा संतुलित रवैया अपनाया है। उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया नहीं, बल्कि सभी को लेकर चलने की बात कही। भारत ने भी समय-समय पर बताया है कि वह बदले नेतृत्व के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार है। BNP की जीत पर तारिक को बधाई देने वाले सबसे पहले वैश्विक नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बात कर संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की पहल कर दी है।

साझा हित । भारत और बांग्लादेश के हित कई क्षेत्रों में साथ जुड़े हुए हैं। भले ही नई दिल्ली ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी हो, लेकिन उसने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से हमेशा दूरी बनाकर रखी। हालांकि जमात-ए-इस्लामी की तुलना में BNP ज्यादा उदार चेहरा है और उसकी बड़ी जीत बताती है कि बांग्लादेश के आम लोगों को भी जमात की कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन नहीं। ऐसे में भारत और बांग्लादेश हाल में आई दूरी को पाट सकते हैं।

जनादेश का सम्मान । दूसरे देशों की संप्रभुता और वहां के जनादेश का सम्मान भारत की नीति रही है। पीएम मोदी का संदेश बताता है कि भारत आगे बढ़ने को तैयार है। इससे पहले भी तमाम तनाव के बावजूद भारत ने पूर्व पीएम खालिदा जिया के इलाज की पेशकश की थी और फिर उनकी मौत पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ढाका पहुंचे थे। अब अगला कदम बांग्लादेश को उठाना होगा। सकारात्मक है कि BNP ने भी संबंधों को मजबूती देने की बात कही है।

जीत पर संदेह नहीं, मगर सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं कर सकते नज़रअंदाज़

भारत को ग़लतियां सुधारनी होंगी

यह सुनने में अच्छा लगता है कि पिछला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद से हमारा रेकॉर्ड अन्य टीमों के मुकाबले दमदार है। तब से हमने कोई सीरीज नहीं गंवाई है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में टाई मैच में मिली जीत के साथ 7-1 का रेकॉर्ड और पिछले T20 एशिया कप में लगातार तीन बार पटखनी देने से हर भारतीय गदगद है। लगता है इस बार भी ऐसा होगा। सीमा पार से टीवी फोड़ने के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। देश की हर गली में जश्न मनेगा।

मनोज जोशी

सिक्के का दूसरा पहलू । यह तो सिक्के का एक पहलू है। मगर दूसरे पहलू को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा फीयर फैक्टर है। हमने इस विश्व कप में दो मैच खेले हैं, लेकिन हमारा चैंपियन वाला अंदाज नहीं दिखा। मध्यक्रम स्ट्रगल करता दिख रहा है। दो एसोसिएट टीमों के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों पर हावी दिखे। हमारी ही जमीं पर स्पिनर भी हम पर हावी हैं।

अमेरिका ने पानी पिलाया । T20 विश्व कप के शुरुआती दो मुकाबलों में विपक्षी हमसे 20 दिखे। अमेरिका और नामीबिया के सामने हमारे प्रदर्शन ने यह सोचने पर मजबूर किया है कि मजबूत टीमों के खिलाड़ियों से हम कैसे भिड़ेंगे। नामीबिया के सामने तो हम 11 गेंदों पर 3 रन बना सके और 5 विकेट गंवा दिए। पिछले T20 विश्व कप में पाकिस्तान को हराने वाली अमेरिका की टीम ने भी हमें पानी पिला दिया। पावरप्ले में चार विकेट लेकर और 77 रनों पर 6 विकेट झटक कर उसने हमें संकट में ला दिया था।

घेरने की तैयारी । पाकिस्तान टीम के कोच माइक हेसन ग्राउंड रियलिटी में यकीन रखते हैं। इसलिए, उनका जोर पाकिस्तान की पेस बोलिंग की जगह स्पिन पर है। रणनीति कारगर दिख रही है। पाकिस्तानी टीम अब एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ 5 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका के खिलाफ सिर्फ तेज गेंदबाज के रूप में शाहीन शाह अफरीदी ही थे। टीम ने बाकी 16 ओवर स्पिनर्स से फेंकवाए। माइक हेसन भारत को भारत के अंदाज में घेरना चाह रहे हैं।

पाकिस्तान की ताकत । भारतीय बल्लेबाज शादाब और नवाज को आसानी से खेल सकते हैं। शादाब औसत स्पिनर हैं और बाएं हाथ के नवाज बल्लेबाज को फुल लेंथ खिलाने के लिए मजबूर करते हैं। यह हमारे खिलाड़ी जानते हैं। उस्मान तारिक को फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज के सामने उन्होंने कभी गेंद नहीं फेंकी है। दूसरी खास बात है कि वह ऑफ स्पिनर हैं और भारत के शीर्ष 8 बल्लेबाजों में 6 बाएं हाथ से खेलते हैं। उस्मान की कैरम बॉल वैरिएशन लाती है। अपनी इन खूबियों से वह 4 T20 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं।

अबरार और सैम की रणनीति । पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबरार अहमद अपने हाई आर्म ऐक्शन के साथ गुगली और लेके ब्रेक गेंद फेंकते हैं। अमूमन उनकी लेंथ एक सी रहती है। उन्होंने अपने 75% से अधिक विकेट गुड लेंथ गेंद फेंक कर झटके हैं। वह बीच के ओवरों में रन बचाकर सामने वाली टीम पर दबाव डालते हैं। पाकिस्तान टीम के ओपनर सैम अयूब से पावरप्ले में बचना जरूरी होगा। हालांकि, पिछले 25 मुकाबलों में उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन पावरप्ले में अपनी सटीक बोलिंग से वह टीम में बने हुए हैं। उन्होंने पावरप्ले में अब तक 10 विकेट लिए हैं। वह ऑफ और लेग स्पिनर दोनों हैं। वह शार्प टर्न भी कर लेते हैं और कैरम बॉल भी फेंकते हैं।

ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी । टीम इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है। टीम में कई पावर हीटर हैं और हर खिलाड़ी हर गेंद पर छक्का मारनो की कोशिश करता है। हालांकि, टीम यह संतुलन दिखा रही है। पहले मैच में सूर्यकुमार ने शुरुआती गेंदों पर बेहद सावधानी बरती और यही काम हार्दिक पांड्या ने दूसरे मैच में किया। इसके अलावा, हमारे खिलाड़ियों को बाउंड्री पर आउट होने से बचना होगा। पहले मैच में हमारे चार बल्लेबाज बाउंड्री पर लपके गए। कोलंबो का मैदान बड़ा है और वहां जब तक पूरा भरोसा न हो तब तक बड़े शॉट्स खेलने से बचना चाहिए। अगर यहां हम जीत गए तो भारत को T20 विश्व कप में पाकिस्तान को आठवीं बार हराने से कोई नहीं रोक सकता।

(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार और टीवी कॉमेंटेटर हैं)

AI Image

सोशल मीडिया की साज़िश!

कैलिफोर्निया में सोशल मीडिया कंपनियों पर ऐतिहासिक मुकदमा चल रहा है। मेटा, गूगल पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे प्लैटफॉर्म बनाए, जो बच्चों और किशोरों को उनका लती बना रहे हैं। जानिए कितना गंभीर है मामला।

5 पॉइंट

1 नाबालिग का आरोप
अमेरिका की एक नाबालिग ने लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट में कहा है कि किशोरावस्था में इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लत के कारण उसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

2 ईमेल का हवाला
पीड़िता के वकील मार्क लेनियर ने अदालत में दावा किया है कि कंपनियों ने एडिक्शन मशीन बनाई। 2015 का ईमेल दिखाया, जिसमें मार्क जकरबर्ग ने प्लैटफॉर्म पर 12% अधिक समय बिताने का लक्ष्य रखा था।

3 युवा आबादी टारगेट
लेनियर ने यूट्यूब पर खास आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म ने जानकर युवाओं को टारगेट किया, क्योंकि उनसे ज्यादा विज्ञापन राजस्व मिलता है। इसे अभिभावकों के लिए डिजिटल बेबीसिटर की तरह पेश किया।

4 स्नैपचैट-टिकटॉक का समझौता
स्नैपचैट और टिकटॉक ने पीड़िता से समझौता कर लिया। पीड़िता के पक्ष में फैसला आने पर मेटा और गूगल को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। करीब 1,600 अन्य मामलों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

5 पूरे देश में चिंता
सोशल मीडिया की लत को लेकर चिंता व्यापक है। अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा से 13 वर्ष से कम आयु वालों के अकाउंट डिलीट करने की मांग की है।

प्रस्तुतिः अभिषेक मिश्र

खुले मन से

हम सामूहिक रूप से क्या हैं, यह एल्गोरिदम बताता है

सुधीर मिश्र

हफीज़ होशियारपुरी का शेर है-

दिल से आती है बात लब पे 'हफ़ीज़'
बात दिल में कहाँ से आती है

सच कहें तो पहले दिमाग से आती थी। आजकल एल्गोरिदम यानी सोशल मीडिया देखने वालों की सामूहिक सोच से। अब देखिए न, सारे उत्तर भारत की निगाह आजकल एक प्राइवेट बैंक की एक शाखा पर अटकी हुई है। एक ठाकुर और एक ब्राह्मण महिला की बहस क्या हुई, एल्गोरिदम ने उसे राष्ट्रीय आपातकाल बना दिया। बात का बतंगड़ कैसे बनता है, इसे देखकर समझ सकते हैं। और लोग हैं कि मीडिया पर सवाल उठाते हैं कि इन लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। सच तो यह है कि आज भी अखबार वाले आपको बेरोजगारी, महंगाई, मिलावट, गंदगी, पर्यावरण, किसानों की आमदनी, शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की बदहाली दिखाना चाहते हैं पर सवाल यह है कि क्या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप पर इन मुद्दों को देखना चाहते हैं? देश के राजनीतिक दल और सरकारें भी जानती हैं कि आपके लिए अब भ्रष्टाचार नॉन इश्यू है और ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी और एससी असली मुद्दा। इसीलिए वे आप को वही दे रही हैं जिनसे आप के पूर्वाग्रहों को संतुष्टि मिलती है। इसीलिए एक ऐसी बहस की रील बनती है और वॉट्सऐप-इंस्टाग्राम पर बंटती है। इतना जरूर है कि इस झगड़े से वह दावे जरूर गलत साबित होते हैं जिनमें कहा जाता है कि अब जात-पात कहां है ? देख लीजिए इतने बड़े बैंक के पढ़े-लिखे स्टाफ तक में है।

दरअसल कोई जाति, धर्म, पढ़ा-लिखा और अनपढ़ इससे अछूता नहीं है। हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही जाति का जिक्र आता है, हमारे भीतर बैठी हुई वर्ण स्मृति अंगड़ाई लेने लगती है। लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी बदल गई है। वह जाति-धर्म की कट्टरता से मुक्त है लेकिन सोशल मीडिया देखिए तो लगता है कि यह जज्बा अब 4K क्वालिटी में सुपर फाइन होकर सामने आने लगा है। एक बैंक में हुई बहस ने साबित कर दिया कि आज के युवा डिजिटल भले हो गए हों, लेकिन पुराने लोगों के संस्कारों से मिली मानसिकता उनकी हार्ड डिस्क के पुराने फोल्डर में कहीं सेव पड़ी है। चेतन मन में व्यवधान आते ही अवचेतन से जातीय दंभ कहीं न कहीं निकलकर सामने आ जाता है। चाहें वह ठाकुर हों, ब्राह्मण या कोई और जाति। माय कास्ट- माय प्राइड का नारा गूंजने लगता है। अब बताइए भला बैंक के कर्मचारियों की छोटी सी आपसी लड़ाई भी कोई राष्ट्रीय चर्चा का विषय बननी चाहिए थी। और लोग हंसते हैं मीडिया पर। अरे भाई हंसने से पहले हम सब अपनी टाइम लाइन क्यों नहीं देखते ? एल्गोरिदम कोई देवता नहीं है। वह हमारी ही सामूहिक सोच, पसंद का आइना है। हम जो चीज जितना देखेंगे, वह हमें उतना ही दिखाता जाएगा। सामूहिक सोच मतलब डिजिटल समाज जिसका निर्माण किसी खास इलाके या भूगोल पर नहीं बल्कि एक जैसी सोच पर निर्भर करता है और इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। यह डिजिटल समाज ही आज सबसे बड़ा संपादक है जो किसी साधारण सी घटना को भी ट्रेंड करा सकता है, उसे लीड बना सकता है। यही वजह है कि देश के असली सवाल हमेशा की तरह लाइन में खड़े हैं, बैंक के काउंटर की तरह क्योंकि यह आप की परेशानी तो है पर आप इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें आपको मजा नहीं आता। अलबत्ता हमारी रुचि ऐसी बहसों में है जहां कोई मुद्दा भले न हो, लेकिन आपकी जातीय पहचान को छूता हो। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को असल मुद्दों से ज्यादा मसालेदार बातें पसंद हैं और मसाला एल्गोरिदम की फेवरेट डिश है। खैर, देश ऐसे ही चलता रहेगा। मसाला बदलेगा तो बहसें बदलेंगी। ट्रेंड बदलेंगे और नए विडियो हलचल मचाएंगे पर क्या हम असल मुद्दों को, अपनी दिक्कतों को कभी ट्रेंड करा पाएंगे ? बहरहाल यह सब देखकर अपना जो हाल है, उस पर जावेद अख्तर साहब का यह शेर और बात खत्म कि-

बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का
हमें ये शौक़ है क्या आस्तीं भिगोने का

सरकार की सहमति बिना चर्चा संभव नहीं

*सदन में अब काम कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष संसदीय कार्यवाही में बाधा डाल रहा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। इस बढ़ते गतिरोध, टकराव, संसदीय प्रक्रिया, स्पीकर की शक्तियों, संवैधानिक प्रावधान और विपक्ष की बोलने की आजादी जैसे मुद्दों पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से **अजय प्रताप तिवारी** की बातचीत। पेश हैं प्रमुख अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू
पीडीटी आचार्य

> सदन पक्ष और विपक्ष के तालमेल से चलता है। विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए पूरी आजादी चाहिए, जबकि सरकार अपने तरीके से चलेगी। यहां संसद इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि विपक्ष की बातें अक्सर मानी नहीं जातीं

■ लोकसभा स्पीकर द्वारा विपक्षी सांसदों के निलंबन का संवैधानिक आधार क्या है, और क्या यह अनुच्छेद 75(1) का उल्लंघन है?

सांसदों का निलंबन सदन करता है, न कि स्पीकर। स्पीकर केवल संबंधित सांसदों के नाम चिह्नित करते हैं। इसके बाद सस्पेंशन मोशन लाना पड़ता है। यह प्रस्ताव मंत्री लेकर आते हैं। इस पर वोटिंग होती है और फिर निलंबन।

■ क्या विपक्ष को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अनिवार्य चर्चा का संवैधानिक अधिकार है, या यह सदन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है?

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 105 के तहत सदन में सभी सदस्यों को बोलने की आजादी दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन (पाबंदी) और रूल (नियम) के दायरे में रखा जाता है। डोकलाम जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है, उस पर चर्चा करा सकता है। नियम के अनुसार, जिस विषय पर चर्चा होनी है, उसके लिए विशेष एडवाइजरी कमिटी बैठती है। कमिटी की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। कमिटी तय करती है कि सदन में किस विषय पर चर्चा होनी है और किस पर नहीं। विपक्ष ने डोकलाम पर चर्चा की मांग रखी पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं हुआ। जब सरकार सहमत न हो, तो मुश्किल होती है। सत्ता पक्ष की सहमति के बिना किसी भी मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं। इसी वजह से विपक्ष गुस्से में रहता है कि उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती।

■ संसदीय गतिरोध के दौरान राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका (अनुच्छेद 85) क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से सत्र स्थगन में?

राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकते हैं। यह संदेश किसी विधेयक या अन्य किसी विषय से संबंधित हो सकता है। लेकिन, राष्ट्रपति ऐसा कोई संदेश प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं भेज सकते। जब संसद में गतिरोध होता है, तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते।

■ बिना बहस बिल पास करना अनुच्छेद-107 का उल्लंघन क्यों माना जाता है, और इसका समाधान क्या हो सकता है?

अनुच्छेद-107 में कहा गया है कि जब तक दोनों सदनों का एग्रीमेंट नहीं होता, बिल पास नहीं हो सकता। एग्रीमेंट तब होगा, जब आप बिल की विषय वस्तु को समझेंगे। एग्रीमेंट के स्थान पर एडॉप्ट शब्द प्रयोग होता, तो हम कह सकते कि कुछ भी एडॉप्ट कर लिया। अनुच्छेद-107 में एग्रीमेंट शब्द का तात्पर्य है, दोनों सदनों को समझना चाहिए कि क्या है एग्री और इसके लिए चर्चा जरूरी है।

■ विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष के बहुमत का उपयोग संविधान की मूल संरचना को कैसे प्रभावित करता है?

बेसिक स्ट्रक्चर से इसका कोई मतलब नहीं है। सदन को चलाने के लिए स्पीकर बैठे हैं। सदन पक्ष और विपक्ष के तालमेल से चलता है। विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए पूरी आजादी चाहिए, जबकि सरकार अपने तरीके से चलेगी। यहां संसद इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि विपक्ष की बातें अक्सर मानी नहीं जातीं। संसद में ज्यादातर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में तभी पूरी तरह से काम हो पाएगा, जब विपक्ष को विश्वास हो जाएगा कि उसकी बात सुनी जा रही है।

■ संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105) के तहत विपक्षी सांसदों को अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए?

अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सदन में सभी सदस्यों को बोलने की आजादी है, लेकिन सब्जेक्टिव ऑफ रूल्स के अनुसार। इसका मतलब यह नहीं कि रूल्स संविधान के अनुच्छेद पर हावी होगा। सभी सदस्यों को सदन में बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। अशोभनीय बातों को बहस से निकाल देना चाहिए। सदस्यों को ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि उन पर किसी का दबाव है। आजादी कोई लाइसेंस नहीं है, यह आजादी ही है। अपनी बात कहने के लिए आजादी मिलनी ही चाहिए।

■ गतिरोध समाप्त करने के लिए पीएम और विपक्ष के नेता के बीच संवाद संवैधानिक रूप से कैसे बाध्यकारी हो सकता है?

पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच संवाद होना ही चाहिए। इससे गतिरोध दूर हो सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच वार्तालाप चलता रहता है। दूसरे देशों में पीएम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेते हैं। जहां संसदीय प्रणाली है, वहां यह प्रथा है। इससे विपक्ष का तनाव और सदन में गतिरोध दूर हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता।

www.nbt.in

पिंपरी की चाय और दादा

खुद अपनी आंख से
आलोक गागड़ेकर

जब भी मैं पुणे के पिंपरी में अपने कंजर भाट दोस्तों से मिलने जाता, तो अक्सर उसी दुकान पर चाय पीता, जहां कभी अजित पवार जाया करते थे। उन्हें कंजर भाट समुदाय के दोस्तों ने उस दुकान पर आमंत्रित किया था। इसके बाद तो उन्होंने युवाओं का मान रखने के लिए कई बार उस दुकान पर चाय की चुस्की ली। इस दुकान पर अजित दादा ने घंटों बिताए होंगे। यह घटना बताती है कि महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजित पवार किस तरह जमीन से जुड़े नेता थे।

साल 1992 में पिंपरी क्षेत्र से ही उन्होंने अपनी राजनीति की मजबूत शुरुआत की। उनकी पकड़ यहां इतनी मजबूत रही कि लोग इसे अंगद के पांव की तरह अडिग मानते हैं। उन्होंने कंजर भाट समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उनके मार्गदर्शन में कई परिवार झोपड़-पट्टी से निकलकर पक्के मकानों में रहने लगे। उस समय समुदाय के कुछ युवा कच्ची शराब के धंधे में भी शामिल थे, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों में एक पहल यह भी थी कि अजित पवार रोज गणपति मंडप में आकर लोगों से मिलते, उन्हें संबोधित करते और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते। उनके भाषण गंभीर मुद्दों पर होते थे, लेकिन वह उन्हें आसान और हल्के अंदाज में कहते, इसलिए बीच-बीच में हंसी के ठहाके भी गूंजते रहते।

अजित पवार ने समुदाय के लोगों को नए-नए रोजगार की तरफ प्रेरित किया। वह चाहे किसी भी गठबंधन में रहे हों, सरकार में हों या विपक्ष में - कंजर भाट समाज के लिए उनका रुख रचनात्मक रहा। उनका साथ पाकर बड़ी संख्या में युवा राजनीति में उतरे और आज भी आ रहे हैं।

पिंपरी हमेशा से कामगारों का इलाका रहा है। यहां के लोगों की ऊर्जा और उत्साह को पवार दादा ने अच्छी तरह समझा। छठे और सातवें वेतन आयोग को लागू कराने में भी उनके प्रयास अहम माने जाते हैं। आज कई कंजर भाट परिवार दिहाड़ी मजदूरी से निकलकर सरकारी व्यवस्था से जुड़े हैं, इसका श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। उनके आकस्मिक निधन ने पूरे समुदाय को गहरे दुख में डाल दिया है। लोगों की आंखों में आंसू हैं और उन आंसुओं में अजित दादा की छवि साफ दिखाई देती है। मैंने पहली बार देखा कि हमारे समुदाय के लोग किसी नेता के निधन पर इस तरह भावुक होकर रोए हों। यह सम्मान और अपनापन उनके काम और व्यवहार की वजह से मिला। मौत से पहले भी उन्होंने समुदाय की बस्ती में मरम्मत कार्य को मंजूरी दी थी। एक छोटे-से समुदाय के प्रति उनके मन में जो संवेदनशीलता थी, उससे दूसरे नेताओं को सीख लेने की जरूरत है।

चलते-चलते...

हाथी अपनी मोटी त्वचा और कमजोर दृष्टि के कारण आसपास की वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाता। हालिया वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हाथी की सूंड पर मौजूद लगभग 1,000 छोटे-छोटे बाल (व्हिस्कर्स) इस काम में मदद करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन बालों की जड़ सख्त और सिरा मुलायम होता है, जिससे बिना हिलाए भी वे स्पर्श का सटीक स्थान पहचान लेते हैं।

रीडर्स मेल

▸ नई सरकार की चुनौतियां

13 फरवरी का संपादकीय 'जनता की कसौटी' पढ़ा। बांग्लादेश की राजनीति ने नया मोड़ लिया है। डेढ़ वर्ष की अनिश्चितता के बाद चुनाव और सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में सकारात्मक संकेत है। हालांकि अवामी लीग की अनुपस्थिति से लोकतंत्र की समावेशिता पर सवाल उठते हैं। संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP) को शानदार जीत मिली है और करीब दो दशक बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भी अपेक्षाओं पर बांग्लादेश की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। अब नई सरकार के लिए स्थिरता, आर्थिक सुधार और जनविश्वास बहाल करना सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

धर्मेंद्र सिंह, शाहदरा

▸ संवाद में कटुता न आए

यह पत्र 13 फरवरी के लेख 'दल नहीं सदन का होता है स्पीकर' से संबंधित है। विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल ने संसदीय राजनीति को एक नए विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया है। 118 सांसदों का हस्ताक्षर इस बात का संकेत है कि विपक्ष के भीतर असंतोष मौजूद है। उनका आरोप है कि सदन में उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। वहीं, संसद केवल विरोध का मंच नहीं, बल्कि संवाद और सहमति का स्थल है। यदि विपक्ष केवल आलोचना तक सीमित रहे और सरकार के सकारात्मक कदमों की सराहना से पूरी तरह बचे, तो संवाद की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। यदि किसी पक्ष को पक्षपात का अनुभव हो रहा है, तो उसे संवाद के माध्यम से दूर करना भी स्पीकर की भूमिका का हिस्सा है।

प्रेरणा श्रीवास्तव, ईमेल से

आर.एन.आई. नं. UPHIN/2019/78296 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कंपनी लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रितेश माथुर, टाइम्स हाउस, 16/79G, सिविल लाइंस, कानपुर-208001 से प्रकाशित तथा बैनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, प्लॉट नं. 407, ग्राम-उत्तरधौना, पी.ओ. चिनहट, अयोध्या रोड, लखनऊ 226028 से मुद्रित। फोन : 0512-2380312, 0522-4154444, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई- 400001। स्थानीय संपादक : सुधीर मिश्र (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)।

संबंध सुधारने का प्रयास होगा

बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। इससे बंगलादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ स्पष्ट हैं क्योंकि यह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है जो 2024 के छात्र-आंदोलन से उभरा था। चूंकि बीएनपी पहले से सत्ता में रहती आई है, इसलिए उसकी जीत के वैश्विक मायने भी हैं। वह यह कि पार्टी कमोबेश पूर्व प्रधानमंत्री स्व. बेगम खालिदा जिया के अधूरे सपनों को ही साकार करेगी, वो भी तब जब उनके पुत्र तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देखा जाए तो बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां जमात को महज 42-68 सीटें ही मिलीं हैं। इस प्रकार तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, देश के संभावित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण। इसलिए उनकी जीत से भारत को सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों की चिंता बढ़ सकती है हालांकि बीएनपी समानता-आधारित संबंधों का वादा कर रही है। खासकर हसीना युग के बाद विदेश नीति में बदलाव से व्यापार, जल बंटवारा और कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। वहीं बीएनपी की जीत से दुनिया के लिए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश ($2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। यह ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध सुधारने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से "बहुत मैत्रीपूर्ण" चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरार है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं, खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातें कीं, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा फखरुल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। वहीं, व्यापार और वीजा बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे, खासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी बीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फेलानी घटना) पर जोर दे रही है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी क्योंकि बीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही है जिसे भारत शरण दे रहा है। इससे जन-भावना भी प्रभावित हो रही है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-चीन झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बीएनपी "समानता-आधारित" पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही है जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएं रीसेट सुनिश्चित करेंगी लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास दूर करने में समय लगेगा। यद्यपि तारिक रहमान, जो बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाते दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंड यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा करते हैं जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, समानता के मद्देनजर "बराबरी के रिश्ते" चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई लेकिन टकराव से बचते हैं। हाँ, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियां "इंडिया-न्यूट्रल" मान रही हैं जो 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव लेकिन पाकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं। देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के 17 मिनट के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के राज पर जोर दिया—जो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, "बांग्लादेश फर्स्ट" नारा यानी "ना दिल्ली, ना रावलपिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश" कहकर तटस्थ विदेश नीति का संकेत दिया जो पुराने भारत-विरोधी रुख से अलग है। उनके सकारात्मक संदेश साफ हैं। वो ये कि अंग्रेजी में अंतरराष्ट्रीय अपील की, समावेशी बांग्लादेश का खाका पेश किया जो खुफिया एजेंसियों ने "री-अश्योरेंस सिग्नल" माना। देखा जाए तो उनके ये भाषण बीएनपी की री-ब्रांडिंग का हिस्सा हैं जहां 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से दूरी दिखाई गई। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के साथ संबंध सुधारने का रणनीतिक संकेत है, हालांकि हसीना प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे लंबित हैं।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

लो जी बंग्लादेश में, अब तारिक रहमान
पता नहीं किस रूप में, लेगा हिंदुस्तान
लेगा हिंदुस्तान, जिया, जिया के लाला
उधर मर गई आज मियां यूसुफ की खाला
कह सुरेश कविराय संभाल हसीना भौजी
हिंदू एक बनाय मार ली सत्ता लो जी

अब बांग्लादेश में नहीं गलेगी चीन की दाल

> बांग्लादेश में युनूस राज के खत्म होते ही अब चीन की दाल भी नहीं गलेगी। कारण कि अमेरिका ने चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने का पूरा प्लान तैयार किया है। जी हां, वॉशिंगटन अब बांग्लादेश को अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के हथियार सिस्टम ऑफर करेगा, ताकि चीन की हथियारों की दुकानदारी पर ब्रेक लगे।

17 साल के देश निकाला के बाद देश लौटे एक नेता के नेतृत्व में, तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने गुरुवार को हुए अहम राष्ट्रीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद पहला चुनाव है, जिस भेज ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के सख्त शासन को खत्म कर दिया था। बांग्लादेश के चुनाव आयोग (ECB) के अनुसार, गुरुवार को हुए मतदान में लगभग 170 मिलियन लोगों के देश में 127 मिलियन से ज्यादा योग्य वोटर शामिल थे, जिसमें देश भर की 299 संसदीय सीटों पर 1,981 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। जैसे-जैसे आधी गिनती आगे बढ़ी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सत्ता के करीब पहुँचती गई। अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बने अंतरिम प्रशासन की जगह लेने के लिए हुए अहम आम चुनाव में, पार्टी ने अपने पुराने साथी जमात-ए-इस्लामी पर बढ़त बनाती गई। शेख हसीना की अब खत्म हो चुकी अवामी लीग के मैदान से गायब होने के कारण, चुनाव BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला रहा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। BNP चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट बुगुरा में जीत हासिल की। रहमान को 2,16,284 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी विरोधी और जमात के उम्मीदवार अबिदुर

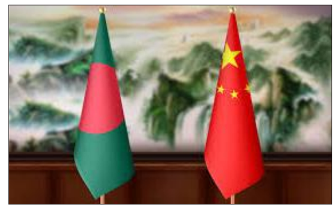

रहमान को 97,626 वोट मिले। BNP ने पहले घोषणा की थी कि अगर वह सत्ता में आती है, तो रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, अब जब नतीजे बीएनपी के पक्ष में आए हैं और उसे पूर्ण बहुमत मिली है तो नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। फिलहाल, बांग्लादेश में युनूस राज के खत्म होते ही अब चीन की दाल भी नहीं गलेगी। कारण कि अमेरिका ने चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, वॉशिंगटन अब बांग्लादेश को अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के हथियार सिस्टम ऑफर करेगा, ताकि चीन की हथियारों की दुकानदारी पर ब्रेक लगे। इससे न केवल बांग्लादेश को फायदा होगा, बल्कि भारत को भी राहत मिलेगी। कारण कि बांग्लादेश में चीन दखल भारत के पड़ोसी देश में कम होगी। अमेरिकी राजदूत ब्रेंट टी। क्रिस्टेंसन ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि दक्षिण एशिया में चीन का असर बढ़ रहा है और अमेरिका बांग्लादेश की नई सरकार के साथ मिलकर इसके जोखिम बताएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ढाका में वॉशिंगटन के एम्बेसडर ने क्रिस्टेंसन ने कहा कि अमेरिका साउथ एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर परेशान है और बांग्लादेश की अगली सरकार को चीनी हार्डवेयर के ऑप्शन के तौर पर अमेरिकी और उसके सहयोगी डिफेंस सिस्टम देने का प्लान बना रहा है। बता दें कि बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर अगस्त 2024 में हुआ था। तब जेन जी के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने भारत समर्थक प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया। इस विरोध-प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना दिल्ली भाग आईं। उसके बाद से भारत का बांग्लादेश में असर कम हो गया। इसी फायदा उठाते हुए चीन ने तेजी से कदम बढ़ाए। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौता किया, जिसमें भारत बॉर्डर के पास ड्रोन फैक्ट्री बनाने का प्लान है। अमेरिका के साथ-साथ यह भारत के लिए भी चिंता की बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में चीन का अधिक दखल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि हाल फिलहाल में चीन ने बांग्लादेश में क्या किया है। दरअसल, चीन ने हाल ही में भारत बॉर्डर के पास एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इससे अमेरिकी और अन्य एशियाई डिप्लोमैट्स परेशान हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर डेवलप किया गया एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। ये सब चीन की सैन्य साझेदारी को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी एम्बेसडर क्रिस्टेंसन ने कहा, 'अमेरिका साउथ एशिया में चीन के बढ़ते असर को लेकर परेशान है और चीन के साथ कुछ तरह के जुड़ाव के रिस्क को साफ तौर पर बताने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए कमिटेड है।' उन्होंने और अधिक जानकारी दिए बिना कहा, 'बांग्लादेश को उसकी मिलिट्री क्षमता की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए अमेरिका कई ऑप्शन देगा है, जिसमें अमेरिकी सिस्टम और सहयोगी पार्टनर के सिस्टम शामिल हैं, ताकि चीनी सिस्टम के विकल्प दिए जा सकें।' उन्होंने साफ-साफ इशारा कर दिया कि चीन के हथियारों के बजाय अमेरिकी या उसके दोस्तों के सिस्टम बांग्लादेश के लिए ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित होंगे। अब बात करे इन नतीजों के आने का बाद भारत में क्या बदलेगा अब अमेरिका भारत-बांग्लादेश रिश्तों को सुधारने पर भी जोर दे रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहती है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे ताल्लुक हों, ताकि इलाके में स्थिरता बनी रहे। शेख हसीना के भागने के बाद दिल्ली-ढाका रिश्ते खराब हो गए हैं। वीजा सर्विस प्रभावित हुईं, और क्रिकेट मैचों तक पर असर पड़ा। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते ठंडे पड़े हैं।अमेरिका का मानना है कि अगर बांग्लादेश नई सरकार के साथ भारत से दोस्ती बढ़ाए, तो दक्षिण एशिया में शांति बनी रहेगी।भारत के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि चीन की बॉर्डर पर ड्रोन फैक्ट्री से सुरक्षा खतरा कम होगा। अमेरिकी प्लान से भारत को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश अगर अमेरिकी हथियार चुनता है, तो चीन-पाकिस्तान का गठजोड़ कमजोर पड़ेगा।खुद क्रिस्टेंसन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे रिश्ते देखना चाहता है। अमेरिका अब बांग्लादेश में व्यापारिक कूटनीति को सबसे ऊपर रख रहा है। क्रिस्टेंसन ने कहा कि कई अमेरिकी कंपनियां बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन वे चाहेंगे कि अगली बांग्लादेशी सरकार जल्दी और साफ़ संकेत दे कि वह बिज़नेस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'कमर्शियल डिप्लोमेसी हमारी टॉप प्रायोरिटी में से एक है, और हम अंतरिम सरकार के साथ हुई प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, खासकर कमर्शियल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संबंधों को मज़बूत करने में।' चेवरॉन जैसी ऊर्जा कंपनी दशकों से बांग्लादेश में काम कर रही है, लेकिन अन्य अमेरिकी ब्रांड कम दिखते हैं। 17.5 करोड़ की आबादी वाले इस घनी आबादी वाले देश में ऊंचे टैक्स और मुनाफा बाहर भेजने की मुश्किलें बाधा हैं। यहां स्टारबक्स या मैकडॉनल्ड्स जैसी चेन नहीं हैं। क्रिस्टेंसन ने कहा कि व्यापारिक कूटनीति हमारी प्राथमिकता है।

■ अशोक भाटिया

भारत में एपस्टीन फाइल्स की चर्चा क्यों?

मीडिया में पिछले कई दिनों से एपस्टीन फाइल्स का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। एपस्टीन फाइल्स नाम अपने आप में चौंका देने वाला है। लोग इसके फोटो, इसके कामकाज, शैली और इसके अंदर दिखाए जाने वाले कुकर्मों पर चर्चा कर रहे हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया गया है। विश्व के लगभग सभी बड़े चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों का यह काला सच है। अमेरिका और बहुत से यूरोपीय देशों में सेक्स की बात होना साधारण सी बात हो सकती है क्योंकि ओपन सेक्स और खुला व्यापार वहां की नीति का हिस्सा है लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मारना, उनका माँस खाना, उनका यौन उत्पीड़न करना आदि इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। अब चलते हैं भारतीय जीवन शैली की ओर। भारतीय जीवन शैली अध्यात्म से जुड़ी हुई है। यह आत्मा के मुक्त होने की साधना पर चलती है। यहां आवागमन के चक्कर से मुक्ति का सबसे बड़ा काम होता है। भारतीय सनातन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो यहां भोगवादी संस्कृति नहीं बल्कि आध्यात्मिक संस्कृति का सबसे बड़ा काम होता है। यहां पर तीज-त्यौहार, व्रत इतने हैं कि लोग उन्हीं में अपने जीवन की व्यवस्था और व्यस्तता को रखते हैं। सुयोग्य वर या वधू के लिए सोलह सोमवार का व्रत करना(भगवान शिव की आराधना करना), ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए युवा मंगलवार का व्रत करते हैं और अपने साधन तथा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। एकादशी को कितने ही स्त्री-पुरुष व्रत करते हैं। ज्येष्ठ मास में तो निर्जला एकादशी का व्रत, जब सूर्य अपने ताप पर होता है और वहां जल

के बिना जीव का रहना, कितनी बड़ी साधना का काम है। इसके साथ जब हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो आप देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग पूरे दिन पानी तक नहीं पीते और रात्रि 12:00 बजे या चंद्रमा के दिखाई देने पर ही अपने व्रत को चरणामृत तथा फल आदि खाकर खोलते हैं। इतने बड़े संकल्प सिद्धि के इस देश में भोगवादी संस्कृति कहां टिकने वाली है। कल्पवास के समय भी प्रयागराज में लोग महीना भर अपना घर त्याग कर, व्रत कर के, बहुत से समाधि पर बैठ जाते हैं। बहुत से कल्पवास में एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। यह सब पारिवारिक लोग हैं जो परिवार की व्यवस्था में हैं। यह व्रत और तीज-त्योहार का पालन पारिवारिक लोग ही कर रहे होते हैं। जब करवा चौथ की बात होती है तो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए महिलाएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती, चंद्रमा को देखकर ही व्रत को खोलती हैं। छठ मईया का व्रत तो पूरी रात जल में खड़ा रहना और सूर्योदय के साथ उसको खोलना है। यह व्रत कई दिनों तक चलता है। इसके साथ और भी बहुत सारे व्रत और तीज-त्योहार जुड़े हुए हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी माताएं करती हैं। संतोषी मां का भी व्रत करती हैं। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार का व्रत भी करते हैं यानी कि भारतीय संस्कृति में व्रत की महिमा है। खाने-पीने या भोग की प्रवृत्ति न होकर अन्न-जल और विषय वस्तुओं को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने की बहुत बड़ी सार्थकता है। आंकड़े बताते हैं कि सन 2025 प्रयागराज के महाकुंभ में लगभग साठ करोड़ लोगों ने स्नान किया। यह सारी बातें जो हो रही हैं, यह सब पारिवारिक लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं जबकि संत समाज की यदि हम बात करें तो वह ज्ञान का प्रकाश पुंज हैं। अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, योग, साधना आदि के सच्चे साधक सभी साधु, संत, महात्माओं को सादर प्रणाम। यह हम सब सामान्य लोगों को दिव्य ज्ञान देते हैं। संत हम सब लोगों को इस भौतिक या भोगवादी युग से दूर ले जाकर आध्यात्मिक चिंतन की ओर जोड़ते हैं। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, कथाएं आदि वैश्विक ज्ञान परंपरा में अग्रणीय हैं। कथाओं के अंदर त्याग ही त्याग है, आत्म शुद्धि है। आत्म शुद्धि के साथ-साथ आवागमन के चक्कर से मुक्ति है। हम यहां भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि और कर्म प्रधान समाज में कर्म करते हुए, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं जबकि इसके दूसरी ओर यदि आप यूरोपीय या अमेरिका के अन्य देशों की बात करें तो वहां पर अध्यात्मवादी नहीं बल्कि भोगवादी संस्कृति आप देखोगे, वहां सेक्स का खुलापन है। वहां कपड़े पहनना ना पहनना, एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ, पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ, अपने संबंध स्थापित कर लेता हैं। ऐसे ही वहां संतान उत्पत्ति हो भी रही है। परिवार के प्रति बहुत कम लोगों का रुझान देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तो शादी ही नहीं करते बल्कि अपनी दैहिक भूख मिटाने के लिए बाजार का सहारा लेते हैं। सही मायनों में यही एपस्टीन फाइल्स हैं। इन देशों में देह बाजार में बिकती है, लोग उपभोग की वस्तु का मूल्य देकर सुख भोग लेते हैं। इन देशों में हर चीज बाजार है। हर वस्तु का भोग ही भोग है। मनुष्यता के नाम पर भी नर-नारी के बीच के संबंधों को ज्यादा महत्ता नहीं देते। यदि एक ऐसी फाइल्स अमेरिका और यूरोप के लोगों को लेकर खुलती है, जिसमें सेक्स के माध्यम से अलग-अलग देशों के बड़े-बड़े धनपति और उद्योगपति दिखाई देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी ओर शोर मच रहा है कि वहां पर कम उम्र के बच्चों के साथ यौवन शोषण हो रहा था। वह उन देशों की विडंबना है। वह किस तरीके से उन सब संबंधों को देखते-समझते रहते हैं, यह उनकी समझ है। माना कि बच्चों के साथ यौन शोषण होना किसी भी हद तक ठीक नहीं है। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इनकी पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान सभी कुछ इनसे ले लेना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय परिवेश अर्थात सनातन संस्कृति में ऐसी चर्चाओं को करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या हम भी इस ओर बढ़ रहे हैं?

■ डॉ. नीरज भारद्वाज

घर वहीं जहां दिल बसता है

मुंबई धारावी की तंग गलियों में, जहाँ ज़िंदगी हमेशा कड़ी मेहनत और उम्मीद की लय में चलती रही है, एक नया एहसास चुपचाप आकार ले रहा है। जैसे-जैसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रफ़्तार पकड़ रहा है, वहाँ रहने वाले उस चीज़ का सपना देख रहे हैं जिसका वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे - एक ऐसा घर जिसे वे आखिरकार अपना कह सकें। कई धारावीकरों के लिए, वह भविष्य का घर सिर्फ़ ईंटों और सीमेंट का एक ढांचा नहीं है। यह उनका वैलेंटाइन है। दशकों से, यहाँ परिवार तंग घरों में रहते आए हैं, दीवारें, पानी की लाइनें और चिंताएँ शेयर करते हैं। लेकिन आज उनसे बात करें, तो आपको एक अलग आवाज़ सुनाई देगी - जो उम्मीद और गर्व से भरी होगी। 52 साल की सोशल वर्कर जुबैदा खान कहती हैं, ₹हमारा नया घर हमारी नई शुरुआत होगी।₹ ₹हम सही वेंटिलेशन, खिड़कियों से धूप और एक सुरक्षित जगह चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे शांति से पढ़ सकें। यही हमारा सपना है।₹ रहने वालों का कहना है कि उनका 'वैलेंटाइन होम' लग्ज़री नहीं बल्कि गर्व की जगह है। वे साफ़ सीढ़ियाँ, काम करने वाली लिफ़्ट, सुरक्षित दरवाज़े और अलग किचन की कल्पना करते हैं। माँएँ टाइल वाले फ़र्श के बारे में बात करती हैं जिन्हें साफ़ करना आसान हो, पिता पक्की बिजली और पानी की सप्लाई की उम्मीद करते हैं, और बच्चे बालकनी का सपना देखते हैं जहाँ वे पौधे उगा सकें या बस आसमान देख सकें। कम्युनिटी स्पेस भी उनकी विश लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। धारावीकर चाहते हैं कि खेल के मैदान हों जहाँ बच्चे आज़ादी से दौड़ सकें, बुजुर्गों के आराम करने के लिए बगीचे हों और साथ मिलकर त्योहार मनाने के लिए कम्युनिटी हॉल हों। कॉलेज स्टूडेंट अरमान खान कहते हैं, "हम अपनी एकता नहीं खोना चाहते।" "हमारी नई बिल्डिंग्स भी एक बड़े परिवार जैसी लगनी चाहिए।" कई लोगों के लिए, इन घरों की इमोशनल वैल्यू सिर्फ़ आराम से कहीं ज़्यादा है। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में अपनी मज़बूती और एडवेंचर के लिए जानी जाती है, वहाँ एक अच्छे बने अपार्टमेंट का मालिक होने का मतलब है पहचान। इसका मतलब है उनके सालों के संघर्ष को मानना। बालचंद्र तिवारी, जो एक छोटी सी इडली की दुकान चलाते हैं, कहते हैं, "यह घर हमारी शान होगा। यह इस बात का सबूत होगा कि हमारी ज़िंदगी मायने रखती है।" रीडेवलपमेंट पर काम कर रहे अर्बन प्लानर्स का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ़ घरों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि धारावी के वाइब्रेंट इकोनॉमिक इकोसिस्टम को बचाना भी है। छोटी वर्कशॉप, रीसाइक्लिंग यूनिट, लेदर बिज़नेस और फ़ूड इंडस्ट्री यहाँ पीढ़ियों से फल-फूल रही हैं। रहने वालों को उम्मीद है कि उनके नए घर तय वर्कस्पेस और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ परिवार की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी दोनों को सपोर्ट करेंगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन क्रेन धारावी के कुछ हिस्सों पर मंडराते हैं, ड्रिलिंग और हथौड़े की आवाज़ उम्मीद का बैकग्राउंड म्यूज़िक बन गई है। बाहर वालों के लिए, यह बस एक और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन धारावीकर्स के लिए, यह बहुत पर्सनल लगता है। इस वैलेंटाइन सीज़न में, जहाँ दुनिया फूलों और चॉकलेट के साथ प्यार का जश्न मना रही है, वहीं धारावी के लोग कुछ ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला जश्न मना रहे हैं – एक सुरक्षित छत, एक प्राइवेट जगह और एक इज्जतदार ज़िंदगी का वादा।

मुंबई के बीचों-बीच, सड़कों पर एक मैसेज गूंज रहा हैः मेरा धारावी, मेरा वैलेंटाइन-क्योंकि घर ही वह जगह है जहाँ हमारा भविष्य है।

आज का कार्टून

साभार

वैलेंटाइन डे की आड़ में गुमनाम होती जवानों की शहादत

जहां देश में युवक और युवती आपसी प्रेम के इजहार को लेकर बड़े ही बेसब्री से 14 फरवरी का इंतजार करते है और पर्व 7 फरवरी से 14 फरवरी तक विभिन्न दिवस के रूप मनाया जाता है लेकिन देश के युवा वैलेंटाइन डे के चक्कर में देश के वीर जवानों की शहादत को ध्यान में न रखकर केवल प्रेम और मोहब्बत के झूठे जंजाल में खुद को बर्बाद कर रहे है। वैलेंटाइन डे के नाम पर जिस तरह युवक और युवती खुद को प्रेम के नाम पर बर्बाद कर रहे है जो कहीं न कहीं देश के भविष्य को लेकर चिंताजनक है। प्रेम के नाम पर केवल मौज मस्ती और दिखावा युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। जहां देश में लोग वीर जवानों की कुर्बानी को याद कर उनके कार्यों को नमन कर रहे है, पुलवामा में हुए हमले के दौरान शहीद हुए जवानों को लोग याद करते है और 14 फरवरी को शहीदों की याद में 'ब्लैक डे' मनाया जाता है लेकिन देश के भविष्य युवा वीरों की शहादत को याद करने की जगह भारतीय संस्कृति को गंदा करने वाले वैलेंटाइन डे जैसे दिन पर मशगूल रहते है। आइये जानते है कि 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है? 14 फरवरी को भारत के इतिहास में 'ब्लैक डे' के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 2019 में पुलवामा में हुआ हमला आतंकवाद का एक विनाशकारी रूप था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जम्मू-कश्मीर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। जैसे ही काफिला अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास पहुंचा, एक वाहन काफिले में शामिल बसों के बहुत करीब आ गया। सैनिकों की ओर से ड्राइवर को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वाहन ने आदेशों की अनदेखी करना जारी रखा। एक भयावह क्षण में, वाहन बसों में से एक से टकरा गया जिससे एक बड़ा

विस्फोट हुआ जिसमें 40 बहादुर सैनिकों की जान चली गई। यह आतंकवादी हमला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवंतीपोरा के गोरीपोरा में हुआ। सीआरपीएफ का काफिला, जिसमें 60 से अधिक सैन्य वाहन और लगभग 2,547 सैनिक शामिल थे, इस क्षेत्र से गुजर रहा था। विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने सैन्य बसों में से एक को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, जो इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था. विस्फोट इतना तीव्र था कि इसने आसपास के क्षेत्र को धुएं और आग के घने बादल में घेर लिया। दुखद रूप से इस भीषण हमले में 40 से अधिक सैनिकों की जान चली गई। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अवंतीपोरा में हुए विनाशकारी हमले की जिम्मेदारी ली। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि काफिले में शामिल कई बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं थीं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकवाद के इस क्रूर कृत्य ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया और सभी की निगाहें सरकार और सेना पर टिक गईं जो शहीद सैनिकों का बदला लेने के लिए एक मजबूत और निर्णायक जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुलवामा आतंकवादी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने 25 फरवरी 2019 की देर रात पाकिस्तान के बालाकोट पर जवाबी हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन के दौरान, लगभग 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इस मिशन में लगभग 2,000 भारतीय वायु सेना के जवानों ने भाग लिया और क्षेत्र में आतंकवादी शिविरों पर लगभग 1,000 किलोग्राम बम गिराए। यह ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ किया गया और पाकिस्तान को चौंका दिया गया। इस निर्णायक कार्रवाई को बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक नाम दिया गया।

सोशल मीडिया की नजर से

कुछ बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए...
1. अपनी योजनाएँ कभी किसी को न बताएँ।
2. अपनी जीवनशैली की private बात न करें।
3. कभी यह न बताएँ कि आप कितने साहसी, दयालू हैं।
4. कभी यह घोषणा न करें कि आप प्रबुद्ध/जागृत /समझदार हैं।
5. परिवार की समस्याओं के बारे में कभी बात न करें।
6. आपने जो अप्रिय बातें सुनी हैं, उन्हें दोहराएँ नहीं।

पिछले साल की घटना
ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार हुआ लड़की ने बलात्कार की घटना अपने मां-बाप को बताई और लड़की के मां-बाप ने तुरंत पड़ोस में रहने वाले दो सवर्ण युवको पर बलात्कार का आरोप लगाकर अनुसूचित जाति आयोग से नियमानुसार लाखों रुपए का मुआवजा भी ले लिया फिर जब पुलिस ने बलात्कार की मामले की जांच किया सीमेन का डीएनए टेस्ट करवाया दूसरे तमाम वैज्ञानिक सबुत इकट्ठा किया और लड़की से सख्ती से पूछताछ की तब पता चला कि उसे लड़की के घर कुछ महीने से उसकी बुआ के देवरानी का लड़का आया था और उसी ने उसे लड़की का बलात्कार किया था जब लड़की ने अपने मां बाप को बलात्कार की घटना बताई तब मां बाप ने कहा कि तुम चुप रहना और उस लड़की के शातिर मां-बाप ने कुछ लाख रुपए मुआवजा लेने के लिए 2 सवर्ण निर्दोष युवकों को बलात्कार के केस में फंसा दिया
रूह कांप जाती है ऐसी खबरें सुनकर। दलितों के लिए SC/ST ACT बिना मेहनत किए पैसे देने बाला रोजगार बन गया है?

भारत सरकार ने 114 राफेल डील पर फाइनल मुहर लगा दी, जो करीब 3.25 लाख करोड़ की डील है।
भारत के इतिहास मे ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है। France के राष्ट्रपति Macron के भारत दौरे से पहले ही इस डील को मंजूरी दे दी गई।
इसके अनुसार... 18 राफेल पूरी तरह तैयार हालत मे France से आएंगे। 96 राफेल Make In India के तहत भारत मे ही बनाए जाएंगे। 60प्रतिशत पार्ट्स भारतीय होंगे।
Dassault Aviation भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी।
नागपुर मे राफेल की असेंबली लाइन लगेगी।
विमानों मे भारतीय मिसाइल, हथियार और रेडार सिस्टम लगाए जाएंगे।
ये जेट भारत के रेडार और सेंसर नेटवर्क से जुड़े रहेंगे।
अब यह प्रस्ताव कीमत तय करने की प्रक्रिया मे जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) इसकी अंतिम मंजूरी देगी।
तैयार रहिए एक और हंगामे के लिए.... पिछली बार तो 36 खरीदने पर इतना हंगामा हुआ था, इस बार तो 114 हैं।

संभल में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है जिसमें अवैध मदरसे को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है जिससे कानून का शासन बनाए रखा जा सके।

जिस चीन से 1962 में भारत युद्ध में हारा
उसी चीन के लिए भारत ने 1963 में UN में सदस्य बनने के लिए चीन के पक्ष में वोट दिया? ये कैसा राष्ट्र प्रेम था?

एक तरफ मदरसे में पढ़ाने वाले मौलानाओं का आतंकवाद से कनेक्शन निकल रहा है।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार बजट के नाम पर चौतीस सौ करोड़ अल्पसंख्यक विभाग को दे रही है।

शहरो के गली मुहल्लो से लेकर विदेशों तक मे देश और सनातन के विरुद्ध जो असंख्य दुश्मन है जो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हैं? सब संदिग्ध है, राहुल तो मोहरा है, सरकार को अपनी सेना पर भी नजर रखनी पड़ेगी, यहां भी बिकाऊ है पहले भी थे आज भी है, सरकार का मेक इन भारत की जुंबिश में इन बिकाऊओ को खाने का नहीं मिलता होगा पहले आर्म्स डील में जरूर कमीशन मिलता होगा जो बिकाऊओ को खल रहा होगा। वह भी, ये सरकार लड़ने को भी तैयार है तो लड़ना भी पड़ेगा, अब तक तो लड़ाई टाली जाती थी तो ऐश थी आर्म्स खरीदारी पर कमीशन भी और आराम भी जो अब नहीं हो रहा है तो वहां भी रेजीम चेंज की आशा होगी, नरवणे के दिल मे तो वैसे भी सरकार के लिए खलिश होगी ही।

मां-बाप को भारत में तड़पता छोड़कर विदेश का आंनद लेने वालों का पासपोर्ट रद्द किया जाए
मां -बाप से हर 6 मास पर संतुष्टि-प्रमाण पत्र लिया जाये...
बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने ।

इमरान मसूद तो टीवी पर आते ही ऐसे भागा जैसे कोई ने कहा हो भाई तेरा टाइम हो गया, अब असली सवालों की बारी है! दो मिनट चिल्लाओ, दो जवाब सुनो और फिर मैं जा रहा हूँ ये क्या नया ड्रामा है? ये लोग डिबेट में आते हैं बहादुरी दिखाने, लेकिन पिटाई शुरू होते ही सरेंडर! बस यही है इनका पैटर्न हल्ला मचाओ, हारो, भागो!
इमरान मसूद सरेंडर

पैसे दिया काँग्रेस ने अच्छे योगी जी लगते हैं- ?
पत्रकार- तुम यहाँ क्यों आए हो?
प्रदर्शनकारी : उन्होंने 300 देकर कार्यक्रम के लिए बुलाया।
पत्रकार- आप PM मोदी को कैसे देखते हैं?
प्रदर्शनकारी : अच्छे हैं
पत्रकार- राहुल गांधी? नहीं! मुझे योगी पसंद हैं

आस्था सिंह और रितु मिश्रा मीडिया को ऐसे ही स्टेटमेंट दे रही है, जैसे बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बिटिया हों, सच पूछा जाए तो माहौल को खराब करने में इन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा जातीय मामला बनाने का प्रयास किया, शर्म आती है, सही बात तो यह है इन दोनों पर पुलिसिया कार्रवाई की जरूरत है।

पप्पू चरसी संसद में बोला अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल पर 18 परसेंट टैरिफ लगाया है लेकिन बांग्लादेश के टेक्सटाइल पर 0प्रतिशत टैरिफ लगाया है और यह बोलते हुए वह मोदी का नाम लेकर छाती कुटने लगा लेकिन पप्पू चरसी ने असल बात छुपा लिया बांग्लादेश के टेक्सटाइल पर जो 0प्रतिशत टैरिफ होगा उसके लिए बांग्लादेश को किस खतरनाक शर्त का पालन करना पड़ेगा
अबे पप्पू थोड़ा बहुत स्टडी किया कर भाई
क्यों अपनी मूर्खता का परिचय पूरी दुनिया में देता है ?
अमेरिका में बांग्लादेश में बने उन्हीं कपड़ों पर जीरो परसेंट टैरिफ होगा जो कपड़े अमेरिका से आयात किए गए कपास या फिर अमेरिका से आपात किए गए मैन मेड फाइबर यानी नायलॉन या पॉलिएस्टर से बनेंगे और यह शर्त बांग्लादेश के लिए बड़ी घाटे का सौदा बन चुकी है क्योंकि अमेरिका से कपास आयात करने का खर्च बांग्लादेश को तीन गुना से ज्यादा पड़ रहा है बल्कि बांग्लादेश को इसे सस्ता कपास भारत चीन और पाकिस्तान से मिल जाता है और अमेरिका से नायलॉन और पॉलिएस्टर मनाने का खर्च भी महंगा पड़ रहा है बांग्लादेश टैक्सटाइल एसोसिएशन ने यूनुस ने जो अमेरिका के साथ यह ट्रेड डील की है उसमें कहा है कि जो 0त्न टैरिफ पर अमेरिका ट्रंप ने जो खतरनाक शर्त लगा दी है अगर हम इस शर्त का पालन करें तो हमको जो कपड़े की कीमत बैठेगी वह चार गुना से ज्यादा चली जाएगी इससे अच्छा है कि हम 19 परसेंट टैरिफ में जाएंगे और अपना कपास या भारत का कपास या पाकिस्तान या चीन के कपास से कपड़े बनाएंगे या हम चीन या पाकिस्तान या भारत से मैन मेड फाइबर इंपोर्ट करेंगे

झारखंड के दुमका में रहने वाली एक महिला का सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में रहने वाले एक व्यक्ति से दोस्ती हुई. महिला अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर एक महिला ने आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के पास चली गई. इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में रहने वाले एक व्यक्ति ने महिला के बताया कि वो काफी अमीर है. इससे प्रभावित होकर दुमका की महिला 1400 किलोमीटर का सफर तय कर मछलीपट्टनम पहुंचीं तो पता चला कि इंस्टाग्राम पर मिला वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं, बल्कि दिहाड़ी मजदूर है। जब पैसा नहीं तो इश्क का भूत भी उतर गया

डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की

ललित गर्ग

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं।डिजिटल युग में सूचना की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तेजी से भ्रम, छल और दुष्प्रचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरों, आवाजों और भाव-भंगिमाओं से भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनित सामग्री के नियमन के लिए आईटी नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। बीस फरवरी से लागू होने जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। यह बदलाव केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि डिजिटल नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक गंभीर हस्तक्षेप है।

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग भयावह रूप से सामने आया है। राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो, अभिनेत्रियों की अश्लील रूप से परिवर्तित तस्वीरें, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले ऑडियो क्लिप और आर्थिक धोखाधड़ी के लिए बनाए गए कृत्रिम संदेश-ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि तकनीक तटस्थ नहीं रहती, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। जब सत्य को जूता जा रहा हो और झूठ को परिष्कृत तकनीक के सहारे प्रमाणिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब समाज में अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियंत्रण की पहल आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिले कि साझा की जा रही सामग्री एआई से निर्मित है या नहीं। इससे पारदर्शिता का एक न्यूनतम मानक स्थापित होगा। साथ ही, तीन घंटे की समयसीमा यह संकेत देती है कि सरकार डिजिटल अपराधों की गंभीरता को समझ रही है। डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद उसका खंडन अक्सर प्रभावहीन हो जाता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई ही नुकसान को सीमित कर सकती है। परंतु यह भी सच है कि इतनी कम समय सीमा में सामग्री की सत्यता की जांच करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत जटिल कार्य है। इससे प्लेटफॉर्मों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो लागत और संचालन दोनों के स्तर पर चुनौतीपूर्ण होगा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ÷आपत्तिजनक÷ या ÷भ्रामक÷ सामग्री की परिभाषा कौन और किस आधार पर तय करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलाधिकार है। यदि नियमन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होगी, तो इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ जन्म लेंगी। अतीत में भी यह देखा गया है कि जब-जब सोशल मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास हुए, तब कुछ वर्गों ने इसे सरकारी अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार और अपराध को रोकने के लिए हो। इस दिशा में स्वतंत्र निगरानी तंत्र, न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य घटक हो सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं। वहाँ की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाली संरचनाएँ विकसित करने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कई युवा जब अपने फोन से दूर किए जाते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक असहजता भी अनुभव करते हैं। यह स्थिति केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं, भारत सहित विकासशील देशों में भी सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन रहा है।

एआई उद्योग स्वयं भी एक नैतिक दुविधा के दौर से गुजर रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियाँ तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में लगी हैं। इस दौड़ में सुरक्षा और नैतिकता के प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हाल ही में एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता द्वारा विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति पर असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना इस तनाव का संकेत है। तकनीक की प्रगति जितनी तेज होगी, नियामक ढाँचे उतनी ही तेजी से अप्रासंगिक होते जाएँगे, यदि उन्हें समयानुकूल अद्यतन न किया जाए। इसलिए नियमन को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सहभागी होना चाहिए।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी संवेदनशील है। यहाँ डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। करोड़ों नए उपयोगकर्ता प्रतिवर्ष ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में यदि असली और नकली के बीच का फर्क स्पष्ट न रहे तो लोकतांत्रिक विमर्श ही संदिग्ध हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक लेन-देन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा-सभी पर डीपफेक का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग का प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि लेबलिंग तभी प्रभावी होगी जब आम उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षर हो। अन्यथा वह लेबल को समझे बिना ही सामग्री साझा करता रहेगा।

आगामी ई-समिट और भारत के 'इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

अंततः यह समझना होगा कि डीपफेक और एआई का संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। कानून आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही, सरकार की पारदर्शिता, न्यायपालिका की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता-इन सबका समन्वय ही इस चुनौती का स्थायी समाधान दे सकता है। यदि नियमन संतुलित और निष्पक्ष होगा तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के बजाय उसे सुरक्षित करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह सत्य और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हो। झूठ को सच में बदलने की तकनीकी क्षमता जितनी बढ़ रही है, उतनी ही दृढ़ता से सत्य की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प भी आवश्यक है। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा है, और यही लोकतांत्रिक समाज की अगली कसौटी भी।

योगी सरकार ने प्रस्तुत किया समग्र विकास का बजट

मृत्युंजय दीक्षित

यूपी के बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की छाप दिख रही है। योगी सरकार का चुनावी वर्ष के पूर्व का यह बजट प्रदेश को समस्त क्षेत्र में विकसित बनाने का आश्वासन देने वाला बजट है, समाज को संतुष्टि प्रदान करने वाला बजटहै । बजट में समाज के चार स्तंभों युवा, किसान, गरीब व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 में संभावित विधानसभा चुनावों से पूर्व 9 लाख करोड़ रु का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सत्तापक्ष, विशेषज्ञ और मीडिया भी इस बजट की सराहना कर रहे हैं। परंपरागत रूप से विपक्ष इसकी आलोचना करते हुए इसे योगी सरकार का अंतिम बजट कह रहा है। योगीराज के इस बजट का आकार भारत के पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट से भी कई गुना बड़ा है। यूपी में योगी बजट की एक और विशेष बात है कि किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 10वां बजट पेश हुआ हो ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार इतने बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। यूपी के बजट में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की छाप दिख रही है। योगी सरकार का चुनावी वर्ष के पूर्व का यह बजट प्रदेश को समस्त क्षेत्र में विकसित बनाने का आश्वासन देने वाला बजट है, समाज को संतुष्टि प्रदान करने वाला बजटहै । बजट में समाज के चार स्तंभों युवा, किसान, गरीब व महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, नारी सशक्तीकरण ,जल सरंक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर पर्याप्त धन आबंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह बजट नारी शक्ति, युवावर्ग, किसान, तथा वंचित वर्ग के उत्थान व खुशहाली को समर्पित है। यह विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं, उत्कृष्ट निवेश का वतावरण, नारी समृद्धि के लिए अभूतपूर्व प्रयास, युवाओं को अद्वितीय अवसर, तकनीक संग रोजगार सृजन वाला बहुआयामी बजट है। योगी सरकार प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह बजट उसका प्रमाण है।

सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने के बाड भी बजट में राजकोषीय अनुशासन पर बल दिया गया है और आधुनिकता पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार लगातार बजट का आकार बड़ा करके प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए नई रणनीतियों के साथ अपनी व्यूह रचना को आगे बढ़ा रही है। महत्वपूर्ण बात है कि आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के बजट में 76 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, कृषि के लिए 20 प्रतिशत सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए विगत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायतों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है और इस बार उनके लिए बजट में 67 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पूर्व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संभावित हैं जिनके कारण सरकार ने नई मांगो के अनुरूप सबसे अधिक 10,695 करोड़ रु की धनराशि पंचायती राज विभाग को आवंटित की है। इस वर्ष के बजट में कई नए क्षेत्रों का सृजन किया गया है व धन आवंटित कर उन्हे पोषित करने का प्रयास किया गया है। एआई तकनीक तथा डाटा सेंटर के साथ औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। हर बार की तरह एक्सप्रेस वे योजनाओं को भी धन आवंटित कर विकास की गंगा बहाने पर ध्यान दिया गया है। बजट में ÷एक जिला एक उत्पाद÷ व ÷एक जिला एक व्यंजन÷ जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई हैं। विकास को गति देने के लिए हर जिले व क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। पर्यटन के माध्यम से भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने व युवाओं के लिए नये रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। बजट को लेकर सरकारी पक्ष का जोरदार दावा है कि नए बजट से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के माध्यम से सरकार ने किसानों को साधने के लिए बजट में बीज से बाजार तक की विस्तृत योजना के साथ धन का खजाना खोल दिया है। सरकार का जोर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता पर तो है ही साथ ही वो किसानों को उद्यम, प्रसंस्करण और बाजार से भी जोड़ना चाहती है। प्रदेश के बजट में पशुधन एवं दुग्ध विकास को भी स्थान देते हुए निराश्रित गोवंश के लिए व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 220 नई दुग्ध समितियां गठित करने की घोषणा की गई है। विकास कार्यों के लिए बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी ग्रामीण अधोसंरचना को गति प्रदान करेगा, इससे सम्बंधित 43.5 हजार करोड़ रु की नई योजनाएं बजट में आवंटित की गई हैं। बजट में बताया गया है कि प्रदेश में हो रहे बदलावों के अनुसार किस प्रकार राजस्व जुटाने में एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, देश में आबकारी निर्यात नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बना है । देश के मोबाइल निर्माण सेक्टर में 65 प्रतिशत मोबाइल यूपी में बन रहे हैं। 44.74 हजार करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात से यूपी देश की ताकत बन चुका है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार तहसीलों के लिए योजना बनाई गई है और शिक्षा पर खर्च बढ़ाया गया है।

विचार

भारतीय राजनीति की सशक्त और संवेदनशील आवाज़ थी सुषमा स्वराज

सुरेन्द्र शर्मा

सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की उन विरल हस्तियों में से थीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, वाक्पटुता, संवेदनशीलता और कार्यकुशलता से जनमानस में विशेष स्थान बनाया। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत, कुशल प्रशासक और करुणामयी नेता थीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की और विशेष रूप से भारत की विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ऐतिहासिक माना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, जिससे बचपन से ही उनके भीतर राष्ट्रसेवा की भावना विकसित हुई। उन्होंने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से विधि (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन में वे एक उत्कृष्ट वक्ता और सक्रिय छात्रनेता रहीं। वे कई बार 'सर्वश्रेष्ठ वक्ता' का पुरस्कार जीत चुकी थीं, जिससे उनकी भाषण कला का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुषमा स्वराज ने बहुत कम आयु में राजनीति में प्रवेश किया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे हरियाणा विधानसभा की सदस्य बनीं और 27 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गईं। उस समय वे देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री थीं। यह उनकी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी जुड़ी रहीं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद सुषमा स्वराज ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रहीं। वर्ष 1998 में वे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, हालांकि उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली। हर पद पर उन्होंने दक्षता और ईमानदारी से कार्य किया। सुषमा स्वराज की पहचान एक ओजस्वी वक्ता के रूप में भी रही। संसद में उनके भाषण तार्किक, प्रभावशाली और मर्यादित होते थे। वे विपक्ष में रहते हुए भी अपनी बात मजबूती से रखती थीं और सत्ता में रहते हुए भी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती थीं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान दक्षता से बोलती थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण विशेष रूप से सराहा गया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को मजबूती प्रदान की। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह पद केवल सरकार की आलोचना करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने, नीतियों की समीक्षा करने और जनता की आवाज़ को संसद में प्रभावी ढंग से उठाने का दायित्व भी निभाता है। सुषमा स्वराज ने वर्ष 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया।

प्रेरणा

भक्तों की सहायता करते हैं ईश्वर

ईश्वर को हम भले ही न देख पाएं लेकिन ईश्वर हर क्षण हमें देख रहा होता है। उसकी दृष्टि हमेशा अपने भक्तों एवं सद्व्यक्तियों पर रहती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में कभी न कभी कठिन समय में ईश्वर स्वयं आकर आपकी सहायता कर चुके हैं। उस कठिन समय में आपके अंदर भक्ति की भावना उमड़ रही होगी और आप ईश्वर को याद कर रहे होंगे। शास्त्र कहता है कि ईश्वर के लिए संसार का हर जीव उसकी संतान के समान है। जो व्यक्ति उसके बनाये नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करता है ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। गजराज की कहानी आपने जरूर सुनी या पढ़ी होगी। नदी में गजराज को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इस कठिन समय में गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान विष्णु प्रकट हो गये। भगवान ने अपने चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज के प्राण की रक्षा की। सूरदास जी के जीवन की भी एक ऐसी ही कथा है। सूरदास जी देख नहीं सकते थे। एक बार गलती से एक गड्ढ़े में गिर गये। गड्ढ़े से निकलने का काफी प्रयास करने पर भी वह बाहर निकलने में असफल रहे।

सूडोकु नवचाल- 7423

★★★★☆ मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवचाल - 7422 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

दैनिक पंचांग

14 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

शनिवार 2026 वर्ष का 45 वा दिन दिशाशूल पूर्व ऋतु शिशिर। विक्रम संवत् 2082 शक संवत् 1947 मास फाल्गुन (दक्षिण भारत में माघ) पक्ष कृष्ण तिथि द्वादशी 16.02 बजे को समाप्त। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 18.16 बजे को समाप्त। योग सिद्धि (अमृत) 03.18 बजे रात को समाप्त। करण तैतिल 16.02 बजे तदनन्तर गर 04.38 बजे प्रातः को समाप्त। चन्द्रायु 24.2 घण्टे रवि क्रान्ति दक्षिण 13°05' सूर्य उत्तरायण कलि अहर्गण 1872620 जूलियन दिन 2461085.5 कलियुग संवत् 5126 कल्पारंभ संवत् 1972949123 सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123 वीरनिर्वाण संवत् 2552 हिजरी सन् 1447 महीना शाबान तारीख 25 विशेष प्रदोष व्रत।

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	कुंभ	06.33 बजे से
चंद्र	धनु में	मीन	08.06 बजे से
मंगल	मकर में	मेष	09.37 बजे से
बुध	कुंभ में	वृष	11.17 बजे से
गुरू	मिथुन में	मिथुन	13.15 बजे से
शुक्र	कुंभ में	कर्क	15.28 बजे से
शनि	मीन में	सिंह	17.44 बजे से
राहु	कुंभ में	कन्या	19.56 बजे से
केतु	सिंह में	तुला	22.07 बजे से
		वृश्चिक	00.22 ब.से
राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक		धनु	02.38 बजे से
		मकर	04.43 बजे से

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
काल	05.55 से	07.23	बजे तक	लाभ	05.37 से	07.10	बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51	बजे तक	उद्वेग	07.10 से	08.42	बजे तक
रोग	08.51 से	10.19	बजे तक	शुभ	08.42 से	10.14	बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46	बजे तक	अमृत	10.14 से	11.47	बजे तक
चर	11.46 से	01.14	बजे तक	चर	11.47 से	01.19	बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42	बजे तक	रोग	01.19 से	02.51	बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10	बजे तक	काल	02.51 से	04.23	बजे तक
काल	04.10 से	05.37	बजे तक	लाभ	04.23 से	05.56	बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें।

काकुरो पहेली - 7180

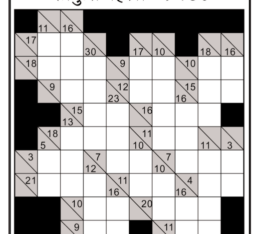

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए. किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणतः

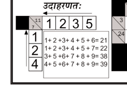

1+2+3+4+5+6=21
1+2+3+4+5+7=22
3+5+6+7+8+9=38
4+5+6+7+8+9=39

काकुरो - 7179 का हल

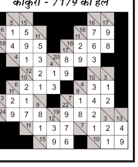

पुलवामा की सातवीं वर्षगांठ

केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संकल्प का अवसर

कर्नल देव आनंद लोहामरोड़
सुरक्षा विशेषज्ञ

"पुलवामा के बाद आंतरिक सुरक्षा ढांचे में भी बदलाव हुए। खुफिया समन्वय को मजबूत किया गया, आतंकी वित्तपोषण पर प्रहार किए गए और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का निर्णय भी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा माना गया, जिसके पीछे यह सोच थी कि आतंकवाद के संरचनात्मक आधार को तोड़े बिना स्थायी शांति संभव नहीं है।"

14 फरवरी 2026 को देश 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की सातवीं वर्षगांठ मना रहा है। सात वर्ष बाद भी वह दिन भारतीय चेतना में एक गहरे घाव की तरह दर्ज है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। यह केवल एक आतंकी वारदात नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा संरचना, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामरिक सोच की निर्णायक परीक्षा थी। पुलवामा से पहले भारत का सुरक्षा परिदृश्य संक्रमण के दौर में था। जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र कमजोर तो हुआ था, पर समाप्त नहीं हुआ था। सीमा पार से छद्म युद्ध और घुसपैठ की रणनीति जारी थी, जबकि भारत की प्रतिक्रिया अधिकतर सामरिक संयम पर आधारित रहती थी। 2016 के उरी हमले के बाद की लक्षित सैन्य कार्रवाई ने नीति में बदलाव का संकेत दिया था, लेकिन पुलवामा ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब "रणनीतिक धैर्य" की पुरानी परिभाषा बदल चुकी है।

हमले के बाद भारत ने शोक के साथ एक स्पष्ट सामरिक संदेश भी दिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई कार्रवाई कर यह स्थापित किया कि आवश्यकता पड़ने पर भारत नियंत्रण रेखा के पार जाकर भी कार्रवाई करेगा। इस कदम ने दशकों पुरानी झिझक तोड़ी और यह संकेत दिया कि आतंकवाद अब केवल कूटनीतिक विरोध का विषय नहीं रहेगा, बल्कि उसका उत्तर प्रत्यक्ष और निर्णायक सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत की नई सुरक्षा नीति प्रतिरोध और दंडात्मक कार्रवाई के संयोजन पर आधारित दिखाई दी।

पुलवामा के बाद आंतरिक सुरक्षा ढांचे में भी बदलाव हुए। खुफिया समन्वय को मजबूत किया गया, आतंकी वित्तपोषण पर प्रहार किए गए और जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का निर्णय भी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा माना गया, जिसके पीछे यह सोच थी कि आतंकवाद के संरचनात्मक आधार को तोड़े बिना स्थायी शांति संभव नहीं है।

आज वैश्विक परिदृश्य और अधिक जटिल है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रतिस्पर्धा और तकनीकी युद्ध के नए आयामों ने अंतरराष्ट्रीय वातावरण को अनिश्चित बना दिया है। मानव रहित विमान, संगणकीय आक्रमण और सामाजिक माध्यम आधारित कट्टरपंथ आधुनिक संघर्ष के उपकरण बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत के लिए सुरक्षा का अर्थ केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक मजबूती भी है।

पुलवामा की सातवीं वर्षगांठ पर भारत के लिए संदेश बहुआयामी होना चाहिए। यह केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि संकल्प का अवसर है। शहीदों का सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह नीतिगत निर्णयों में भी दिखाई देना चाहिए। सैनिकों का मनोबल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से बनता है। हाल में दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट से जुड़े निर्णयों ने सैनिक समुदाय में चिंता उत्पन्न की है। दिव्यांगता पेंशन सेवा के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति है, न कि सामान्य आय। ऐसे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सैनिकों का विश्वास ही राष्ट्रीय सुरक्षा की असली नींव है।

पुलवामा की सातवीं वर्षगांठ पर भारत के लिए संदेश बहुआयामी होना चाहिए। यह केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि संकल्प का अवसर है। शहीदों का सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह नीतिगत निर्णयों में भी दिखाई देना चाहिए। सैनिकों का मनोबल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से बनता है। हाल में दिव्यांगता पेंशन पर आयकर छूट से जुड़े निर्णयों ने सैनिक समुदाय में चिंता उत्पन्न की है। दिव्यांगता पेंशन सेवा के दौरान हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति है, न कि सामान्य आय। ऐसे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सैनिकों का विश्वास ही राष्ट्रीय सुरक्षा की असली नींव है।

भारत आज एक उभरती वैश्विक शक्ति है। उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, कूटनीतिक प्रभाव बढ़ा है और रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण जारी है। लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भारत को संयम और दृढ़ता का संतुलन बनाए रखना होगा। न तो उकसावे में आकर अस्थिरता बढ़ानी है और ना ही अपने नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता करना है।

पुलवामा ने देश को झकझोरा, पर उसी झटके ने सुरक्षा नीति को अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासी बनाया। सात वर्ष बाद असली प्रश्न यह है कि क्या हमने उस चेतावनी को स्थायी राष्ट्रीय रणनीति में बदल दिया है। यदि स्मृति केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया बनकर रह जाए तो उसका महत्व सीमित है, लेकिन यदि वह आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, तकनीकी नवाचार और सैनिक कल्याण को मजबूत करे, तो वही राष्ट्र-निर्माण का आधार बनती है। पुलवामा की वर्षगांठ पर भारत का संदेश स्पष्ट होना चाहिए-हम शांति चाहते हैं, पर कमजोरी नहीं, हम संवाद के पक्षधर हैं, पर आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं। और सबसे बढ़कर, यह उन वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित किया, कि हम उनके कल्याण से जुड़ी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सोचें, न कि उनमें कटौती करें। सैनिक सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और संवेदनशील नीति से सिद्ध होता है-यही शहीदों के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यंग्य

प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है!

प्रभात गोस्वामी
व्यंग्यकार

देश और दुनिया में इन दिनों वेलेंटाइन के प्यार का मौसम हिलोरे ले रहा है। हर कोई प्यार की फसल काट रहा है। पुराने दौर की मानिंद कोई उसकी तीखी धार से कट नहीं रहा है। हर कोई प्यार के लिए किसी न किसी को चुन रहा है। पहले जैसे कोई प्यार की खातिर दीवार पर चुना नहीं जा रहा है। वे दिन हवा हो गए जब पसीना गुलाब हुआ करता था। प्यार का पहला खत लिखने के दिन भी लद चुके हैं। कहीं प्यार के विरुद्ध समाज की रुसवाइयों के बीच वह आवाज नहीं आती कि 'कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को।' रोमियो-जूलियट से लेकर लैला-मजनूं और शीरीं-फरहाद तक, सबकी बस एक कहानी रह गई है। सच्चा प्यार अब सिर्फ इतिहास लिखने के काम आता है। आज सारे प्रेमी एक सुर में गा रहे हैं, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। पहले प्यार में मन के तार झनझनाते थे, रातों की नींद उड़ जाया करती थी और दिन का चैन लुट जाता था। अब प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार अब एक भावना नहीं, मस्ती का एक वेलेंटाइन उत्सव बन गया है। सात दिन इसके रंग में रंगकर आगे बढ़ जाओ। पहले प्यार आंखों से अभिव्यक्त किया जाता था, अब सोशल मीडिया से इजहार किया जा रहा है। हमारे वक्त में प्यार के संदेशे कबूतर लेकर जाते थे। फिर मोहल्ले के किसी मासूम बच्चे को एक टॉफी देकर अपना प्रेम-पत्र आगे भिजवाते थे। कई बार तीर गलत दिशा में चल जाता था। प्रेम-पत्र माशूका की जगह उसकी मां के हाथों में थमा दिया जाता था। फिर क्या? मोहल्ले भर में प्यार की ऐसी दुर्गति होती थी कि आदमी प्यार करने से डरता था। उन दिनों हमारे बालसखा भोलू को प्यार का कीड़ा काट गया तो उसका मन मचलने लगा। रोज छत से अपनी प्रस्तावित प्रेमिका से आंख-मटक्का करते-करते कुछ उम्मीद जगी। सोचा, अब वक्त आ गया है जब प्रेम-पत्र लिखा जाए। दोस्तों से सलाह-मशविरा किया गया। कई बड़े-बड़े शायरों के मजमुआ बाजार से खरीदकर लाए गए। कादर खान की मानिंद हम दोस्तों से प्यार में डूबे संवाद लिखने की गुजारिश भी की गई। ढेरों शेर ढूंढे गए, शब्दों की कसीदाकारी के लिए पुरानी किताबें टटोली गईं। भोलू भाई रोजाना सौ-पचास खत लिख-लिखकर रद्दी की टोकरी में डालते रहे। दोस्तों ने आगाह किया कि जल्दी-जल्दी लिख डालो। भोलू भोलेपन से कहते, 'प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है!' दो महीने बाद जब खत तैयार हुआ तो उसे माशूका तक पहुंचाने के लिए मोहल्ले के बबलू को पटाया गया, चॉकलेट दी गई, बहलाया-फुसलाया गया। लेकिन खत पहुंचने से पहले ही बैरंग लौट आया। माशूका के पिता ने अपनी लड़की का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया। आज तक कुंवारे भोलू को लगता है कि काश वह आज के दौर में पैदा हुआ होता! आज प्रेम में किसी प्रेम-पत्र या इजहार के लिए पंचवर्षीय योजना जैसा कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। प्यार के लिए मात्र सात दिन चाहिए, रोज डे मनाओ, प्रपोज करो, चॉकलेट दो, टेडी दो, वादे करो, गले लगाओ, किस करो और वेलेंटाइन डे मना लो।

लेखकों से आग्रह है...
वे 'सच बेधड़क' में प्रकाशन के लिए अपने लेख, कविता, कहानी, व्यंग्य आदि रचनाएं हमें Editor@sachbedhadakdaily.com पर ई मेल करें। साथ में रचना के अप्रकाशित होने का स्वघोषणा पत्र भी भेजें।

बांग्लादेश में आम चुनाव में बीएनपी की जीत

तारिक अनवर कर सकते हैं भारत के साथ रिश्तों में नई पहल

गजानन्द शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आ गए हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को मिले प्रचंड बहुमत से यह साफ है कि बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथी ताकतों को नकार दिया है। चुनावों के बीच बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी के प्रमुख बने उनके बेटे तारिक अनवर के अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करने वाले छात्र नेताओं को बांग्लादेश की जनता ने समर्थन नहीं दिया। जनता ने उन्हें हीरो नहीं माना। चुनाव में वे जमात-ए-इस्लामी के साथ नजर आए, संभवतः जनता ने इसलिए भी उन्हें नकार दिया।

शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद कुछ शक्तिशाली पश्चिमी ताकतों की भूमिका पर सवाल उठे थे और उनकी पार्टी ने यह भी कहा था कि द्वीप अमेरिका को नहीं सौंपा गया, इसलिए उनकी सरकार को हटा दिया गया। छात्र नेताओं को जनता ने इस आरोप से मुक्त नहीं किया। वहीं, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी की हार पाकिस्तान के लिए झटका है। पाकिस्तान जमात के कंधे पर सवार होकर 1971 के बाद के इतिहास को पलटना चाहता है। उसकी मंशा बांग्लादेश और चीन के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों के माध्यम से भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की रही है। बांग्लादेश की जनता ने उसकी इस मंशा को भी लाल झंडी दिखा दी है।

बांग्लादेश के चुनाव नतीजों का एक पहलू यह भी है कि वहां करीब 60 प्रतिशत मतदान हुआ, यानी बड़ी संख्या में लोग चुनाव से दूर रहे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था। यदि वह चुनाव मैदान में होती तो यह तय है कि बीएनपी को इतनी शानदार जीत नहीं मिल पाती। माना जा रहा है कि अवामी लीग के ज्यादातर समर्थक और हिंदू समुदाय या तो चुनाव से दूर रहे या उनमें से अधिकांश ने बीएनपी के पक्ष में मतदान किया।

बांग्लादेश की जनता का संदेश साफ है कि वह देश में कट्टरपंथी ताकतों की वापसी नहीं चाहती। जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव से एक-दो दिन पहले हालांकि हिंदुओं को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की थी कि यदि उसकी सरकार बनती है तो वह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद जो हालात बने, उनसे हिंदू समुदाय जमात के इस बयान से आश्वस्त नहीं हो पाया। अब देखना है कि चुनाव नतीजों के बाद जमात क्या रुख अपनाती है।

फिलहाल भारत के लिए संतोष की बात यही है कि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी सत्ता में नहीं आ रही है। अभी 'इंतजार करो और देखो' वाली स्थिति है कि बीएनपी प्रमुख तारिक अनवर प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद क्या रुख अपनाते हैं और जमात को सत्ता में भागीदारी देते हैं या दूर रखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शोक व्यक्त करने ढाका गए थे और तब उनकी मुलाकात तारिक अनवर से हुई थी। उम्मीद है कि बीएनपी की सरकार के सत्ता संभालने के बाद संवाद का सिलसिला नए सिरे से आगे बढ़ेगा और रिश्तों को नई दिशा मिलेगी।

बांग्लादेश के चुनाव नतीजों पर भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ अमेरिका की भी नजरें लगी थीं। शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस ने अपने करीब डेढ़ वर्ष के शासनकाल में भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने और भारतीय हितों पर चोट करने के एजेंडे को आगे बढ़ाया तथा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने लगातार ऐसे कदम उठाए, जिनसे भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा। इसलिए अब देखना है कि तारिक अनवर भारत के साथ रिश्तों को पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। उनके सामने भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन साधने की चुनौती होगी। यूनुस के शासनकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गर्त की ओर जाने लगी है और भारत के साथ रिश्तों में सुधार के बिना उसे आसानी से पटरी पर नहीं लाया जा सकता। बांग्लादेश की धमनियां भारत से जुड़ी हैं, तारिक की सरकार को यह मानकर ही आगे बढ़ना होगा।

यूनुस का भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अपनी चीन यात्रा के दौरान यह कहकर भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हैं और उनकी समुद्र तक पहुंच नहीं है। बंगाल की खाड़ी का एकमात्र संरक्षक बांग्लादेश है और चीन को वहां आकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वृहद बांग्लादेश की अवधारणा को हवा देने का प्रयास किया। कुछ तत्व भारत के पूर्वोत्तर हिस्से पर कब्जा करने की मंशा जताते दिखे। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के भारत के साथ रिश्ते सुधरें। वह जमात के माध्यम से दोनों देशों के रिश्तों को पूर्वी पाकिस्तान वाले दौर में ले जाना चाहता है। अब देखना है कि पाकिस्तान और यूनुस की युति क्या नया दांव चलती है।

यूनुस का शासनकाल बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रहा। हिंदुओं, उनकी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर सुनियोजित तरीके से हमले हुए, उन्हें डराया-धमकाया गया और बार-बार निशाना बनाया गया। ऐसे में तारिक के सत्ता में आने के बाद हिंदू समुदाय की पहली उम्मीद यही होगी कि देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल फिर से बने और उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला बंद हो। बीएनपी के पिछले शासनकाल को भारत के साथ रिश्तों का मानक मानकर फिलहाल न तो कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है और ना ही कोई पुख्ता धारणा बनाई जा सकती है।

सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश की नई सरकार बदलते वैश्विक परिदृश्य और दक्षिण एशिया की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी। वह बांग्लादेश में भारत-विरोधी अवधारणा को बढ़ावा देकर कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। सबसे अहम सवाल यह भी है कि बीएनपी की सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को लेकर क्या रुख अपनाती है। वह टकराव का रास्ता चुनती है या सुलह और सहयोग का नया पुल बनाती है, यह देखना होगा। भारत अपनी पूर्वी सीमा पर नया मोर्चा खोलने के पाकिस्तान के मंसूबों को किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने देगा।

भारत ने यूनुस प्रशासन की शत्रुतापूर्ण मंशा को देखते हुए जवाबी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सवाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी 'चिकन नेक' की सुरक्षा का हो या अन्य सैन्य सुविधाओं के विस्तार का, भारत मजबूती के साथ जरूरी कदम उठा रहा है। भारत बीएनपी के पिछले शासनकाल की उन घटनाओं को भी नहीं भूल सकता, जिनमें बांग्लादेश से भारत भेजी गई हथियारों की खेप का पकड़ा जाना और पूर्वोत्तर के अलगाववादी तत्वों को मिला समर्थन शामिल है। तत्कालीन खालिदा जिया सरकार का पाकिस्तान के प्रति रुख दोस्ताना भले ही न हो, नरम जरूर था।

चुनाव नतीजों के बाद बीएनपी के एक बड़े नेता अमीर खसरू महमूद चौधरी की यह टिप्पणी गौर करने लायक है कि किसी भी देश के साथ हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, हित और दखल न देने की नीति पर आधारित होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बीएनपी की नई सरकार पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर भारत के साथ रिश्तों में सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बैंकिंग शुल्कों की अनैतिक वसूली व जवाबदेही का प्रश्न

भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर लोकसभा की याचिका समिति ने जो आंकड़े पेश किए है वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि बैंकिंग की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि बैंकों में 'सेवा' से अधिक 'वसूली' को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि (मिनिमम बैलेंस) न रख पाने के एवज में आमजन से 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करना किसी भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह राशि उन करोड़ों निम्न-मध्यम आय वाले खाताधारकों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ते समय आसान व सुलभ वित्तीय भविष्य के सपने दिखाए गए थे। विडंबना है कि यह वसूली उस वर्ग से की गई, जो पहले से ही आर्थिक तंगी के कारण अपने खाते में कुछ हजार रुपए भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा था।

समिति की रिपोर्ट में यह तथ्य सबसे अधिक परेशान करने वाला है कि यह वसूली अक्सर 'हिडन चार्जेज' के नाम पर की जाती है, जिसकी भनक ग्राहकों को तब लगती है जब उनके खाते से रकम कट चुकी होती है। आधुनिक डिजिटल युग में, जहां पारदर्शिता को बैंकिंग का मूल आधार माना जाना चाहिए, वहां सूचना के अभाव में इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई अनैतिक भी है। निजी क्षेत्र के बैंकों का यह रवैया और भी संदेहास्पद है कि उनके पास पुराने रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने 2772 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। बड़े निजी बैंकों की ओर से हजारों करोड़ रुपए केवल जुर्माने के रूप में वसूलना यह दर्शाता है कि बैंकों के लाभ का एक बड़ा हिस्सा अब सेवाओं के बदले नहीं, बल्कि ग्राहकों की मजबूरियों व चूक के दंड से आ रहा है।

लोकसभा की याचिका कमेटी की इस जुर्माने को पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश एक स्वागत योग्य कदम है। समिति ने इसे आम उपभोक्ताओं पर 'अतिरिक्त बोझ' करार दिया है, जो पूरी तरह तर्कसंगत है। एक बचत खाताधारक का बैंक के साथ संबंध भरोसे का होता है, न कि डर का। यदि न्यूनतम राशि न रख पाने पर ग्राहक को दंडित किया जाता है, तो यह उसे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से दूर धकेलने जैसा है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अब इस दिशा में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि उसने दंड शुल्क से कितना राजस्व एकत्र किया, बल्कि इस बात से आंका जाना चाहिए कि उसने कितने नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। बैंकों को यह समझना होगा कि वे समाज के प्रति भी उत्तरदायी हैं। यदि कोई खाताधारक न्यूनतम राशि नहीं रख पा रहा है, तो बैंक का प्राथमिक कर्तव्य उसे दंडित करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए जागरूक करना या उसे ऐसे बचत खाते की ओर मोड़ना होना चाहिए, जहां न्यूनतम शेष की बाध्यता नहीं होती।

सम्पूर्ण क्रिया माया आधारित है, ब्रह्म केवल रथी है। ब्रह्म सम्पूर्ण यात्रा में निर्लिप्त रहता है। उसके मन में कामना उत्पन्न करने से लेकर बुद्बुद् निर्माण तक माया ही सक्रिय है। सम्पूर्ण चक्र कामना से शुरू होता हुआ कारण शरीर में प्रतिष्ठित अव्यय तक पहुंचता है।

माया स्त्रैण भाव का केन्द्र

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

स्त्रैण जीवन का केन्द्र तो माया भाव ही है। पति की शक्तिरूपा बनकर जीना ही है। जीवन के दो भाग होते हैं। एक भाग धरती पर आना और अपना विस्तार करना। दूसरा, भाग पुनः अपने स्थान को लौट जाना। दोनों ही भूमिका स्त्री ही निभाती है।

हमारे तीन शरीर हैं–कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तीन-तीन स्वरूपों में ब्रह्म और माया भी हैं–अव्यय-अक्षर-क्षर तथा माया-योगमाया और प्रकृति। अक्षर व क्षर को कृष्ण अपनी परा एवं अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा जड़ प्रकृति देह रूप में तथा चेतन प्रकृति भोक्ता रूप में देह में प्रवेश कर स्वकर्म के द्वारा सबको धारण करती हैं। मेरी ये दोनों प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हैं और मैं ही इनके साथ जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। मैं ही लय का कारण भी हूं।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।। (15.16)
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।। (7.6)

अक्षर भी सगुण-निर्गुण दो रूप है। सगुण का अर्थ है माया के आधीन। शक्ति प्रत्येक जीव में चार प्रकार की है–देह अधिभूत है, प्राण अधिदैव है, मन और बुद्धि अध्यात्म हैं। ईश्वर अधियज्ञ है। यही ब्रह्म है। इसकी नाना शक्तियां हैं। अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से विश्व रूप में सर्वत्र व्याप्त होकर विद्यमान है। यह जगत ही उनकी मूर्ति है। हमारी मां है। अहं के भीतर प्रकाशित हो रही है। वह अदृश्य है किन्तु उसके कार्यों को देख पा रहे हैं। माया और ब्रह्म के कर्म सुसूक्ष्म हैं।

वैदिक नाम भले ही ब्रह्म-माया हो, तात्त्विक रूप में तो अग्नि-सोम रूप में ही समझ में आते हैं। ब्रह्म आग्नेय प्राण है। गति-स्थिति रूप है। कामना से क्षुब्ध प्राण अप् रूप होकर प्राण-आप (पुरुष-स्त्री) दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्राण आप में ही प्रविष्ट हो जाता है। आप ही सौम्या है। यह आप ही आपः-वायु-सोम रूप होता है। शरीर में इसकी स्थिति क्रमशः स्थूल-सूक्ष्म-कारण में प्रधान होती है। सृष्टि विकास के लिए सोम ही आहुति द्रव्य होता है। इसी भार्गव तत्त्व में स्नेहन-वायु-शर्करा तीन घटक होते हैं। ये तीनों माया के अस्त्र भी हैं। स्थूल पुरुषाग्नि में पहली आहुति भी इन्हीं तीनों की होती है। द्वितीय आहुति में ये तीनों ही शुक्र के स्वरूप निर्माता होते हैं। योषाग्नि में आहुत हो जाते हैं। मूल में तो प्राण-आप ही हैं। तृतीय आहुति प्रधान है। शोणित से डिम्ब की यात्रा यूं तो प्रथम यज्ञ से आरंभ हो जाती है, पुंभ्रूण और स्त्रीभ्रूण का योग भी मार्ग में ही हो जाता है। मातरिश्वा ही अन्तिम आहुति में रेतोधा बनता है। आगे माया द्वारा ब्रह्म का स्थानान्तरण ही है।

सम्पूर्ण क्रिया माया आधारित है, ब्रह्म केवल रथी है। ब्रह्म सम्पूर्ण यात्रा में निर्लिप्त रहता है। उसके मन में कामना उत्पन्न करने से लेकर बुद्बुद् निर्माण तक माया ही सक्रिय है। सम्पूर्ण चक्र कामना से शुरू होता हुआ कारण शरीर में प्रतिष्ठित अव्यय तक पहुंचता है। वहां से ब्रह्मांश लेकर (माया आवरित) पुनः स्थूल में पूर्ण होता है।

प्राणों के तपन से प्राण द्वारा जो आप पैदा हुआ, वही माया नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने विस्तार के लिए आग्नेय प्राण को युगल तत्त्व की आवश्यकता थी। यही सृष्टि के आरंभ के अग्नि-सोम तत्त्व कहलाए। अद्भुत बात तो यह है कि प्राण ने आप को पैदा किया और उसमें प्रविष्ट हो गया–**तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्।** अग्नि भीतर और सोम आवरण बना। वही सोम वायु के सहयोग से बुद्बुद् बन गया। सोम ऋत है। उसके लिए कहा गया है कि अग्नि को प्रज्वलित देखकर सोम दौड़ता है- आहुत होने को। ऋग्वेद का एक मंत्र है–

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति।
अग्निर्जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः।। (ऋ. 5/44/15)

अग्नि सत्य है- ऋत सोम ही आहुत होने के लिए आता है। गौण भाव में सखा रूप रहता है। अग्नि को शान्त करता है और अग्नि के साथ चिति रूप निर्माण करता है।

स्थूल जीवन में ब्रह्म ही आत्म रूप कार्य करता है। स्त्री आत्मा जाता है आहुत होने। दिखाई शरीर देता है–माध्यम रूप में। स्त्री में ऋतुमति होने के साथ ही माया की कामना करवटें बदलने लगती हैं। पुरुष को 3-4 साल अधिक लगते हैं। माया टटोलने लगती है। पुरुष का आधा स्त्री भाग भी अपूर्ण होता है, पौरुष भाग अपरिपक्व। माया को उल्टे पांव लौटना पड़ता है। यह दृश्य स्मृति पटल से कभी ओझल नहीं होता।

यह जीवन की बड़ी अभाव की अनुभूति है। स्त्री की कामना में एक स्थायित्व का बोध रहता है। पुरुष की कामना क्षणिक है। स्त्री-पुरुष दोनों के तीन-तीन शरीर कामनापूर्ति के साधन बनते हैं। कामना का केन्द्र केवल मन होता है- श्वोवसीयस मन। यही जीवन की दिशा तय करता है। यही सृष्टि की ओर दौड़ता है। इसका एकमात्र लक्ष्य ही एकोऽहं बहुस्याम् है। चौरासी लाख योनियों में यही मन है। सृष्टि में यही मन महन्मन, सर्वेन्द्रिय मन और इन्द्रिय मन के रूप में कार्य करता है। मन का निर्माण अन्न से होता है। शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा के अन्न भिन्न-भिन्न होते हैं और सभी त्रिगुणी (सत्व-रज-तम) रूप होते हैं। 'जैसा खावे अन्न-वैसा होवे मन।' अन्न स्थूल भी होता है-सूक्ष्म भी (विचार रूप), किन्तु मन तो सूक्ष्म ही होता है। कामना भी सूक्ष्म ही होती है। दोनों में ही क्रिया नहीं होती, किन्तु अन्न के गुण-दोष विकार रूप में मन को प्रभावित करते हैं- इच्छाएं बदलती हैं। भिन्न-भिन्न अन्न की ओर मन को आकर्षित करती हैं। काल का समन्वय एक बड़ा द्वन्द्व रहता है। समय के साथ मन गहरा होता है। विचारों की नई श्रृंखला बनती है। जीवन के नए विषय, नए लोग वातावरण बदलते हैं। अपने आत्म तत्त्व का ज्ञान होता है। जीवन में दूर तक दृष्टि जाने लगती है। एक विचार उभरने लगता है- मैं माया हूं। देशकाल के अनुरूप अपनी भूमिका निभानी है। मैं शरीर नहीं हूं। मुझे अपने युगल तत्त्व तक पहुंचना है। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है। स्वयं को तैयार भी करना है।

माया रूप मां ही अध्यापिका भी है। सहेलियां स्थूल-सूक्ष्म दोनों धरातलों पर सहायक रहती हैं। आज सूक्ष्म धरातल छूट गया। वार-त्यौहार, खान-पान, वेश-भूषा छूटते जा रहे हैं। शरीर-मन-बुद्धि-अहंकार का स्थूल दृष्टि से विकास होता है। मां को विवाह बाद के जीवन का ज्ञान रखकर- परोक्ष भाषा में- कई विषय खोलने पड़ते हैं। परोक्ष भाषा के विषय माया भाव के साथ सम्बन्ध रखते हैं। विवाह पश्चात् स्त्री शरीर से नहीं- आत्मा से- आत्मा के लिए- आत्मज के लिए जीती है, स्वयं के लिए नहीं। जब कभी पीहर जाती है, तब स्वयं का- शरीर का- अल्हड़ काल का ध्यान आता है। अगले दिन ससुराल पहुंचते ही फिल्म समाप्त हो जाती है। पुनः माया भाव जाग्रत हो जाता है। जीवात्मा की भूमिका भी- संस्कारों के अनुरूप- लौट आती है।

स्त्रैण जीवन का केन्द्र तो माया भाव ही है। पति की शक्तिरूपा बनकर जीना ही है। जीवन के दो भाग होते हैं। एक भाग धरती पर आना और अपना विस्तार करना। दूसरा, भाग पुनः अपने स्थान को लौट जाना। दोनों ही भूमिका स्त्री ही निभाती है। एक भाग विवाह पूर्व से विवाह पश्चात 50 वर्ष की आयु तक का। दूसरा भाग 50 की आयु के बाद वानप्रस्थ और संन्यास का। सभी भूमिकाएं माया ही संभालती है।

आज के जीवन की बड़ी त्रासदी यही है कि कोई भी मां अपने पुत्र को पुत्र/पति के स्वरूप की व्याख्या नहीं समझाती। उसके मूल स्त्रैण भाव का विकास भी नहीं करती। न उसको गर्भ में संस्कारित करती है- अभिमन्यु की तरह। न ही स्त्रैण भावों को पूरित ही करती है क्योंकि उसका स्वयं का भी पौरुष भाव ही आज प्रबल है। उस बालक की यही अपूर्णता समाज को कैसे पूर्णता दे सकती है?

-क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

बुक इनसाइट

क्वीन ऑफ फेसेज

पेट्रा लॉर्ड का फैंटेसी उपन्यास 'क्वीन ऑफ फेसेज' एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, जहां तबाही मचाने वाली बाढ़ और एक जानलेवा बीमारी के बीच लोग पैसे देकर अपना'नया शरीर' खरीद सकते हैं। शरीर बदलना यहां आम बात है, लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल बेहद असाधारण हैं कि व्यक्ति की पहचान क्या है? शरीर और मन का रिश्ता कितना गहरा है? और क्या नई देह सचमुच नया जीवन दे सकती है? इस कहानी की नायिका एनाबेल गेज, जो गरीबी में पली है, एक बीमारी के बाद एक बूढ़े और तेजी से खराब हो रहे पुरुष शरीर में फंस जाती है। वह अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में एक नया शरीर चुराना चाहती है, लेकिन अमीर और प्रभावशाली 'नेल' उसकी राह में आ खड़ी होती है। इस किताब में लेखिका बॉडी स्वैपिंग जैसे साइंस फिक्शन विचार को न केवल रोमांच तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उसे शरीर व आत्म पहचान जैसे विषयों से जोड़ती हैं।

आर्ट एंड कल्चर

एआइ से कितना बदलेगा सिनेमा?

क्या यह सिनेमा का भविष्य है, जिसमें हम अपनी पसंद के अभिनेता-अभिनेत्री तैयार कर सकते हैं, अपनी पसंद की आवाज में गीत तैयार कर सकते हैं, अपनी सुविधा से म्यूजिक बना सकते हैं... कोई कापीराइट का मामला नहीं। सब कुछ आपके हाथों क्रिएटेड, आपका अपना। प्रयोग धर्मी फिल्मकार प्रतीक शर्मा दो साल पहले 3.15 मिनट का एक वीडियो एआइ से तैयार किया था, जिसमें मनुष्य की भागीदारी सिर्फ गीत के बोल और परिकल्पना तक थी। बाकी सब के सब एआइ पर कमांड का कमाल है। मतलब गायिका की आवाज, संगीत कंपोजिशन, लोकेशन, अभिनेता सब कुछ। उस समय इंडस्ट्री के लिए यह थोड़ा चौंकाने वाला भी था और भयभीत करने वाला भी कि जब पूरी फिल्म ही मशीन पर बनने लगेगी फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे लाखों कलाकार स्टार से लेकर स्पाटबॉय तक आखिर क्या करेंगे। जब शुरुआत से अंत तक फिल्म एक लैपटॉप पर ही बन जानी है, फिर कोई शहर क्यों बसाए सिनेमा के लिए। प्रतीक वहीं नहीं रुके उन्होंने बाद में प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' पर एक खूबसूरत शार्ट फिल्म बनाकर एआइ की असीम संभावनाओं को भी रेखांकित किया। उस समय कतई यह अंदाजा नहीं था कि कुछेक दिनों बाद ही देश एआइ जनरेटेड फीचर फिल्म के लिए तैयार हो जाएगा, टेलीविजन पर एआइ जनरेटेड शो आने लगेंगे। लेकिन बीते कुछेक महीनों में यह सबकुछ संभव होता गया। भारत की पहली एआइ जनरेटेड फीचर फिल्म 'नाइसा' विवेक अंचलिया के निर्देशन में बनकर तैयार हो गई। मतलब आपको अपनी फिल्म के लिए स्टार चाहिए, लेकिन बजट इजाजत नहीं दे रहा तो एआइ की मदद से वैसा ही कुछ तैयार कर सकते हैं। जाहिर है धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जहां भव्य सेट और महंगे कॉस्ट्यूम की आवश्यकता होती है, एआइ किसी वरदान से कम नहीं। वास्तव में मौलिकता एआइ की सीमा है। आपके पास एक कहानी होनी चाहिए या फिर एक गीत, फिर एआइ उसे आपका मनचाहा आकार दे सकता है। जाहिर है, एक अर्थ में कहें तो युवा फिल्मकार जो अपने गांव में, अपनी जमीन पर रहकर अपनी कहानी परदे पर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए तो यह वरदान है। हालांकि एआइ की सहूलियतें हैं तो खतरे भी, खासकर सिनेमा जैसी रचनात्मक विधा में। एआइ से नायक-नायिका तो गढ़ लिए जाएंगे, लेकिन इमोशन देखने के आदि भारतीय दर्शक उन कृत्रिम चेहरों से कितना रिलेट कर पाएंगे, आने वाले दिन तय करेंगे।

सवाल यह भी है कि क्या जिस तरह हम मुकेश से लेकर अरिजीत सिंह की आवाज या अक्षय कुमार तक के चेहरे से हम एक इमोशन महसूस कर पाते हैं। दक्षिण में जिस तरह अपने सितारों के लिए प्रशंसक जान देने तक को आतुर हो जाते, वह अहसास एआइ जनित आवाज-चेहरे से कैसे आ सकता। जाहिर है भविष्य में एआइ का भी सिनेमा होगा, पर सिनेमा का भविष्य एआइ में नहीं हो सकता।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

विश्लेषण बीएनपी की वापसी से बदलेगी पूर्वी पड़ोसी की प्राथमिकताएं

ढाका का नया जनादेश, दिल्ली के लिए होगी नई चुनौती

डॉ. जे जगन्नाथन
एसो. प्रोफेसर, इंटरनेशनल स्टडीज स्कूल, जेएनयू
नई दिल्ली
@patrika.com

बांग्लादेश की जनता का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पक्ष में दिया गया प्रचंड जनादेश शेख हसीना काल के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब तारिक रहमान एक प्रमुख राजनेता के रूप में उभरे हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। बीएनपी की जीत भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना काल जैसे घनिष्ठ संबंधों के अंत का भी संकेत है। यह ध्यान रहे कि वहां जमात-ए-इस्लामी अब मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। भारत के प्रति बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही है। बीएनपी अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रवादी रुख अपनाती है, लेकिन भारत के साथ उसकी निकटता सीमित मानी जाती है। वैचारिक स्तर पर उसके संबंध इस्लामी राजनीतिक ताकतों से अधिक जुड़े रहे हैं।

शेख हसीना के कार्यकाल में भारत को खुफिया सहयोग, भारत-विरोधी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई और संपर्क व सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्ट समर्थन था। बीएनपी सरकार भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है, जिससे नई दिल्ली पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। भारत के लिए इसका अर्थ है कि पूर्वी पड़ोस में एक बेहद अनुकूल शासन अब नहीं रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सीमा पार सक्रिय नेटवर्क, तस्करी और अवैध प्रवास के कारण संवेदनशील क्षेत्र है। बीएनपी के सत्ता में आने के बाद सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। पिछले बीएनपी कार्यकाल में सीमा क्षेत्रों में कुछ इस्लामी कट्टरपंथी समूहों और भारतीय उग्रवादी संगठनों को पनाह मिली थी। आशंका है कि अब खुफिया सहयोग महज औपचारिक सूचना साझा करने तक सीमित रह जाए। रणनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा बदलाव चीन के बढ़ते प्रभाव के रूप में सामने आ सकता है। बीएनपी, अवामी लीग की तुलना में चीन के प्रति अधिक खुला रुख रखती है। इससे बंदरगाह, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में चीनी निवेश बढ़ सकता है। ढाका खुद को भारत और चीन के बीच संतुलन साधने वाले देश के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसका असर बंगाल की खाड़ी में सामरिक संतुलन और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पर पड़ सकता है। भारत के नजरिये से यह स्थिति कुछ हद तक श्रीलंका या नेपाल जैसी परिस्थिति पैदा कर सकती है, जहां चीन का प्रभाव समय-समय पर बढ़ता रहा है। भारत ने बांग्लादेश के साथ पूर्वोत्तर तक रेल-सड़क संपर्क, ऊर्जा व्यापार, बिजली ग्रिड और नदी परिवहन जैसी कई अहम योजनाएं शुरू की थीं। आशंका है कि बीएनपी सरकार इन परियोजनाओं की शर्तों की समीक्षा कर भारत-केंद्रित संपर्क को धीमा करे और चीनी निवेश को प्राथमिकता दे। इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए बांग्लादेश को प्रवेश-द्वार बनाने की भारत की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

बीएनपी की जीत भारत के लिए आपदा नहीं, पर सामरिक तौर पर एक गिरावट अवश्य है। इससे घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग और राजनीतिक पूर्वानुमेयता कम हो सकती है और पूर्वी पड़ोस अधिक अनिश्चित व प्रतिस्पर्धी बन सकता है। भारत-बांग्लादेश संबंध अब अधिक लेन-देन आधारित हो सकते हैं। नई दिल्ली को वैचारिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आर्थिक प्रोत्साहन, ठोस परियोजनाओं और जन-स्तर के संपर्क पर जोर देना चाहिए।

वियतनाम के खेतों में सूखती रंगों की फसल

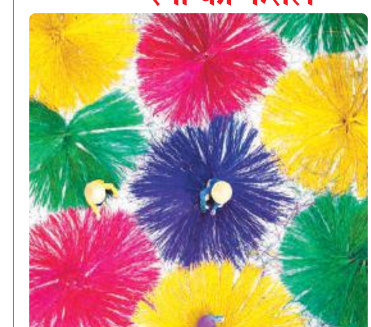

***वियतनाम** के फू येन प्रांत के ग्रामीण इलाकों में यह दृश्य रंगों और परंपरा का संगम है। यहां गांववासी रंगे हुए सेज घास के रेशों को खुले मैदानों में सावधानी से फैलाकर सुखाते हैं, ताकि उनसे पारंपरिक चटाइयां बुनी जा सकें। जब सेज की कटाई कर उसे पीले, लाल, हरे और बैंगनी जैसे चमकीले रंगों में रंगा जाता है। ये रेशे रंगीन कालीन या आतिशबाजी जैसे दृश्य का आभास कराते हैं।*

आपकी बात

यातायात नियमों का पालन जरूरी

अक्सर देखा जाता है कि जब पुलिस हेलमेट या वाहन चेकिंग अभियान चलाती है, तब लोग नियमों का पालन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अभियान खत्म होता है, लापरवाही फिर से शुरू हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि लोग नियमों का पालन डर से नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए करें। सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं। **- चंपालाल दुबे,** भोपाल

भ्रष्टाचार से बिगड़ते सड़कों के हाल

सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकारें हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट तय करती हैं। कागजों में सड़कों को दुरुस्त दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में कई जगह कुछ ही समय बाद सड़कें धंस जाती हैं। अक्सर निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं। यदि सख्त कार्रवाई हो, तो हालात सुधर सकते हैं। **- गोपाल अरोड़ा,** जोधपुर

स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करें

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम और जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच यह है कि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन की आधारशिला है। रोजाना कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना बेहद जरूरी है। नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान भी अहम है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन की हर उपलब्धि सार्थक लगेगी। **- निर्मला वशिष्ठ,** अलवर

आज का सवाल

सड़क किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

मानसिक संकट जब किसी को मृत्यु जीवन से आसान लगने लगे, तो यह संकेत है कि सहारा, संवाद और संवेदना की आवश्यकता है

आत्महत्याओं को रोकने के लिए कारगर तंत्र बनाने की जरूरत

कृष्ण प्रताप सिंह
स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

आत्महत्या आज के समय में एक गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। तेजी से बदलती जीवनशैली, प्रतिस्पर्धा का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं कई बार व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती हैं। यहीं नहीं, अब सामूहिक आत्महत्या के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।

पिछले दिनों मथुरा के एक गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की खबर ने विचलित कर दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में हर चार मिनट से भी कम में अपनी जिंदगी या जीवन स्थितियों से हताश-निराश कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दिहाड़ी मजदूरों और किसानों की आत्महत्याएं समस्या का दूसरा ही पहलू सामने लाती हैं। मनोवैज्ञानिकों की मानें तो मनोविकारों या मनोरोगों से पीड़ित और अवसादग्रस्तों को छोड़ दें तो कोई भी व्यक्ति यों ही अपने जीवन का अंत नहीं करता। वह तब तक अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है, जब तक उसे लगता है कि उसके सामने उपस्थित रात की कोई न कोई सुबह जरूर है। उसका यह विश्वास बनाए रखने में आसपास के परिवेश, परिजनों और प्रियजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब वे यह भूमिका नहीं निभा पाते और संबंधित व्यक्ति इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि अब उसकी कोई सुबह नहीं बची, तभी वह आत्महत्या के फैसले तक पहुंचता है।

हम जिस सामाजिक ताने-बाने में रह रहे हैं, उसमें हत्याएं, (जो आत्महत्याओं की अपेक्षा बहुत कम होती हैं) रोकने या अपराधियों को दंड दिलाने के लिए तो कई कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जेल व न्यायालय हैं, लेकिन आत्महत्याओं के विरुद्ध कोई कारगर तंत्र बनाने पर विचार तक नहीं किया जाता। बस, साल में एक दिन आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाकर कर्तव्य समाप्त मान लिया जाता है। मानसिक अवसाद आत्महत्याओं का सबसे बड़ा कारक है। अभी तक उन समूहों को ठीक से चिह्नित करने का काम भी पूरा नहीं हुआ है, जिनमें आत्महत्या की दर या आशंकाएं अधिक देखी गई है।

परीक्षाओं में विफल छात्र, पारिवारिक तनाव से जूझते पुरुष-महिलाएं, जटिल परिस्थितियों में तनाव के बीच काम करने वाले सैन्य व अर्धसैनिक बलों के जवान और थोड़े से वेतन में जिंदगी को जैसे-तैसे घसीटते रहने को अभिशप्त लोगों की संख्या आत्महत्या करने वालों में अधिक है। आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वालों में 67 प्रतिशत लोग 18 से 45 साल की उम्र के बीच के होते हैं और उनमें पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी कम नहीं होती। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से हेल्पलाइन नंबर एवं जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद गांवों-कस्बों और दूरदराज के क्षेत्रों के साथ महानगरों तक में हालात चिंताजनक हैं।

आत्महत्या एक गहरे टूटे हुए मन की पुकार है। जब हमारे बीच कोई किसान, बेरोजगार, महिला, पुरुष, वयस्क या अवयस्क इस हद तक निराश हो जाता है कि उसे जीवन से अधिक मृत्यु आसान लगने लगे, तो यह संकेत है कि उसे सहारा, संवाद और संवेदना की जरूरत है। यह केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अकेलेपन को पनपने न दे। बढ़ती घटनाएं हमें चेतावनी ही नहीं, समय रहते मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने का, सहयोग की संस्कृति बनाने का और ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करने का अवसर भी देती हैं, जहां हर व्यक्ति खुद को सुने और समर्थित महसूस करे। हम मिलकर संवेदनशील, सहायक और जागरूक समाज का निर्माण करें।

दाढ़ी पर नहीं, सोच पर बहस जरूरी

संपादकीय

नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी

स्त्री की गरिमा और उसका सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रहे हैं। हमारे यहां नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है तथा शास्त्रों में कहा गया है-'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' यहां पाठकों को बताता चलूं कि यह प्रसिद्ध संस्कृत वचन 'मनुस्मृति' से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जहां नारी का सम्मान और आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में, यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दशार्ता है। नारी को शक्ति, करुणा, त्याग और सृजन की प्रतीक माना गया है।सच तो यह है कि परिवार और समाज की असली आधारशिला नारी ही होती है और जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा मिलती है, वह समाज और देश प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत, जहां नारी का अपमान होता है, वहां अशांति और पतन का वातावरण बनता है। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अहिल्याबाई होल्कर जैसी महान महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार और समाज के निर्माण में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है; वह मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन को संवेदना, संतुलन और संस्कार प्रदान करती है। आज के आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री का सम्मान केवल परंपरा या शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में उन्नत और सभ्य बन सकेगा। बहरहाल, स्त्रियों की गरिमा व सम्मान के क्रम में हाल ही में जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। जब कुछ लोग वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि जैस्मीन सैंडलस एक प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी पंजाबी गायिका और गीतकार हैं, जिन्होंने अपने अलग अंदाज और दमदार आवाज से संगीत जगत में खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 4 सितंबर 1985 को पंजाब के जालंधर में हुआ और बाद में वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में पली-बढ़ीं। उन्होंने 2007 में अपने करियर की शुरूआत की और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हुईं। बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म 'किक' के गीत 'यार ना मिले' से मिली। उनके गानों में पॉप, आर एंड बी और पंजाबी फोक का मिश्रण देखने को मिलता है।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

डॉ. सत्यवान सौरभ

> "ईश्वर, संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा में भी संतुलन आवश्यक है। हमारी परंपराएँ अत्यंत विविध रही हैं। कहीं जटाधारी तपस्वी हैं, तो कहीं सुसज्जित देव-प्रतिमाएँ; कहीं वैराग्य है, तो कहीं श्रृंगार। सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आचरण, करुणा, संयम और विवेक है। यदि हम सौंदर्य को केवल चेहरे, दाढ़ी या फैशन तक सीमित कर दें, तो हम अपनी ही सांस्कृतिक गहराई को कम कर देते हैं।"

हर दौर की अपनी पहचान होती है। यह पहचान केवल कपड़ों, हेयर-स्टाइल या चेहरे पर उगे बालों से नहीं बनती, बल्कि उस सोच से बनती है जो व्यक्ति और समाज–दोनों को दिशा देती है। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे कैसे दिखते हैं यह कम, और क्या सोचते हैं तथा किसका अनुकरण करते हैं–यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बाहरी आकर्षण, सोशल मीडिया की चमक और तात्कालिक लोकप्रियता ने पहचान की परिभाषा को सतही बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में दाढ़ी को लेकर एक तीखी बहस उभरी है। कुछ लोग इसे आधुनिक फैशन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक भ्रम और अंधानुकरण का उदाहरण। यह बहस तब और जटिल हो जाती है जब इसे धर्म, राजनीति या साज़िश से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर, शोर से दूर रहकर, विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टि से इस विषय को देखें। क्योंकि जब मुद्दे विचार के बजाय पहचान की लड़ाई बन जाते हैं, तब समाधान नहीं, विभाजन पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि दाढ़ी और क्लीन शेव–दोनों ही भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। वैदिक काल के ऋषि-मुनि जटाधारी थे, तो राजदरबारों में सुसज्जित, साफ-सुथरे व्यक्तित्व भी दिखाई देते थे। मध्यकाल हो या आधुनिक काल–हर युग में दोनों प्रकार के रूप साथ-साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरू–सभी का रूप अलग था, पर उद्देश्य एक। स्पष्ट है कि दाढ़ी कोई नई या बाहरी चीज नहीं है, और न ही क्लीन शेव कोई विदेशी अवधारणा। दोनों ही समय, परिस्थिति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बदलते रहे हैं।आज दाढ़ी का चलन केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक फैशन का हिस्सा बन चुका है। हॉलीवुड, यूरोपीय फैशन,

खेल जगत, संगीत उद्योग और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स–हर जगह दाढ़ी अलग-अलग शैलियों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इन रुझानों को और तेज कर दिया है। एक तस्वीर, एक वीडियो या एक रील के जरिये ट्रेंड पल भर में दुनिया भर में फैल जाते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि कोई एक उद्योग, समूह या विचारधारा ही किसी फैशन को ह्लफैलाह्व रही है, वास्तविकता का सरलीकरण होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अंधानुकरण एक गंभीर समस्या बन चुका है। जब युवा किसी भी ट्रेंड को बिना सोचे-समझे केवल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय है या ह्लकूलह्व माना जा रहा है, तब उनका व्यक्तित्व उधार का हो जाता है। फैशन तब समस्या बनता है जब वह सोच पर हावी हो जाए और पहचान को केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित कर दे। सवाल दाढ़ी रखने या न रखने का नहीं है; सवाल यह है कि क्या हम अपने चुनाव के कारण जानते हैं, या सिर्फ. भीड़ के साथ चल रहे हैं?

इस संदर्भ में सिनेमा और डिजिटल मीडिया की भूमिका पर चर्चा जरूरी है। मनोरंजन उद्योग न केवल कहानियाँ सुनाता है, बल्कि जीवन-शैली के मानक भी गढ़ता है। बार-बार एक ही तरह के ह्लुकह्व, ह्लस्टाइलह्व और ह्लहीरोइज्मह्व को आदर्श बनाकर प्रस्तुत करने से युवाओं के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। इससे विविधता कम होती है और एकरूपता बढ़ती है। जिम्मेदार मीडिया वही है जो समाज की बहुलता को दिखाए–जहाँ सादगी भी आकर्षक हो, और अलग-अलग व्यक्तित्व भी स्वीकार्य हों। लेकिन दर्शक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दिखावे और मूल्य में अंतर करना सीखें।

ईश्वर, संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा में भी संतुलन आवश्यक है। हमारी परंपराएँ अत्यंत विविध रही हैं। कहीं जटाधारी तपस्वी हैं, तो कहीं सुसज्जित देव-प्रतिमाएँ; कहीं वैराग्य है, तो कहीं श्रृंगार। सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आचरण, करुणा, संयम और विवेक है। यदि हम सौंदर्य को केवल चेहरे, दाढ़ी या फैशन तक सीमित कर दें, तो हम अपनी ही सांस्कृतिक गहराई को कम कर देते हैं।

आज के युवाओं के सामने असली खतरा किसी एक फैशन से नहीं, बल्कि आत्मबोध की कमी से है। जब युवा अपने इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक बहुलता को समझते हैं, तब वे किसी भी ट्रेंड को अपनाएँ–या न अपनाएँ–वह उनका सजग और स्वतंत्र निर्णय होता है। लेकिन जब पहचान केवल बाहरी प्रतीकों पर टिक जाती है, तब भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता है। समाधान डर, आरोप या साज़िश की भाषा में नहीं है। समाधान शिक्षा, संवाद और आत्मविश्वास में है। युवाओं को यह समझाना जरूरी है कि फैशन क्षणिक होता है, लेकिन चरित्र स्थायी। आज जो ट्रेंड है, कल बदल जाएगा; पर जो मूल्य आप अपनाते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए चयन सोच-समझकर होना चाहिए–न दबाव में, न डर में, और न ही अंधानुकरण में। समाज को विभाजन की भाषा से भी सावधान रहना चाहिए। जब हम किसी चलन को डर या साज़िश के चश्मे से देखते हैं, तो संवाद बंद हो जाता है और ध्रुवीकरण बढ़ता है। इसके विपरीत, जब हम प्रश्न पूछते हैं–ह्लक्यों?ह्व, ह्लकैसे?ह्व और ह्लकिस हद तक?ह्व–तब समझ विकसित होती है। स्वस्थ समाज वही है जो असहमति को जगह देता है, लेकिन सम्मान और तथ्य के साथ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम युवाओं को आलोचनात्मक सोच सिखाएँ–ताकि वे हर ट्रेंड को आँख बंद करके न अपनाएँ। उन्हें अपने शरीर, समय और पहचान पर अधिकार का बोध हो। फैशन अपनाना गलत नहीं; गलत है फैशन के पीछे खुद को खो देना। व्यक्तित्व की असली सुंदरता बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और विवेक में होती है।

अंततः, यह बहस दाढ़ी की नहीं, दिशा की है। हम अपनी पहचान किस पर बना रहे हैं–दिखावे पर या विचार पर? यदि हम युवाओं को शिक्षा, अवसर और आत्मसम्मान देंगे, तो वे किसी भी फैशन में सुरक्षित रहेंगे–क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होंगी। समाज का भविष्य बाहरी रूपों से नहीं, सोच की मजबूती से तय होता है। और वही सोच हमें यह सिखाती है कि ट्रेंड आते-जाते रहते हैं, लेकिन मूल्य वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं।

(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)

आज भी प्रासंगिक हैं महर्षि दयानंद

(डॉ. सुधाकर आशावादी)

समाज में भिन्न भिन्न प्रकार से जातीय विभेद उत्पन्न किये जाने से उपजी समस्याओं का एकमात्र निदान युगपुरुष महर्षि दयानन्द की शिक्षाएं हैं, जिनका अनुपालन करके व्यक्ति 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित दुःख भाग्भवेत' की भावना से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जिस तार्किक आधार पर मानव मात्र की भलाई के लिए आर्यसमाज की स्थापना की, उस आधार पर देश में जातीय संकीर्णता को समाप्त कर कल्याणकारी समाज की रचना की जा सकती है। सर्व विदित है कि भारतीय समाज में विघटन व बिखराव का एक बड़ा कारण अन्धविश्वास एवं पाखंड है। धार्मिक आडंबर एवं पाखंड के चलते आम आदमी तर्क की कसौटी पर सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं को परख नहीं पाता तथा किसी व्यक्ति या विचार का अंधानुकरण करने लगता है।

उसकी स्थिति उस अंध भेड़ जैसी होती है, जिसे केवल भीड़ का हिस्सा बने रहने में संतुष्टि मिलती है। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद की शिक्षाएं ही देश को सही दिशा प्रदान कर सकती है।

गुजरात के टंकारा गांव में जन्मे बालक मूल शंकर के महर्षि दयानंद बनने का सफर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि पर्व की उस रात्रि से प्रारंभ हुआ, जब अपने पिता की आज्ञा से बालक मूल शंकर ने व्रत रखकर गाँव के शिवालय में रात्रि जागरण किया। मन में श्रद्धा भाव लिए वह भगवान शिव के ध्यान में मग्न थे, कि उन्होंने देखा कि एक मूषक शिव की पिंडी पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहा है। मूल शंकर के मन में प्रश्न उपजा कि जो शिव चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते , वह भला सच्चे शिव कैसे हो सकते हैं। मूल शंकर ने तभी सच्चे शिव की खोज का प्रण लिया तथा सत्य की खोज में निकल पड़े। तदुपरांत उन्हें मथुरा में जन्मांध गुरु विरजानंद जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, जिन्होंने उन्हें वेदों व संस्कृत का ज्ञान दिया तथा समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।

वेदों के प्रचार और समाज सुधार के उद्देश्य से 10 अप्रैल 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में वर्ष 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया तथा देश भर में आर्य समाज का विस्तार हुआ। मानव कल्याण के उद्देश्य से तर्कसंगत जीवन शैली अपनाने के लिए आर्य समाज ने दस नियम बनाए, जिसमें पहला नियम था - सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदिमूल परमेश्वर है। संसार को चलाने वाली परम शक्ति की अवधारणा में दूसरा नियम है - ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवार्धार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तयार्मी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है।

विचार

बांग्लादेश में सत्ता का पुनसंयीजनः भारत के लिए अवसर-

प्रो. आरके जैन अरिजीत

बांग्लादेश में हालिया चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की स्पष्ट और सशक्त अभिव्यक्ति बनकर सामने आया है। 12 फरवरी 2026 को हुए इस ऐतिहासिक मतदान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 क्षेत्रों वाले चुनाव में 209-212 सीटें जीतकर निर्णायक बहुमत हासिल किया। यह परिणाम वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक असंतोष, प्रशासनिक कमजोरियों और लोकतांत्रिक अपेक्षाओं का स्वाभाविक नतीजा है। इस जनादेश ने बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दी है और क्षेत्रीय संतुलन पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारत के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पड़ोसी देश की स्थिरता, नीतियाँ और नेतृत्व सीधे उसकी सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हितों से जुड़े हुए हैं। यह चुनाव केवल सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की आधारशिला रखने वाला महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है।

इस परिवर्तन की धुरी में तारीक रहमान का नेतृत्व सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता दिखाई देता है। सत्रह वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद उनकी स्वदेश वापसी और फिर दो सीटों से निर्णायक जीत, बांग्लादेशी राजनीति में दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। उन्होंने स्वयं को केवल एक राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और प्रतिरोध से तपकर निकले नेता के रूप में स्थापित किया है। उनका चुनावी अभियान सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने जनता के मन में यह विश्वास जगाया कि व्यवस्था को बदला जा सकता है और शासन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। भारत के लिए यह तथ्य विशेष महत्त्व रखता है कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार विस्तार और स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि यह दृष्टिकोण ठोस नीतियों में बदलता है, तो भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊर्जा और मजबूती मिल सकती है।

इस राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि वर्ष 2024 के छात्र आंदोलनों में गहराई से जुड़ी हुई है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को जड़ से हिला दिया था। उनका सत्ता से हटना केवल एक सरकार का अंत नहीं, बल्कि केंद्रीकृत शासन, कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के विरुद्ध जनता के व्यापक असंतोष की खुली अभिव्यक्ति था। इसके बाद गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व मुहम्मद यूनुस ने किया, जिन्होंने सीमित समय और दबावपूर्ण परिस्थितियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया। इस संक्रमणकाल में भारत ने संयम, संतुलन और संवाद की नीति अपनाई, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता को फैलने से रोका जा सका। यह भारत की परिपक्व और जिम्मेदार कूटनीति का स्पष्ट उदाहरण माना जाता है।

बीएनपी की इस ऐतिहासिक विजय का सबसे मजबूत आधार जनता का गहरा और व्यापक असंतोष रहा है। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन ने आम नागरिक के धैर्य की सीमा को तोड़ दिया था। बीएनपी ने ह्लोकतंत्र की बहालीह्व और ह्लनया बांग्लादेशह्व जैसे प्रभावशाली नारों के माध्यम से इस असंतोष को संगठित राजनीतिक चेतना में परिवर्तित किया। इसके विपरीत, जमात-ए-इस्लामी गठबंधन अपेक्षित जनसमर्थन हासिल करने में असफल रहा। भारत के दृष्टिकोण से यह स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कट्टरपंथी शक्तियों को सीमित समर्थन मिलना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है।

इससे सीमा पार उग्रवाद और अस्थिरता की आशंकाएं फिलहाल कम होती हुई दिखाई देती हैं।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और आर्थिक सहयोग की गहरी नींव पर टिके हुए हैं। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, व्यापारिक मार्गों का विस्तृत जाल और पीढ़ियों से जुड़े सामाजिक संबंध दोनों देशों को स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों की जीवनरेखा, समुद्री संपर्क का प्रमुख द्वार और क्षेत्रीय व्यापार का अहम सेतु है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआईः DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।
संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)
'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना
पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यंग्य

वैलेंटाइनः प्रदर्शन बनाम आत्मिक संवेदना

लेखकःप्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश

वर्तमान समय में वैलेंटाइन दिवस भारतीय समाज में केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विमर्श और विवाद का एक द्वंद्व बन चुका है। प्रतिवर्ष फरवरी के इस पखवाड़े में प्रेम की चर्चा जितनी तीव्र होती है, उसका विरोध भी उतना ही मुखर होता है। किंतु इस शोर के बीच हम अक्सर उस मूल प्रश्न को भूल जाते हैं कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या यह केवल सार्वजनिक प्रदर्शन और उपहारों के आदान-प्रदान तक सीमित है, अथवा यह एक गहरी आत्मिक संवेदना है जिसे आज के बाजारवाद ने जकड़ लिया है?

?भाषाई दृष्टि से देखें तो 'वैलेंटाइन' शब्द लैटिन के 'वेलनटिनस' से उपजा है, जिसका अर्थ है-शक्तिशाली, साहसी और दृढ़ हृदय वाला। यह परिभाषा प्रेम के उस प्रचलित स्वरूप को चुनौती देती है जिसे हम आज केवल कोमल भावनाओं या क्षणिक आकर्षण के रूप में देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से संत वैलेंटाइन ने दमनकारी सत्ता के विरुद्ध खड़े होकर मानवीय संबंधों की गरिमा की रक्षा की थी।

अतः वैलेंटाइन का मूल भाव दुर्बल भावुकता नहीं, बल्कि वह आत्मिक शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस प्रदान करती है।

आज वैलेंटाइन का अर्थ बदलकर गुलाब, महँगे उपहार और सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक स्थानों पर किए जाने वाले प्रदर्शन तक सिमट गया है। बाजार ने इस मानवीय संवेदना को एक 'उत्पाद' में बदल दिया है। जब प्रेम का पैमाना 'उपभोग' बन जाता है, तब उसकी पवित्रता का क्षरण निश्चित है। आज की युवा पीढ़ी जिसे प्रेम समझ रही है, वह अक्सर केवल बाह्य आकर्षण और सार्वजनिक प्रदर्शन की होड़ है। यही वह बिंदु है जहाँ सांस्कृतिक विरोध के स्वर जन्म लेते हैं। विरोध प्रेम का नहीं, बल्कि उसके उस विकृत और बाजारी स्वरूप का है जो मयार्दाओं की सीमा लांघता प्रतीत होता है।

भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में प्रेम कोई नई या आयातित अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम को 'काम' से ऊपर उठाकर 'राम' तक ले जाने की परंपरा रही है। जहाँ पश्चिमी बाजारवाद प्रेम को 'अधिकार' की तरह देखता है, वहीं भारतीय मनीषा इसे 'कर्तव्य' और 'त्याग' के रूप में परिभाषित करती है।

अखिलेश बढ़ाएंगे पीडीए का दायरा

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति को और मजबूत करने में जुटे हैं। पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक, जो कभी मुलायम सिंह यादव का सबसे मजबूत किला था, हाल के उपचुनावों में कमजोर पड़ा दिखा, जिसके बाद अखिलेश ने खुलकर मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने वाली राजनीति शुरू कर दी है। 2024 के उपचुनावों में मुस्लिम बहुल सीटों पर मिली हार ने सपा को झकझोर दिया, जहां ओवैसी की एआईएमआईएम और कांग्रेस जैसे दल मुस्लिम वोटों में सेंध लगा रहे हैं। अखिलेश ने इसके जवाब में दूसरी पीढ़ी के युवा मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने का मेगा प्लान बनाया है। सलीम इकबाल शेरवानी को पश्चिमी यूपी और अताउर्रहमान को पूर्वांचल व रुहेलखंड में मुस्लिम मिशन की कमान सौंपी गई है, जो समाजवादी सद्भावना संवाद जैसे कार्यक्रमों के जरिए समुदाय से सीधा संवाद कर रहे हैं। रामपुर में आजम खान के परिवार से हालिया मुलाकात इसका जीता-जागता प्रमाण है, जहां अखिलेश ने मुस्लिम मतदाताओं की सियासी ताकत को फिर से एकजुट करने का संकल्प जताया।

सपा अब केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी की नजरें पीडीए समीकरण को व्यापक बनाने पर हैं, जिसमें यादव के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां जैसे कुर्मी, मौर्य, जाट, गुर्जर, केवट, मल्लाह, राइथ, कोइरी, निषाद, बिंद, कश्यप और गहमरी जैसी जातियों पर केंद्रित हैं। दलित समाज में जाटव, पासी, रविदास, धोबी, कोरी, वाल्मीकि और अन्य उपजातियों को लुभाने के लिए छोटे-मझोले नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ओबीसी वोटों को मजबूत करने के लिए सपा ने संगठन में बड़े बदलाव शुरू किए हैं, जहां निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय कार्यकताओं को बूथ स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। अखिलेश का फोकस 360 से अधिक सीटें जीतने पर है, इसलिए टिकट वितरण में पीडीए समीकरण को प्राथमिकता मिलेगी।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी
संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

मनमोहन सिंह की याद में !

पूरे देश की राजनीति में संसद से लेकर सड़क तक विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों को लेकर जब एक ओर कोहराम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ से ऐसी खबर आयी है जिससे अशान्त चित्त को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। यह खबर है कि आगामी 26 फरवरी को स्वर्गीय प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की याद में आयोजित प्रथम व्याख्यानमाला में जर्मनी की पूर्व चांसलर श्रीमती एंजेला मर्केल भाषण देंगी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत-जर्मनी सम्बन्धों पर प्रकाश डालेंगी। डॉ. मनमोहन सिंह को देश की जनता बहुत कम बोलने वाले प्रधानमन्त्रियों में से एक के रूप में देखती है मगर उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को आमूलचूल रूप से बदलने वाला प्रधानमन्त्री भी मानती है। दरअसल मनमोहन सिंह ने 1991 से जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया था और भारत के बाजारों को विदेशी कम्पनियों के लिए खोला था उसी का परिणाम है कि आज हम बाजारमूलक अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं और इससे भारत की राजनीति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी है।

वास्तव में मनमोहन सिंह ने जब 1991 में देश का वित्त मन्त्री रहते भारत के बाजारों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोला था तो इसके लाभ व खतरे भी एक समानरूप से थे क्योंकि उस समय भारत ने नेहरू-इन्दिरा गांधी की समाजवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धान्तों को अलविदा कह दिया था और 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ के आर्थिक सिद्धान्त पर अमल करना शुरू किया था। आजादी के बाद पं. नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जिसमें निजी क्षेत्र व राज्य की भागीदारी इस प्रकार स्थापित की गई थी कि समाज व देश का विकास राष्ट्रीय विकास स्रोतों पर राज्य के मालिकाना हकूकों को ऊंचे रखकर हो सके। जबकि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मानते थे कि व्यापार व कारोबार से सरकार को अलग रहते हुए यह कार्य निजी क्षेत्र पर छोड़ना चाहिए और भारत को अपना समग्र विकास बाजार की शक्तियों को साधते हुए करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने वास्तव में यही रास्ता अपनाया था जिसके कारण भारत में प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी निवेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। मनमोहन सिंह ने इस काम को बहुत सिलसिलेवार ढंग से किया और सुनिश्चित किया कि भारत अपने आधारभूत विकास के ढांचे में निजी क्षेत्र को अधिकाधिक स्थान दे। उनके शासनकाल में पूंजी की महत्ता बढ़ी और विकास का वह मॉडल तैयार हुआ जिसने वित्तीय क्षेत्र से लेकर बुनियादी क्षेत्र तक में निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत पारंपरिक रूप से बचत की अर्थव्यवस्था के बजाय खर्च की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने लगा जिसमें नये उपभोक्तावाद का उदय होना निश्चित था। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नवोदित आर्थिक भूमंडलीकरण से जोड़ा जिससे भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक बहुत बड़ा बाजार बनकर उभरा। व्यापार व कारोबार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध विश्व व्यापार संगठन के छाते तले टूटने लगे और अधिकाधिक देश एक -दूसरे के यहां उपलब्ध आवश्यक आय स्रोतों का लाभ उठाने लगे। मगर इसका असर राजनीति पर पड़े बगैर नहीं रह सकता था। खासकर लोकतान्त्रिक देशों में चुनावों के माध्यम से बनने वाली सरकारों के गठन में पूंजी का महत्व बढ़ने लगा।

इस पूंजी को प्रभावित करने के लिए विदेशी कम्पनियों की भूमिका भी धीरे-धीरे बढ़ती रही और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार भी बढ़ता रहा। बाजार की शक्तियां श्रम का मूल्य निर्धारण करने लगीं मगर इसके असर से भारत जैसे देशों में औद्योगीकरण तेज हुआ, बदलती बाजार जरूरतों के अनुसार इसमें नवाचार भी हुआ। बाजार की शक्तियों ने प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने का कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता की वजह से किया। मगर इस आर्थिक उदारीकरण से भारत की विदेश नीति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती थी।

इस पूंजी को प्रभावित करने के लिए विदेशी कम्पनियों की भूमिका भी धीरे-धीरे बढ़ती रही और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार भी बढ़ता रहा। बाजार की शक्तियां श्रम का मूल्य निर्धारण करने लगीं मगर इसके असर से भारत जैसे देशों में औद्योगीकरण तेज हुआ, बदलती बाजार जरूरतों के अनुसार इसमें नवाचार भी हुआ। बाजार की शक्तियों ने प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने का कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता की वजह से किया। मगर इस आर्थिक उदारीकरण से भारत की विदेश नीति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती थी। अत: मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही भारत पर अमेरिका की तरफ से यह दबाव बनने लगा था कि वह ईरान से पेट्रोलियम तेल न खरीदे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रसंघ में भारत को कई बार ऐसा रुख अख्तियार करना पड़ा जिनसे दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था लेकिन मनमोहन सिंह ने 1990 में ही सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद रक्षा से लेकर उच्च टैक्नोलॉजी के क्षेत्र तक में भारत की वरीयता तय करने की गरज से अमेरिका से 2008 में परमाणु समझौता किया और बिना परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर किये ही भारत को विश्व को छठी वैध परमाणु शक्ति बनाया तथा अद्यतन टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। यदि हम गौर से 2008 के वर्ष की राजनीति पर ध्यान दें तो उस समय भी संसद से लेकर सड़क तक परमाणु करार को लेकर कोहराम मचा हुआ था और इस मुद्दे पर मनमोहन सरकार तक खतरे में आ गई थी। उनकी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने अपना हाथ खींच लिया था। यह परमाणु करार कोई सामान्य आपसी समझौता नहीं था क्योंकि इसे करने के लिए अमेरिका को भी अपने संविधान में संशोधन करना था। डॉ. मनमोहन सिंह ने इस समझौते की बागडोर तब अपने विदेशमन्त्री भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी को पकड़ा दी थी। तब प्रणव दा अमेरिका जाकर ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश से मिलकर साफ कर आये थे कि भारत समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकता जब तक कि इसकी संसद उसे इजाजत न दे दे। संसद में लोकसभा में मनमोहन सरकार वामपंथियों के समर्थन वापस लेने से अपना बहुमत लगभग खो चुकी थी मगर मनमोहन सिंह को विश्वास था कि ऐतिहासिक परमाणु करार के राष्ट्रहित में होने की वजह लोकसभा में उनकी सरकार को विश्वास मत मिल जायेगा जिसकी वजह से जुलाई 2008 में उन्होंने लोकसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया और अपनी सरकार के प्रति विश्वास मत रखा। अत: डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल का यह दौर बहुत राजनीतिक उथल-पुथल वाला रहा। आज देश में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष इस समझौते की भारी आलोचना कर रहा है। जबकि अभी इस समझौते का विस्तृत ब्यौरा बन ही रहा है। सौभाग्य से संसद बजट सत्र चालू है केवल इसका प्रथम चरण ही आज समाप्त हुआ है। मार्च महीने में दूसरा चरण फिर से शुरू होगा। अत: हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करेंगे वह भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए ही करेंगे।

हरियाली की सांसों को...

गीता पाढा

"अरावली पर्वतमाला पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहेदिल से आभार हैं,
पर्यावरणविदों के लिए यह लेकर आया शुभ समाचार है,,
हरियाली की सांसों को फिर से जीने का मिला अधिकार है,
प्रकृति की रक्षा में यह निर्णय एक मजबूत दीवार है...।।"

संसदीय राजनीति में बढ़ती कर्कश भाषा

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

भारत की संसद में ऐसे अवसर भी आ चुके हैं जब पूरे के पूरे सत्र शोर- शराबे में ही बेकार जाते रहे हैं। ऐसे मौके बोफोर्स कांड से लेकर 2-जी घोटाले तक कई बार आए, मगर ऐसे अवसर भी कम नहीं आये जब संसद के सदस्यों ने अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में दोनों सदनों में रचनात्मक बहस की और देश को आगे बढ़ाने में अपने कीमती सुझाव रखे। बेशक संसद के चालू बजट सत्र के प्रथम चरण का अवसान हो गया है, मगर उम्मीद की जा रही है कि आगामी 9 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण में जब वित्त विधेयक पारित होगा तो संसद गंभीरता का परिचय देते हुए राष्ट्र के समक्ष ज्वलन्त समस्याओं का हल ढूंढेगी और लोगों को आश्वस्त करेगी कि उसके चुने हुए प्रतिनिधी अपने उस दायित्व से बेखबर नहीं हैं जो जनता ने उन्हें सौंपा है। समाप्त हुए पहले चरण को संभवत: इसलिए याद किया जायेगा कि इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हो सकी और हद यह हो गई कि न तो विपक्ष के नेता ही बोल पाये और न ही प्रधानमन्त्री अत: प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से ही पारित कर दिया गया। संसद का जब भी नये साल का बजट सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा व लोकसभा सदस्यों की संयुक्त बैठक बुला कर उसे सम्बोधित करते हैं और देश को सत्तारूढ़ दल की सरकार की नीतियों व कार्यों से अवगत कराते हैं। राष्ट्रपति हमारी संसद का ही अंग होते हैं क्योंकि उन्हीं के आदेश से संसद का कोई सत्र बुलाया जाता है और उन्हीं के निर्देश पर इसका सत्रावसान होता है। बेशक उनके पास सरकार चलाने के कार्यकारी अधिकार नहीं होते मगर वह ही सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। लोकसभा में बहुमत के आधार पर चुनी गई किसी भी राजनीतिक दल की सरकार उनकी ही अपनी सरकार होती है जो उनके नाम पर देश का शासन चलाती है। भारत में राष्ट्रपति के पद का भी हर पांच साल बाद चुनाव होता है। चुनाव संसद व विधानमंडलों के सदस्य करते हैं जिनका चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किया जाता है अत: भारत के राष्ट्रपति भी जनता के नुमाइन्दे ही होते हैं इसलिए जब वह साल में एक बार संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हैं तो संसद उनका धन्यवाद ज्ञापन करती है। एक मायनों में यह भारत के लोकतन्त्र के असली मालिक मतदाताओं के प्रति ही धन्यवाद होता है जिसकी वजह से संसद में यह परंपरा डाली गई कि अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो, क्योंकि भारत के मतदाता ही सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष में बैठे सभी सांसदों का चुनाव करते हैं। यह भारत के जीवन्त लोकतन्त्र की परंपरा है जो यह सचेत करती है कि सत्ता में बैठाई गई पार्टी की जवाबदेही सीधे मतदाताओं के प्रति होती है, लेकिन इस बार लोकसभा में जो हुआ उसे भविष्य में कभी भी न दोहराने की कसम भी सांसदों को उठानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत का संसदीय लोकतन्त्र बेदाग रहते हुए चलता रहे, लेकिन लोकसभा के इसी सत्र में इसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला के विरुद्ध उन्हें पद से हटाये जाने का प्रस्ताव भी लाया गया। इसमें कोई पुरानी परंपरा नहीं टूटी है, क्योंकि पूर्व में भी तत्कालीन अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं हालांकि तीनों ही बार ये प्रस्ताव गिर भी गये। आगामी 9 मार्च को जब श्री बिरला के खिलाफ प्रस्ताव आयेगा तो उसका गिरना भी सुनिश्चित है क्योंकि सदन में सत्तारूढ़ दल भाजपा व उसके सहयोगी दलों का पूर्ण बहुमत है अत: विरोध सांकेतिक ही माना जायेगा, मगर संसदीय प्रणाली में इसके नैतिक संकेत काफी गंभीर होंगे। यह नैतिक संकेत यह होगा कि लोकतन्त्र लोकलज्जा से ही नहीं चलता बल्कि यह सीधे लोगों की भागीदारी से भी चलता है। संसद में जो दल विपक्ष में बैठता है उसके सदस्यों के अधिकार भी सत्ता पक्ष के सदस्यों के बराबर ही होते हैं क्योंकि अध्यक्ष की नजर में वे सभी सांसद होते हैं। सभी सांसदों के एक समान विशेषाधिकार होते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य के पास भी अपनी बात

सदन में पूरी तरह बेखौफ रहते हुए कहने का अधिकार होता है। यह केवल विपक्षी सांसदों का ही विशेषाधिकार नहीं होता, मगर यह भी सच है कि सदन अपनी ही बनाई गई नियमावली के अनुसार चलता है जिसमें विपक्षी सांसद सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं।

विपक्षी सांसद पूरी जिम्मेदारी का परिचय दे सकें और सदन के भीतर केवल सत्य पर आधारित तथ्यों को ही रखें, नियमावली का यही मूल उद्देश्य रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकसभा में सत्तारूढ़ व विपक्ष के सांसद दो दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और एक- दूसरे के प्रति बहुत कर्कश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतन्त्र उस भाषा के इस्तेमाल की इजाजत देता है जिसमें विरोधी के विचारों को भी सम्मान के साथ देखा जाये जिनमे तीखी आलोचना का भाव होता है। आलोचना लोकतन्त्र का अविभाज्य अंग होती है, क्योंकि आम जनता सत्ता पक्ष व विपक्ष का चुनाव जब करती है तो वह परस्पर एक-दूसरे के विरोधी दलों द्वारा की गई आलोचना के आधार पर ही करती है। लोकतन्त्र में प्रत्येक दल संविधान के प्रति समर्पित होता है मगर समाज व राष्ट्र के विकास के प्रति उनका नजरिया अलग- अलग होता है जिसकी वजह से उनके सिद्धान्तों में अन्तर होता है। जाहिर है कि संसद में जो बजट सरकार की तरफ से इसकी वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने रखा उसे विपक्षी नेता अपने नजरिये से उतना कल्याणकारी नहीं मानते जितना कि वे अपने सिद्धान्तों की नजर से उसे बनाने की कूवत रखते, मगर यह बात कड़वाहट भऱे शब्दों की जगह समालोचना की दृष्टि से की जानी चाहिए। इसी प्रकार भारत- अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह बवंडर खड़ा किया जा रहा है उससे यह आभास कराने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं की है। यह केवल एक नजरिया है, क्योंकि व्यापार समझौता तभी सफल माना जायेगा जबकि उसके सिरे चढ़ने से भारतीयों को भविष्य में लाभ होगा। यदि ऐसा न होता तो स्व. राजीव गांधी अपने कार्यकाल के दौरान भारत में सूचना व कम्प्यूटर क्रान्ति न कर पाते।

उनके कार्यकाल के दौरान संसद में बैठे विपक्षी दलों ने कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने पर बवाल खड़ा कर दिया था और कहा था कि इसके आने से भारत मे बेरोजगारी बेइन्तहा बढ़ जायेगी, मगर आज का भारत इसी क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बना हुआ है। इसी प्रकार जब भारत-अमेरिका परमाणु समझौता हुआ था तो विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया था। कहने का मतलब इतना सा है कि लोकतन्त्र में जब भी कोई सरकार सत्ता में होती है तो उसका पहला ध्येय राष्ट्रहित व उसके लोगों का विकास ही होता है। अत: विपक्ष को पिछले उदाहरणों से सीख लेते हुए अपने नजरिये में परिमार्जन करना चाहिए और आलोचना करते हुए कठोर शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति इतनी रंजिश भरी होती जा रही है कि संसद के भीतर भी शब्दों की मर्यादा समाप्त होती जा रही है, मगर इस स्थिति से भी हमे संसद ही बचा सकती है।

सरकारी दावत और शाकाहारी फूड मेन्यू की चर्चा

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

विदेशी मेहमानों के लिए सरकारी दावतों में परोसे जा रहे पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन इंडियन फूड मेन्यू

डिप्लोमैटिक सर्कल में चर्चा का विषय बन गए हैं। नई दिल्ली में तैनात डिप्लोमैट खाने के विकल्पों को देखकर हैरान और उलझन में हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे भारत में मिलने वाली स्वादिष्ट नॉन-वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डिशेज़ की बड़ी वैरायटी से परिचित हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में सेशेल्स के दौरे पर आए राष्ट्रपति, डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के लिए राष्ट्रपति भवन के मेन्यू में ऐसी डिशेज़ थीं जो दावत में बुलाए गए भारतीय मेहमानों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया। इनका नमूना लें, दही के झाग में जले हुए अनानास के साथ कोशाम्बरी, खाने योग्य गन्ने के सींक पर कटहल और केले के फूल, भरी हुई लौकी, मसालेदार रतालू और दही की चटनी में कच्चा केला। पहले वाले को राष्ट्रपति भवन का दक्षिण भारतीय सलाद बताया गया था जिसमें मूंग दाल और खीरा होता है, जिसमें सरसों के बीज का तड़का लगाया जाता है। दूसरा आइटम केरल का बताया गया, जिसे देखकर मलयाली भी हैरान रह गए। तीसरा आइटम कन्नड़ स्टाइल की दही वाली डिश का टेक-ऑफ था। पिछले दिसंबर में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की दावत का मेन्यू भी वैसा ही वेजिटेरियन था। इसमें वेजिटेबल झोलमोमो के साथ स्पाइसी चटनी, अचारी बैंगन और पालक मटर मेथी साग जैसे आइटम शामिल थे। मेनू कार्ड पर लिखा था कि यह मेन्यू हेल्दी, हाई-प्रोटीन और लो-शुगर पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कूटनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि इन हेल्दी वेजिटेरियन दावतों के बाद विदेशी डिग्निटरीज़ नाखुश और भूखे रह जाते हैं। लगता है, होटल वापस आने पर वे अपने कमरों में ज़्यादा जाना-पहचाना नॉन-वेजिटेरियन इंडियन खाना ऑर्डर करते हैं।

चार साल बाद खुला मुंबई मेयर का बंगला

साउथ मुंबई के बायकुला जू कॉम्प्लेक्स में मुंबई के मेयर के हेरिटेज बंगले में चार साल बाद कोई रहने वाला आ गया है, जब रितु तावड़े शहर की पहली भाजपा मेयर चुनी गईं। बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2022 में भंग होने और चुनाव इस साल की शुरुआत तक टलने के बाद से यह बंगला पिछले चार साल से खाली पड़ा था।

क्योंकि यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है, इसलिए इसमें कोई बड़ा स्ट्रक्चरल या दूसरा बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन चार साल की अनदेखी के बाद इसे संवारा जा रहा है। असल में, मुंबई के मेयर पारंपरिक रूप से दादर शिवाजी पार्क के बंगले में रहते आए हैं। हालांकि, 2019 में, बीएमसी, जिसका प्रमुख तब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूनाइटेड शिवसेना थी, ने इसे अपने कब्जे में लेने और इसे शिवसेना के फाउंडर बाल ठाकरे की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया। जाहिर है, बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाने के बाद अपनी पहली रैली मेयर के बंगले के सामने शिवाजी पार्क में की थी। शिवसेना ने सेंटीमेंटल वजहों से पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। मेमोरियल अभी तक आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, हालांकि यह लगभग सात साल से बन रहा है।

सबसे पहले बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी। उन्होंने नतीजों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही अपना बधाई

मैसेज ट्वीट कर दिया था। उन्होंने इसे सुबह 9 बजे पोस्ट किया था, जिसमें बीएनपी की साफ जीत दिख रही थी। पाकिस्तान ने लगभग आधे घंटे बाद इस पर एक्शन लिया, जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुबह 9:28 बजे अपना ट्वीट पोस्ट किया। इसके बाद दूसरे देशों, खासकर अमेरिका से मैसेज आने लगे। पीएम का तुरंत जवाब यह दिखाता है कि भारत महीनों की तनातनी के बाद अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है।

रेडियो है एक विश्वसनीय आवाज : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो की स्थायी प्रासंगिकता और परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डाला और इसे एक विश्वसनीय आवाज बताया जो दूरदराज के गांवों और हलचल भरे शहरों में लोगों को समान रूप से जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विश्व रेडियो दिवस एक ऐसे माध्यम का जश्न मनाने का दिन है जो दूरदराज के गांवों से लेकर हलचल भरे शहरों तक, लोगों की विश्वसनीय आवाज है। वर्षों से, रेडियो समय पर जानकारी देता रहा है, प्रतिभा को निखारता रहा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता रहा है। यह दिन इस माध्यम से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों को स्वीकार करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात' पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे यह कार्यक्रम नागरिकों के साथ सीधे संवाद के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में विकसित हुआ है। पीएम ने आगे कहा, मन की बात के माध्यम से मैंने रेडियो की उस क्षमता का प्रत्यक्ष अनुभव किया है जिसके द्वारा यह हमारे लोगों की सामाजिक शक्ति को उजागर कर सकता है।

> **“ आज विश्व रेडियो दिवस है और जश्न मनाने का दिन भी है। सच बात तो यह है कि रेडियो वर्षों से समय-समय पर जानकारी देता रहा है। यह प्रतिभाओं को निखारता रहा है और रचनात्मकता को प्रोत्साहित भी करता रहा है। मेरे मन की बात कार्यक्रम को इसी रेडियो ने एक अद्वतीय मंच भी बनाया। रेडियो सही मायनों में हमारे लोगों की सामाजिक शक्ति को उजागर कर सकता है।**

इस महीने का कार्यक्रम रविवार, 22 फरवरी को प्रसारित होगा। कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव अवश्य साझा करें। प्रधानमंत्री की टिप्पणियां संचार के सबसे गतिशील, प्रतिक्रियाशील और आकर्षक माध्यमों में से एक के रूप में रेडियो के निरंतर महत्व को रेखांकित करती हैं।तेजी से हो रहे तकनीकी विकास और डिजिटल प्लेटफार्मों के प्रसार के बावजूद, रेडियो ने सहजता से खुद को अनुकूलित कर लिया है, और श्रोताओं को भाग लेने और जुड़ने के नए और इंटरैक्टिव तरीके प्रदान कर रहा है। भारत में, राष्ट्रीय प्रसारक और प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। इसकी घरेलू सेवा में देश भर में 400 से अधिक स्टेशन शामिल हैं, जो भारत के लगभग 92 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और कुल जनसंख्या के 99.19 प्रतिशत तक पहुंचते हैं। प्रसारक 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो देश की समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाता है।रेडियो एक शक्तिशाली और कम लागत वाले संचार उपकरण के रूप में काम करता रहता है, जो विशेष रूप से दूरस्थ समुदायों और समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त है, जिसमें निरक्षर, विकलांग व्यक्ति, महिलाएं, युवा और आर्थिक रूप से वंचित समूह शामिल हैं।

बंगाल में मतदान अधिकारियों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग

कोलकाता, (पंजाब केसरी): भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) शनिवार से शुरू होने वाले मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा। राज्य में मतदाता सूची के दस्तावेजों पर आपत्तियों और दावों पर सुनवाई पूरी करने की विस्तारित समय सीमा शनिवार को समाप्त हो जाएगी। सुनवाई सत्र में प्रस्तुत मतदाताओं के पहचान दस्तावेजों की जांच का चरण 21 फरवरी तक जारी रहेगा। हालांकि, इसी बीच, चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए ईसीआई द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों ने सुनवाई सत्रों के दौरान सहायक पहचान दस्तावेजों के रूप में केवल ईसीआई-सूचीबद्ध दस्तावेजों को स्वीकार करने के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से विचलन के कई उदाहरणों को उजागर किया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अनुसार, इसलिए यह शुक्रवार होने वाली बैठक के एजेंडे का एक प्रमुख बिंदु होगा और आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह सभी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को केवल 13 ईसीआई-सूचीबद्ध दस्तावेजों को प्रामाणिक पहचान प्रमाण के रूप में मानने के संबंध में दिशानिर्देशों के बारे में एक बार फिर याद दिलाएगा।

साथ ही, उन्होंने कहा कि वर्चुअल बैठक में ईसीआई द्वारा सीईओ के कार्यालय से उन चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा जा सकता है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

आज का पंचांग

शनिवार, 14 फरवरी, 2026
तिथि-द्वादशी-16:01 तक
नक्षत्र-पूर्वाषाढा-18:15 तक
प्रथम करण-तैतिल-16:01 तक
द्वितीय करण-गर-28:37 तक
पक्ष-कृष्ण
योग-सिद्ध-27:17 तक
सूर्योदय-07:01/सूर्यास्त-18:09
चंद्रमा-धनु
राहुकाल-09:48-11:11
विक्रमी सम्वत-2082
मास-फाल्गुन
शक सम्वत-1947, विश्वावसु
शुभ मुहूर्त-अभिजीत-12:13-12:57

आज का राशिफल

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,अ)

आज का दिन आपके लिए भावनाओं की नाव को संभालने का है, जहां हर लहर पर नियंत्रण जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप अपने सबसे करीबियों के दिलों को जीतने वाले जादूगर हैं। एक मुस्कान, एक संयमित शब्द से सब कुछ बदल सकता है। किसी भी काम में लापरवाही न दिखाएं, वरना बाद में उलझनें आपको घेर लेंगी, जैसे अनियोजित यात्रा में रास्ता भटक जाना। अपनी वाणी और व्यवहार को संयम की चाबी से बंद रखें, तो आपकी साख आसमान छुएगी और सम्मान नई ऊंचाइयों को पार करेगा।

वृषभ (इ,उ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)

आज निवेश करते समय दिमाग को ब्रेक दें। हर पैसा सोच-समझकर लगाएं, जैसे खजाने की रक्षा करने वाला पहरेदार। धन को थोड़ा किनारे पर रखें, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। कामों पर फोकस रखें, कोई चूक न हो। अगर प्रॉपर्टी डील लटकी हुई है, तो आज वह पंख लगाकर उड़ान भर सकती है। लोन अप्लाई करने का सही समय है। कानूनी मामले में जीत की खुशबू आ रही है, लेकिन भावनाओं के भंवर में बहकर फैसला न लें।

मिथुन (की,कु,घ,ङ:,छ,के,को,ह)

परिजनों का साथ कंधों पर बोझ उतार देगा आप सबको एक परिवार की तरह जोड़ने में जुटे रहेंगे। मन की कोई पुरानी इच्छा आज फलित हो सकती है, जैसे लंबे समय से चाहा हुआ गैजेट हाथ लगना। घर में नया मित्र आएगा, जो हंसी-खुशी का तड़का लगाएगा। जीवनसाथी आपके हर कदम पर सहारा बनेगी, लेकिन जरूरी जानकारी किसी को शेयर न करें। रहस्य सुरक्षित रखें। बिजनेस में थोड़ी टेंशन रहेगी, लेकिन आय बढ़ने से चेहरा खिल उठेगा।

कर्क (हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)

तर्क-वितर्क के जाल में फंसने से बचें, वरना ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। शासन और प्रशासन के मामलों में आंखें तरेरी रखें। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं, जैसे सब्सिडी का फायदा पक्का करना। घूमने-फिरने के दौरान कोई कीमती जानकारी मिलेगी, जो भविष्य को रोशन करेगी। विरोधियों की चालों में न फंसें, आत्मविश्वास को स्टील जैसा मजबूत रखें। काम की रफ्तार तेज होगी, लेकिन सतर्कता न छोड़ें।

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)

आर्थिक मोर्चे पर आज सूरज चमकेगा। पैसे की बारिश हो सकती है। लंबी यात्रा की प्लानिंग करें, जो तरोताजा कर देगी। भाई-बंधुओं से जमकर पटेगी, और कारोबार में लाभ की लहर दौड़ेगी। लंबे समय से नाराज मित्र आज मन थाम लेगा, जैसे पुरानी दोस्ती नई हो जाए। लेकिन संतान की पढ़ाई पर ध्यान भटके तो टेंशन न लें। उन्हें गाइड करें। धन के लेन-देन में अजनबी पर भरोसा न करें, वरना नुकसान होगा।

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण:,ठ,पे,पो)

परोपकार के मैदान में हीरो बनेंगे। दान, मदद से दिल जीतें। पुरानी गलतियों से सबक लें जैसे गलत निवेश से सीखकर स्मार्ट बनना। कामों को प्लान से चलाएं, अपरिचितों से दूरी रखें। भावनाओं में बहकर फैसला न लें। स्वास्थ्य पर नजर रखें। खान-पान साफ-सुथरा रखें। विद्यार्थी मानसिक बोझ से मुक्त होंगे। इसे ऐसे सोचें एक छोटा परोपकारी कदम समुदाय को प्रेरित करेगा।

तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)

नेतृत्व की चमक आज बढ़ेगी, और प्रेम में गहराई आएगी। साथी की भावनाओं का सम्मान करें, खुलकर इच्छाओं पर बात करें। रिश्ता और मजबूत होगा। किसी काम के देरी से निराशा हो सकती है, लेकिन नए अनुबंध लाभ लाएंगे। लोगों का दिल जीतें, वाणी की मिठास से सम्मान पाएं। जैसे मीटिंग में सॉफ्ट टोन से डील क्लोज हो जाए। संतुलन बनाए रखें, सफलता नजदीक है।

वृश्चिक (ना,नी,नु,ने,नो,या,यी,यू)

धैर्य और संयम आपकी ढाल हैं आज। खर्चों का बजट बनाएं, मन की इच्छा पूरी होकर खुशी दोगुनी करेगी। परिवार में नया मेहमान हंसी लाएगा। विरोधी की बातों में न फंसें, वाहन सावधानी से चलाएं। दुर्घटना का खतरा टलेगा। सहयोगी की मदद करें, पैसे का इंतजाम हो जाएगा।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ)

आज का दिन आपके लिए एक रोमांचक साहसिक यात्रा जैसा है। ठीक-ठाक लेकिन भरपूर ऊर्जा वाला। जीवनसाथी के साथ पटेगी, जैसे पुराने दोस्तों की तरह हंसी-मजाक चलेगा। दोनों मिलकर भविष्य की रूपरेखा खींचेंगे। घर, करियर या बच्चों की प्लानिंग पर गहरी बातें होंगी, जो रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। जरूरी कामों की लिस्ट बनाकर टिक मार्क करें, ताकि दिन उत्पादक बने।

मकर (जा,जी,जू,जे,जो,खा)

आज सोच-समझकर हर कदम उठाएं, जैसे पहाड़ चढ़ते हुए रस्सी पकड़ना। दूसरों के मामलों में बोलने से बचें, वरना अनावश्यक उलझनें बढ़ेंगी। आपके अंदर ऊर्जा का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। हर काम तत्परता से निपटेगा, चाहे वह ऑफिस का टास्क हो या घर का काम। रहन-सहन का स्तर ऊंचा रहेगा, नए कपड़े, घर की सजावट या फिटनेस रूटीन से खुद को अपग्रेड करें। तर्क-वितर्क के जाल से दूर रहें, शांति बनाए रखें।

कुंभ (गू,गे,गो,सो,सी,सू,से,सो,दा)

हंसी-खुशी का माहौल बनेगा। बिजनेस या जॉब में अनजान व्यक्ति की सलाह न लें, वरना समस्याएं दोगुनी हो जाएंगी। अपने अनुभव पर भरोसा करें। पुराना मित्र लंबे समय बाद मिलेगा, जो सरप्राइज गिफ्ट या सलाह लाएगा। पुरानी गलती पर परेशान न हों, इसे सबक मानें और आगे बढ़ें, जैसे गलत निवेश से सीखकर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्मार्ट बनाना। विद्यार्थी जो विदेश पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है।

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)

आनंदमय दिन, जैसे समुद्र की लहरों में तैरना। परिवार में अगर कड़वाहट चल रही थी, तो वह पिघलकर मिठास में बदल जाएगी। खुलकर बात करें। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो नई दोस्ती या अवसर लाएंगी। अनावश्यक खर्च टालें। सरकारी काम जो लंबे अटका था, आज पूरा हो सकता है। दस्तावेज तैयार रखें। पिताजी की कोई बात बुरी लगे तो मन पर न लें, गहरी सांस लें और आगे बढ़ें। दूसरों के मामलों में बेवजह न बोलें।

वेलेन्टाइन डे - संतमत के दृष्टिकोण से

वेलेन्टाइन डे के अवसर पर क्यों न हम भौतिक प्रेम से ज्यादा आध्यात्मिक प्रेम की और ध्यान दें। अपने आप को एक प्रेमपूर्ण इंसान बनाएं जोकि पूरी मानवता के प्रति सारी सृष्टि के प्रति प्रेम व करुणा का भाव रखता...

- संत राजिंदर सिंह जी महाराज -

14 फरवरी सेंट वेलेन्टाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके विषय में एक कहानी प्रचलित है कि सेंट वेलेन्टाइन बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार सेंट वेलेन्टाइन को जेल में बंद कर दिया गया और उनके चहेते बच्चे यह सहन नहीं कर पाए। इन बच्चों ने कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अपनी कोमल भावनाओं को अंकित किया एवं जेल की सलाखों में से उन तक पहुंचाया। कदाचित, यहां से प्रेम से परिपूर्ण भावनाओं के आदान-प्रदान का सिलसिला आरंभ हुआ जो अब तक समय के अनुसार कई रूप बदल चुका है।

यद्यपि आज के युग में वेलेन्टाइन डे प्रेमी और प्रीतम के बीच का ही एक उत्सव रह गया है परंतु इसका भी एक अध्यात्मिक पहलू है। वेलेन्टाइन डे संत वेलेन्टाइन व उनके शिष्यों के बीच प्रेम का प्रतीक है। ये प्रतीक है अध्यात्मिक प्रेम का जोकि एक गुरु और शिष्य के बीच या प्रभु व भक्त के बीच होता है जोकि एक इंसान का पूरी सृष्टि व मानवता के लिए होता है।

हमारा इंसान होने का परम लक्ष्य अपने आप को जानना और परमपिता परमात्मा को पाना है। ये लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन प्रेम ही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, *'साच कहु सुन लहो सभेह, जिन प्रेम कीयो तिन हि प्रभ पायो।'*

परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश होने के नाते वही सारे गुण रखती है जो परमात्मा के हैं। ऐसे हमारी आत्मा भी प्रभु प्रेम का ही अंश है और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम का ही रास्ता है।

प्रश्न यह उठता है कि यह प्रेम मिलता कहां से है? इस दिव्य प्रेम की किरणें एक पूर्ण महापुरुष की प्रभु प्रेम में मदमस्त आंखों से हम तक आती हैं। हमारी सदियों से सोई आत्मा को धीरे-धीरे जागृत करती हैं और चेतनता के महासागर तक की यात्रा पूर्ण करवाती हैं। वास्तव में स्वयं परमात्मा ही संत सतगुरु के रूप में अपने अंशों को वापिस ले जाने के लिए इस धरा पर आते हैं। संत सतगुरु इन्हें जगाने के लिए मात्र प्रेम का प्रयोग करते हैं।

यह सामर्थ्य केवल एक संत सतगुरु में होता है कि प्रेम का पात्र बदलकर किसी हृदय को परमार्थ की राह पर चला दे। संत सतगुरु के अनंत प्रेम का अनुभव पाकर ही आत्मा भय, भ्रम और द्वैत की जकड़न से मुक्त हो सकती है।

सदियों से संत महापुरुष प्रभु प्रेम व गुरु प्रेम को अत्याधिक महत्ता देते आए हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख संत ईसा मसीह का भी मूल संदेश प्रेम का संदेश था। ईसा ने अपने शिष्यों को जो महान संदेश दिया, उसको 2 आज्ञाओं में समेट सकते हैं...

'आप अपने प्रभु को पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से तथा पूरे मन से प्यार करें। और अपने पड़ोसी को आप अपने जैसा प्यार करें।' उन्होंने स्पष्ट किया इन 2 आज्ञाओं पर ही सभी नियम और पैगंबर आधारित होते हैं। ***(मैथ्यू - 22:37, 39:40)***

ईसा ने इन 2 आज्ञाओं को केवल दिया ही नहीं, बल्कि वे इनके अनुसार जिये भी। यही संतों की सच्ची विशेषता है क्योंकि वे प्यार की प्रतिमूर्ति होते हैं।

प्रभु प्रेम है। हमारी आत्मा उस प्रेम की एक किरण है और प्रेम एक ओर तो प्रभु और मनुष्यों के बीच तथा दूसरी ओर मनुष्यों तथा प्रभु की सृष्टि के बीच एक सूत्र है। प्रेम जीवन और प्रकाश के नियम की पूर्णता है।

आइये, हम सोचें कि क्या हमारे जीवन में यह प्यार झलकता है? क्या हम एक-दूसरे की प्यार से सेवा करते हैं?

क्या हम उनके प्रति उदार तथा सहनशील हैं जिनके विचार हमसे भिन्न होते हैं? क्या हम प्रभु के सभी जीवों से प्यार करते हैं तथा क्या हम सबको अपना समझकर गले लगाने के लिए तैयार हैं?

क्या दलितों के प्रति हम में दया और सहानुभूति है? क्या हम बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि हम प्यार से नहीं रहते तो अभी हम प्रभु से काफी दूर हैं तथा धर्म से परे हैं। यदि हम सही मायने में प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें यह हमें अपने आचरण में भी लाना होगा।

इस वेलेन्टाइन डे के अवसर पर क्यों न हम भौतिक प्रेम से ज्यादा आध्यात्मिक प्रेम की और ध्यान दें। अपने आप को एक प्रेमपूर्ण इंसान बनाएं जोकि पूरी मानवता के प्रति सारी सृष्टि के प्रति प्रेम व करुणा का भाव रखता है। वेलेन्टाइन डे मनाने का यही सर्वोत्तम तरीका होगा।

महाभारत : कौरवों के पास था बहुत धन, पांडव थे काफी गरीब और फिर अचानक...

महाभारत में कौरवों के पास पांडवों की तुलना में काफी पैसा और वैभव था। पांडव उनके सामने धन के मामले में कहीं नहीं थे। फिर कैसे पांडवों की किस्मत ऐसी बदली कि कौरवों को उनसे जलन होने लगी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को चमचमाती हुई राजधानी बनाया तो वाकई हर कोई उनके वैभव को देखकर हैरान हो उठा...

महाभारत के दौर को धन संपदा के लिहाज से देश के सबसे समृद्ध दौर में गिना जाता है। बड़े-बड़े महल। सोने और आभूषणों का अंबार। क्या आपको मालूम है कि उस दौर में कौन ज्यादा अमीर था कौरव या पांडव?

क्या आपको मालूम है कि उस दौर में कौरव ज्यादा अमीर थे या पांडव? जब तक पांडव हस्तिनापुर में कौरवों के साथ रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर कैसे बदली उनकी किस्मत, किस गुप्त खजाने ने उन्हें समृद्धि से भर दिया।

महाभारत काल में धन और संपत्ति की तुलना करें तो कौरवों की संपत्ति पांडवों से अधिक थी लेकिन समय के साथ हालात बदले। हालांकि, ये बात सही है कि जब पांडव को खांडप्रस्थ वन देकर कहा गया कि इसे लेकर तुम अपनी राजधानी बना लो तो वहां केवल जंगल थे। पांडवों ने श्रीकृष्ण की मदद से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया था।

इंद्रप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है 'इंद्र का मैदान' या 'इंद्र का शहर'। इस नगरी को महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने डिजाइन किया और बनाया था।

इसे बनवाने के दौरान पांडवों के पास जितना भी धन था, वो खत्म हो गया। जब कृष्ण ने युद्धिष्ठिर और पांडवों से कहा कि अब राजसूर्य यज्ञ कराना चाहिए तो युद्धिष्ठिर ने लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनके पास इतना धन नहीं है कि इस बेहद खर्चीले काम को कर सकें। तब कृष्ण ने उन्हें एक खजाने के बारे में बताया। ऐसे में वो कौन-सा खजाना था जिसने पांडवों की किस्मत बदल दी।

तब कौरव ज्यादा अमीर थे

पांडवों और कौरवों के बीच जब बंटवारा नहीं हुआ था, तब कौरव अमीर थे। जब हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी थी तो कौरव बहुत अमीर थे। हस्तिनापुर पूरे आर्यावर्त (भारत) के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में एक था।

राजकोष, सेना, हाथी-घोड़े, और जमीन की दृष्टि से कौरव बहुत धनवान थे। जब तक पांडव हस्तिनापुर में कौरवों के साथ रह रहे थे, तब तक उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी लेकिन जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया तो उन्हें एक बड़ा खजाना मिला।

दुर्योधन सबसे धनी लोगों में था

दुर्योधन के पास सोने के महल थे और वह राजाओं को दान देता था जिससे उसकी समृद्धि और वैभव सिद्ध होता है। ये कहा भी गया है कि दुर्योधन उस दौर के सबसे धनी लोगों में गिना जाता है।

कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के पास हस्तिनापुर राज्य का विशाल कोष था। वह एक शक्तिशाली राजकुमार था। उसके पास बहुत बड़ी सेना और धन-संपत्ति से भरा खजाना था।

तब पांडवों के पास कुछ नहीं था

जब तक पांडव यानि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर में रहते थे, उनके पास व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं था। जब राज्य विभाजन हुआ तो उन्हें एक बंजर भूमि मिली जिसे उन्होंने माया सभ्यता की मदद से स्वर्ग के समान बना दिया।

इसमें कृष्ण और मय दानव ने भी सहायता की। इसके बाद ही युधिष्ठिर और पांडवों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। यकीनन जब भीम ने राजा मरुत के हिमालय में छिपे खजाने को ढूंढ निकाला तो पांडवों के राज्य का खजाना जबरदस्त तरीके से भर गया।

तब पांडवों का खजाना था खाली

इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाने के बाद जब पांडवों के पास खजाना खाली हो गया, ऐसे में उन्हें किस राजा का छिपा हुआ खजाना मिला जिसने उन्हें अमीर बना दिया...ये कहानी भी दिलचस्प है।

मरुत का खजाना जो युधिष्ठिर को मिला

जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, तब उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इस समस्या का समाधान भगवान श्रीकृष्ण ने किया। उन्होंने युधिष्ठिर को मरुतों का खजाना हासिल करने की सलाह दी। यह खजाना प्राचीन काल में राजा मरुत का था। राजा मरुत तो स्वर्गवासी हो गए थे लेकिन खजाना धरती पर ही रह गया था।

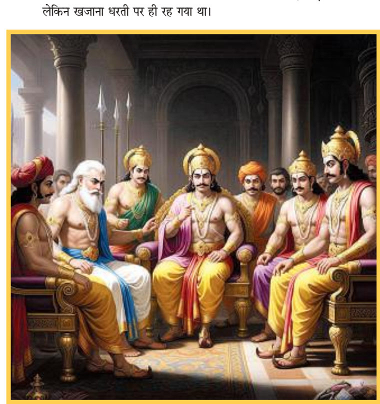

हिमालय की गुफाओं में था ये खजाना

यह खजाना हिमालय की गुफाओं में छिपा था। ना तो इसके बारे में किसी को मालूम था और न ही कोई इसको पा सका था। तब कृष्ण ने न केवल इसके बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि ये कहां और कैसे मिलेगा। इस खजाने को लाने के लिए भीम को भेजा गया। उन्होंने इसे खोज निकाला। इसने पांडवों को बहुत अमीर बना दिया।

फिर कौरवों ने हड़प ली सारी धन-संपत्ति

इसके बाद दुर्योधन ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया। उनकी पूरी संपत्ति, राज्य, धन, सेना को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय कौरवों के पास फिर सबसे ज्यादा धन-संपत्ति हो गई। पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा। वो वनवास में चले गए।

महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर सबसे अमीर बने

वनवास के दौरान पांडवों ने अपने संपर्क कई राजाओं से बेहतर किए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो अपने गठजोड़ के कारण ताकतवर हो चुके थे। महाभारत युद्ध में कौरवों की संपत्ति, सेना और राज्य सभी का विनाश हो गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। अब पांडवों के पास अपार संपत्ति थी लेकिन उन्होंने इसे राज्य की सेवा में लगाया।

कई और लोग भी थे अमीर

महाभारत काल में कई और लोग भी खासे अमीर थे जिनके पास अपार धन-संपत्ति थी। वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे।

- **कर्ण :** दानवीर कर्ण के पास अंगदेश का राज्य था। वो भी बहुत धनी थे। उन्होंने अपनी दानवीरता के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी।
- **भीष्म :** भीष्म पितामह के पास भी अपार संपत्ति थी। वह कुरु वंश के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्तियों में एक थे।
- **द्रुपद :** पांचाल के राजा द्रुपद भी बहुत धनी थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था।
- **राजा विराट :** राजा विराट मत्स्य देश के शासक थे और उनके पास अपार संपत्ति, विशाल सेना और घोड़े थे। यह वही राजा हैं जिनके यहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी।
- **श्रीकृष्ण :** श्रीकृष्ण को भी उनकी दिव्य शक्तियों और संपत्ति के लिए जाना जाता था। वे द्वारका के राजा थे। उनके पास अपार धन-संपत्ति थी।

कुबेर थे सबसे धनवान लेकिन...

कुबेर उस दौर में सबसे धनवान थे लेकिन वह मानव नहीं थे, बल्कि देवता माने जाते थे। वह देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते थे। सैकड़ों यक्ष हमेशा उनके अपार खजाने की रक्षा करते रहते थे। उनके पास त्रिलोक का खजाना था जिसे 'निधि' कहा जाता है।

कौन-सी मुद्राएं तब चलती थीं

महाभारत काल में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। ये सोने, चांदी और तांबे से बनी होती थीं...

- **कार्षापण :** यह सबसे प्रचलित मुद्रा थी जो चांदी या तांबे से बनी होती थी।
- **सुवर्ण :** यह सोने की मुद्रा थी जिसका मूल्य कार्षापण से अधिक होता था।
- **निष्क :** यह भी सोने की मुद्रा थी जो सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान होती थी।
- **माषक :** यह तांबे की मुद्रा थी जिसका मूल्य कार्षापण से कम होता था।
- **काकणी :** यह सबसे छोटी मुद्रा थी जो तांबे या मिट्टी से बनी होती थी।

(यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं।)

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग आसान नहीं

बेबाक विचार

राजीव रंजन तिवारी

अब वहां भी तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पिछले दिनों जारी हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई) में पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नेतृत्व की कमी सामने आई है। सीपीआई की 31वीं रिपोर्ट में 180 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों को पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। 80 से ज्यादा स्कोर पाने वाले देशों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 12 से घटकर सिर्फ पांच रह गए हैं। डेनमार्क ने लगातार आठवीं बार सबसे ज्यादा 89 अंक हासिल किए हैं। उसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के प्रमुख फ्रांसुआ वैलेरियन का कहना है कि कई सरकारें अब भ्रष्टाचार से लड़ना अपनी प्राथमिकता नहीं मानती। सरकारों को यह लगने लगा है।

भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उसके खिलाफ लड़ाई अब आसान नहीं रही। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वालों का जो हश्र होता है, वह बेहद चिंताजनक है। अब आप दुनिया के विकसित देशों की मिसाल भी नहीं दे सकते कि वहां भ्रष्टाचार कम है। दुनिया के अनेक देश लगातार भ्रष्टाचार के चंगुल फंसते जा रहे हैं। डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बड़े-बड़े लोकतंत्रिक देश भी धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक रहे हैं। यह देश और समाज के लिए चिंताजनक है। यदि इसी तरह से हालात बदलते रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। अमेरिका और स्वीडन जैसे देश जो कभी भ्रष्टाचार से लड़ने में आदर्श माने जाते थे। अब वहां भी तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पिछले दिनों जारी हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (सीपीआई) में पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नेतृत्व की कमी सामने आई है। सीपीआई की 31वीं रिपोर्ट में 180 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों को पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक किया गया है। रिपोर्ट में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है। 80 से ज्यादा स्कोर पाने वाले देशों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 12 से घटकर सिर्फ पांच रह गए हैं। डेनमार्क ने लगातार आठवीं बार सबसे ज्यादा 89 अंक हासिल किए हैं। उसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के प्रमुख फ्रांसुआ वैलेरियन का कहना है कि कई सरकारें अब भ्रष्टाचार से लड़ना अपनी प्राथमिकता नहीं मानती। सरकारों को यह लगने लगा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए काफी कुछ कर लिया है। आपको बता दें कि सीपीआई हर देश को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करता है। इसके अनुसार 0 का मतलब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार और 100 का मतलब साफ छवि वाला देश है। इस पैमाने के अनुसार अमेरिका का स्कोर गिरकर 64 पर पहुंच गया है, जो कि अब तक का उनका सबसे कम स्कोर है। साल 2016 के मुकाबले देखे तो यह तब से दस अंक नीचे गिर चुका है। अमेरिका का राजनीतिक माहौल पिछले एक दशक से तेजी से बिगड़ा है। हालिया आंकड़े पूरी तरह उस बदलाव को नहीं दिखाते, जो पिछले साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद हुए हैं। बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका की रैंकिंग स्थिर थी। लेकिन पिछले साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े बड़े नैतिक घोटालों को स्कोर गिरने की बड़ी वजह बताया गया। वैलेरियन कहते हैं कि हर चीज

के लिए ट्रंप दोषी नहीं हैं, क्योंकि कुछ चिंताजनक चीजें उनके आने से पहले ही शुरू हो चुके थे। अमेरिका में भी सरकारी पद का इस्तेमाल स्वतंत्र आवाजों को दबाने के लिए करना, स्वार्थ और लेन-देन वाली राजनीति को सामान्य बनाना, प्रॉसिक्यूशन फैसलों का राजनीतिकरण करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला कदम उठाया जा रहा है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरूआत से कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है। इसके तहत वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे सरकारी प्रसारकों को खत्म किया गया और सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों जैसे बाइडेन प्रशासन और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। काफी पहले वैलेरियन ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने कार्यकारी आदेश के जरिए एफसीपीए में बदलाव कर उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के औजार में बदल दिया। उन्होंने ट्रंप के क्रिप्टोकरेंसी (जैसे बिटकॉइन) के समर्थन की भी आलोचना की थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है। उन्होंने अमीर विदेशियों के लिए तेजी से नागरिकता/वीजा देने की योजना की भी आलोचना की थी। वैलेरियन कहते हैं कि ऐसे वीजा कार्यक्रम भ्रष्ट लोगों और अपराधियों को आकर्षित कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में पश्चिमी देशों में भ्रष्टाचार की धारणा सबसे ज्यादा ब्रिटेन में गिरी है। ब्रिटेन का स्कोर 11 अंक गिरकर 70 पर पहुंच गया है। इसकी वजह मंत्रियों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के लिए नैतिक नियमों को ठीक से लागू न कर पाना है। रिपोर्ट में कोविड-19 के दौरान घोटालों का भी जिक्र है, जब सत्ता के करीबी लोगों को बिना पर्याप्त जांच के पीपीई (मास्क, मेडिकल सामान) सप्लाई करने के ठेके मिले थे। कई अन्य देशों में भी गिरावट देखी गई है। जैसे न्यूजीलैंड 9 अंक गिरकर 81, स्वीडन 8 अंक गिरकर 80, कनाडा 7 अंक गिरकर 75 पर आ गए हैं। साथ ही, जर्मनी पिछले 10 साल में 4 अंक गिरकर 77 पर आ गया है। हालांकि, यह आंकड़ा पिछले साल से दो अंक बढ़ा है। इस इंडेक्स के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में फ्रांस का स्कोर चार अंक गिरकर 66 हो गया है। हालांकि रिपोर्ट ने पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति, निकोला सारकोजी की सजा को एक सकारात्मक कदम बताया। लेकिन सरकोजी को अवैध फंड लेने का दोषी ठहराया गया था, जिसमें लीबिया के पूर्व नेता मुआम्मर गद्दाफी से मिला पैसा भी शामिल था, जिसे राष्ट्रपति चुनाव के अभियान में इस्तेमाल किया गया था। वैलेरियन कहते हैं कि कई यूरोपीय देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आगे थे। लेकिन अब यूरोपीय संघ ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2012 के बाद से 50 देशों की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है। खास तौर पर तुर्की, हंगरी और निकारागुआ में भारी गिरावट है।ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार अब संगठित अपराध (माफिया/ड्रग कार्टेल) को लैटिन अमेरिका की राजनीति में घुसने का मौका दे रहा है। यहां तक कि कोस्टा रिका और उरुग्वे, जिन्हें पहले क्षेत्र के सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता था। वह अब कोलंबिया, मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों की तरह भ्रष्टाचार का सामना कर रहे हैं। वैलेरियन ने कहा कि सत्ता जितनी ज्यादा कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है, उतना ही सत्ता का दुरुपयोग बढ़ता है और जितनी ज्यादा सत्ता गोपनीय होती है, उसका दुरुपयोग करना उतना ही आसान हो जाता है। रिपोर्ट में जेफ्री एप्सटीन की हाल ही में जारी फाइल्स शामिल नहीं हैं, जो पिछले महीने ही सामने आई थी। इन फाइल्स में कई देशों के अधिकारियों पर गलत काम, भ्रष्टाचार या दोषी यौन अपराधी जेफ्री एप्सटीन से संदिग्ध संबंधों के आरोप लगे हैं। संस्था ने चिंता जताई है कि कई देशों में सरकारें गैर-सरकारी संगठनों के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही हैं, खासकर उन संगठनों के खिलाफ जो सरकार की आलोचना करते हैं। जॉर्जिया, इंडोनेशिया और पेरू में ऐसे संगठनों पर कार्रवाई और फंडिंग कटौती बढ़ी है। रिपोर्ट में यूक्रेन की भ्रष्टाचार विरोधी कोशिशों की भी तारीफ की गई है। हाल में रक्षा क्षेत्र में सामने आए घोटाले ने उजागर किया है कि भ्रष्टाचार भी एक समस्या है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन मामलों का सार्वजनिक रूप से सामने आना और अदालत में उजागर होना दिखाता है कि यूक्रेन का नया भ्रष्टाचार विरोधी सिस्टम सुचारू तरीके से काम कर रहा है। वैलेरियन ने कहा कि एक देश यानी यूक्रेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जबकि रूस ने इसके उलट रास्ता चुना है। उन्होंने बताया कि रूस ने भ्रष्टाचार रोकने और सजा देने वाले कई कानून खत्म कर दिए हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रूस का स्कोर 22 है और वह नीचे के देशों में बना हुआ है। जबकि, यूक्रेन का स्कोर 36 है, जो पिछले 10 सालों में सात अंक बढ़ा है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, तानाशाही वाले देशों जैसे वेनेजुएला और अजरबैजान में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नए भ्रष्टाचार इंडेक्स में दुनिया के दो-तिहाई से ज्यादा देशों का स्कोर 50 से नीचे रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन देशों का स्कोर 25 से कम है। वह आमतौर पर युद्ध, हिंसा या सख्त दमनकारी शासन से प्रभावित हैं। इसमें 13 अंक के साथ लीबिया, यमन, इरिट्रिया देश हैं। साथ ही, सोमालिया और साउथ सूडान जैसे देश 9 अंक के साथ शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बातें भी कही गई हैं। कुछ देश जैसे अल्बानिया, अंगोला, द आइवरी कोस्ट, लाओस, सेनेगल, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इसके अलावा, उच्च अंक पाने वाले एस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, भूटान और सेशेल्स जैसे देशों ने लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन किया है।

(लेखक आज समाज के संपादक हैं।)

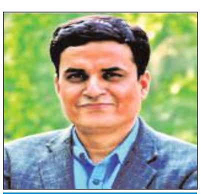

राकेश सिंह

एक तरफ अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है और दूसरी तरफ बीएनपी, जो खालिदा जिया की थी और अब उसे उनके बेटे तारिक रहमान चलाते हैं। अवामी लीग इंडिया के काफी क्लोज रही है। शेख हसीना के समय में दोनों देशों के बीच ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर अच्छा समन्वय था। लेकिन 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स ने सब कुछ उलट-पलट कर रख दिया। शेख हसीना को भागना पड़ा और वो भारत आ गईं, जहां उन्हें आश्रय मिला। इससे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट भड़क गया, खासकर युवाओं में। अब बीएनपी की जीत के बाद, तारिक रहमान ने दावा किया है कि ये लोगों का विश्वास है उनकी लीडरशिप पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेमोक्रेटिक बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। तारिक रहमान की जीत भारत के लिए कैसी रहेगी? बीएनपी हमेशा से खुद को ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक बताती आई है, खासकर जमात-ए-इस्लामी की तुलना में। जमात वो पार्टी है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी मानी जाती है और पाकिस्तान के साथ उसके पुराने लिंक हैं।

तारिक की जीत, भारत के लिए चुनौती या मौका?

बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों में तारिक रहमान की लीडरशिप वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने जबरदस्त जीत हासिल की है। ये वो पहला चुनाव था जो 2024 की स्टूडेंट अपराइजिंग के बाद हुआ, जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं और 17 साल लंदन में निर्वासन में रहे, अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीएनपी की सरकार में जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टी का हाथ लग गया तो क्या होगा? पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए ये सब कैसा रहेगा? रिश्ते सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से दो बड़े कैंपों में बंटी रही है। एक तरफ अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है और दूसरी तरफ बीएनपी, जो खालिदा जिया की थी और अब उसे उनके बेटे तारिक रहमान चलाते हैं। अवामी लीग इंडिया के काफी क्लोज रही है। शेख हसीना के समय में दोनों देशों के बीच ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर अच्छा समन्वय था। लेकिन 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स ने सब कुछ उलट-पलट कर रख दिया। शेख हसीना को भागना पड़ा और वो भारत आ गईं, जहां उन्हें आश्रय मिला। इससे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट भड़क गया, खासकर युवाओं में। अब बीएनपी की जीत के बाद, तारिक रहमान ने दावा किया है कि ये लोगों का विश्वास है उनकी लीडरशिप पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेमोक्रेटिक बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। तारिक रहमान की जीत भारत के लिए कैसी रहेगी? बीएनपी हमेशा से खुद को ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक बताती आई है, खासकर जमात-ए-इस्लामी की तुलना में। जमात वो पार्टी है जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी मानी जाती है और पाकिस्तान के साथ उसके पुराने लिंक हैं। अगर तारिक जमात को सरकार में नहीं लाते या उनका असर कम रखते हैं, तो भारत के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है।

क्योंकि बीएनपी भारत के साथ संबंध को रिस्टोर करने की बात कर रही है। तारिक ने खुद कहा है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रिश्ता चाहते हैं। दोनों देशों का बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, ट्रेड अरबों डॉलर का है, भारत बांग्लादेश को विद्युत प्रदान करता है। ऐसे में, तारिक रहमान को पता है कि वे भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। पीएम मोदी का मैसेज भी यही इंडिकेट करता है कि भारत संबंध को मजबूत करने के लिए तैयार है। अगर तारिक रहमान हिंदुओं पर हो रही हिंसा को रोकते हैं, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो ये भारत के लिए राहत की बात होगी। क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला बढ़े थे और भारत ने इस पर चिंता जताई थी। लेकिन दूसरा पक्ष भी कम नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है शेख हसीना का। शेख हसीना अभी भारत में हैं, और बीएनपी वाले चुनाव कैंपेन में बार-बार कहते रहे कि भारत उन्हें वापस भेजे। अब सरकार बनने के बाद वो फॉर्मली एक्सट्राडिशन की डिमांड कर सकते हैं। शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई केस हैं, यहां तक कि डेथ सेंटेंस भी कुछ मामलों में है। अगर भारत ने उन्हें नहीं भेजा तो रिश्ते में टेंशन आएगी। तारिक रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये भारत पर निर्भर करता है, लेकिन ये साफ है कि हसीना फैक्टर संबंध में रोड़ा बनेगा। दूसरा, पब्लिक सेंटिमेंट। बांग्लादेश के लोग, खासकर जेन जेड, भारत के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत ने हसीना को सपोर्ट किया। तारिक रहमान अगर भारत के साथ क्लोज होते हैं, तो घरेलू बैकलैश का खतरा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तारिक रहमान को बैलेंस करना पड़ेगा, भारत से संबंध सुधारें लेकिन पब्लिक को नाराज न करें। अब अगर जमात-ए-इस्लामी सरकार में आ गई तो? यही वो लाइन है जहां पाकिस्तान का नाम आता है। जमात के पाकिस्तान और आईएसआई से पुराने कनेक्शन हैं। 1971 की वॉर में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अगर पीएनपी-जमात का कोलिशन हुआ, तो बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा झुक सकता है। चीन पहले से बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और पाकिस्तान ने तारिक की जीत पर बधाई दिया है। भारत के लिए ये खतरा है क्योंकि इससे नॉर्थईस्ट में सुरक्षा बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान-लिंक्ड ग्रुप्स बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये चाइना-पाकिस्तान-बांग्लादेश का ट्रायंगल बन सकता है, जो भारत की जियोपॉलिटिक्स के लिए खतरा है। रोहिंग्या मुद्दे ,क्लाइमेट चेंज और रेडिकलाइजेशन के रिस्क भी बढ़ेंगे। भारत को अपनी रेड लाइंस क्लियर रखनी होंगी। लेकिन बीएनपी ने सिग्नल दिया है कि वो जमात को ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद को लिबरल दिखाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों पर असर क्या होगा? शॉर्ट टर्म में, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। भारत को वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तारिक की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ टिल्ट करेगी, भारत की तरफ या दूर? ट्रेड जारी रहेगा, क्योंकि दोनों को फायदा है। लेकिन सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। अगर जमात का असर बढ़ा, तो बॉर्डर पर टेंशन बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में, अगर तारिक भारत के साथ काम करते हैं, तो संबंध और मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि बीएनपी की बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी में भारत का रोल बड़ा है। लेकिन अगर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा, तो भारत को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेसी कड़ा करनी पड़ेगी।

(लेखक आईटीवी नेटवर्क के प्रबंध संपादक हैं।)

पंकज चतुर्वेदी

फिर जांच करवाई तो पता चला आंतों में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन प्रक्रिया के जरिए तेजी से बढ़ रहा है और मियादी बुखार या टाइफाइड इस हाल में है कि मरीज को ठीक होने में कम से कम एक महीना लगेगा। आजकल टाइफाइड के लगभग सारे मरीजों से ऐसी ही कहानी सुनने को मिल रही है। भारत में महानगरों से दूरस्थ गांवों तक टाइफाइड एक बड़ी महामारी के रूप में फैलता जा रहा है और दुखद यह है कि इससे निपटने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं बनाया गया। वर्ष 2023 के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में इस महामारी के 49 लाख से अधिक मामले सामने आए, जबकि 7850 लोगों की मौत हो गई। इनमें से लगभग 29 फीसदी 3.21 लाख बच्चे थे। आंकड़ों के अनुसार पांच साल से कम आयु के करीब 3.21 लाख बच्चों को टाइफाइड के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कुल भर्ती मरीजों का 44 फीसदी है। इस आयु वर्ग के 2600 बच्चों की मौत हो गई। वहीं पांच से नौ साल के करीब 2.65 लाख बच्चों को टाइफाइड के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लगभग 2900 बच्चों की जान गई।

दूषित पेयजल से महामारी बनता टाइफाइड

छह महीने से चार साल तक के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का जोखिम सबसे ज्यादा पाया गया। पहले तो अत्यधिक थकान और सुस्ती महसूस हो रही थी, फिर बुखार के साथ-साथ तेज सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शुरू हो गया। घर में रखी दवा बगैर डॉक्टर की सलाह के खा ली तो भूख लगना ही बंद हो गया और उल्टी-दस्त सा लगने लगा। लक्षण तो टाइफाइड के थे लेकिन पहली बार टेस्ट में उसकी पुष्टि हुई नहीं। फिर जांच करवाई तो पता चला आंतों में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन प्रक्रिया के जरिए तेजी से बढ़ रहा है और मियादी बुखार या टाइफाइड इस हाल में है कि मरीज को ठीक होने में कम से कम एक महीना लगेगा। आजकल टाइफाइड के लगभग सारे मरीजों से ऐसी ही कहानी सुनने को मिल रही है। भारत में महानगरों से दूरस्थ गांवों तक टाइफाइड एक बड़ी महामारी के रूप में फैलता जा रहा है और दुखद यह है कि इससे निपटने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं बनाया गया। वर्ष 2023 के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में इस महामारी के 49 लाख से अधिक मामले सामने आए, जबकि 7850 लोगों की मौत हो गई। इनमें से लगभग 29 फीसदी 3.21 लाख बच्चे थे। आंकड़ों के अनुसार पांच साल से कम आयु के करीब 3.21 लाख बच्चों को टाइफाइड के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कुल भर्ती मरीजों का 44 फीसदी है। इस आयु वर्ग के 2600 बच्चों की मौत हो गई। वहीं पांच से नौ साल के करीब 2.65 लाख बच्चों को टाइफाइड के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और लगभग 2900 बच्चों की जान गई। अध्ययन के मुताबिक छह महीने से चार साल तक के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु का जोखिम सबसे ज्यादा पाया गया। यह खुलासा लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गहन शोध में हुआ। सर्विलांस फॉर एंटरिक फीवर इन इंडिया (2017-2020), ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2021 और जुलाई 2025 तक प्रकाशित अध्ययनों की समीक्षा से तैयार ये अध्ययन विश्व प्रसिद्ध जर्नल द लैंसेट में रीजनल हेल्थ : साउथ ईस्ट एशिया के तरह प्रकाशित हुए हैं।एक बात और, तीन राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका प्रकोप अधिक है। यहां बीमारी के कुल मामलों के 29 प्रतिशत मरीज पाए गए। इन राज्यों में न सिर्फ संक्रमण ज्यादा दर्ज किया गया है, बल्कि एंटीबायोटिक प्रभावहीन रहने और मरने वालों की संख्या भी अधिक रहने की बात सामने आई है। हालात दो कारणों से भयावह हो रहे हैं, एक तो इस बीमारी के मूल कारक दूषित पेयजल और भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा, दूसरे, इस बीमारी का रामबाण इलाज कही जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं तेजी से बेअसर होती जा रही हैं। बच्चों में संक्रमण और मृत्यु दर अधिक होने से यह संकट और गहरा हो गया है। हाल ही में इंदौर में दूषित पेयजल से बहुत सी मौतें हुईं। उसी दौरान गुजरात के गांधीनगर में भी दूषित पेयजल से सैकड़ों लोग बीमार हुए और ये सभी टाइफाइड के ही शिकार थे। शहरी आबादी के बीच पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था खराब होना इस बीमारी के प्रसार का बड़ा कारण है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से गंदे पानी और दूषित भोजन से फैलता है। महानगरों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव, पुरानी और जर्जर पेयजल पाइपलाइनें, और सीवरेज सिस्टम का पेयजल लाइनों के साथ मिलना इस संक्रमण को घर-घर पहुंचा रहा है।

जब देश तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है और अधिकांश शहरीकरण अनियोजित है तो पीने का साफ पानी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही बगैर गुणवत्ता के सड़क के किनारे धूल और गंदगी में खुल रहे खाने-पीने के स्टाल बीमारी के प्रसार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यदि समय रहते दवा-प्रतिरोध, साफ पानी और स्वच्छता पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है. एक तो इस रोग से बचने के लिए टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन (टीसीवी) को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में प्रभावी ढंग से शामिल करना होगा, ताकि बच्चों को संक्रमण के शुरूआती चरण में ही सुरक्षा मिल सके। फिर हर घर जल या शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत अधिक लोगों तक पानी पहुंचाने के आंकड़े बढ़ाने से बेहतर होगा कि अभियानों को केवल पाइप पहुंचाने तक सीमित न रखकर, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और पाइपलाइनों के रखरखाव पर जोर दिया जाए। इसी तरह सड़क किनारे हो या बड़े रेस्टोरेंट, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम और सतत निरीक्षण करना होगा। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद-बिक्री पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। डॉक्टरों और मरीजों, दोनों को दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक करना होगा। टाइफाइड के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी हैं। यह बीमारी केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। दवाओं का बेअसर होना हमें उस दौर की ओर ले जा रहा है जहां सामान्य बीमारियां महामारी का रूप ले लेती थीं। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता और साफ पानी पर किया गया निवेश भविष्य में इलाज पर होने वाले भारी खर्च और जान-माल के नुकसान से कहीं सस्ता है। सरकार, समाज और चिकित्सा जगत को मिलकर इस मियादी संकट का समाधान खोजना होगा, अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी एक ऐसे भविष्य में कदम रखेगी जहां दवाएं तो होंगी, लेकिन वे बेअसर होंगी।

(लेखक स्तंभकार हैं। यह इनके निजी विचार हैं।)

इंडिया न्यूज
RNI NO. CHHIN/25/A2235
प्रकाशक, मुद्रक एवं कार्यकारी निदेशक **राकेश शर्मा** द्वारा मै. गुडमॉर्निंग इंडिया मीडिया प्रा. लिमिटेड के लिए गांव सद्दोपुर स्प्रिंग फील्ड पब्लिक स्कूल के सामने, अम्बाला-चंडीगढ़ हाइवे, अम्बाला-134004, हरियाणा से मुद्रित कराकर, एससीओ-349, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर-35बी चंडीगढ़ से प्रकाशित। **संपादक : राणा यशवंत***
*** पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी**

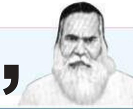

"साथ शत्रु मन प्रबुल है, जीवन मरण झकोर।
विषय विलास समास में, दुख सुख जन्म करोर।"

संपादकीय

बजट में फोकस

दुनिया जिस जियो-पॉलिटिकल उथल पुथल से गुजर रही है और उसकी वजह से देश के सामने जो मुश्किलें हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उनसे बाहर निकलने का एक रोडमैप पेश किया। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी जोर दिया गया है। सरकार ने जीडीपी में इसका योगदान 25% तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी तक 20% का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 6 प्रायॉरिटी क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इनमें सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, टेक्सटाइल और अर्बन इकॉनमिक क्लस्टर्स शामिल हैं। सरकार का फोकस डोमेस्टिक इकॉनमी को और मजबूत करने पर है, ताकि देश को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर एंप्लॉयमेंट को मजबूती देने के लिए भी सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनका पॉजिटिव असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। इसके साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का ध्यान बना हुआ है। वित्त वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10% की बढ़ोतरी के साथ 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। पिछले कई वर्षों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी की सरकार की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मजबूत ग्रोथ के लिए वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश बढ़ाना जारी रखेगी। इसके साथ स्ट्रैटेजिक पहलू को ध्यान में रखकर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ जैसे सेग्मेंट को बढ़ावा देने की बात भी सरकार ने कही है। कुछ समय पहले जिस तरह से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी, उसे देखते हुए यह पहल अहम है। बजट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, डेटा और क्लाउड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, जो तेजी से बदलती दुनिया और जियो-पॉलिटिक्स के लिहाज से अहमियत रखते हैं। बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की 7.4% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ बड़ी बात कही जा सकती है। वित्त वर्ष 2027 में सरकार ने ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान लगाया है, जो दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक होगी। इस बजट में ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण को लेकर भी पॉजिटिव घोषणाएं की हैं। वित्त वर्ष 2026 में डेफिसिट जहां जीडीपी का 4.4% रहा, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिहाज से यह आंकड़ा अहम है। रेटिंग मजबूत रहने से घरेलू कंपनियों-संस्थानों की कर्ज जुटाने की लागत कम रहती है।

आज का विचार

किसी राष्ट्र में स्त्रियों की स्थिति ही उसकी प्रगति का वास्तविक मापदंड है।

दादी के बाद अब पोते पर लटक विशेषाधिकार हनन का मामला

बाल मुकुंद ओझा

आजकल विशेषाधिकार की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। विपक्ष के ने राहुल गांधी पर इन दिनों विशेषाधिकार हनन की तलवार लटकी हुई 1978 में लोकसभा में पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के खिल विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की सदस्य भी चली गई और कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालां फिलहाल भाजपा ने इसे टाल दिया बताया। सरकार ने अब अपनी रणनी बदल ली है। कहा जाता है राहुल गाँधी का यही रवैया रहा तो आज नहीं कल उन्हें विशेषाधिकार हनन कासामना करना पड़ सकता है। आइये अ हम विशेषाधिकार और उसके हनन के बारे में चर्चा करते है। भारत संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कर्तव्यों का प्रभा ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार और छूट प्र की गई हैं। जब इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी भी त से सदन या उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उ विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की शुरुअ स्पीकर को लिखित नोटिस दिए जाने से होती है। नोटिस मिलने पर स्पीक तय करेंगे कि मामला विशेषाधिकार हनन का बनता है या नहीं। अ लोकसभा अध्यक्ष नोटिस स्वीकार करते हैं तो उसे विशेषाधिकार समिति पास भेजा जा सकता है।

लोकसभा में यह समिति आम तौर पर 15 सांसदों की होती है, जब राज्यसभा में 10 सांसदों की। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिप लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट को सदन में रखा जाए और फिर सदन तय करेगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर स्पीक मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं। अपनी जांच पूरी करने बाद समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे सदन के पटल पर रख है। दोषी पाए जाने पर भी समिति खुद सजा नहीं देती बल्कि सजा सिफारिश करती है। विशेषाधिकार समिति दोषी पाए जाने पर दोषी सद को चेतावनी देने या फटकार लगाने की सिफारिश कर सकती है। अ ज्यादा गंभीर नहीं लगे तो समिति उन्हें सदन में बिना शर्त माफी मांगने खेद जताने का निर्देश दे सकती है। मामला गंभीर लगने पर समिति उ कुछ दिनों या पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से अलग रखने सिफारिश कर सकती है। बेहद गंभीर मामलों में समिति सदस्यता रद्द क की भी सिफारिश कर सकती है। इसे सदन में वोटिंग के जरिए लागू कि जाता है। जेल की बेहद ही गंभीर मामलों में सदन संबंधित सांसद कारावास की सजा भी सुना सकता है। हालांकि ऐसा दुर्लभ मामलों में होता है। पहले भी विशेषाधिकार हमले की गाज कई लोगों पर गिर चुकी इनमें देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता भी शामिल है। लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने इंदिरा गांधी को 1975 के एक मामले में सदन अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया था। इस मामले में सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की गई बल्कि सत्र खत्म होने तक उन्हें जेल भेजा गया था। इमरजेंसी के दौरान सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप ल कि उन्होंने विदेश में रहकर भारत विरोधी प्रचार किया और सदन की गरि को ठेस पहुंचाई। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर उ राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसद में सवाल पूछने के बद पैसे लेने के स्टिंग में फंसे 11 सांसदों की सदस्यता एक झटके में ख कर दी गई थी। विशेषाधिकार समिति और पवन बंसल समिति सिफारिशों के आधार पर सदन ने इसे सदन की अवमानना माना था। स के अंदर दिए गए बयानों पर अदालती कार्यवाही नहीं होती, लेकि विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जा सकती है। इस मामले में अध्य का निर्णय सर्वोपरि होता है।

हज योग संदेश

श्री सद्गुरु देव जी की अनुभव वाणी

ज्ञान युक्ति भक्ति करे, तीक्षण ले बैराग।
कृतकृत्य व हंस सो सद्गुरु पद अनुराग।

जारी

महर्षि सदाफल देव जी महाराज

जगमार्ग के शानदार 13 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता की उज्ज्वल यात्रा

डॉ. सुभाष चंद्र गर्ग 'पार्थ'

सी भी समाचार पत्र का जीवन केवल वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, ल्कि उस साहस, प्रतिबद्धता और जनविश्वास से आँका जाता है जो वह माज के बीच अर्जित करता है। जगमार्ग के तेरह वर्ष इसी कसौटी पर एक शक्त, प्रेरक और गौरवपूर्ण यात्रा के परिचायक हैं। यह केवल एक प्रकाशन वर्षगाँठ नहीं, बल्कि जनचेतना, जनभागीदारी और जनसरोकारों की सतत धना का उत्सव है। पत्रकारिता का मूल धर्म सत्ता से प्रश्न करना, समाज आवाज़ बनना और सत्य को निर्भीकता से सामने रखना है। जगमार्ग ने पने आरंभ से ही इस सिद्धांत को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे वहार में उतारकर दिखाया। जब भी जनहित के मुद्दे उपेक्षित हुए, जब भी म नागरिक की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, तब इस पत्र ने निर्भीकता उन प्रश्नों को उठाया जिनसे व्यवस्था को आत्ममंथन करना पड़ा। यही रण है कि यह समाचार पत्र केवल पाठकों तक समाचार पहुंचाने का ध्यम नहीं रहा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय सहभागी बना। इन ह वर्षों में जग मार्ग ने पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए हैं। स्थानीय मस्याओं से लेकर राष्ट्रीय विमर्श तक, ग्रामीण सरोकारों से लेकर युवा कांक्षाओं तक,हर विषय को संवेदनशीलता और तथ्यपरकता के साथ तुत करना इसकी विशिष्ट पहचान रही है। विशेष रूप से जनहित से जुड़े द्दों, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता, पर्यावरण, और सामाजिक न्याय इसकी सतत दृष्टि ने इसे विश्वसनीयता का प्रतीक बनाया है। आज जब चना का प्रवाह तीव्र है और समाचार माध्यमों पर तात्कालिकता का दबाव ढ़ गया है, तब भी जग मार्ग ने संतुलित और जिम्मेदार पत्रकारिता का हरण प्रस्तुत किया है। सनसनी से दूरी और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन चुनिंदा पत्रों में स्थान दिलाया है जिन पर पाठक विश्वास करते हैं। ही विश्वास किसी भी मीडिया संस्थान की सबसे बड़ी पूँजी होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस पत्र ने युवा पत्रकारों को मंच देकर नई पीढ़ी की चारशक्ति को दिशा दी है। नई सोच, नई भाषा और नए दृष्टिकोण के साथ कारिता को समृद्ध करने का जो प्रयास जग मार्ग ने किया है, वह भविष्य मीडिया परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तेरह वर्ष का पड़ाव एक उपलब्धि अवश्य है, परंतु यह मंज़िल नहीं, एक नए अध्याय प्रारंभ है। आने वाले वर्षों में चुनौतियाँ भी होंगी और अवसर भी। डिजिटल में सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखना, जनसरोकारों को केंद्र में रखना र सत्यनिष्ठा के मानदंडों को और ऊँचा उठाना,ये सभी लक्ष्य इसके सामने विश्वास है कि जग मार्ग अपनी परंपरा के अनुरूप इन चुनौतियों को वसर में बदलते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में और ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा। अंततः, वर्षगाँठ केवल संस्थान की नहीं, बल्कि उन पाठकों की भी है जिन्होंने इसे पनाया, सराहा और सशक्त बनाया। जनसमर्थन ही वह शक्ति है जिसने ग मार्ग को एक समाचार पत्र से आगे बढ़ाकर एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया है। जगमार्ग के संस्थापक श्री रमेश सिंघल जी तथा मैनेजिंग यरेक्टर श्री अमित सिंघल जी को इस गौरवपूर्ण अवसर पर हार्दिक बधाई एवं लमय शुभकामनाएँ। जगमार्ग के इस गौरवपूर्ण 14वें वर्ष के प्रवेश पर हार्दिक भकामनाएँ, सत्य की यह यात्रा निरंतर, निर्भीक और जनोन्मुखी बनी रहे।

लेखक चिकित्सक एवं सामाजिक चिंतक हैं।

भारत एआई अनुप्रयोग भंडार

प्रभाव के लिए संदर्भ-नवाचार के पैमाने का विस्तार

एन दयासिंधु व ऋषिकेश टी कृष्णन

भारत में एआई की अंतिम सफलता इसके जीपीयू क्लस्टरों के आकार से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि हमारे एआई अनुप्रयोग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार ला सकते हैं - उदाहरण के लिए, जब एआई आशा कार्यकर्ताओं को उच्च जोखिम वाली गर्भवती स्त्रियों का पता लगाने में मदद करता है, या छोटे किसानों को कीटनाशक की खपत पर महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद करता है, या एक दूर-दराज स्थित सरकारी स्कूल के बच्चे की पढ़ाई और गणित में अंक बढ़ाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 इस बात में व्यावहारिक है कि भारत एआई का लाभ कैसे उठा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय एआई आर्थिक परिषद ने प्रस्ताव किया है कि एआई का प्रमुख उद्देश्य मानव प्रधानता और आर्थिक हित पर आधारित है। इस बात में स्पष्टता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एआई अपनाने की नीति को मानव कल्याण और आर्थिक समावेश में सहायक होना चाहिए। एआई को घरेलू आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और एआई अपनाने के लाभ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और सभी नागरिकों तक पहुँचने चाहिए। सौभाग्य से, हमारे लिए, भारतीय नवोन्मेषक ऐसे एआई अनुप्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करते हैं, जो तात्कालिक तौर पर और भारत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी प्रबंधन और आपदा तैयारी से जुड़े अनुप्रयोग आशाजनक हैं। सही समर्थन के साथ, इनमें से कई अनुप्रयोगों का पूरे भारत में विस्तार किया जा सकता है और भविष्य में इन्हें भारत एआई अनुप्रयोग भण्डार में शामिल किया जा सकता है, और यहां तक कि इन्हें वैश्विक बाजारों में भी ले जाया जा सकता है। आइए कुछ रोचक पहलों पर नजर डालें। स्वास्थ्य देखभालः निरामई ने बिना किसी दवा-सुई वाला (नॉन-इनवेसिव), गोपनीयता के प्रति जागरूक स्तन कैंसर जांच उपकरण विकसित किया है, जो पारंपरिक मैमोग्राफी के बजाय एआई-संचालित थर्मल इमेजिंग का उपयोग करता है। यह उपकरण सभी उम्र की महिलाओं में असामान्य स्थिति का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिसमें घने स्तन ऊतक भी शामिल हैं जहां मैमोग्राफी अक्सर विफल हो जाती है। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक और किफायती है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच को व्यावहारिक बनाता है। त्त्ह्वह्द्र.ड्डढ्ढ एक एआई उपकरण है, जो सेकंडों में एक्स-रे और सीटी स्कैन का विश्लेषण करता है, टीबी, फेफड़ों के कैंसर और दिल की समस्या जैसी 35 से अधिक स्थितियों का पता लगाता है। यह समाधान संसाधन-सीमित परिस्थितियों में बहुत प्रभावी है जहां रेडियोलॉजिस्ट अनुपलब्ध हैं तथा दूरदराज के जिलों में तेजी से प्राथमिक परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं। एआईस्टेथ, एक एआई-संचालित स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ों को सटीक, दूरस्थ निदान के लिए दृश्य तरंग रूपों में बदल देता है। यह किफायती उपकरण 93% सटीकता के साथ ग्रामीण भारत में स्वास्थ्यकर्मियों को शुरुआती दौर में ही हृदय और श्वसन समस्याओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह विशेषज्ञ देखभाल में मौजूद महत्वपूर्ण कमी को समाप्त करता है और इसमें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की क्षमता है। कृषिः न्योपर्क एक हल्का-फुल्का उपकरण है, जो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके पारंपरिक लैब रसायनों के बिना तुरंत मिट्टी के स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है। यह पांच मिनट से कम समय में 12 प्रमुख मृदा-मानकों पर लैब-सटीक परिणाम प्रदान करता है। यह किसानों को उर्वरक के उपयोग पर डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और इनपुट खर्च में कमी आती है। वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्थान का कॉटनऐस एक एआई -आधारित मोबाइल ऐप है जो किसानों को जाल में पकड़े गए कीड़ों के फोटो अपलोड करने की सुविधा देता है और कीटनाशक के उपयोग को लेकर तत्काल, स्थान-अनुकूल सलाह प्राप्त करता है। यह ऐप हज़ारों छोटे कपास किसानों को पिंक बुलवर्म जैसे कीड़ों से अपनी फसल की रक्षा करने में मदद करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की फसल मिलती है और आय में वृद्धि होती है। निको रोबोटिक्स एआई -संचालित रोबोट का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर विज़न (दिन और रात वाले कैमरे) से लैस हैं, ताकि वास्तविक समय में कीड़े और खरपतवार की पहचान की जा सके। यह प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव को सक्षम बनाता है तथा इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि रसायनों का उपयोग केवल आवश्यक जगहों पर ही किया जाएगा। इससे कीटनाशकों के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी आई है (कुछ मामलों में 60-90% तक), जिससे किसानों की लागत घटती है और पर्यावरण विषाक्तता कम होती है। क्रॉपिन एक एआई-सक्षम डिजिटल इकोसिस्टम है जो खेत की निगरानी, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण और किसान सहभागिता तक फैला हुआ है। यह स्थायी उत्पादकता और जलवायु-अनुकूल निर्णयों को बढ़ावा देता है, हिस्सों में बंटी प्रथाओं को अनुमान-योग्य कृषि प्रणालियों में बदल देता है, जिसका वैश्विक स्तर विस्तार किया जा सकता है। शिक्षाः पढ़ाईविदएआई एक एआई-संचालित व्यक्तिगत ज्ञान-प्राप्ति प्लेटफार्म का उपयोग करता है, जिसे सरकारी स्कूलों में गणित सीखने के कमजोर परिणामों में को सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केवल छह सप्ताह में, इस पहल ने उत्तीर्ण होने की दर और उच्च-प्राप्त करने वालों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किया। यह ग्रामीण भारतीय शिक्षा में सीखने के अंतर को पाटने के लिए एक ऐसे मॉडल के रूप में काम करता है, जिसके पैमाने का विस्तार किया जा सकता है। राकेट लर्निंग के पास अप्पू (एक जनरेटिव एआई हाथी) नामक एआई संचालित शिक्षा साथी है, जो माता-पिता और बच्चों के साथ व्हाट्सएप के जरिए संवाद करता है। यह छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और अंकगणित कौशल प्राप्त करने में मदद करने के लिए छोटे-छोटे, खेल-आधारित गतिविधियाँ प्रदान करता है। बेलगावी स्मार्ट सिटी अपने सार्वजनिक पुस्तकालय में डीप लर्निंग-सक्षम ई-बुक्स को एकीकृत कर रहा है। उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने और कहानी की रूपरेखा, शब्दावली और कठिनाई स्तर को वास्तविक समय में अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन की गई इन किताबों ने सहभागिता और समझ के स्तर में सुधार किया है। केवल दो सप्ताह में पढ़ने की गति में 12% वृद्धि हुई है। सरकार इन जमीनी स्तर पर केंद्रित एआई नवाचारों के लिए एक शक्तिशाली इकोसिस्टम आयोजक बन सकती है और इन्हें पूरे भारत में उच्च-प्रभाव वाले अनुप्रयोगों तक विस्तार करने में मदद कर सकती है। सरकार का एक मुख्य ध्यान इन एआई अनुप्रयोगों के लिए बाजार बनाने में सहायता करना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार खरीद की सुविधा प्रदान कर सकती है, जहां सूचीबद्ध घरेलू एआई अनुप्रयोग सरकार (राज्य सरकार सहित) के विभागों, अस्पतालों, स्कूलों आदि के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि में एआई के लिए मानक स्थापित करके, सरकार एक विश्वसनीय वातावरण बना सकती है, ताकि ग्राहक और नागरिक इन्हें आसानी से अपना सकें। एक बार जब ये एआई अनुप्रयोग खुद को साबित कर लेते हैं, तो सरकार सबसे प्रभावशाली अनुप्रयोगों को भारत एआई अनुप्रयोग भंडार में एकीकृत करने में सुविधा प्रदान कर सकती है - यानी, ऐसे समाधान जो भारत के पैमाने और विविधता के लिए बनाए गए हैं और विश्व स्तर पर उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय एआई अनुप्रयोग भंडार के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय शासन रूपरेखा, जो यूरोपीय जीडीपीआर जैसी अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ मेल खाती हो, इस भंडार को कई देशों में तुरंत शुरू करने (प्लग-एंड-प्ले) के योग्य बना सकता है। **लेखक (ऋषिकेश टी कृष्णन आईआईएम बैंगलोर में रणनीति के प्रोफेसर हैं। एन दयासिंधु इतिहास रिसर्च एंड डिजिटल के सह-संस्थापक और सीईओ हैं।)**

एफआईआर न्याय पाने का दस्तावेज कम और डराने का औजार ज्यादा

वर्दी का सौदा: जब कानून ब्लैकमेल की भाषा बोलने लगे

डॉ. प्रियंका सौरभ

याणा पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर का निलंबन महज़ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उस सड़ांध की र इशारा करता है जो वर्दी के भीतर चुपचाप फैल रही है। रोप है कि एक कॉलोनाइज़र को तंत्र-विद्या के जाल में ाकर, एफआईआर रद्द कराने के बदले शारीरिक संबंध ाए गए और बाद में डर व ब्लैकमेल के सहारे एक लाख ये की 'मंथली' मांगी गई। यदि ये आरोप सही साबित हैं, तो यह मामला केवल व्यक्तिगत नैतिकता या चरित्र सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे आपराधिक न्याय तंत्र की श्वसनीयता पर गहरा सवाल खड़ा करता है। यह घटना लिए भी अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तीन कतवर हथियार एक साथ इस्तेमाल हुए—वर्दी की सत्ता, धविश्वास का भय और कानून का डर। भारत में तंत्र-मंत्र, ा-टोटका और अंधविश्वास आज भी केवल अशिक्षा या छड़ेपन का प्रतीक नहीं हैं। बड़े शहरों, पढ़े-लिखे समाज र आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग में भी डर के क्षणों में विवेक जोर पड़ जाता है। जब इस डर को कोई वर्दीधारी धिकारी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, तो पीड़ित क्ति मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से पूरी तरह हाय हो जाता है। यह मान लेना भूल होगी कि यह कोई केला या अपवादात्मक मामला है। देश के अलग-अलग सों से समय-समय पर पुलिस और प्रभावशाली तंत्रों की ठ-गाँठ के मामले सामने आते रहे हैं। कहीं जमीन विवाद केस दर्ज करने की धमकी देकर पैसे वसूले जाते हैं, कहीं या धोखाधड़ी के मामलों में 'सेटिंग' के नाम पर देबाज़ी होती है। कई बार आरोपी और फरियादी दोनों ही के चक्कर काटते हैं, यह जानते हुए कि न्याय नहीं, झौता ही अंतिम रास्ता है। इस मामले में एक अहम बात यह भी है कि आरोप एक महिला अधिकारी पर हैं। समाज अक्सर यहीं आकर भटक जाता है। बहस अपराध की बजाय महिला-पुरुष, नैतिकता और चरित्र पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आरोपी महिला है या पुरुष। सवाल यह है कि क्या वर्दी पहनते ही कोई व्यक्ति कानून से ऊपर हो जाता है? कानून का तकाज़ा यह नहीं कि हम आरोपी के लिंग पर बहस करें, बल्कि यह है कि सत्ता के दुरुपयोग को बिना किसी संकोच के बेनकाब किया जाए। कानून के सामने लिंग, जाति, पद या प्रभाव नहीं—सिर्फ़ अपराध मायने रखता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह अपराध सिर्फ़ ब्लैकमेल या भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि न्याय की अवधारणा पर सीधा हमला है। यह उस भरोसे का कत्ल है, जो आम नागरिक पुलिस और प्रशासन पर करता है। आज एफआईआर आम आदमी के लिए सुरक्षा की गारंटी कम और डर का प्रतीक ज़्यादा बनती जा रही है। एक काग़ज़, कुछ धाराएँ और कुछ हस्ताक्षर—और पूरा जीवन शक, बदनामी और भय में बदल जाता है। नौकरी खतरे में पड़ जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और परिवार मानसिक दबाव में आ जाता है। जब इसी डर को सौदे की शक्ल दे दी जाती है, तब कानून न्याय का माध्यम नहीं, बल्कि बाज़ारू हथियार बन जाता है। इस मामले में एक लाख रुपये की मंथली माँग यह साफ़ करती है कि यह कोई भावनात्मक या क्षणिक चूक नहीं थी, बल्कि सुनियोजित वसूली का तंत्र था। भारत में ऐसे 'मंथली सिस्टम' किसी से छिपे नहीं हैं। अवैध शराब, खनन माफिया, कॉलोनाइज़र, सट्टा-जुआ—हर जगह एक तय रेट, एक तय तारीख और यह भरोसा कि 'सब मैनेज है।' अगर आरोप सही हैं, तो यह मानना कठिन है कि यह सब एक व्यक्ति के बूते पर हो रहा था। असली परीक्षा इस बात की है कि जाँच कितनी निष्पक्ष, कितनी गहरी और कितनी ईमानदार होती है। दुर्भाग्य से, ऐसे मामलों में निलंबन को ही सबसे बड़ी कार्रवाई बताकर पेश कर दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि निलंबन कोई सज़ा नहीं, बल्कि सिर्फ़ एक अस्थायी विराम है। कई बार जांच लंबी चलती है, सबूत कमजोर पड़ते हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि जाँच समयबद्ध हो, कॉल डिटेल्स, बैंक लेनदेन, संपत्ति और संपर्कों की पूरी पड़ताल की जाए और दोष सिद्ध होने पर बर्खास्तगी के साथ आपराधिक मुकदमा भी चले। यह मामला केवल पुलिस सुधार या प्रशासनिक जवाबदेही तक सीमित नहीं है। यह समाज को भी आईना दिखाता है। जब हम अंधविश्वास को पालते हैं, जब हम डर के आगे विवेक गिरवी रख देते हैं और जब हम 'किसी तरह बच निकलने' की मानसिकता को सामान्य मान लेते हैं, तब ऐसे सौदे पनपते हैं। कानून तभी मज़बूत होगा, जब नागरिक डर के बजाय अधिकार की भाषा बोलना सीखेंगे। आज डर एक कॉलोनाइज़र को था। कल यह डर किसी शिक्षक, किसी कर्मचारी, किसी छोटे व्यापारी या किसी आम नागरिक को हो सकता है। अगर कानून के रक्षक ही डर का व्यापार करने लगें, तो समाज न्याय नहीं, समझौते खोजने लगता है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। यह मामला चेतावनी है कि वर्दी जितनी ऊँची होती है, जवाबदेही उतनी ही भारी होनी चाहिए। वर्दी सम्मान का प्रतीक है, सौदेबाज़ी का लाइसेंस नहीं। अगर समय रहते ऐसे मामलों पर सख़्ती नहीं हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब थानों में कानून की भाषा नहीं, बल्कि ब्लैकमेल की बोली आम हो जाएगी। और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि दोषी कौन है, बल्कि यह होगा कि क्या इस देश में सचमुच न्याय नाम की कोई चीज़ बची है?

दाढ़ी पर नहीं, सोच पर बहस जरूरी

डॉ. सत्यवान सौरभ

हर दौर की अपनी पहचान होती है। यह पहचान केवल कपड़ों, हेयर-स्टाइल या चेहरे पर उगे बालों से नहीं बनती, बल्कि उस सोच से बनती है जो व्यक्ति और समाज—दोनों को दिशा देती है। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे कैसे दिखते हैं यह कम, और क्या सोचते हैं तथा किसका अनुकरण करते हैं—यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बाहरी आकर्षण, सोशल मीडिया की चमक और तात्कालिक लोकप्रियता ने पहचान की परिभाषा को सतही बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में दाढ़ी को लेकर एक तीखी बहस उभरी है। कुछ लोग इसे आधुनिक फैशन का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे सांस्कृतिक भ्रम और अंधानुकरण का उदाहरण। यह बहस तब और जटिल हो जाती है जब इसे धर्म, राजनीति या साज़िश से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर, शोर से दूर रहकर, विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टि से इस विषय को देखें। क्योंकि जब मुद्दे विचार के बजाय पहचान की लड़ाई बन जाते हैं, तब समाधान नहीं, विभाजन पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि दाढ़ी और क्लीन शेव—दोनों ही भारतीय समाज का हिस्सा रहे हैं। वैदिक काल के ऋषि-मुनि जटाधारी थे, तो राजदरबारों में सुसज्जित, साफ़-सुथरे व्यक्तित्व भी दिखाई देते थे। मध्यकाल हो या आधुनिक काल—हर युग में दोनों प्रकार के रूप साथ-साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित नेहरू—सभी का रूप अलग था, पर उद्देश्य एक। स्पष्ट है कि दाढ़ी कोई नई या बाहरी चीज़ नहीं है, और न ही क्लीन शेव कोई विदेशी अवधारणा। दोनों ही समय, परिस्थिति और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार बदलते रहे हैं। आज दाढ़ी का चलन केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक फैशन का हिस्सा बन चुका है। हॉलीवुड, यूरोपीय फैशन, खेल जगत, संगीत उद्योग और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स—हर जगह दाढ़ी अलग-अलग शैलियों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया ने इन रुझानों को और तेज़ कर दिया है। एक तस्वीर, एक वीडियो या एक रील के ज़रिये ट्रेंड पल भर में दुनिया भर में फैल जाते हैं। ऐसे में यह मान लेना कि कोई एक उद्योग, समूह या विचारधारा ही किसी फैशन को 'फैला' रही है, वास्तविकता का सरलीकरण होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अंधानुकरण एक गंभीर समस्या बन चुका है। जब युवा किसी भी ट्रेंड को बिना सोचे-समझे केवल इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय है या 'कूल' माना जा रहा है, तब उनका व्यक्तित्व उधार हो जाता है। फैशन तब समस्या बनता है जब वह सोच पर हावी हो जाए पहचान को केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित कर दे। सवाल दाढ़ी रखने न रखने का नहीं है; सवाल यह है कि क्या हम अपने चुनाव के कारण ज हैं, या सिर्फ़ भीड़ के साथ चल रहे हैं? इस संदर्भ में सिनेमा और डिजि मीडिया की भूमिका पर चर्चा ज़रूरी है। मनोरंजन उद्योग न केवल कहा सुनाता है, बल्कि जीवन-शैली के मानक भी गढ़ता है। बार-बार एक ही के 'लुक', 'स्टाइल' और 'हीरोइज़्म' को आदर्श बनाकर प्रस्तुत क से युवाओं के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं। इससे विविधता कम होत और एकरूपता बढ़ती है। जिम्मेदार मीडिया वही है जो समाज की बहुलता दिखाए—जहाँ सादगी भी आकर्षक हो, और अलग-अलग व्यक्तित्व स्वीकार्य हों। लेकिन दर्शक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम दि और मूल्य में अंतर करना सीखें। ईश्वर, संस्कृति और सौंदर्य की चर्चा म संतुलन आवश्यक है। हमारी परंपराएँ अत्यंत विविध रही हैं। कहीं जटा तपस्वी हैं, तो कहीं सुसज्जित देव-प्रतिमाएँ; कहीं वैराग्य है, तो कहीं श्रृं सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि आचरण, करुणा, संयम विवेक है। यदि हम सौंदर्य को केवल चेहरे, दाढ़ी या फैशन तक सीमित दें, तो हम अपनी ही सांस्कृतिक गहराई को कम कर देते हैं। आज के युव के सामने असली खतरा किसी एक फैशन से नहीं, बल्कि आत्मबोध की से है। जब युवा अपने इतिहास, मूल्यों और सांस्कृतिक बहुलता को सम हैं, तब वे किसी भी ट्रेंड को अपनाएँ—या न अपनाएँ—वह उनका सजग स्वतंत्र निर्णय होता है। लेकिन जब पहचान केवल बाहरी प्रतीकों पर जाती है, तब भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता समाधान डर, आरोप या साज़िश की भाषा में नहीं है। समाधान शिक्षा, स और आत्मविश्वास में है। युवाओं को यह समझाना ज़रूरी है कि फै क्षणिक होता है, लेकिन चरित्र स्थायी। आज जो ट्रेंड है, कल बदल जाए पर जो मूल्य आप अपनाते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए च सोच-समझकर होना चाहिए—न दबाव में, न डर में, और न ही अंधानुक में। समाज को विभाजन की भाषा से भी सावधान रहना चाहिए। जब किसी चलन को डर या साज़िश के चश्मे से देखते हैं, तो संवाद बंद हो ज है और ध्रुवीकरण बढ़ता है।

जनसंपादकीय

प्रेम कोई बंधन नहीं

चित्रा माली

मनुष्य के मनोभावों में से एक प्रेम है जो मानवीय जीवन का आधारभूत तत्व है। प्रेम विहीन सृष्टि या कहें दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। गांधी जी प्रेम के सार्वभौमिक नियम में विश्वास करते थे,वे किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते थे। उनके अनुसार प्रेम सृष्टि का नियम है, प्रेम हमेशा देता है, प्रेम स्वयं पीड़ा भोगता है, कभी दोष प्रकट नहीं करता,कभी बदला नहीं लेता। हमारी जनरेशन ने प्रेम के विचार को कई भावानुवादों से जाना समझा है जिसमें आदर,सम्मान,देखभाल,विश्वास,
दोस्ती और प्रतिबद्धता समाहित है। इसके अतिरिक्त प्रेम के विचार को साहित्य की अलग अलग विधाओं और सिनेमा जिसकी परिधि में हमेशा प्रेम रहा है पढ़कर,सुनकर और देखकर समझा है और उसके प्रतिरोधी स्वरूप को भी जाना है। समाज-वैज्ञानिक प्रेम के विषय में गहन और व्यापक विचार-विमर्श कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रेम की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर प्रेम अपनी आत्मनिष्ठता के बावजूद वस्तुनिष्ठ संरचनाओं (कास्ट,क्लास, जेंडर, सत्ता, उत्पादन संबंध और बाजार) से भी प्रभावित होता है। समाज-विज्ञान के विकास से पूर्व प्रेम जैसे विषयों पर केवल साहित्य और दर्शन में ही चर्चा होती थी। साहित्य की तमाम विधाओं में प्रेम को सार्वभौम माना जाता था लेकिन समाज - विज्ञान अलग-अलग संस्कृतियों,समाजों,सामाजिक संरचनाओं के चलते प्रेम के एक रूप को स्वीकार नहीं करता है। प्रेम के आधुनिक विमर्श में उसका वर्गीकरण छह श्रेणियों में किया गया है। श्रेणियों के नामकरण प्राचीन यूनानी दर्शन के पदों पर आधारित है। प्रेम की पहली श्रेणी 'इरोज'है जो काम का यूनानी देवता है। इससे जाहिर होता है कि इरोज के नाम से जो प्रेम की श्रेणी है उसमें दैहिकता की प्रधानता है इसलिए इसे ऐंद्रिक प्रेम भी कहा जा सकता है। प्रेम की दूसरी श्रेणी 'मैनिया' है। यह एक तरह का उन्मादी प्रेम है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेमी/प्रेमिका के पीछे दीवाना हो जाता है। अपने प्रेमी/प्रेमिका पर कब्जा करने की इच्छा रखने वाला प्रेम हिंसक भी हो सकता है। कभी कभी एकतरफा प्रेम होने के कारण इसके दुष्परिणाम घोर आपराधिक कृत्यों में भी सामने आते हैं। प्रेम की तीसरी श्रेणी 'स्टोर्ज' की होती है। जिसका विकास धीरे- धीरे शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय में होता है। प्रेम की चौथी श्रेणी को 'एगैप' यानी परोपकार प्रधान प्रेम जिसमें व्यक्ति प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता और अपने प्रेमी/प्रेमिका को अधिक से अधिक देना चाहता है। प्रेम की पांचवी श्रेणी 'प्रैग्मा' यानी व्यावहारिक और परिणामवादी प्रेम। इसमें व्यक्ति अपने साथी की खूबी या सामाजिक आर्थिक स्थिति और उपलब्धियों पर फिदा हो जाता है। प्रेम की छठी श्रेणी 'लुडुस' जो अत्यंत अल्पकालीन और क्षणिक है। इसमें किसी को अपने मकसद के लिए बहलाना,फुसलाना और मकसद पूरा हो जाने पर अलग हो जाना शामिल है। प्रेम की इन छह श्रेणियों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार रोमानी प्रेम का है जिसमें रोमानी,ऐंद्रिक और उन्मादी प्रेम को शामिल किया जा सकता है जिसकी जमीन भावपूर्ण,कामनाप्रधान और तर्क से परे होती है। दूसरा प्रकार सहचर-उन्मुख प्रेम का है जो अधिक सचेत और जागरूक मानी जाती है जिसकी समझ अपेक्षाकृत समझ-बूझ कर अपना साथी चुनने के लिए बनती है। प्रेम की श्रेणी विभाजन का यह कतई मतलब नहीं है कि कोई भी प्रेमी/प्रेमिका प्रेम किसी एक श्रेणी के ही होकर रह जाते हैं। उनकी भावना,उनके मनोभाव समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं तो भले ही उनके प्रेम की शुरूआत ऐंद्रिकता से हुई हो लेकिन मैत्रीपूर्ण या परोपकार प्रधान प्रेम के रूप में भी विकसित हो सकती है। इसी के साथ कोई एक व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के साथ अलग-अलग किस्म का प्रेम भी कर सकता है। एक के लिए उसके मन में ऐंद्रिक प्रेम हो सकता है और दूसरे के लिए परोपकारी प्रेम भी विकसित हो सकता है। प्रेम को और अधिक विस्तृत रूप से मनोविज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग और उनके साथियों की मान्यता है कि रोमानी प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति अचानक पैदा हुए अनकॉन्सस अट्रैक्शन से उपजता है। युंग के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के दो हिस्से होते है सचेत (कॉन्शस) और अचेत (अनकॉन्स)। आम तौर पर पुरुष के भीतर का हिस्सा स्त्री लिंग की ओर स्त्री के भीतर पुरुष लिंग की नुमाइंदगी करता है। कार्ल युंग के इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब किसी के प्रति अचानक आकर्षण महसूस करता है तो वह अपनी ही चेतना के उस हिस्से से प्रेम कर रहा होता है जिसके बारे में उसे पता नहीं है और उसके भीतर मौजूद विपरीत जेंडर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पुरुष का यह अवचेतन उसकी मां से और स्त्री का अवचेतन उसके पिता से प्रभावित होगा। प्रेम के स्त्री-पुरुष के लैंगिक आयामों की कई धारणाएं है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले अधिक रोमांटिक होती हैं यह बताया गया है और पुरुष सोच समझकर प्रेम में पड़ता है यह बताया गया है। लेकिन यह धारणा अनुसंधान पर खरी नहीं उतरती है। अनुसंधान बताते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ऐंद्रिक या उन्मादी प्रेम में कम पड़ती हैं वे मैत्रीपूर्ण और परिणामवाद प्रेम की तरफ झुकती है। इसके सामाजिक कारण भी है,स्त्री स्थायित्व और सुरक्षा चाहती है। प्रेम में विफल होने पर स्त्री को सामाजिक तौर पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंथनी गिडेंस ने उत्तर-आधुनिक युग के लिए रोमानी प्रेम के बरक्स संगमी प्रेम की अवधारणा प्रतिपादित की है। संगमी प्रेम (कॉनफ्लुएंट लव) इस प्रेम में स्त्री/पुरुष अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखते हुए साथ रहते है ठीक दो नदियों के समान जो साथ साथ बहती हैं और एक खास मुकाम पर एक-दूसरे के साथ संगम करती है और फिर अपने अपने रास्ते पर बहती चली जाती हैं। इरिगरे ने प्रेम विमर्श में स्व-प्रेम की धारणा को विकसित किया। इरिगरे तर्क देती हैं कि स्व-प्रेम ही द्विपक्षीयता की कुंजी है। दोनों पक्षों को एक-दूसरे से प्रेम करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना ही होगा। प्रेम करने वालों को पता होना चाहिए कि अलग कैसे हुआ जाता है और फिर साथ कैसे आया जाता है। इन सभी विमर्शों और सिद्धांतों पर बात करने का आशय महज इतना है कि हम समाज-विज्ञान के प्रेम विमर्श और खासकर युवाओं के मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझ सकें और नई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सकें। वैसे प्रेम की सभी श्रेणियों को फिल्मों में भी दशार्या गया है। अभी हाल में सैयारा फिल्म युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हुई है जिसमें प्रेम की रोमानी,ऐंद्रिक उन्मादी और 'एगैप' सभी श्रेणियां मौजूद हैं। नफरत के इस दौर में आवश्यक है कि प्रेम,मोहब्बत और इश्क के पैगाम को फैलाया और विस्तृत किया जाए जो मानव,मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

संगमी प्रेम (कॉनफ्लुएंट लव) इस प्रेम में स्त्री/पुरुष अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखते हुए साथ रहते है ठीक दो नदियों के समान जो साथ साथ बहती हैं और एक खास मुकाम पर एक-दूसरे के साथ संगम करती है और फिर अपने अपने रास्ते पर बहती चली जाती हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

(वेलेंटाइन डे की भावना में कोई दोष नहीं है। दोष तो केवल एक दिवसीय उत्सव की उस संस्कृति में है, जो सारी बर्जनाओं को ध्वस्त करके एक बड़े बाजार की संस्कृति का हिस्सा बन रही है। भारतीय संस्कृति में प्रेम कभी भी प्रदर्शन का विषय नहीं रहा। यहाँ का प्रेम कर्तव्य,मयार्दा और दीर्घकालिक सीमाओं से जुड़ा रहा है। माता-पिता का त्याग,गुरु का मार्गदर्शन और जीवनसाथी का अटूट रिश्ता सदैव प्रेम और समर्पण का भाव अभिव्यक्त करते रहे हैं। इसलिए यदि वेलेंटाइन डे के वर्तमान विस्तारित स्वरूप को रोकना है तो हमें अपने परिवारों के स्नेह व प्रेम से बंचित होती संस्कृति पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा।)

प्रेम से अधिक बाजार का उत्सव

विशेष

डा. विशेष गुप्ता

वेलेन्टाइन डे पर आर्चीज के मँहगें कार्डस, गुलाब के फूलों की दुनिया, होटल, रेस्ट्रा, पब यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थान भी अब प्रेम के बाजार की कहानी खुद ही वयाँ कर रहे हैं। बहरहाल वेलेंटाइन डे को आप चाहें इसे पसंद करें या न करें, यह दिवस युवाओं के लिए एक विशाल उत्सव बन चुका है। इस उत्सव का कड़वा सच यह है कि यह अब 28 हजार करोड़ रुपयों से भी अधिक का बाजार बन चुका है। अगले सालों में यह बाजार 30 हजार करोड़ रुपयों के होने का अनुमान है। इस कुल खर्च में ज्वैलरी,डेट,डिनर,चॉकलेट और उपहार इत्यादि पर सर्वाधिक खर्च किया गया। यह दिवस अब केवल उपहारों के आदान-प्रदान तथा प्रेम के मासूम पलों की साझेदारी का ही नहीं रह गया है, बल्कि अब यह प्रेम के स्थान पर खुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का दिवस भी बन रहा है। इसी बजह से समय रहते इस वेलेंटाइन डे से जुड़े मनोविज्ञान पर दृष्टिपात करना समय की माँग अनुभव हो रही है।

कहना न होगा कि हर वर्ष 14 फरवरी आते ही वेलेंटाइन डे के पक्ष में वैश्विक युवा संस्कृति का खुमार एवं विपक्ष में समाज की भौंहे चढ़नी शुरू हो जाती हैं। परन्तु इस प्रकार के दिवसों के पीछे हम कभी उस विचारधारा को समझने का प्रयास नहीं करते जो विचाराधारा इस प्रकार के दिवसों पर अपनी भूमिका अदा करती है। दरअसल यह वह विचारधारा है जो लोगों में घटते प्रेम व वात्सल्य के एहसास को उदारीकृत बाजार से प्राण वायु लेकर विस्तार देने का प्रयास कर रही है। जरा इतिहास में झांकने की कोशिश करें तो हमें उस संत वेलेंटाइन के बारे में कोई पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती जिसके नाम पर यह वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी के साथ सीधे तौर पर एक मान्यता यह जुड़ी है कि वेलेंटाइन नामक पादरी को उस समय के यूनानी शासक क्लाउडियस ने ईसा के मत के प्रचार के अपराध में जेल में डाल दिया और इस दिन उसे मृत्युदण्ड देते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उसे मौत के घाट उतराया गया उसी रात उसकी मृत्यु से पहले उसने जेलर की बेटी को अलविदा का एक पत्र लिखा था, जिसके अन्त में उसने लिखा था ह्युतुम्हारा वेलेंटाइनह्य। ऐसी सम्भावना है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया था। तभी से दण्डित किये गये सेंट वेलेंटाइन के मार्मिक और अपूर्ण रहे प्रेम की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दूसरी मान्यता यह भी जुड़ी है कि वेलेंटाइन जब जेल में था तो उसे रोम के बच्चों के असंख्य पत्र प्राप्त हुए थे जो उसे बेतहाशा प्यार करते थे। कुछ इस दिवस की जड़ें उस पुरानी यूरोपीय लोकमान्यता के भीतर भी तलाशते हैं जहाँ यह धारणा उन दिनों खूब प्रचलित थी कि चौदह फरवरी के दिन संसार भर की सभी प्रजातियों के पक्षी चौदह अपना जोड़ा बनाकर प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं।

वेलेंटाइन डे से जुड़ा इतिहास व किंवदन्तियाँ चाहें जो भी हों। परन्तु इतना अवश्य है कि कहीं न कहीं यह दिवस प्रेम की प्राकृतिक भावनाओं को संजोते हुए श्रृंगार को अभिव्यक्त करने का दिवस है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज अब प्रतिर्स्पधा से जुड़े वैश्विक व उदारीकृत समाज की शक्ल ले रहा है। परन्तु यह भी कड़वी सचाई है कि भारतीय समाज को विदेशी बाजारों के लिए खोल देने के बाद पश्चिमी संस्कृति का प्रवेश यहॉ आक्रामक रुप से सामने आ रहा है। इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वेलेंटाइन डे जैसे उत्सव हमारी अपनी स्वदेशी संस्कृति से मेल नहीं खाते। परन्तु इस बेमेल संस्कृति को भारत में लाने के लिए उन्हीं नीति निर्धारकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है जो नब्बे के दशक में खुले बाजार के हिमायती तो रहे हैं,परन्तु आज उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इसके लिए हम खुद ही उत्तरदायी हैं। आज के बच्चे यदि इस संस्कृति को अपनाने, रेव पार्टियों के आयोजित करने अथवा वेलेंटाइन डे के प्रति समर्पण करने में जो अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उसमें परिवारों की घटती भूमिका प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कड़वा सत्य यह है कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में परिवारजनों की घटती भूमिकाऐं, बच्चों के मध्य पारिवारिक साझेदारी एवं उनसे प्रेम करने की भावना बच्चों में प्रेममय सुख एवं सुरक्षा की भावना का संचार करती है। घर का प्रेम व वात्सल्य बच्चों में एक प्रकार की सुरक्षा का आवरण प्रदान करता है। परन्तु अफसोस की बात यह है कि परिवार की स्नेह से परिपूर्ण वात्सल्यी संस्कृति के पीछे छूट जाने से बाल व किशोर मन की संवेदनाएं घायल अवस्था में हैं। उस पर मरहम लगाने का काम न तो परिवार कर रहे हैं और न ही स्कूल और स्कूली पाठ्यक्रम। व्यावसायिक सिनेमा ,दूरदर्शन के सीरियलों से जुड़े संवाद एवं पात्रों के दोहरे-तिहरे चरित्र का तीन चौथाई भाग भी प्रेम प्रसंगों से ही भरा रहता है। यही कारण है कि उन पात्रों के प्रेम प्रसंग किशोरों के जीवन को रोल मॉडल के रुप में सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इससे किशोर मनों की बर्जनाएं टूट रही हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ रही है, विवेक लुप्त हो रहा है और प्रेम के प्रसंग उनको तात्कालिक सुख की अनुभूति करा रहे हैं। दूसरे यह मीडिया संचार और सोसल मीडिया क्रान्ति का भी प्रभाव है कि इससे यौनगत आजादी का प्रसार तेजी से हुआ है तथा विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों की अवधारणा निरन्तर विस्तार ले रही है। संदर्भवश विश्व स्वास्थय सर्वे और अध्ययन बताते हैं कि हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख किशोरियॉ गर्भधारण करतीं हैं। इनमें नौ लाख से अधिक गर्भपात 20 वर्ष से कम की आयु की किशोरियों द्वारा कराये जाते हैं। इन तथ्यों की गम्भीरता बताती है कि वैलेंनटाइन डे से लगातार विस्तारित होती हुयी खुली यौन स्वछन्दता की पृष्ठभूमि में छिपी इस घटना का अध्ययन करना भी प्रासंगिक होगा।

निश्चित ही वेलेंटाइन डे की भावना में कोई दोष नहीं है। दोष तो केवल एक दिवसीय उत्सव की उस संस्कृति है, जो सारी बर्जनाओं को ध्वस्त करके एक बड़े बाज की संस्कृति का हिस्सा बन रही है। भारतीय संस्कृति प्रेम कभी भी प्रदर्शन का विषय नहीं रहा। यहॉ का प्रे कर्तव्य,मयार्दा और दीर्घकालिक सीमाओं से जुड़ा र है।

माता-पिता का त्याग,गुरु का मार्गदर्शन और जीवनसा का अटूट रिश्ता सदैव प्रेम और समर्पण का भा अभिव्यक्त करते रहे हैं। इसलिए यदि वेलेंटाइन डे वर्तमान विस्तारित स्वरूप को रोकना है तो हमें अप परिवारों के स्नेह व प्रेम से बंचित होती संस्कृति पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। परिवारों में हमें झॉककर यह देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा बच्चों से भावनात्मक रागात्मक अलगाव उन्हें प्रेम की इस अंधी गली ओर तो नहीं ले जा रहा। कहीं हमारी खुदगर्जी व मौ मस्ती का हमारा निजी जीवन बच्चों का रोल मॉड़ बनकर उन्हें अपरिपक्व प्रेम की ज्वाला में तो न झोंक रहा है। यदि हमें इस युवा पीढ़ी के बीच विस्त लेती इस प्रकार के भौंड़ी संस्कृति को रोकना है तो ह बच्चों के बीच पनपने वाले अधकचरे प्रेम को अप स्नेहिल ऑचल की छॉव देनी होगी। तभी इस ए दिवसीय बाजारू प्रेम की संस्कृति से बच्चों का बचा किया जा सकता है। आइये हम सब मिलकर इ बेलेन्टाइन डे की संस्कृति को स्वदेशी स्वरुप प्रद करते हुए इसे मॉ-बाप और बच्चों,शिक्षक शिक्षार्थी,गुरु व शिष्य के बीच घटते प्रेम, बात्सल्य संवाद की संस्कृति के साथ-साथ क्षरण होते हु नैसर्गिक प्रेम को सम्मान, संवेदना, सुरक्षा औ आत्मसम्मान से भरने का प्रयास करें। आज चुण समाधान नहीं है। बल्कि बच्चों के मध्य सघन संवा की संस्कृति,निरन्तर उनका मार्गदर्शन और उन भावनात्मक जुड़ाव करते हुए बेलेन्टाइन डे की बाजा संस्कृति से बचा जा सकेगा।

(2/125 बुद्धि विहार, आवास विकास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, संपर्क 9412245301)

प्रेम के नाम पर मुनाफे का व्यापार

प्रसंगवश

हर्षवर्धन पान्डे

पिछले कुछ समय से ग्लोबलाइज्ड समाज में प्यार भी ग्लोबल ट्रेंड का हो गया है। आज जहाँ इजहार और इकरार करने के तौर तरीके बदल गए हैं वहीँ इंटरनेट के इस दौर में प्यार भी बाजारू हो चला है । पहली बार शहरी चकाचौंध से इतर प्यार का यह उत्सव एक बड़ा बाजार को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर जगह वैलेंटाइन की संस्कृति पसरती जा रही है । आज युवा भी इसकी गिरफ्त में पूरी तरह से नजर आते है तभी तो शहरों से लेकर कस्बो तक वैलेंटाइन का जलवा देखते ही बनता है। आलम यह है ये बड़ा उत्सव बन चुका है जो भारतीयों में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है।

वैलेंटाइन के चकाचौंध पर अगर दृष्टि डालें तो इस सम्बन्ध में कई किस्से प्रचलित हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की माने तो यह 'वैलेंटाइन 'अथवा 'वलेंतिनस' नाम के तीन लोगों को मान्यता देता है जिसमें से दो के सम्बन्ध वैलेंटाइन डे से जोड़े जाते है लेकिन बताया जाता है इन दो में से भी संत ' वैलेंटाइन ' खास चर्चा में रहे । कहा जाता है संत वैलेंटाइन प्राचीन रोम में एक धर्म गुरू थे। उन दिनों वहाँ पर क्लाउडियस दो का शासन था। उसका मानना था अविवाहित युवक बेहतर सैनिक हो सकते हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में उन्हें अपनी पत्नी या बच्चों की चिंता नही सताती। अपनी इस मान्यता के कारण उसने तत्कालीन रोम में युवको के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया।

किन्दवंतियो की मानें तो संत वैलेंटाइन के क्लाउडियस के इस फेसले का विरोध करने का फैसला किया। बताया जाता है कि वैलेंटाइन ने इस दौरान कई युवक युवतियों का प्रेम विवाह करा दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फासी की सजा दे दी । कहा जाता है संत के इस त्याग के कारण हर साल 14 फरवरी को उनकी याद में युवा 'वैलेंटाइन डे' मनाते हैं । 1260 में संकलित की गई 'ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वॉराजिन' नामक पुस्तक में भी सेंट वेलेंटाइन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रोम में तीसरी शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस के अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती है। उसने फरमान जारी किया कि उसका कोई सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा। संत वेलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया। उन्हीं के आ'ान पर अनेक सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह किए।

कैथोलिक चर्च की एक अन्य मान्यता के अनुसार एक दूसरे संत वैलेंटाइन की मौत प्राचीन रोम में ईसाईयों पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के दरमियान हो गई। यहाँ इस पर नई मान्यता यह है ईसाईयों के प्रेम का प्रतीक माने जाने वाले इस संत की याद में ही वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एक अन्य किंदवंती के अनुसार वैलेंटाइन नाम के एक शख्स ने अपनी मौत से पहले अपनी प्रेमिका को पहला वैलेंटाइन संदेश भेजा जो एक प्रेम पत्र था। उसकी प्रेमिका उसी जेल के जेलर की पुत्री थी जहाँ उसको बंद किया गया था। उस वेलेंनटाइन नाम के शख्स ने प्रेम पत्र लिखा ' फ्रॉम यूअर वेलेंनटाइन '। आज भी यह वैलेंटाइन पर लिखे जाने वाले हर पत्र के नीचे लिखा रहता है। क्लॉडियस ने 14 फरवरी को संत वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। तब से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि सेंट वेलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया व जेकोबस को एक पत्र लिखा, जिसमें अंत में उन्होंने लिखा था 'तुम्हारा वेलेंटाइन'। 14 फरवरी के बहाने जिसे बाद में इस संत के नाम पूरे विश्व में निःस्वार्थ प्रेम से मनाया जाने लगा ।

यही नहीं वैलेंटाइन के बारे में कुछ अन्य बातें भी है। इसके अनुसार तर्क यह दिए जाते है प्राचीन रोम के प्रसिद्ध पर्व 'ल्युपरकेलिया ' के ईसाईकरण की याद में मनाया जाता है । यह पर्व रोमन साम्राज्य के संस्थापक रोम्योलुयास और रीमस की याद में मनाया जाता है। इस आयोजन पर रोमन धर्मगुरु उस गुफा में एकत्रित होते थे जहाँ एक मादा भेडिये ने रोम्योलुयास और रीमस को पाला था इस भेडिये को ल्युपा कहते थे और इसी के नाम पर उस त्यौहार का नाम ल्युपर केलिया पड़ गया। इस अवसर पर वहां बड़ा आयोजन होता था । लोग अपने घरो की सफाई करते थे साथ ही अच्छी फसल की कामना के लिए बकरी की बलि देते थे। कहा जाता है प्राचीन समय में यह परम्परा खासी लोक प्रिय हो गई।

एक अन्य किंदवंती यह कहती है 14 फरवरी को फ्रांस में चिडियों के प्रजनन की शुरूआत मानी जाती थी जिस कारण खुशी में यह त्यौहार वहा प्रेम पर्व के रूप में मनाया जाने लगा । प्रेम के तार रोम से भी सीधे जुड़े नजर आते हैं । वहाँ पर क्यूपिड को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाने लगा जबकि यूनान में इसको इरोश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन वैलेंटाइन संदेश के बारे में भी लोगो में एकरूपता नजर नही आती । कुछ ने माना है कि यह इंग्लैंड के राजा ड्यूक ने लिखा जो आज भी वहां के म्यूजियम में रखा हुआ है।

आज युवाओं में वैलेंटाइन की खुमारी सर चढ़कर बोल रही है। इस दिन के लिए सभी पलके बिछाये बैठे रहते हैं। भईया प्रेम का इजहार जो करना है ? वैलेंटाइन प्रेमी इसको प्यार का इजहार करने का दिन बताते है। यूँ तो प्यार करना कोई गुनाह नही है लेकिन जब प्यार किया ही है तो इजहार करने मे देर नही होनी चाहिए लेकिन अभी का समय ऐसा है जहाँ युवक युवतिया प्यार की सही परिभाषा नही जान पाये हैं। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे है प्यार को आप एक दिन के लिए नहीं बाँध सकते। वह तो प्यार को हंसी मजाक का खेल समझ रहे है । आज का प्यार मैगी के नूडल जैसा बाजारू बन गया है जो दो मिनट चलता है। सच्चे प्रेमी के लिए तो पूरा साल प्रेम का प्रतीक बना रहता है लेकिन आज के बाजार ने प्यार की परिभाषा बदल दी है। इसका प्रभाव यह है 14 फरवरी को प्रेम दिवस का रूप दे दिया गया है जिसके चलते संसार भर के कपल प्यार का इजहार करने को उत्सुक रहते हैं। जहां चीन में यह दिन 'नाइट्स ऑफ सेवेन्स' प्यार करने वालों के लिए खास होता है, वहीं जापान व कोरिया में इस पर्व को 'वाइट डे' का नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इन देशों में इस दिन से पूरे एक महीने तक लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। आज 14 फरवरी का कितना महत्व बढ गया है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है इस अवसर पर बाजारों में खासी रौनक छा जाती है। गिफ्ट सेंटर में उमड़ने वाला सैलाब, चहल पहल इस बात को बताने के लिए काफी है यह किस प्रकार आम आदमी के दिलो में एक बड़े पर्व की भांति अपनी पहचान बनने में कामयाब हुआ है। इस अवसर पर प्रेमी होटलों , रेस्तारा में देखे जा सकते हैं ।

यूं तो हमारी संस्कृति में प्रेम को परमात्मा का दूसरा रूप बताया गया है अतः प्रेम करना गुनाह और प्रेम का विरोधी होना सही नहीं होगा लेकिन वैलेंटाइन के नाम पर जिस तरह का पश्चिमीपरस्त विस्तार हो रहा है वह सही नहीं है। वैसे भी यह प्रेम की स्टाइल भारतीय जीवन मूल्यों से किसी तरह मेल नहीं खाती। आज का वैलेंटाइन डे भारतीय काव्य शास्त्र में बताये गए मदनोत्सव का पश्चिमी संस्करण प्रतीत होता है लेकिन बड़ा सवाल जेहन में हमारे यह आ रहा है क्या आप प्रेम जैसे चीज को एक दिन के लिए बाध सकते है? शायद नहीं। एक समय ऐसा था जब राधा, कृष्ण , मीरा वा प्रेम हुआ करता था जो आज के वैलेंटाइन प्रेमियों का जैसा न होता था। आज लोग प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रहे है। ही रांझा, लैला- मजनू रोमियो- जूलियट के प्रसंगों का हवाला वाले हमारे आज के प्रेमी यह भूल जाते है मीरा वाला प्रेम सच आत्मा से सम्बन्ध रखता था। आज तो प्यार बाहरी आकर्षण चीज बनती जा रही है। प्यार को गिफ्ट और पॉकिट में तोला ज लगा है। वैलेंटाइन के प्रेम में फसने वाले कुछ युवा सफल तो कु असफल साबित होते है। जो असफल हो गए तो समझ लो बरब हो गए क्युकि यह प्रेम रुपी 'बग' बड़ा खतरनाक है। एक बार अ इसकी जकड में आप आ गए तो यह फिर भविष्य में भी पीछा न छोडेगा। असफल लोगों के तबाह होने के कारण यह वैलेंटाइन घातक बन जाता है। वैलेंटाइन के नाम पर आज हमारे समाज जिस तरह की उद्दंडता हो रही है वह चिंतनीय ही है। संपन्न तब साथ आज का मध्यम वर्ग और अब निम्न तबका भी इसके मक जाल में फसकर अपना पैसा और समय दोनों खराब करते जा है। आज वैलेंटाइन की स्टाइल बदल गई है। गुलाब, गि दिए,पार्टी में थिरके बिना काम नही चलता। यह मनाने के लि आपकी जेब गर्म होनी चाहिए । यह भी कोई बात हुई क्या ज प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए जेब की बोली लगानी पड़ती आज के समय में वैलेंटाइन प्रेमियों की तादात बढ रही है। साल दर -साल। इस बार भी प्रेम का सेंसेक्स पहले से ही कुलाचे म रहा है। वैलेंटाइन ने एक बड़े उत्सव का रूप ले लिया है। मॉल गिफ्ट, आर्चीस , डिस्को थेक का आज इससे चोली दामन साथ बन गया है। अगर आप में यह सब कर सकने की साम नही है तो आपका प्रेमी नाराज । बस फिर प्रेम का द एंड समझ प्यार का स्टाइल समय बदलने के साथ बदल रहा है। वैलेंटा प्रेमी भी हर साल बदलते ही जा रहे है। आज प्यार की परिभा बदल गई है। वैलेंटाइन का चस्का हमारे युवाओ में तो सर चढ़ बोल रहा है लेकिन उनका प्रेम आज आत्मिक न होकर क्षणिक ब गया है। उनका प्यार पैसों में तोला जाने लगा है। आज की यु पीढ़ी को न तो प्रेम की गहराई का अहसास है न ही वह सच्चे प्र को परिभाषित कर सकती है । उनके लिए प्यार मौज मस्ती अ सैर - सपाटे का खेल बन गया है जहाँ बाजार में प्यार नीलाम गया है और पूरे विश्व में इस दिन प्यार के नाम पर मुनाफे का ब कारोबार किया जा रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वे अफसर थे

व्यंग्य

अखिलेश श्रीवास्तव चमन

वे अफसर थे। अपने समय के कड़क अफसर। राज्य सरकार के रोबदार विभाग के वजनदार अफसर। किसी सूखे विभाग के नहीं बल्कि भरपूर गीलापन के लिए कुख्यात विभाग के अफसर। ए.सी. चैम्बर में बैठ कर फाइलें निपटाने वाले अफसर नही आम जनता के बीच डंडा फटकारने वाले अफसर। तिल को ताड़ और राई को पहाड़ बना देने की कला में पारंगत अफसर। बैल से दूध और मुर्गे से अंडा बरामद कर सकने की योग्यता वाले अफसर। सीधे-सादे गऊ छाप आदमी को शातिर अपराधी तथा दुर्दांत अपराधी को भले मानुष का सर्टिफिकेट दे सकने की क्षमता सम्पन्न अफसर। ईशारा आप समझ गए होंगे। जी हॉं, वे पुलिस विभाग में अफसर थे।

जिस खानदान में उनका आविर्भाव हुआ था वहॉं स्कूल के मुकाबले अखाड़े को ऊँचा दर्जा प्राप्त था। वहॉं किताब से अधिक महत्व कसरत का था। वहॉं दिमाग से अधिक देह को मॉंजने का रिवाज था। वे जिस इलाके के निवासी थे उस इलाके के युवकों का सबसे बड़ा सपना होता था दरोगा बनना। दरोगा बनने के प्रयास में लगे वहॉं के लड़के दौड़ते-भागते गिरते-पड़ते दरोगा न सही सिपाही तो बन ही जाते थे। अफसर जी ने भी परम्परा का पालन किया था। किशोरावस्था को प्राप्त होते ही उन्होंने अपने मन में दरोगा बनने का सपना पाल लिया था। अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए वे दण्ड-बैठक करने और शरीर को मॉंजने में जुट गए थे। किस्मत ने उनका साथ दिया। उनका सपना साकार हो गया। वे दरोगा बन गए। और खरामा-खरामा आगे बढ़ते अपनी सेवानिवृत्ति से सवा साल पहले डिप्टी एस.पी. यानी सी.ओ. के पद तक पहुँचने में सफल रहे। और अंततः सेवा निवृत्ति की गति को प्राप्त हो गए।

दुनिया लाख कहे कि वे पुलिस अफसर थे लेकिन उन्होंने ह्यथे' को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनका मानना है कि ह्यवन्स ए किंग इज आलवेज ए किंग'। यानी वे अफसर थे अफसर हैं और अपनी अंतिम सांस तक अफसर ही रहेंगे। वे साल के तीन सौ पैंसठ दिन अफसर हैं। खाते-पीते सोते-जागते बोलते-बतियाते राह चलते चौबीसों घंटे अफसर हैं। गॉव में हों या शहर में घर में हों या बाजार में सब्जी खरीद रहे हों या किराना किसी बारात में जा रहे हों या शवयात्रा में हर जगह अफसर हैं, हर हालत में अफसर हैं। अपनी अफसरी को वे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं क?ते हैं।

एक तो करेला दूसरे चढ़ी नीम वाली बात थी। एक तो पुलिस विभाग की अफसरी दूसरे तुनक मिजाजी स्वभाव। गुस्सा हर समय उनकी नाक पर रहा करता था। रिटायरमेंट के साथ ही पद प्रभाव जाता रहा वर्दी पेटी भी उतर गयी लेकिन उनके सर से अफसरी का नशा नहीं उतर सका था। वे गली-मुहल्ला हाट-बाजार बात-बेबात ताव खा जाया करते थे। नाई धोबी मिस्त्री मेकेनिक हर किसी से उलझ पड़ते थे। ठेले वाले खोमचे वाले मिठाई वाले किराने वाले हर किसी पर रोब गॉंठने लगते थे। वे जिस पर भी गुस्सा होते उसको धमकाते हुए कहते- ह्यह्यअबे ! तू जानता नहीं है मुझको। मैं डिप्टी एस.पी. हूँ...डिप्टी एस.पी.। खाल खिंचवा कर उसमें भूस भर दूँगा अभी।"

कहावत है कि नंगा खुदा से बड़ा। नंगे से सभी बचते हैं। और जहॉं तक नंगई की बात है पुलिस से बड़ा नंगा आज तक कोई हुआ ही नहीं। पुलिस यानी घोषित नंगा, पोषित नंगा, स्वीकृत नंगा, अधिकृत नंगा, सुगठित नंगा, संगठित नंगा परिष्कृत नंगा, लाइसेंसधारी नंगा, उत्कृष्ट नस्ल का नंगा। कहना न होगा कि ऐसे उच्च श्रेणी के नंगे के संग उलझने का मतलब था अपनी भद्द पिटवाना।

चूँकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है इसलिए उन अफसर जी की धमकी और घुड़की सुन कर अगला आदमी चुप हो जाता था। गलती न हो तो भी अपनी गलती मान लेता था। शराफत के चलते माफी मॉंग लेता था और चुपचाप एक ओर खिसक लेता था। परिणाम इसका यह होता था कि अफसर जी की अफसरी का नशा थोड़ा और बढ़ जाया करता था।

लेकिन पुरानी कहावत है कि ह्यसब दिन जाय न एक समाना'। बड़े बुजुर्गों का भी कहना है कि देर-सवेर हर सेर को सवा सेर जरूर मिलता है। वही हुआ। एक दिन धोखा हो गया। उस दिन अफसर जी की गीदड़ भभकी काम नहीं आयी। सरेआम उनकी कलई उतर गयी। बेचारे की भद्द पिट गयी।

हुआ यूँ कि अफसर जी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। ड्राइवर की सीट पर खुद विराजमान थे और बराबर वाली सीट पर उनकी पत्नी यानी अफसराइन बैठी थीं। कार के आगे एक मोटर सायकिल चली जा रही थी। मोटर सायकिल पर एक बावर्दी सिपाही बैठा हुआ था। सिपाही अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करता आम जनता की तरह सड़क के बायें किनारे चलता तो पुलिस की वर्दी पेटी और बिल्ले की बेइज्जती थी। अतः वह बेधड़क सड़क के बीचो बीच मोटर सायकिल को दायें बाएं लहराता हुआ चल रहा था। कार सवार अफसर जी आगे निकलने के लिए परेशान थे लेकिन सिपाही उनको निकलने की जगह नहीं दे रहा था। अफसर जी हार्न बजा-बजा कर थक गए लेकिन पुलिसिया ऐंठ में ऐंठा सिपाही हार्न की परवाह किये बगैर अपनी ही धुन में चला जा रहा था। हार्न की आवाज पर वह पीछे मुड़ कर देखता तो था लेकिन मोटर सायकिल को किनारे नहीं करता था। अफसर जी मारे गुस्सा के आग-बबूला हुए जा रहे थे। दॉंत पीस रहे थे। सिपाही की माँ बहन से रिश्ता जोड़तीं गालियाँ बक रहे थे लेकिन सिपाही पर रंच मात्र भी असर नहीं हो रहा था।

दरअसल बात ये थी कि इधर अफसर जी को सिपाही के पीछे चलने और सिपाही द्वारा उनके हार्न की आवाज को तवज्जो न देने में अपनी अफसरी की तौहीनी लग रही थी। तो उधर किनारे हट कर कार को प देने में सिपाही को अपने शरीर पर धारण की गई वर्दी पेटी और बिल की तौहीनी लग रही थी। रोटी दोनों ने ही पुलिस विभाग की खायी इसलिए कोई किसी से कम नहीं था। दोनों के बीच काफी देर तक यूँ लाग डाट चलती रही। आखिर एक जगह जरा सा मौका मिला अफसर जी ने खतरा मोल लेते हुए अपनी कार झटके से आगे बढ़ा और मोटर सायकिल के आगे ले जा कर खड़ा कर दी।

'क्यों बे हरामी की औलाद ! सुनाई नहीं दे रहा है तुमको। आधे घंटे हार्न दे रहा हूँ मैं।" अफसर जी सिपाही की तरफ ऑंखें तरेरते बोले।

'अबे साले ! बावर्दी सिपाही को तूने गाली दी ? तेरी इतनी मजाल। तो ऐसी की तैसी। अभी नशा उतारता हूँ तेरा।ह्यह्य सिपाही ने कहा, मो सायकिल से उतरा और अफसर जी की कालर पकड़ कर घसीट लि

'जानता नहीं तू....मैं रिटायर्ड डिप्टी एस.पी. हूँ। विभाग में शिकायत के तुम्हारी वर्दी पेटी उतरवा लूँगा।" अफसर जी ने अपनी आदत मुताबिक रोब गॉंठी।

'अबे...तुम्हे जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। तुम्हारे जैसे रिटायर्ड डि एस.पी. को मैं अपने बूट की नोंक पर रखता हूँ।" सिपाही ने कहा दे दनादन लत्तम जुत्तम शुरू हो गया।

फिर तो अफसर जी लाख चीखते रहे चिल्लाते रहे। लाख अपने पुलि अफसर होने की दुहाई देते रहे। विभागीय शिकायत की लाख धमकि देते रहे। लेकिन सब बेअसर रहा। वर्तमान वर्दीधारी ने भूतपूर्व वर्दीध की एक नहीं सुनी। उसने मार-मार कर अफसर जी को जमीन पर पस दिया। अंततः अफसराइन ने बीच-बचाव किया। वह हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगीं, रोने लगीं तो सिपाही ने छोड़ दिया। लेकिन तब त अफसर जी की की फुल मरम्मत हो चुकी थी

(सी-2, एच-पार्क महानगर लखनऊ-226006
मो. 6394976289)

सम्पादकीय...

राहुल गांधी की सदस्यता

राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर एक के बाद एक किये जा रहे हमलो से पूरी भाजपा हिल गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी नहीं दे पाए, उनके ऊपर कांग्रेस के सांसद हमला कर सकते थे एहसास लोकसभा अध्यक्ष ने बोलकर उन्हें जवाब नहीं देने की सलाह दी थी। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है जिस पर 118 सदस्यों के हस्ताक्षर है उसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के नेता को सदन में नहीं बोलने देने पर अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया है। राहुल गांधी द्वारा सदन में एपस्टिन फाइल का उल्लेख करने तथा पूर्व सेनापति जनरल नरवडे कि पहले आत्मकथा के अंश बताने और बाद में किताब को संसद में लाने तथा अमेरिका की ट्रेड डील पर पूरी सरकार हिल गई थी। सरकार के लिए परेशानी का कारण यह है कि राहुल गांधी को कैसे मैनेज करें क्योंकि वह किसी भी रूप में किसी से भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ 8 मार्च को बहस होनी है यदि उस दिन राहुल गांधी सदन में रहेंगे तो विपक्ष को संभालना भारी होगा फिर राहुल गांधी खुद साफ कर देंगे कि उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया गया वे अपने द्वारा उठाए गए मामलों के सबूत भी पेश कर देंगे सरकार नहीं चाहती की चीन के मामले में सीमा पर जो हुआ उसका पूरा पता देश को लगे अब नया मामला अमेरिका के साथ ट्रेड डील का भी आ गया है। भाजपा समझ नहीं पा रही है कि कैसे इन मामलों से पीछा छुड़ाया जाए इसलिए सब मामलों की एक ही दवा मान ली गई है कि राहुल गांधी को बाहर कर दो सारी बातें दबे की तो नहीं पर फिलहाल लोकसभा में शांत हो जाएगी।

वैभव लोढ़ा...

इतिहास में आज

1881 – भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना।
1939 मुंबई: के तत्कालीन प्रशासन ने शहर में शराबबंदी का प्रस्ताव रखा।
1990 – बंगलौर में इंडियन एयरलाइंस 605 पर सवार 92 लोग विमान दुर्घटना में मारे गये।
2007 – मध्य प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल का निधन हुआ।
2009 – सानिया मिर्ज़ा ने पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया।

-धर्म चंद मेहता

क्रॉस फायर

- **राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भाजपा सांसद का नोटिस।**
  - ना रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी।
- **114 राफेल खरीदे जाएंगे।**
  - अनिल अंबानी के मार्फत या डायरेक्ट।
- **राहुल गांधी बोले किसानों के लिए लड़ता रहूंगा।**
  - और कोई लड़ेगा लगता नहीं है।
- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे।**
  - फिर एडवांस लिए पेमेंट को लौटाना पड़ेगा।
- **सुप्रीम कोर्ट बोला दागी बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा रेरा कुछ नहीं कर रहा है।**
  - बिल्डरों कोई फायदा पहुंचाने का उद्देश्य है।
- **नीति आयोग ने रिपोर्ट में कहा डीजल वाहनों को हटाए सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाए।**
  - सरकार ऐसी नीति बनाएं तभी होगा।
- **राजस्थान विधानसभा में राइट टु हेल्थ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में घमासान।**
  - मामला सारे प्रदेश की जनता का है।
- **राजस्थान में हाईवे से सैकड़ो मंदिर मजार और हजारों दुकान मकान हटाने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए।**
  - पहले शराब की दुकान तो हटाओ।

..............अंजू लोढ़ा

आज का राशिफल

शनिवार 14 फरवरी, 2026

मेष राशि: दूसरे से सहयोग लेने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मबूत होगा। राजनैतिक सहयोग लेने में सफल होंगे।

वृषभ राशि: संबंधित अधिकारी से सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

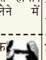

मिथुन राशि: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

कर्क राशि: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। नेत्र या उदर विकार के प्रति सचेत रहें।

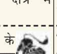

सिंह राशि: संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। चल या अचल संपत्ति के मामले सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा मिलेगी।

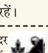

कन्या राशि: नेत्र या उदर विकार के प्रति सचेत रहें। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

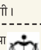

तुला राशि: मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद रहेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

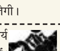

वृश्चिक राशि: गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। झगड़ा विवाद या दुर्घटना की आशंका है।

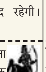

धनु राशि: आर्थिक योजना फलीभूत होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

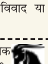

मकर राशि: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। संबंधों में मधुरता आएगी।

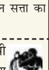

कुम्भ राशि: जीवनसाथी का सहयोग और सान्निध्य मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मीन राशि: व्यावसायिक कार्य में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। नेत्र, उदर विकार के प्रति सचेत रहें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो।

राजेन्द्र गुप्ता
ज्योतिषी और हस्तरेखाविद, मो. 9611312076

नोट– अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या इसी व्हाट्स एप नम्बर पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें, इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल और हैंडप्रिंट्स भेजें।

प्रेम का उत्सव या बाज़ार का प्रभाव वेलेंटाइन डे परंपरा, परिवर्तन और आज का युवा मन

कांतिलाल मांडोत

प्रतिवर्ष 14 फरवरी को विश्वभर में प्रेम दिवस के रूप में 'वेलेंटाइन डे' मनाया जाता है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों से यह दिन विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ है। हालांकि समाज का एक वर्ग इसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हुए इसका विरोध करता रहा है, फिर भी यह सच है कि प्रेम जैसी सार्वभौमिक भावना किसी सीमा या संस्कृति की मोहताज नहीं होती। यदि हम इस दिन को केवल पश्चिमी परंपरा के चश्मे से देखने के बजाय व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझें, तो पाएंगे कि प्रेम और वसंत का संबंध हमारी अपनी परंपराओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वेलेंटाइन नामक संत के बारे में मान्यता है कि उन्होंने प्रेम को सामाजिक बंधनों से ऊपर माना और प्रेमी युगलों का विवाह करवाने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनकी शहादत प्रेम की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बन गई। भारतीय संदर्भ में देखें तो प्रेम की यह भावना कोई नई नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण और राधा का संबंध केवल लौकिक प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। कृष्ण का प्रेम मर्यादा और माधुर्य दोनों का अद्भुत संगम है। संस्कृत साहित्य में भी वसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु कहा गया है। कालिदास, भास और शूद्रक जैसे साहित्यकारों ने अपने नाटकों और काव्यों में वसंत को मिलन और अनुराग का प्रतीक बताया है। 'मदनोत्सव' और 'वसंतोत्सव' जैसी परंपराएं इस बात की साक्षी हैं कि प्रेम और उल्लास का उत्सव मनाना भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग रहा है। वेलेंटाइन डे के आसपास ही भारत में वसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी से लेकर होली तक का समय प्रकृति के नवोन्मेष का काल होता है। सरसों के पीले फूल, कोयल की कूक और मंद समीर वातावरण में एक मधुर भाव जगाते हैं। सूफी संतों ने भी वसंत को प्रेम और भक्ति से जोड़ा। अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए बसंत और होली के गीतों की रचना की। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम का उत्सव मनाने की परंपरा केवल पश्चिम की देन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी हिस्सा रही है। जहां तक 'बेलन टाइम डे' से 'वेलेंटाइन डे' तक की हास्यपूर्ण कथा का प्रश्न है, वह एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है, जो सामाजिक संबंधों में सम्मान और समानता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसका ऐतिहासिक आधार चाहे जो भी हो, संदेश यह है कि दांपत्य संबंध प्रेम और आदर पर आधारित होने चाहिए, न कि उत्पीड़न पर। आधुनिक समाज में भी यह संदेश प्रासंगिक है। आज के समय में युवाओं का वेलेंटाइन डे के प्रति बढ़ता आकर्षण कई कारणों से है। एक ओर वैश्वीकरण और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में विश्वास करती है। उनके लिए यह दिन अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह प्रकट करने का अवसर है। वे इसे केवल प्रेमी–प्रेमिका के संबंध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि मित्रता, पारिवारिक स्नेह और आत्म–प्रेम तक भी विस्तारित कर रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में 'फ्रेंडशिप डे' या 'रोज डे' जैसी गतिविधियां युवाओं को अभिव्यक्ति का मंच देती हैं। किन्तु इसके साथ कुछ प्रश्न भी जुड़े हैं। क्या प्रेम को केवल एक दिन तक सीमित कर देना उचित है? क्या उपहार, महंगे फूल और रेस्टोरेंट में डिनर ही प्रेम की अभिव्यक्ति हैं? आज वेलेंटाइन डे पर बाजार का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कंपनियां विशेष ऑफर और विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करती हैं। इससे प्रेम का भाव कहीं–कहीं प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है। जिन युवाओं के पास आर्थिक साधन कम होते हैं, वे स्वयं को हीन महसूस कर सकते हैं।

इस प्रकार प्रेम का सहज और सरल भाव उपभोगवाद की चकाचौंध में दब जाता है। समाज पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार अपरिपक्व आयु में आकर्षण को प्रेम समझ लिया जाता है, जिससे भावनात्मक आघात या पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दिखावटी रिश्तों का दबाव भी युवाओं को भ्रमित करता है। कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार सामाजिक असहजता का कारण बनता है। अतः आवश्यक है कि युवा प्रेम और आकर्षण के अंतर को समझें और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। इसके विपरीत, यदि वेलेंटाइन डे को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो यह आपसी सम्मान, संवाद और संवेदनशीलता को बढ़ाने का अवसर भी हो सकता है। प्रेम केवल रोमांटिक संबंध नहीं, बल्कि सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना है। यदि इस दिन को हम माता–पिता, मित्रों, शिक्षकों या समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाएं, तो इसका स्वरूप अधिक व्यापक और सार्थक हो सकता है। भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश देती है, जिसमें समस्त विश्व को परिवार माना गया है। इस दृष्टि से प्रेम दिवस का अर्थ केवल युगल प्रेम तक सीमित नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण से है। आज वेलेंटाइन डे आवश्यक है या नहीं, इसका उत्तर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। प्रेम तो हर दिन व्यक्त किया जा सकता है, फिर भी विशेष दिवस हमें ठहरकर अपने संबंधों को संवारने का अवसर देते हैं। यदि हम इसे अंधानुकरण या उग्र विरोध के बजाय संतुलित दृष्टिकोण से अपनाएं, तो यह सांस्कृतिक संघर्ष का कारण नहीं बनेगा। भारतीय समाज की विशेषता यह रही है कि उसने बाहरी प्रभावों को आत्मसात करते हुए उन्हें अपनी संवेदना के अनुरूप रूपांतरित किया है। ठीक उसी प्रकार वेलेंटाइन डे को भी हम भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं। अंततः प्रेम एक सार्वभौमिक और शाश्वत भावना है। इसमें वासना नहीं, बल्कि समर्पण और सम्मान का भाव होना चाहिए। चाहे वह राधा–कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम हो, सूफी संतों की भक्ति हो या संत वेलेंटाइन की शहादत। सभी का मूल संदेश यही है कि प्रेम मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रेम को दिखावे या बाजारवाद से ऊपर उठाकर उसकी पवित्रता को बनाए रखें। यदि वेलेंटाइन डे हमें यही सीख देता है, तो यह केवल एक विदेशी पर्व नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का उत्सव बन सकता है।

संसदीय विमर्श के नए मानक और राघव चड्ढा की तथ्यपरक राजनीति

महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में जन सरोकारों की अभिव्यक्ति जब आंकड़ों की शुचिता और तार्किक प्रखरता के साथ होती है, तो वह केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज बन जाती है। हाल के वर्षों में राज्यसभा के पटल पर एक युवा सांसद के रूप में राघव चड्ढा ने जिस परिपक्वता और आर्थिक समझ का परिचय दिया है, उसने संसदीय विमर्श के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। विशेष रूप से वर्ष 2026 के बजटीय सत्र के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य भारत की बदलती कर संरचना और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंतन की मांग करते हैं। एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पृष्ठभूमि होने के कारण चड्ढा का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि पूर्णतः गणितीय और वस्तुनिष्ठ होता है। उन्होंने इस तथ्य को मजबूती से रेखांकित किया है कि वर्तमान में देश का मध्यम वर्ग सरकार के लिए एक मूक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) बनकर रह गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कर इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब व्यक्तिगत आयकर का संग्रह कॉर्पोरेट कर की तुलना में अधिक हो गया है। फरवरी 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें गैर–कॉर्पोरेट यानी व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों का योगदान 8.90 लाख करोड़ रुपये पर सिमट गया। यह विडंबना ही है कि जो वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जो ईमानदारी से कर का भुगतान करता है, उस पर कर का बोझ 5.91 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि बड़े उद्योगों को मिलने वाली रियायतें उनके कुल योगदान को कम कर रही हैं। यह असंतुलन केवल सांख्यिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि एक गहरी नीतिगत खामी की ओर संकेत करता है। चड्ढा ने संसद में इस बात को प्रमाणों के साथ रखा कि मध्यम वर्ग न केवल प्रत्यक्ष कर के बोझ तले दबा है, बल्कि महंगाई की दोहरी मार भी झेल रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में महंगाई दर 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसमें शिक्षा पर खर्च में 8 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं में 9 प्रतिशत और आवास के किराए में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इन परिस्थितियों में वेतनभोगी वर्ग के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए मानक कटौती की सीमा को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का जो प्रस्ताव दिया, वह करोड़ों करदाताओं की अंतरात्मा की आवाज बनकर उभरा। संसदीय वाद–विवाद में चड्ढा का योगदान केवल करों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने लोक स्वास्थ्य के उस भयावह पहलू को भी छुआ है जिसे अक्सर विकास की चकाचौंध में अनदेखा कर दिया जाता है। फरवरी 2026 में उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट के संकट को एक राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शोधों का हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार भारतीय मसालों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में हानिकारक कीटनाशकों की उपस्थिति पाई गई है, जिन्हें विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन पदार्थों में कैंसरकारी तत्वों की मौजूदगी राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता और दंडात्मक शक्तियाँ देने की वकालत की ताकि गुमराह करने वाले विज्ञापनों और स्वास्थ्य के शत्रुओं पर लगाम कसी जा सके। इस मुद्दे की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके तर्कों के बाद सरकार को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देने पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी कमियों पर बोलते हुए उन्होंने अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, चिकित्सकों पर कार्य का अत्यधिक दबाव और शल्य चिकित्सा के लिए मिलने वाली लंबी प्रतीक्षा तिथियों को मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता को एक राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाओं ने प्राथमिक चिकित्सा को सुलभ बनाया है। उनके अनुसार, जब तक राष्ट्र के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों पर खर्च नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना केवल कागजों तक सीमित रहेगा। वित्तीय संघवाद और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर भी चड्ढा के विचार अत्यंत मौलिक और प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की प्रकृति पर सवाल उठाया। वर्तमान व्यवस्था में केंद्र राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए जो सहायता देता है, वह अक्सर कड़ी शर्तों और ऋण के रूप में होती है। चड्ढा ने मांग की कि राज्यों को ऋण के बजाय सीधे पूंजीगत अनुदान दिए जाने चाहिए। उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपये के अनुदान का जो खाका प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य राज्यों को सिंचाई, सड़क और शहरी बुनियादी ढांचे में स्वतंत्र रूप से निवेश करने हेतु सक्षम बनाना है। यह दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की उस भावना को पुष्ट करता है जहाँ राज्य केवल केंद्र के अभिकर्ता न होकर विकास के बराबर के भागीदार होते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए 'राइट टू रिकॉल' अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का मुद्दा उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका प्रस्ताव है कि यदि कोई विधायक या सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो 18 महीने के प्रदर्शन काल के बाद मतदाताओं के पास उसे पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 50 प्रतिशत मतदान की अनिवार्यता का सुझाव दिया, जो राजनीति में अपराधीकरण और अकर्मण्यता को समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आर्थिक सुधारों की दिशा में चड्ढा ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया है। उनका सुझाव है कि भूमि अभिलेखों को ब्लॉकचेन तकनीक पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। भारत में दीवानी मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति विवादों से संबंधित होता है, जिससे न केवल न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है बल्कि आर्थिक निवेश भी प्रभावित होता है। ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शी व्यवस्था से इन विवादों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर की जटिलताओं को दूर कर इसे अधिक सरल और व्यापक बनाने के लिए इसके दूसरे संस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका तर्क है कि जब तक घरेलू निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, तब तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। चड्ढा के भाषणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्या गिनाने के साथ–साथ समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वे आंकड़ों को इस प्रकार बुनते हैं कि सरकार के लिए उन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होता। उनके संसदीय सफर का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष दल की विचारधारा के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रखरता ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि विपक्षी दल तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, तो वे सरकार को लोक–लुभावन घोषणाओं के बजाय ठोस नीतिगत बदलावों के लिए विवश कर सकते हैं। अंततः, राघव चड्ढा की राजनीति आंकड़ों की शुचिता, मध्यम वर्ग के अधिकारों की रक्षा और एक पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के इर्द–गिर्द घूमती है, जो आने वाले समय में भारतीय संसदीय परंपरा के लिए एक आदर्श मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।

दादी के बाद अब पोते पर लटका विशेषाधिकार हनन का मामला

बाल मुकुन्द ओझा

आजकल विशेषाधिकार की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। विपक्ष के नेता राहुल गाँधी पर इन दिनों विशेषाधिकार हनन की तलवार लटकी हुई है। 1978 में लोकसभा में पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की सदस्यता भी चली गई और कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि फिलहाल भाजपा ने इसे टाल दिया बताया। सरकार ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। कहा जाता है राहुल गाँधी का यही रवैया रहा तो आज नहीं तो कल उन्हें विशेषाधिकार हनन का सामना करना पड़ सकता है। आइये आज हम विशेषाधिकार और उसके हनन के बारे में चर्चा करते है। भारत में संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष अधिकार और छूट प्रदान की गई हैं। जब इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी भी तरह से सदन या उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की शुरुआत स्पीकर को लिखित नोटिस दिए जाने से होती है। नोटिस मिलने पर स्पीकर तय करेंगे कि मामला विशेषाधिकार हनन का बनता है या नहीं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नोटिस स्वीकार करते हैं तो उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है। लोकसभा में यह समिति आम तौर पर 15 सांसदों की होती है, जबकि राज्यसभा में 10 सांसदों की। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा और फिर सदन तय करेगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर स्पीकर मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपते हैं। अपनी जांच पूरी करने के बाद समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे सदन के पटल पर रखती है। दोषी पाए जाने पर भी समिति खुद सजा नहीं देती बल्कि सजा की सिफारिश करती है। विशेषाधिकार समिति दोषी पाए जाने पर दोषी सदस्य को चेतावनी देने या फटकार लगाने की सिफारिश कर सकती है। अगर ज्यादा गंभीर नहीं लगे तो समिति उन्हें सदन में बिना शर्त माफी मांगने या खेद जताने का निर्देश दे सकती है। मामला गंभीर लगने पर समिति उन्हें कुछ दिनों या पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से अलग रखने की सिफारिश कर सकती है। बेहद गंभीर मामलों में समिति सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश कर सकती है। इसे सदन में वोटिंग के जरिए लागू किया जाता है। जेल की बेहद ही गंभीर मामलों में सदन संबंधित सांसद को कारावास की सजा भी सुना सकता है। हालांकि ऐसा दुर्लभ मामलों में ही होता है। पहले भी विशेषाधिकार हमले की गाज कई लोगों पर गिर चुकी है। इनमें देश के प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता भी शामिल है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने इंदिरा गांधी को 1975 के एक मामले में सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया था। इस मामले में न सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की गई बल्कि सत्र खत्म होने तक उन्हें जेल भी भेजा गया था। इमरजेंसी के दौरान सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप लगा कि उन्होंने विदेश में रहकर भारत विरोधी प्रचार किया और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के स्टिंग में फंसे 11 सांसदों की सदस्यता एक झटके में खत्म कर दी गई थी। विशेषाधिकार समिति और पवन बंसल समिति की सिफारिशों के आधार पर सदन ने इसे सदन की अवमानना माना था। सदन के अंदर दिए गए बयानों पर अदालती कार्यवाही नहीं होती, लेकिन विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की जा सकती है।

नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी है।

सुनील कुमार महला

स्त्री की गरिमा और उसका सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रहे हैं। हमारे यहां नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है तथा शास्त्रों में कहा गया है–'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' यहां पाठकों को बताता चलूं कि यह प्रसिद्ध संस्कृत वचन 'मनुस्मृति' से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जहां नारी का सम्मान और आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। वास्तव में, यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दर्शाता है। नारी को शक्ति, करुणा, त्याग और सृजन की प्रतीक माना गया है।सच तो यह है कि परिवार और समाज की असली आधारशिला नारी ही होती है और जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा मिलती है, वह समाज और देश प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत, जहां नारी का अपमान होता है, वहां अशांति और पतन का वातावरण बनता है। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अहिल्याबाई होल्कर जैसी महान महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार और समाज के निर्माण में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है; वह मां, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन को संवेदना, संतुलन और संस्कार प्रदान करती है। आज के आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री का सम्मान केवल परंपरा या शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में उन्नत और सभ्य बन सकेगा। बहरहाल, स्त्रियों की गरिमा व सम्मान के क्रम में हाल ही में जैस्मीन सैंडलस ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। जब कुछ लोग वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि जैस्मीन सैंडलस एक प्रसिद्ध भारतीय–अमेरिकी पंजाबी गायिका और गीतकार हैं, जिन्होंने अपने अलग अंदाज़ और दमदार आवाज़ से संगीत जगत में खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 4 सितंबर 1985 को पंजाब के जालंधर में हुआ और बाद में वह अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में पली–बढ़ीं। उन्होंने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हुईं। बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म 'किक' के गीत 'यार ना मिले' से मिली। उनके गानों में पॉप, आर एंड बी और पंजाबी फोक का मिश्रण देखने को मिलता है। जैस्मीन न सिर्फ गायिका हैं बल्कि अपने कई गीत स्वयं लिखती भी हैं, और अपनी बेबाक शैली व ऊर्जावान स्टेज परफ़ॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं।जैस्मीन सैंडलस ने संगीत कार्यक्रम के दौरान यह बात साफतौर पर कहीं कि जब तक महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, वह मंच पर नहीं गाएंगी। वास्तव में,यह घटना बताती है कि आज भी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। दुख की बात यह है कि ऐसे मामलों में कई लोग सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं।आज आए दिन मीडिया की सुर्खियों में यह खबरें हमें पढ़ने को मिलतीं रहतीं हैं कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को आज अभद्र टिप्पणियों, घूरने, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस, ट्रेन, बाजार, दफ्तर या यहां तक कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी वे असुरक्षा की भावना से घिरी रहती हैं। कहना ग़लत नहीं होगा।

रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध से सरकार और स्टेकहोल्डर्स दोनों को हुआ भारी नुकसान!

सुमेर सिंह चुण्डावत

प्रधान संपादक

मो. 7737275324

ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 पर सरकार ने उद्योग संगठनों को स्टेकहोल्डर मीटिंग्स, संसदीय बहस और आधिकारिक बयानों के माध्यम से आश्वासन दिए। जिसमें मुख्य फोकस रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध के बावजूद स्किल-बेस्ड सेक्टर की सुरक्षा और विकास पर था।

सच मीडिया

ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 में रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने से सरकार और स्टेकहोल्डर्स दोनों को अल्पकालिक व दीर्घकालिक नुकसान हुआ है। हालांकि, सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानती है, जबकि उद्योग जगत दीर्घकालिक हानि का दावा करता है। आंकड़े बताते हैं कि आम बजट 2026 और उससे ठीक पहले आए आर्थिक सर्वे भी केंद्र सरकार के बढ़ते वित्तीय घाटे की ओर इशारा कर चुके हैं, इसलिए बेहतर तो यह होता कि मोदी सरकार ऐसे द्विपक्षीय हानिप्रद फैसले लेने से पहले इससे जुड़े उद्योग जगत व अन्य स्टेक होल्डर्स से उन्मुक्त हृदय से बातचीत के बाद ही किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचती।

जहां तक सरकार को नुकसान की बात है तो सरकार को सालाना 15,000-20,000 करोड़ जीएसटी (GST) राजस्व का सीधा नुकसान हुआ, क्योंकि रियल मनी सेक्टर 86% राजस्व का स्रोत था। वहीं, इस क्षेत्र में सक्रिय 400+ कंपनियों के बंद होने से कॉर्पोरेट टैक्स और FDI (25,000 करोड़) प्रभावित हुए। वहीं, जहां तक स्टेकहोल्डर्स को हानि की बात है तो रियल मनी गेम्स सेक्टर में 2 लाख नौकरियां (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से) खतरे में हैं, जिसमें डेवलपर्स, मार्केटर्स और फिनटेक शामिल हैं। जिससे 50 करोड़ गेमर्स अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ने के आसार प्रबल हैं।

हालांकि, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया है कि 45 करोड़ लोगों को ?20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि नए प्रतिबंध से ई-स्पोर्ट्स (.1-2 बिलियन) मजबूत होगा। इस प्रकार लंबे समय में नया राजस्व (टूर्नामेंट्स, स्पॉन्सरशिप) नुकसान की भरपाई करेगा।

बताया जाता है कि जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 को अगस्त 2025 में संसद के दोनों सदनों से मात्र दो दिनों में पारित किया गया, वह त्वरित निर्णय है, जिसने 'रियल मनी गेम्स' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जो अर्थव्यवस्था पर कई दुष्प्रभाव डाल चुका है और आगे भी पड़ेगा।

जहां तक नौकरियों पर प्रभाव की बात है तो इससे लगभग 2 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, क्योंकि 400 से अधिक कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। इंडस्ट्री बॉडीज के अनुसार, 25 अरब डॉलर के सेक्टर का बड़ा हिस्सा रियल मनी गेमिंग था, जिसका अचानक अंत होने से मानव संसाधन संकट पैदा हो गया। वहीं, जहां तक सरकारी राजस्व हानि की बात है तो सरकार को सालाना ?20,000-25,000 करोड़ रुपये के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, जिसमें जीएसटी (GST) प्रमुख है। इससे डिजिटल इकोसिस्टम जैसे फिनटेक, विज्ञापन और कंटेंट क्रिएशन प्रभावित हुए हैं।

दिलचस्प तो यह कि सरकार के तुगलकी फैसलों का असर भारत में होने वाले विदेशी निवेश पर भी पड़ेगा। इसलिए जहां तक निवेश प्रभाव की बात है तो देश में होने वाले 25,000 करोड़ के विदेशी निवेश (FDI) पर असर पड़ा है, क्योंकि नीतिगत अनिश्चितता से निवेशक पीछे हट रहे हैं। आखिर इसके त्वरित पारित होने से परामर्श की कमी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास कमजोर किया। वहीं, जहां तक अन्य जोखिम की बात है तो उपभोक्ता अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स या ग्रे मार्केट की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सकता है। हालांकि ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन समग्र आर्थिक नुकसान प्रमुख चिंता है।

यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 पर सरकार ने उद्योग संगठनों को स्टेकहोल्डर मीटिंग्स, संसदीय बहस और आधिकारिक बयानों के माध्यम से आश्वासन दिए। जिसमें मुख्य फोकस रियल मनी गेमिंग प्रतिबंध के बावजूद स्किल-बेस्ड सेक्टर की सुरक्षा और विकास पर था। इसलिए संक्रमणकालीन समर्थन देते हुए सरकार ने 6-12 महीने का ट्रांजिशन पीरियड घोषित किया, जिसमें प्रभावित कंपनियों को लाइसेंस कन्वर्जन और रिस्किलिंग फंड की सुविधा दी गई। साथ ही FIFA और अन्य बॉडीज को आश्वस्त किया कि ई-स्पोर्ट्स को पूर्ण संरक्षण मिलेगा।

जहां तक निवेश व नीतिगत सुरक्षा की बात है तो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना से नियामक स्पष्टता का वादा किया गया, FDI को प्रोत्साहन के लिए टैक्स इंसेंटिव्स बढ़ाए। वहीं खेल मंत्रालय ने स्टार्टअप्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स का ऐलान किया, जो 500 करोड़ का है। जहां तक कानूनी निपटारा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि अधिनियम व्यवसाय स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि जुआ रोककर स्वस्थ इकोसिस्टम बनाता है। इससे उद्योग का अधिकांश विरोध शांत हुआ।

यही वजह है कि ई-स्पोर्ट्स उद्योग ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 पर मुख्य रूप से चिंता जताई, लेकिन पूर्ण विरोध कम था। दरअसल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन (EPWA) ने बिल पारित होने से ठीक पहले पीएम मोदी को पत्र लिखकर स्किल-बेस्ड गेम्स और चांस-बेस्ड गेम्स के बीच अंतर न करने पर आपत्ति दर्ज की। क्योंकि इनकी प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित हैं- पहला, एसोसिएशन ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से खिलाड़ियों की आजीविका (कोचिंग, स्ट्रीमिंग, टूर्नामेंट आयोजन, कंटेंट क्रिएशन) खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर गेमर्स के अवैध प्लेटफॉर्म्स की ओर मुड़ने और भारत की वैश्विक ई-स्पोर्ट्स प्रतिष्ठा को नुकसान का डर जताया।

यह बात अलग है कि ईपीडब्ल्यूए के विरोध का स्वरूप सिर्फ विरोध पत्र के रूप में सीमित रहा, न कि मुकदमेबाजी; बल्कि उन्होंने बिल का स्वागत किया लेकिन सभी गेम्स को एकसमान मानने के खिलाफ आग्रह किया। साथ ही 450 मिलियन गेमर्स वाले उद्योग को बचाने के लिए स्टेकहोल्डर परामर्श की मांग की। बाद में अधिनियम के ई-स्पोर्ट्स को मान्यता देने वाले प्रावधानों से अधिकांश चिंताएं कम हुईं।

हालांकि ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 से संबंधित ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन (EPWA) की चिंताओं पर सरकार ने औपचारिक लिखित जवाब सार्वजनिक रूप से तो नहीं दिया। लेकिन, बिल पारित होने के बाद जारी आधिकारिक बयानों और प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि सरकार ने इनका अप्रत्यक्ष संज्ञान लिया। जहां तक उद्योग जगत की चिंताओं का समाधान की बात है तो EPWA द्वारा उठाई गई स्किल गेम्स और चांस गेम्स के अंतर की मांग को अधिनियम ने स्वीकार किया, ई-स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल का दर्जा देकर प्रतिबंध से बाहर रखा। खेल मंत्रालय ने पत्र के बाद स्टेकहोल्डर मीटिंग्स में आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी। चूंकि यह नीतिगत कदम है, इसलिए सरकार ने ट्रेनिंग अकादमियां और छात्रवृत्तियों की योजना तेज की, जो EPWA की आर्थिक चिंताओं का प्रत्युत्तर मानी जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत लंबित याचिकाओं पर केंद्र ने कहा कि अधिनियम उद्योग को बढ़ावा देगा, नुकसान नहीं। इससे EPWA की अधिकांश आपत्तियां शांत हुईं।

देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 को पारित होने के तुरंत बाद कई विवाद और कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। इससे जुड़े मुख्य विवाद इसके त्वरित पारित होने, रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध और परिभाषाओं की अस्पष्टता पर केंद्रित हैं।

जहां तक नए नियम से प्रभावित होने वाले उद्योग संगठनों की बात है तो उन्होंने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमें ठोक दिए हैं। गेमिंग इंडस्ट्री की प्रमुख बॉडीज जैसे स्न्नह्वस्न्न और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, और दावा किया कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है। वे तर्क देते हैं कि स्किल-बेस्ड गेम्स को जुआ घोषित करना मनमाना है और पर्याप्त स्टेकहोल्डर परामर्श की कमी थी।

इसलिए इस नए अधिनियम की संवैधानिक वैधता विवाद छिड़ गया है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम को मनी बिल के रूप में पेश न करने और लोकसभा में त्वरित बहस (केवल 2 दिन) पर सवाल उठाए, जो विधायी प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन मानते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 तक कई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, लेकिन स्थगन नहीं दिया। वहीं राज्य सरकारों के मामले अलग हैं। खासकर कई राज्य जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने अपने पुराने प्रतिबंधों के साथ संघर्ष का हवाला देकर हाई कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि अधिनियम केंद्र-राज्य समन्वय को अनिवार्य बनाता है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ प्रवर्तन पर PIL भी लंबित हैं। इसप्रकार ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 की त्वरित पारित होने से कई चुनौतियां और सीमाएं उजागर हुई हैं। यह रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन कार्यान्वयन में अस्पष्टताएं बनी हुई हैं। जहां तक कार्यान्वयन चुनौतियां की बात है तो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना में देरी और राज्यों के साथ समन्वय की कमी से नियमों का पालन मुश्किल हो रहा है। वहीं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि वैश्विक प्रवर्तन सीमित है।

जहां तक आर्थिक सीमा की बात है तो एंरियल मनी सेक्टर के नुकसान की भरपाई ई-स्पोर्ट्स से तुरंत नहीं हो पा रही, जिससे 2 लाख नौकरियां प्रभावित हैं। लिहाजा, निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है, क्योंकि नीतिगत स्पष्टता की कमी बनी हुई है। जहां तक कानूनी व नियामक कमियां की बात है तो स्किल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स की परिभाषा अस्पष्ट होने से विवाद बढ़ सकते हैं, जबकि अपील प्रक्रिया धीमी है। लिहाजा लंबे समय में अवैध जुआ को रोकने के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का अभाव प्रमुख बाधा है।

गौरतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) अधिनियम, 2025 ई-स्पोर्ट्स को स्किल-बेस्ड प्रतियोगिताओं के रूप में मान्यता देता है, जिससे इसे रियल मनी गेमिंग से अलग कर आधिकारिक खेल का दर्जा मिला। यह अधिनियम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत ई-स्पोर्ट्स को मुख्यधारा का खेल बनाता है। बताया जाता है कि वर्तमान अधिनियम ई-स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को आधिकारिक खेल का दर्जा देकर आर्थिक विकास को गति देगा। इससे निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, हालांकि रियल मनी गेमिंग बैन के बाद शुरुआती संक्रमण चुनौतीपूर्ण रहेगा।

जहां तक निवेश वृद्धि की बात है तो ई-स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत मान्यता से स्न्नष्ठद्ब और स्पॉन्सरशिप आकर्षित होगी, जो इंडस्ट्री को .1-2 बिलियन तक बढ़ा सकती है। वहीं विशेषज्ञ इसे अनिश्चितता दूर करने वाला कदम मानते हैं, जिससे इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, जहां तक रोजगार सृजन की बात है तो ट्रेनिंग अकादमियां और रिसर्च सेंटर्स से हजारों नौकरियां पैदा होंगी, खासकर कोचिंग, इवेंट मैनेजमेंट और टेक डेवलपमेंट में। इस प्रकार लंबे समय में यह रियल मनी सेक्टर के नुकसान की भरपाई कर 50,000+ जॉब्स जोड़ सकता है।

जहां तक राजस्व लाभ की बात है तो सरकारी समर्थन से टूर्नामेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग और मर्चेंडाइज से नया राजस्व स्ट्रीम बनेगा, जिसमें त्नस्ञ्ज संग्रह भी शामिल है। भारत को ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हब बनाने से निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं, जहां तक आधिकारिक मान्यता की बात है तो ई-स्पोर्ट्स को अब क्रिकेट या फुटबॉल जैसी पारंपरिक खेलों के बराबर एक्सपोजर और वैधता मिलेगी।

आवश्यकता

दैनिक सच मीडिया समाचार पत्र में बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर ग्रामीण में ब्लॉक स्तर पर संवाददाता व प्रतिनिधी की आवश्यकता है। अनुभवी, ईमानदार पत्रकार ही सम्पर्क करें।

सम्पर्क
संपादक-सुमेरसिंह चुण्डावत
मो. 7737275324
रानीदान रावल
मो. 9784179113

FPO जैतारण के हैमेन्द्र सिंह को नाबार्ड राजस्थान से मिला उत्कृष्ट FPO सम्मान

सच मीडिया

जोधपुर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 में किसान उत्पादक संगठन (FPO) जैतारण को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ FPO सम्मान प्रदान किया गया।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव V. Srinivas एवं नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक R. Ravi Babu द्वारा FPO जैतारण के अध्यक्ष हैमेन्द्र सिंह लौटोती को जैतारण क्षेत्र के किसानों के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।

साथ ही, FPO के कार्यों को और सशक्त बनाने हेतु 30 लाख का क्रेडिट समर्थन भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा किसान उत्पादक संगठन जैतारण के कार्यों पर आधारित प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

FPO जैतारण द्वारा किए जा रहे प्रमुख उत्कृष्ट कार्य

1. Food and Agriculture Organization (संयुक्त राष्ट्र) की परियोजना STDF के अंतर्गत किसानों की फसलों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच दिलाना।
2. समन्वित कीट प्रबंधन (IPM) खेती के माध्यम से क्षेत्र के किसानों के मसालों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न एवं तेल फसलों पर प्रभावी कार्य करना।
4. कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत फसल अवशेष से कोयला (कोल) बनवाकर किसानों को उनके अपशिष्ट का उचित मूल्य दिलाना और आय में वृद्धि करना।

पाली वार्ड 37 में गंदगी-सीवरेज और आवारा कुत्तों के आतंक पर प्रशासन हरकत में

सच मीडिया

पाली ब्यूरो। पाली शहर के बीचों-बीच स्थित वार्ड नंबर 37 इन दिनों गंदगी, कचरे के ढेर, जाम सीवरेज, बदहाल नालियों और आवारा कुत्तों के आतंक से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वार्डवासियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर पार्षद विकास बुबकिया के नेतृत्व में वार्डवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था। जिसके तत्पश्चात नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम शुक्रवार को वार्ड में पहुंची और पार्षद विकास बुबकिया के साथ वार्ड वासियों से मिलकर हालात का जमीनी स्तर पर जायजा लिया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया वार्ड का सर्वे

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी कलीम अख्तर, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिलीप कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मण कुमार, स्वास्थ्य जमादार अशोक कुमार की टीम ने वार्ड में फैल रही गंदगी, नालियों की सफाई व्यवस्था और सीवरेज की जाम स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की।

पार्षद विकास बुबकिया के साथ बड़ी संख्या में वार्डवासी रहे मौजूद

निरीक्षण के समय पार्षद विकास बुबकिया के साथ वार्ड के कई जागरूक नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से आदित्य सालेचा, गौरव गौतम चौपड़ा, दीपक मेहता, धर्मेश गेमावत, सुनील सोनी, नवीन सोनी सहित अनेक वार्डवासी शामिल रहे।

कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का ज्वार, गाजे-बाजे के साथ निकाली कलश यात्रा

ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत

सच मीडिया

ब्यावर/शीतल कुमारी। सेंदड़ा ग्राम के मुख्य बाजार से राज श्री गार्डन तक 1051 नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा अपने सिर पर कलश में पानी भरकर कलश यात्रा निकाली गई। जिसका मुख्य बाजार में ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। आस्था का ऐसा ज्वार पहली बार देखा गया। नागेश्वर महादेव मंदिर मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मुख्य बाजार में हर वर्ष की भांति भरा जाने वाला विशाल मेला महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होगा। नागेश्वर महादेव विकास कमेटी सेंदड़ा के सदस्यों ने बताया कि वेद मूर्ति तपोनिस्ठ युग दृष्टा ब्रह्म ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं माताजी शांतिकुंज हरिद्वार के सूक्ष्म संरक्षण में प्रकृति की गोद में बसे सेंदड़ा नागेश्वर महादेव मंदिर मैं शुक्रवार को 1051 कलशो की सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई और ध्वजारोहण के साथ अखंड जाप प्रारंभ हो गए वही आज शनिवार को पंच कुंडीय गायत्री यज्ञ एवं रात्रि महजागरण आयोजित होगा। वही 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल मेला आयोजित होगा। इस दोहरानमेला कमेटी अध्यक्ष राधेश्याम मेवाडा दिलीप गुप्ता जी एडवोकेट कमल कुमार समाजसेवी दादा सिंह चौहान सनी आहूजा एडवोकेट गौतम पालीवाल मानक लाल संतोष कुमार गणपत सिंह गिरधारी सिंह दिलीपसिंहकृष्ण मालवीय अशोक कुमार देवेंद्र कुमार रणजीत सिह रावत इत्यादि।

14 फरवरी 2026 शनिवार :

आज क्या कहते हैं आपके सितारे जाने अपना राशिफल

पण्डित चैतन्य श्रीमाली
श्री देव ज्योतिष एवं पूजन सामग्री केंद्र न्यू हाउसिंग बोर्ड पाली, राजस्थान
सम्पर्क-9314863990

मेष

धनार्जन सुगम होगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता अर्जित करेगा। पठन-पाठन में मन लगेगा। दूर यात्रा की योजना बन सकती है। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा। वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। बेचैनी रहेगी।

वृषभ

वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के व्यवहार से क्लेश हो सकता है। पुराना रोग उभर सकता है। दु:खद समाचार मिल सकता है, धैर्य रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। पारिवारिक चिंता में वृद्धि होगी। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलेगी। तनाव रहेगा।

मिथुन

शत्रु नतमस्तक होंगे। विवाद को बढ़ावा न दें। प्रयास सफल रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा। चोट व रोग से बाधा संभव है। फालतू खर्च होगा। मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रसन्नता रहेगी। जल्दबाजी न करें।

कर्क

लेन-देन में सावधानी रखें। शारीरिक कष्ट संभव है। परिवार में तनाव रह सकता है। शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें।

सिंह

रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

कन्या

अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। किसी विवाद में उलझ सकते हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। जोखिम न उठाएं। घर-बाहर असहयोग मिलेगा। अपेक्षाकृत कार्यों में विलंब होगा। आय में कमी हो सकती है।

तुला

बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। बेचैनी रहेगी। थकान महसूस होगी। वरिष्ठजन सहयोग करेंगे।

वृश्चिक

नई आर्थिक नीति बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग मिलेगा। कारोबारी अनुबंधों में वृद्धि हो सकती है। समय का लाभ लें। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। नेत्र पीड़ा हो सकती है। कानूनी बाधा आ सकती है। विवाद न करें।

धनु

बेचैनी रहेगी। चोट व रोग से बचें। काम का विरोध होगा। तनाव रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम अनुकूल होंगे। पूजा-पाठ में मन लगेगा। तीर्थयात्रा की योजना बनेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। सुख के साधनों पर व्यय हो सकता है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। प्रमाद न करें।

मकर

स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवाद से क्लेश संभव है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। अपेक्षित कार्यों में अप्रत्याशित बाधा आ सकती है। तनाव रहेगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें। राज्य के प्रतिनिधि सहयोग करेंगे।

कुंभ

कष्ट, भय, चिता व बेचैनी का वातावरण बन सकता है। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। मातहतों से संबंध सुधरेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। जल्दबाजी न करें। कुबुद्धि हावी रहेगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा।

मीन

धन प्राप्ति सुगम होगी। ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है। भूमि, भवन, दुकान व फैक्टरी आदि के खरीदने की योजना बनेगी। रोजगार में वृद्धि होगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अपरिचितों पर अतिविश्वास न करें। प्रमाद न करें।

रेरा से भी मिली निराशा

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अर्थात रेरा को जो कड़ी फटकार लगाई, उसके लिए वही उत्तरदायी है। इस प्राधिकरण का गठन जिन उम्मीदों के साथ किया गया था, वह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। रेरा की लचर कार्यप्रणाली के चलते न जाने कितने लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होते हैं और सब जानते हैं कि वहां से न्याय मिलने में समय लगता है। रेरा की निराशाजनक कार्यप्रणाली को इससे समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसे बंद करना ही बेहतर है। उसने यह कठोर टिप्पणी भी की कि वह दिवालिया बिल्डरों को राहत देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वह फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करने के स्थान पर उन बिल्डरों की पक्षधरता करता है, जिन पर उसे निगाह रखनी चाहिए, ताकि वे अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें और उनमें मनमाने तरीके से बदलाव न कर सकें। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के खिलाफ कठोर टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के एक मामले में की हो, लेकिन उसका यह आकलन तो लगभग सभी राज्यों के रेरा पर लागू होता है कि जिन लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था, वे निराश और हताश हैं और उन्हें कोई प्रभावी राहत नहीं मिल रही है। संभवतः इसीलिए उसने यहां तक कहा कि यदि इस संस्था को समाप्त भी कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ गया है कि सभी राज्य रेरा के नए सिरे से गठन पर विचार करें। इसमें संदेह है कि उसकी ओर से स्पष्ट निर्देश के बिना ऐसा हो सकेगा। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार यह देखे कि सभी राज्यों के रेरा सही तरह काम करें, क्योंकि सबमें खामियां घर कर गई हैं। कई मामलों में यह देखने में आया है कि रेरा ने उन बिल्डरों का बचाव किया, जो फ्लैट खरीदारों से साफ तौर पर वादाखिलाफी कर रहे थे। यदि रेरा के अस्तित्व में होने के बाद भी देश भर में लाखों प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं तो इसका अर्थ है कि कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। बहुत दिन नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही यह उजागर हुआ था कि दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बिल्डरों ने बैंकों से मिलकर लाखों फ्लैट खरीदारों के साथ ठगी की। यह ठगी सबवेंशन स्कीम के जरिये की गई। सबवेंशन स्कीम के तहत किसी परियोजना के तहत स्वीकृत राशि सीधे बिल्डरों के खातों में भेजी जाती थी। उन्हें घर खरीदारों को फ्लैट सौंपने तक ईएमआई का भुगतान करना होता था, लेकिन कई मामलों में बिल्डरों ने फ्लैट तैयार किए बिना ईएमआई का भुगतान बंद कर दिया। इस पर बैंक फ्लैट खरीदारों से शेष ईएमआई की मांग करने लगे। इसे अन्याय और अंधेर के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

उपभोक्ता आन्दोलन की 40 वर्ष की यात्रा - कितनी न्यायकारी

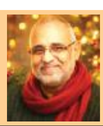

अविनाश राय खन्ना
पूर्व सांसद

उपभोक्ता आन्दोलन का सूत्रपात 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून के द्वारा हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं के प्रति बरती गई लापरवाहियों जैसे खराब वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाँच करके यथोचित आदेश पारित करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तरों पर न्यायालयों के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किए गए। वर्ष 2019 में इस कानून में अनेकों बदलाव भी लाए गए, किन्तु आज यदि 40 साल की इस उपभोक्ता संरक्षण यात्रा का आंकलन करें तो ऐसा लगता है कि न्याय मांगने वालों को शीघ्र न्याय में विलम्ब तो देश के सामान्य न्याय व्यवस्था की तरह ही झेलना पड़ रहा है, जब कि दूसरी तरफ देशवासियों की बहुत बड़ी संख्या तो अभी तक अपने इस बहुमूल्य अधिकार के बारे में अंजान ही दिखाई देती है।

इसलिए सबसे पहले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के प्रति अज्ञानता की इस मूल कमी को दूर करने के लिए इसे शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में तो यह एक अच्छा विषय बनाया जा सकता है, बल्कि हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू सहित देश की सभी भाषाओं की पुस्तकों में मैट्रिक और इंटर स्तर पर भी कुछ न कुछ पाठ जोड़े जा सकते हैं। जब तक ऐसे पाठ्यक्रम सम्भव न हों, तब तक विद्यालयों में गोष्ठियों या नुक्कड़ नाटकों की तरह जागरुकता अभियान चलाए जा सकते हैं। देश के गैर सरकारी सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी ऐसे अभियानों में शामिल किया जा सकता है।

उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से जो उपभोक्ता संरक्षण अभियान तीव्र गति से चलना चाहिए था, वह भी आज दिखाई नहीं दे रहा। कहने को उपभोक्ता अदालत व्यवस्था इस रूप में गठित की गई थी कि जिसमें एक सामान्य शिकायत पत्र पत्र कार्यवाही सम्भव हो सकती थी, परन्तु यहाँ भी सामान्य अदालतों की तरह छोटी सी राशि वाले मामले में भी वकील करना पड़ता है, मुकदमा तैयार होता है, दस्तावेज लगाए जाते हैं, फिर गवाहों की उपस्थिति से याचिका के तथ्यों को सिद्ध करना पड़ता है और अन्त में वकीलों की बहस और फिर आदेश की प्रतीक्षा। इतना ही नहीं तीन स्तर की अपील पद्धति शिकायतकर्ता के लिए आशा के स्थान पर निराशा, थोड़ी सी राशि का दावा करने के स्थान पर उससे अधिक राशियाँ इस अदालत व्यवस्था की भेंट चढ़ाना और पल भर के निर्णय के स्थान पर दिन, महीने, साल यूं गुजरते जाएंगे तथा तारीख पर तारीख जैसे डायलाग उपभोक्ता अदालतों पर भी बोले जाते हैं।

सामान्यतः उपभोक्ताओं की शिकायत किसी घरेलू वस्तु या सेवा से सम्बन्धित होती है। ऐसी छोटी-छोटी शिकायतों के निरीक्षण, परीक्षण में सामान्य विवेक का प्रयोग करते हुए भी शीघ्र निर्णय सम्भव है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ राशि का भुगतान करने के लिए चैक जारी किया। दूसरे व्यक्ति ने वह चैक अपने बैंक में जमा करवा दिया। बैंक द्वारा राशि प्राप्त होने पर वह राशि किसी गलत खाते में जमा कर दी गई। अब ऐसी सामान्य त्रुटि वाली शिकायत पर किस चीज का गम्भीर या गहरा परीक्षण किया जाना है। शिकायत के साथ व्यक्ति चैक जमा कराने की कॉपी और जिस बैंक से राशि निकली, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे मामलों में सारी अदालती प्रक्रिया को लम्बी अवधि की तारीखों के साथ निबटाने में यदि एक दो वर्ष लग जाते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपभोक्ता न्याय प्रणाली में विवेकशीलता या गतिशीलता का तो कोई स्थान ही नहीं है।

सामान्य अदालतों की तरह अब उपभोक्ता अदालतों में भी ई-फाईलिंग अर्थात याचिका और सभी दस्तावेजों को पी. डी. एफ. के रूप में अदालतों के निर्धारित काउंटर पर फाईल करना और इसी प्रक्रिया का अनुसरण जवाब, गवाहियां और लिखित बहस तक किया जाना किसी भी दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अभियान को एक जन आन्दोलन बनने में सहायता नहीं कर सकता।

सूचना के अधिकार ने भी एक आन्दोलन की तरह कानून का रूप लिया था। निःसंदेह यह अभियान तीव्र गति से चल रहा है। हाथ से लिखकर किसी भी विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। सामान्यतः 30 दिन के अन्दर उत्तर भी आ ही जाता है। संतोषजनक उत्तर न होने पर अपील भी हस्तलिखित दी जा सकती है और उसका निबटारा भी शीघ्र होता है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सूचना आयोग भी इसी प्रकार यथा सम्भव तीव्र गति और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई के लिए 15-15 मिनट के स्लैब निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पक्षकारों का समय व्यर्थ नहीं होता। वकील के माध्यम से बहस करो या पक्षकार स्वयं बहस करे, बहस किसी भी भाषा में की जा सकती है और यहाँ तक की आवश्यकता पड़ने पर लिखित बहस के रूप में हाथ से ही संक्षिप्त बिन्दु लिखकर अदालत को दे दिए जाए। उपभोक्ता आन्दोलन को भी सूचना के अधिकार जैसी पद्धति अपनानी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सरकारें बार-बार कानूनों में संशोधन करें या अनुशासन की किसी कड़ी प्रक्रिया को लागू करें। वास्तव में उपभोक्ता अदालतों के न्यायाधीशों को स्वयं ही अपने अन्दर यह विवेक जाग्रत करना चाहिए कि जो आदमी अपने उपभोक्ता के अधिकार को कुछ हजार रुपये के रूप में लागू करवाना चाहता है, उसे उस अधिकार की राशि से अधिक राशि और लम्बा समय खर्च करना तो अपने आप में ही एक गम्भीर अन्याय है। औपचारिक अदालती प्रक्रियाओं को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करके सीधा याचिकाकर्ता से सम्वाद स्थापित करके उपभोक्ता आन्दोलन को वास्तव में न्यायकारी बनाया जा सकता है।

बांग्लादेश में नई सरकार, भारत को क्या दरकार

डॉ. प्रभात ओझा

बांग्लादेश में चुनाव नतीजों से साफ हो गया कि वहां बीएनपी की सरकार होगी और तारिक रहमान देश के नये प्रधानमंत्री होंगे। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह सहज ही है कि आंतरिक और बाह्य राजनीतिक ताकतें चुनाव परिणाम को सकारात्मक ढंग से लें। बांग्लादेश के लिए भी यह परंपरा मान्य होनी चाहिए, हालांकि इसको लेकर कुछ संशय चुनाव के साथ ही शुरू हो चुके हैं। इसे समझने के लिए दो बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला यह कि चुनाव प्रक्रिया पर देश के अंदर से ही सवाल उठाये गये हैं। दूसरा बिंदु पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में आश्रय लेना है। यह स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती कि पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी बांग्लादेश में बैन कर दी गई। फिर जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, वे ही निर्वाचन प्रक्रिया से ही संतुष्ट नहीं हैं। भारत के लिए तो यह निर्वाचन इसलिए मायने रखता है कि प्रधानमंत्री के रूप में जो नेता उसके अनुकूल रहीं, उन्हें बांग्लादेश से निर्वासित होकर आना पड़ा। बात इतनी ही होती तो चिंता न होती। उन्हें शरण देने के पहले से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल रहा है।

फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत पर पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को बधाई दी। उन्होंने इसे रहमान के नेतृत्व पर बांग्लादेश की जनता का भरोसा बताया। मोदी ने खुद भरोसा दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। उन्होंने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तारिक रहमान के साथ काम करने के लिए उत्सुकता जताई।

स्वाभाविक कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश और पड़ोसी होने के नाते भारत यह रुख अपनाये। इसके विपरीत हाल के घटनाक्रम आगे की राह आसान नहीं होने के ही संकेत देते हैं। भारत के राजनयिक पड़ोस में हो रहे चुनाव के दौरान जमात-ए-इस्लामी के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए थे। भारत का मानना रहा है कि बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रभाव में रहती है। जमात इस चुनाव में अपने को सत्ता हासिल करने के करीब मानकर चल रहा था। उसने 11 दलों के साथ गठबंधन बनाया था। स्वाभाविक है कि ये छोटे दल हैं और पूरी तरह से जमात की ही पकड़ में रहे हैं। जमात ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भारत विरोधी रुख को छिपाया भी नहीं। अब हार के बाद उसकी हताशा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल के रूप में सामने आई है। यहीं नहीं, साल 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन करने वाली नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने भी चुनाव नतीजों में हेरफेर के आरोप लगाये हैं।

सच है कि बांग्लादेश में अति कट्टरपंथियों की हार खुद अपने लोगों और भारत के अनुकूल है। जिस तरह के हालात से बांग्लादेश गुजरा है, नई सरकार को स्थिति सामान्य करने में समय लगेगा। शेख हसीना के देश से बाहर आ जाने के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बना माहौल भारत के खिलाफ ही रहा। हालात यह हो चले थे कि हिन्दू नागरिकों की लींचिंग के दौरान हत्या तक हुई। यह वही क्षेत्र है, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जहां लोकतांत्रिक आंदोलन को भारत ने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि बांग्लादेश के उदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश के नायक शेख मुजीब की हत्या के बाद से भारत को अपने इस पड़ोसी के साथ रिश्तों को लेकर सजग रहना पड़ा है। सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी के बूते भारत ने इसे सम्भाले रखा।

यह भी देखना होगा कि जिस पाकिस्तान से निकल कर बांग्लादेश अस्तित्व में आया, शेख हसीना के दौर में वहां पाकिस्तान की दाल नहीं गली। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में भारत विरोधी रुख बने रहने की उम्मीद ही नहीं, कोशिश भी करेगा। शेख हसीना के हटने के बाद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में उसे अपने मकसद में कामयाबी मिलती दिखी। यूनुस पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में तेजी से चल रहे थे।

देखना होगा कि अब जबकि बीएनपी सत्ता में होगी, चीन के साथ ही पाकिस्तान के साथ वह अपने रिश्ते कैसा रखती है। भारत ने तो शेख हसीना को शरण देने के साथ बीएनपी से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जताना और उनके निधन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने को खास माना जा सकता है। खुद खालिदा जिया के शासनकाल में भारत का उनके देश के साथ रिश्ते को बहुत अच्छा नहीं, तो खराब भी नहीं कह सकते। तारिक रहमान उन्हीं के बेटे हैं। युवा हैं, अभी पिछले साल के अंत में ही लंबे समय बाद स्वतः निर्वासन की स्थिति से लौटे हैं। उम्मीद की जाती है कि वे भारत से अपने देश के रिश्तों को बदलती दुनिया के हिसाब से देखेंगे। हमेशा की तरह भारत तो बेहतर रिश्ते ही चाहेगा। **(हि.स.)**

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

बजट 2026 : AI से खेती में क्रांति या सिर्फ एक सपना?

एडवोकेट जयदेव राठी

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक गेम चेंजर के रूप में पेश किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने रिकॉर्ड 11 बार एआई का जिक्र किया और 'भारत विस्तार' नामक एक बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की। सवाल यह है कि क्या यह तकनीकी हस्तक्षेप वाकई भारत के लगभग 14 करोड़ किसानों की तस्वीर बदल सकेगा, या यह महज एक और सरकारी घोषणा बनकर रह जाएगी?

बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। इसमें सबसे उल्लेखनीय है 'भारत विस्तार' प्लेटफॉर्म की स्थापना। यह एक बहुभाषी एआई टूल है जो एग्री स्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सत्यापित कृषि पद्धतियों को एआई सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु परिस्थितियों और फसल के आधार पर वैयक्तिकृत कृषि सलाह मिलेगी। मौसम का सटीक पूर्वानुमान, कीट और रोग प्रबंधन, बाजार की जानकारी और क्षेत्रीय भाषा समर्थन भी इसके प्रमुख फीचर्स हैं। इसके अतिरिक्त, 'कृषि साथी' नामक एआई चैटबॉट की भी घोषणा की गई है, जो वॉयस और वीडियो के माध्यम से किसानों के सवालों का जवाब देगा।

आधुनिक तकनीक और एआई के सही इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव संभव हैं। प्रिसिजन फार्मिंग के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। एआई आधारित सिस्टम यह बता सकता है कि किस खेत के किस हिस्से में कितना पानी, उर्वरक या कीटनाशक चाहिए, जिससे लागत में 20-30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। समय पर सही जानकारी मिलने से फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। मौसम का सटीक पूर्वानुमान, बीमारियों की शीघ्र पहचान और बाजार की सही जानकारी से किसान बेहतर फैसले ले सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपज में 15-25 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है।

जोखिम प्रबंधन में भी सुधार होगा। एआई सिस्टम ऐतिहासिक डेटा और वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण से फसल विफलता के जोखिम को पहले से भांप सकता है और निवारक उपाय सुझा सकता है। यह खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो एक ही फसल पर निर्भर रहते हैं। बाजार से बेहतर जुड़ाव भी मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ सकते हैं, बिचौलियों की भूमिका कम कर सकते हैं और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला सकते हैं।

हालांकि, एआई की इन संभावनाओं के बावजूद, भारतीय कृषि क्षेत्र में इसके व्यापक कार्यान्वयन में कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर छोटे और सीमांत किसानों में डिजिटल साक्षरता की गंभीर कमी है। जो किसान 85 प्रतिशत कृषक समुदाय का हिस्सा हैं, उनमें से अधिकांश स्मार्टफोन का बुनियादी उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन एआई-आधारित जटिल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। एक औसत भारतीय किसान की उम्र 50 वर्ष से अधिक है और उनमें से कई अनपढ़ या अर्ध-साक्षर हैं। यदि 'भारत विस्तार' जैसे प्लेटफॉर्म को सफल बनाना है, तो सिर्फ बहुभाषी इंटरफेस काफी नहीं है। किसानों को इन तकनीकों के उपयोग का व्यापक प्रशिक्षण देना होगा, जिसके लिए जमीनी स्तर पर कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी।

भारत के लगभग 6.44 लाख गाँवों में से 6.13 लाख से अधिक गाँवों में 3%/4% इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध हैं। गांवों में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जहां इंटरनेट उपलब्ध है, वहां भी कनेक्टिविटी अस्थिर और धीमी है। एआई-आधारित प्लेटफॉर्म को काम करने के लिए स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। बिना मजबूत डिजिटल अवसंरचना के, ये सारी योजनाएं कागज पर ही रह जाएंगी। हालांकि सरकार ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस और भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त है।

एआई-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। छोटे और सीमांत किसान, जो भारत के किसान समुदाय का 85% हिस्सा हैं, इस तरह के निवेश का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। उनकी औसत वार्षिक आय ही इतनी कम है कि वे मूलभूत कृषि आदानों के लिए कर्ज पर निर्भर रहते हैं। बजट में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी और ऋण की बात की गई है, लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि इन योजनाओं का लाभ अक्सर बड़े किसानों तक ही सीमित रह जाता है। छोटे किसानों तक पहुंचने के लिए इन योजनाओं को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाना होगा।

एआई सिस्टम के लिए किसानों का व्यक्तिगत और कृषि संबंधी डेटा एकत्र करना आवश्यक है। लेकिन इस डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल हैं। किसानों की जमीन, फसल, आय और अन्य संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। इस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, इसका उपयोग कैसे होगा, और क्या किसानों की सहमति ली जाएगी - ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब अभी नहीं मिले हैं। भारत में व्यापक डेटा संरक्षण कानून का अभाव इस चिंता को और बढ़ाता है।

एआई और आधुनिक तकनीक पर अत्यधिक जोर देने से यह खतरा है कि पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक कृषि पद्धतियों और स्थानीय ज्ञान की उपेक्षा हो सकती है। भारतीय किसानों ने सदियों से अपनी मिट्टी, जलवायु और फसलों के बारे में गहन ज्ञान विकसित किया है। एआई सिस्टम को इस पारंपरिक ज्ञान के साथ एकीकृत करना होगा, उसे प्रतिस्थापित नहीं करना है। स्वचालन और एआई के बढ़ते उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यदि मशीनें और एआई मानव श्रम का स्थान लेने लगें, तो लाखों खेत मजदूरों के लिए यह अस्तित्व का संकट बन सकता है।

इन चुनौतियों को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि बजट 2026 में घोषित एआई पहल अकेले किसानों की तस्वीर बदल देगी। हां, इसमें संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सबसे पहले, डिजिटल अवसंरचना में व्यापक सुधार जरूरी है। हर गांव तक तेज और स्थिर इंटरनेट पहुंचाना होगा। दूसरा, किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देना होगा। राष्ट्रीय कृषि ई-गवर्नेंस योजना और फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम जैसी पहलों को मजबूत करना होगा। हर पंचायत में डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित करने होंगे और कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को एआई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना होगा।

वित्तीय सहायता को वास्तव में समावेशी बनाना होगा। छोटे और सीमांत किसानों तक सब्सिडी और ऋण पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना होगा। स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सामूहिक रूप से तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे लागत कम होगी। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए मजबूत कानूनी ढांचा बनाना होगा। किसानों को उनके डेटा पर स्वामित्व और नियंत्रण देना होगा। पारंपरिक ज्ञान को एआई सिस्टम में एकीकृत करना होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने होंगे।

केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य पहले से ही एआई-आधारित कृषि परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यूपी प्रगति परियोजना के तहत एआई 4 शुगर और एआई 4 राईस जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो विश्व बैंक और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से संचालित हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसी पहल करनी होगी। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख कृषि राज्यों को एआई और डिजिटल कृषि में निवेश बढ़ाना होगा।

कृषि में एआई क्रांति लाने में निजी क्षेत्र और कृषि-तकनीक स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में पहले से ही कई सफल एग्रीटेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो किसानों को डिजिटल समाधान प्रदान कर रहे हैं। सरकार को इन स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना चाहिए और 'भारत विस्तार' जैसे प्लेटफॉर्म को एक ओपन इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना चाहिए, जहां विभिन्न सेवा प्रदाता अपने समाधान एकीकृत कर सकें।

बजट 2026 में एआई को कृषि का केंद्रीय तत्व बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह सही दिशा में एक कदम है। लेकिन यह केवल पहला कदम है, अंतिम समाधान नहीं। किसानों की तस्वीर बदलने के लिए तकनीक के साथ-साथ नीतिगत सुधार, संस्थागत समर्थन और सामाजिक बदलाव की भी जरूरत है। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह जादू की छड़ी नहीं है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ लागू किया जाता है।

यदि यह केवल बड़े किसानों और कॉर्पोरेट कृषि तक सीमित रह गई, तो यह असमानता को और बढ़ाएगी। लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया और छोटे किसानों को इसमें शामिल किया गया, तो यह वाकई भारतीय कृषि में क्रांति ला सकती है। सरकार को यह समझना होगा कि किसानों की असली समस्या केवल तकनीक की कमी नहीं है। उनकी मूल समस्याएं हैं - फसलों का उचित मूल्य न मिलना, कृषि ऋण का बोझ, छोटी जोत का आकार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। इन मूलभूत समस्याओं के बिना समाधान के एआई जैसी तकनीक केवल सतही सुधार ही ला सकती है।

इसलिए, बजट 2026 की एआई पहल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, फसल बीमा योजना में सुधार, कृषि ऋण माफी, सिंचाई अवसंरचना का विस्तार और कृषि उपज मंडी समिति सुधारों जैसे व्यापक कृषि सुधारों के साथ जोड़ना होगा। तभी किसानों की तस्वीर वाकई बदल सकती है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि 'भारत विस्तार' और अन्य एआई पहलें जमीन पर कितना प्रभाव डालती हैं। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। लेकिन एक बात तय है - डिजिटल और एआई क्रांति अब अपरिहार्य है, और भारतीय कृषि को इसके साथ तालमेल बिठाना ही होगा। सवाल यह है कि क्या हम इस बदलाव को समावेशी और न्यायसंगत बना पाएंगे, या यह एक और डिजिटल विभाजन का कारण बन जाएगा।

स्वतंत्र टिप्पणीकार

भारत एआई अनुप्रयोग भंडार - प्रभाव के लिए संदर्भ-नवाचार के पैमाने का विस्तार

श्री एन दयासिंधु - श्री ऋषिकेश टी कृष्णन

भारत में एआई की अंतिम सफलता इसके जीपीयू क्लस्टरों के आकार से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि हमारे एआई अनुप्रयोग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार ला सकते हैं - उदाहरण के लिए, जब एआई आशा कार्यकर्ताओं को उच्च जोखिम वाली गर्भवती स्त्रियों का पता लगाने में मदद करता है, या छोटे किसानों को कीटनाशक की खपत पर महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद करता है, या एक दूर-दराज स्थित सरकारी स्कूल के बच्चे की पढ़ाई और गणित में अंक बढ़ाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 इस बात में व्यावहारिक है कि भारत एआई का लाभ कैसे उठा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय एआई आर्थिक परिषद ने प्रस्ताव किया है कि एआई का प्रमुख उद्देश्य मानव प्रधानता और आर्थिक हित पर आधारित है। इस बात में स्पष्टता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एआई अपनाने की नीति को मानव कल्याण और आर्थिक समावेश में सहायक होना चाहिए। एआई को घरेलू आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और एआई अपनाने के लाभ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और सभी नागरिकों तक पहुँचने चाहिए।

सौभाग्य से, हमारे लिए, भारतीय नवोन्मेषक ऐसे एआई अनुप्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करते हैं, जो तात्कालिक तौर पर और भारत के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शहरी प्रबंधन और आपदा तैयारी से जुड़े अनुप्रयोग आशाजनक हैं। सही समर्थन के साथ, इनमें से कई अनुप्रयोगों का पूरे भारत में विस्तार किया जा सकता है और भविष्य में इन्हें भारत एआई अनुप्रयोग भण्डार में शामिल किया जा सकता है, और यहां तक कि इन्हें वैश्विक बाजारों में भी ले जाया जा सकता है। आइए कुछ रोचक पहलों पर नजर डालें।

स्वास्थ्य देखभाल : निरामई ने बिना किसी दवा-सुई वाला (नॉन-इनवेसिव), गोपनीयता के प्रति जागरूक स्तन कैंसर जांच उपकरण विकसित किया है, जो पारंपरिक मैमोग्राफी के बजाय एआई-संचालित थर्मल इमेजिंग का उपयोग करता है। यह उपकरण सभी उम्र की महिलाओं में असामान्य स्थिति का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिसमें घने स्तन ऊतक भी शामिल हैं जहां मैमोग्राफी अक्सर विफल हो जाती है। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक और किफायती है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच को व्यावहारिक बनाता है। Qure.ai एक एआई उपकरण है, जो सेकंडों में एक्स-रे और सीटी स्कैन का विश्लेषण करता है, टीबी, फेफड़ों के कैंसर और दिल की समस्या जैसी 35 से अधिक स्थितियों का पता लगाता है। यह समाधान संसाधन-सीमित परिस्थितियों में बहुत प्रभावी है जहां रेडियोलॉजिस्ट अनुपलब्ध हैं तथा दूरदराज के जिलों में तेजी से प्राथमिक परीक्षण और उपचार की सुविधा प्रदान करते हैं। एआईस्टेथ, एक एआई-संचालित स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ों को सटीक, दूरस्थ निदान के लिए दृश्य तरंग रूपों में बदल देता है। यह किफायती उपकरण 93% सटीकता के साथ ग्रामीण भारत में स्वास्थ्यकर्मियों को शुरुआती दौर में ही हृदय और श्वसन समस्याओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। यह विशेषज्ञ देखभाल में मौजूद महत्वपूर्ण कमी को समाप्त करता है और इसमें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की क्षमता है।

कृषि : न्योपर्क एक हल्का-फुल्का उपकरण है, जो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करके पारंपरिक लैब रसायनों के बिना तुरंत मिट्टी के स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है। यह पांच मिनट से कम समय में 12 प्रमुख मृदा-मानकों पर लैब-सटीक परिणाम प्रदान करता है। यह किसानों को उर्वरक के उपयोग पर डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और इनपुट खर्च में कमी आती है। वाधवानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संस्थान का कॉटनऐस एक एआई -आधारित मोबाइल ऐप है जो किसानों को जाल में पकड़े गए कीड़ों के फोटो अपलोड करने की सुविधा देता है और कीटनाशक के उपयोग को लेकर तत्काल, स्थान-अनुकूल सलाह प्राप्त करता है। यह ऐप हज़ारों छोटे कपास किसानों को पिंक बुलवर्म जैसे कीड़ों से अपनी फसल की रक्षा करने में मदद करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता की फसल मिलती है और आय में वृद्धि होती है। निको रोबोटिक्स एआई -संचालित रोबोट का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर विज़न (दिन और रात वाले कैमरे) से लैस हैं, ताकि वास्तविक समय में कीड़े और खरपतवार की पहचान की जा सके। यह प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव को सक्षम बनाता है तथा इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि रसायनों का उपयोग केवल आवश्यक जगहों पर ही किया जाएगा। इससे कीटनाशकों के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी आई है (कुछ मामलों में 60-90% तक), जिससे किसानों की लागत घटती है और पर्यावरण विषाक्तता कम होती है। क्रॉपिन एक एआई-सक्षम डिजिटल इकोसिस्टम है जो खेत की निगरानी, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण और किसान सहभागिता तक फैला हुआ है। यह स्थायी उत्पादकता और जलवायु-अनुकूल निर्णयों को बढ़ावा देता है, हिस्सों में बंटी प्रथाओं को अनुमान-योग्य कृषि प्रणालियों में बदल देता है, जिसका वैश्विक स्तर विस्तार किया जा सकता है।

शिक्षा : पढ़ाई विद एआई एक एआई-संचालित व्यक्तिगत ज्ञान-प्राप्ति प्लेटफार्म का उपयोग करता है, जिसे सरकारी स्कूलों में गणित सीखने के कमजोर परिणामों में को सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केवल छह सप्ताह में, इस पहल ने उत्तीर्ण होने की दर और उच्च-प्राप्त करने वालों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार किया। यह ग्रामीण भारतीय शिक्षा में सीखने के अंतर को पाटने के लिए एक ऐसे मॉडल के रूप में काम करता है, जिसके पैमाने का विस्तार किया जा सकता है। राकेट लर्निंग के पास अप्पू (एक जनरेटिव एआई हाथी) नामक एआई संचालित शिक्षा साथी है, जो माता-पिता और बच्चों के साथ व्हाट्सएप के जरिए संवाद करता है। यह छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और अंकगणित कौशल प्राप्त करने में मदद करने के लिए छोटे-छोटे, खेल-आधारित गतिविधियाँ प्रदान करता है। बेलगावी स्मार्ट सिटी अपने सार्वजनिक पुस्तकालय में डीप लर्निंग-सक्षम ई-बुक्स को एकीकृत कर रहा है। उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने और कहानी की रूपरेखा, शब्दावली और कठिनाई स्तर को वास्तविक समय में अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन की गई इन किताबों ने सहभागिता और समझ के स्तर में सुधार किया है। केवल दो सप्ताह में पढ़ने की गति में 12% वृद्धि हुई है।

सरकार इन जमीनी स्तर पर केंद्रित एआई नवाचारों के लिए एक शक्तिशाली इकोसिस्टम आयोजक बन सकती है और इन्हें पूरे भारत में उच्च-प्रभाव वाले अनुप्रयोगों तक विस्तार करने में मदद कर सकती है। सरकार का एक मुख्य ध्यान इन एआई अनुप्रयोगों के लिए बाजार बनाने में सहायता करना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार खरीद की सुविधा प्रदान कर सकती है, जहां सूचीबद्ध घरेलू एआई अनुप्रयोग सरकार (राज्य सरकार सहित) के विभागों, अस्पतालों, स्कूलों आदि के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि में एआई के लिए मानक स्थापित करके, सरकार एक विश्वसनीय वातावरण बना सकती है, ताकि ग्राहक और नागरिक इन्हें आसानी से अपना सकें।

एक बार जब ये एआई अनुप्रयोग खुद को साबित कर लेते हैं, तो सरकार सबसे प्रभावशाली अनुप्रयोगों को भारत एआई अनुप्रयोग भंडार में एकीकृत करने में सुविधा प्रदान कर सकती है - यानी, ऐसे समाधान जो भारत के पैमाने और विविधता के लिए बनाए गए हैं और विश्व स्तर पर उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय एआई अनुप्रयोग भंडार के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय शासन रूपरेखा, जो यूरोपीय जीडीपीआर जैसी अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ मेल खाती हो, इस भंडार को कई देशों में तुरंत शुरू करने (प्लग-एंड-प्ले) के योग्य बना सकता है।

(ऋषिकेश टी कृष्णन आईआईएम बैंगलोर में रणनीति के प्रोफेसर हैं। एन दयासिंधु इतिहास रिसर्च एंड डिजिटल के सह-संस्थापक और सीईओ हैं।)

पर्यावरण विचार

भोजन की श्रृंखला जो मेन कहते उसे हम फूड चेन

-डॉ. संजीव कुमारी